



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 3, 1979/कार्तिक 12, 1901
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 3, 1979/KARTIKA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रखा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the
Administrations of Union Territories)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ERRATUM

New Delhi, the 17th October, 1979

S.O. 3643.—In the Election Commission's Notification published in Hindi as का० प्रा० 535 (प्र) and in English as 'S.O. 535(E)' at pages 935 and 936 of the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3(ii) dated the 19th September, 1979 for नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1979 and 'New Delhi, the 19th September, 1979', appearing respectively, as the date of the Notification read नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1979 and "New Delhi, the 15th September, 1979"

[No. 429/DNH/79/5031]

O. N. NAGAR, Under Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1979

का० प्रा० 3644.—एक प्राधिकार एवं निरन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एन. नगर द्वारा मैसर्स केन्ट लीड्स मीटर मैन्यु-

फैक्ट्रिंग कम्पनी लि० (प्रब मैसर्स के० एल० एम० इंजीनियरिंग कम्पनी लि० के नाम से ज्ञात है) के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1205/75) के निरस्तकरण को अधिसूचित करती है।

[का० सं० 23/12/79-एम० (1)]

इन्द्रलाल नागपाल, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 16th October, 1979

S.O. 3644.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s. Kent Leeds Meter Manufacturing Company Limited (now known as M/s. KLM Engineering Company Ltd.) under the said Act (Certificate of Registration No. 1205/75).

[F. No. 23/12/79-M(I)]

I. L. NAGPAL, Under Secy.

गृह मंत्रालय

(कांसक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1979

कां०ब्रा० 3645.—खण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा भारत के किसी भी राज्य या संघ शासित क्षेत्र जिसमें उपरोक्त धारा के उपबन्ध लागू होते हैं, में कानून द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालयों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा ट्रायल न्यायालयों में दायर किये गये मामलों तथा अपीलों, पुनरीक्षणों या इन मामलों से उत्पन्न अन्य विषयों के संचालन के लिये केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के श्री सी० सहाय, बरिष्ठ लोक अभियोजक को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 225/42/79-ए०बी०डी०-2]

टी० के० सुब्रमनियम, प्रवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 18th October, 1979

S.O. 3645.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri C. Sahay, Senior Public Prosecutor in the Central Bureau of Investigation as a Special Public Prosecutor for the conduct of cases instituted by Delhi Special Police Establishment in trial courts, and appeals, revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate Courts, established by law in any State or Union Territory of India to which the provisions of the aforesaid section apply.

[No. 225/42/79-AVD-II.]

T. K. SUBRAMANIAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1979

प्राय-कर

कां०ब्रा० 3646.—प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (ii) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा 30 जनवरी 1979 को जारी की गई अधिसूचना संख्या 2690 (फा०सं० 404/27/क०व०म०-बड़ौदा/79-प्रा०क०सं०) एतद्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या 3011(फा०सं० 404/27/क०व०म०-बड़ौदा/79-प्रा०क०सं०)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th September, 1979

INCOME TAX

S.O. 3646.—The Notification issued in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 2690 (F. No. 404/27/TRO-Baroda/79-ITCC) dated 30-1-1979 in pursuance of sub-clause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) is hereby cancelled.

[No. 3011 (F. No. 404/27/TRO-Baroda/79-ITCC)]

कां०ब्रा० 3647.—प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एच०बी० लापसीवाला को, जो केन्द्रीय सरकार के

राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. श्री पी० टी० मलानी की कर वसूली अधिकारी के रूप में जो नियुक्ति 30 जनवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 2694(फा०सं० 404/27/क०व०म०-बड़ौदा/79-प्रा०क०सं०) के अन्तर्गत की गई थी वह एतद्वारा रद्द की जाती है।

3. यह अधिसूचना, श्री एच० बी० लापसीवाला द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख से लागू होगी।

[संख्या 3013(फा०सं० 404/27/क०व०म०-बड़ौदा/79-प्रा०क०सं०)]

S.O. 3647.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri H. B. Lapsiwala being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri P. T. Malani as Tax Recovery Officer made under Notification No. 2694 (F. No. 404/27/TRO-Baroda/79-ITCC) dated 30-1-79 is hereby cancelled.

3. This Notification shall come into force with effect from the date Shri H. B. Lapsiwala takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 3013 (F. No. 404/27/TRO-Baroda/79-ITCC)]

कां०ब्रा० 3648.—प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री डी० एच० जोशी को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. श्री वी०एम० शेलट की कर वसूली अधिकारी के रूप में जो नियुक्ति 14 जुलाई, 1975 की अधिसूचना संख्या 962(फा०सं० 404/63/75-प्रा०क०सं०) के अन्तर्गत की गई थी वह एतद्वारा रद्द की जाती है।

3. यह अधिसूचना, श्री डी० एच० जोशी द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 3015(फा०सं० 404/27/क०व०म०-बड़ौदा/79-प्रा०क०सं०)]

एच० वेंकटरामन्, उप सचिव

S.O. 3648.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of the Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri D. H. Joshi being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri V. M. Shelat as Tax Recovery Officer made under Notification No. 962 (F. No. 404/63/75-ITCC), dated 14-7-75 is hereby cancelled.

3. This Notification shall come into force with effect from the date Shri D. H. Joshi takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 3015 (F. No. 404/27/TRO-Baroda/79-IECC)]

H. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

(राजस्व व बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1979

प्राय-कर

कां०ब्रा० 3649.—केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री तुलजा भवानी मंदिर ट्रस्ट, तुलजापुर" को, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 2991(फा०सं० 176/58/79-प्रा०क० (ए I))]

(Department of Revenue & Insurance)

New Delhi, the 3rd September, 1979

INCOME TAX

S.O. 3649.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) (b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961

(43 of 1961) the Central Government hereby notifies Shri Tulja Bhawani Mandir Trust, Tuljapur, to be a place of public worship of renewal throughout the State of Maharashtra for the purposes of the said Section.

[No. 2991 (F. No. 176/58/79-IT(AI))]

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर 1979

आय-कर

का० प्रा० 3650.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 1 (फा० सं० 55/233/63-प्रा० क०) तारीख 18-5-64 से संशोधन अनुसूची में क्रम सं० 89 के पश्चात् निम्नलिखित परिवर्धन करता है;

नीचे अनुसूची के स्तंभ 3, 4, 5, 6 और 7 में विनिर्दिष्ट अधिकारी अनुसूची के स्तंभ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की बावत, क्रमशः आयकर अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) आयकर आयुक्त (अपील) और आयकर आयुक्त के सभी कृत्यों का पालन करेंगे।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
90	ब्रिटिश एयरोस्पेस के भारत में कहीं भी सैनिक कर्मचारी	आयकर अधिकारी प्राइवेट सेल मकिल VI नई दिल्ली	आयकर रेंज 1-ग नई दिल्ली के सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)	क-रेंज नई दिल्ली के सहायक आयकर आयुक्त (अपील)	आयकर आयुक्त (अपील-I) नई दिल्ली	आयकर आयुक्त दिल्ली I नई दिल्ली

यह अधिसूचना 1-9-1979 से प्रभावी होगी।

[सं० 2985 (फा० सं० 188/3/79-सा० का० (ए I))]

बी०एम० सिंह अथर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 1st September, 1979

(INCOME-TAX)

S.O. 3650.—In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following additions to the Schedule annexed to its Notification No. 1 (F. No. 55/233/63-IT) dated 18-5-64 as amended from time to time, after S. No. 89.

The Officers specified in the 3rd, 4th, 5th, 6th and the 7th columns of the Schedule below shall perform all the functions of an Income-tax Officer, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Commissioner of Income-tax (Appeals) and the Commissioner of Income-tax respectively in respect of the persons specified in the corresponding entry in the 2nd Column thereof.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
90	Employees of British Aerospace Private Salary Circle (BAE) stationed VI, New Delhi. anywhere in India.	Income-tax Officer Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Range, 1-C, New Delhi.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax 'A' (Appeals-I), Ranage New Delhi.	Commissioner of Income-tax	Commissioner of Income-tax, Delhi-1, New Delhi.	

This notification shall take effect from 1-9-1979.

[No. 2985 (F. No. 188/3/79-IT(A-D))]

B. M. SINGH, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1979

क्रा०प्रा० 3651.—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का 15) की धारा (10) की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के परामर्श से, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नयी दिल्ली के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री बी० बी० सिंह को 19 अक्टूबर, 1979 से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 9/12/79-बी०ओ०-1]
बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 16th October, 1979

S.O. 3651.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government, after consultation with the Industrial Development Bank of India, hereby appoints Shri B. B. Singh, Chairman and Managing Director, National Fertilizers Ltd., New Delhi, as the Chairman of the Industrial Finance Corporation of India with effect from 19th October, 1979.

[No. F. 9/12/79-B.O.-1]
BALDEV SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1979

क्रा०प्रा० 3652.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री एन० पी० डूबे को सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 24 अक्टूबर, 1979 से प्रारम्भ होकर 23 अक्टूबर, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री डूबे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 1-7/79-प्रार०प्रार०बी०]
दिनेश चन्द्र, निदेशक

New Delhi, the 22nd October, 1979

S.O. 3652.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri N. P. Dubey as the Chairman of the Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur and specifies the period commencing on the 24th October, 1979 and ending with the 23rd October, 1982 as the period for which the said Shri Dubey shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-7/79-RRB]
DINESH CHANDRA, Director

सीमा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय

बंगलौर, 19 सितम्बर, 1979

सीमा शुल्क

(परिशिष्ट)

क्रा०प्रा० 3653.—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं रवीन्द्र नाथ शुक्ल, समाहर्ता, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कर्नाटक समाहर्तालय, बंगलौर, इस अधिसूचना द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 1968 की पहले वाली अधिसूचना के साथ उपाबद्ध सारणी में निर्दिष्ट मंगलौर स्थित घाट संख्या 48 के पोर्ट-लैंड क्षेत्र जिसका माप 2671-30 वर्गमीटर है (टी० एस०

संख्या 1587/1 ब्लॉक 31) को सर्व श्री कर्नाटक इंजीनियरिंग और मरीन कम्पनी मंगलौर द्वारा अस्थायी तौर पर 31-3-1980 तक बजरे और नौका उपस्कर स्टोर करने, इत्याद के बजरे और नौका निर्माण करने तथा उनके मीथरण के लिये अनुमोदित करता हूँ।

[सं० 5/79-सी० नं० VIII/48/226/79-सीमाशुल्क]

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Bangalore, the 19th September, 1979

CUSTOMS

(Addendum)

S.O. 3653.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Customs Act, 1962. I, R. N. Shukla, Collector of Customs and Central Excise, Karnataka Collectorate, Bangalore, hereby approve the port land area measuring 2671.30 Square metres (T.S. No. 1587/1 Block 31) Part of wharf No. 48, Mangalore, specified in the table appended to the earlier Notification dated 23rd September, 1968, issued by this Collectorate, for the purpose of storing barge and boat equipments, to manufacture steel barges and boats and for shipments thereof by M/s. Karnataka Engineering and Marine Company, Mangalore upto 31-3-1980.

[No. 5/79/C. No. VIII/48/226/79-Cus.]

शुद्धि-पत्र

बंगलौर, 23 जनवरी, 1979

सीमा शुल्क

क्रा०प्रा० 3654.—घाट संख्या 7 के संबंध में, क्रम संख्या 1 के सामने कारवार पोर्ट (सदाशिवगढ़ सहित) के कालम 4 (बांडवरी के विवरण सहित घाट की सीमा) में प्रविष्ट अंक तथा शब्द 11,000 वर्ग मीटर को, 16,000 वर्ग मीटर पढ़ा जाये।

[अधिसूचना सं० 1/79 सं० VIII/48/262/77-सीमाशुल्क]

CORRIGENDUM

Bangalore, the 23rd January, 1979

CUSTOMS

S.O. 3654.—The figure and words 11,000 Sq. metres appearing in column 4 (limit of the wharf including details of boundaries etc.) against serial No. 1 Karwar Port (including Sadashivagad) in respect of Wharf No. 7 is to be read as 16,000 Sq. meters.

[Notification No. 1/79/C. No. VIII/48/262/77-Cus.]

बंगलौर, 27 सितम्बर, 1979

क्रा०प्रा० 3655.—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 2 के उप-धारा (34) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कर्नाटक समाहर्तालय, बंगलौर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय के क्षेत्राधिकार में सीमाशुल्क के समाहर्ता के रूप में नियुक्त होने के फलस्वरूप, देखिए भारत सरकार वित्त मंत्रालय की (राजस्व तथा सीमा विभाग) अधिसूचना सीमा शुल्क संख्या 37/63 सीमा शुल्क दिनांक 1-2-1963 एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के कालम-1 में विनिर्दिष्ट, सारणी के कालम 2 की प्रविष्टि में वर्णित, अधिकारियों को सीमाशुल्क 1962 के विभिन्न धाराओं के अनुसार उचित अधिकारी के कार्य करने के लिये नियुक्त करता हूँ।

सारणी

(1)	(2)
1. सीमा शुल्क के सभी अधिकारी तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क के निरीक्षक तथा उनके स्तर से उच्च पद के अधिकारी	11एम, 106-ए०
2. सीमा शुल्क का सहायक समाहर्ता, सीमाशुल्क निरीक्षण बंगलौर, (मेट्रोपालिटन सिटी—जहाँ तक संबंधित क्षेत्राधिकार है)	11 सी० तथा 11 जे०
सहायक समाहर्ता सीमाशुल्क, बंगलौर अधीक्षक सीमाशुल्क कारवार सर्कल कारवार तथा सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बंगलौर निरीक्षण-II मैसूर, हुबली, दारवाणगेरे, बल्लारी, निपाणि एवं बेलगांव ।	

[संख्या 6/79-सी०नं० VIII/1/4/79-सी०-2]
आर०एन० शुक्ल, समाहर्ता

Bangalore, the 27th September, 1979

S.O. 3655.—In exercise of the powers conferred by sub-section (34) of Section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), I, Collector of Central Excise, Bangalore having been appointed as Collector of Customs, within the jurisdiction of the Karnataka Central Excise and Customs Collectorate, vide Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue and Insurance), Notification Customs No. 37/63-Cus. dated 1-2-1963 hereby assigns to the Officers mentioned in Column 1 of the table below, the functions of the "Proper Officer" referred to in the various Sections of the Customs Act, 1962, given in the corresponding entry in Column 2 of the table:

TABLE

(1)	(2)
1. All officers of Customs, of and above the rank of Inspector of Customs and Central Excise.	11M, 106-A.
2. Assistant Collector of Customs, Customs Division, Bangalore (Metropolitan City—jurisdiction is concerned) Assistant Collector of Customs, Mangalore, Superintendent of Customs, Karwar Circle, Karwar and Assistant Collectors of Central Excise, Bangalore-II Dn., Mysore, Hubli, Davangere, Bellary, Nipani and Belgaum.	11C and 11J

[No. 6/79/C.No.VIII/1/4/79 C-2]
R.N. SHUKLA, Collector

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विंग)

सीमा शुल्क

कोचीन, 2 जुलाई, 1979

क्र०आ० 3656.—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के खण्ड (क) के अन्तर्गत जारी वित्त मंत्रालय की

दिनांक 18 जुलाई, 1975 की अधिसूचना सं० 79 सीमा शुल्क फा०सं० 473/2/75-सी०शु०-VII के साथ पठित, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 के 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एतद्वारा केरल स्थित त्रिचूर जिले के मुकुन्दपुरम ताल्लुक के "कोडाकारा" गांव की "भांडागारण स्टेशन" घोषित करता हूँ।

[सं० 1/सी०शु०/79/सी०सं० VIII/48/119/79-सी०शु० पोल]

टी०एस० स्वामीनाथन, समाहर्ता

OFFICE OF THE COLLECTORATE OF CENTRAL
EXCISE AND CUSTOMS
(Central Excise Wing)
CUSTOMS

Cochin, the 2nd July, 1979

S.O. 3656.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with Ministry of Finance Notification No. 79 Customs F. No. 473/2/75-Cus. VII dated the 18th July, 1975 issued under Clause (A) of Section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), I hereby declare 'KODAKARA' Village of Mukundapuram Taluk in Trichur District in Kerala as a 'Warehousing Station'.

[Notification No. 1/Cus./79/C. No. VIII/48/119/79-Cus. Pol.]

T. S. SWAMINATHAN, Collector

कार्यालय, आयकर आयुक्त, विल्ली, सेंट्रल-1

नई दिल्ली, 13 जून, 1979

क्र०आ० 3657.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पहले की अधिसूचना का अधिक्रमण करने हुए, आयकर आयुक्त, विल्ली (सेंट्रल-1) नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कायम-2 में निदिष्ट रेंजों के निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, उसी अनुसूची के कायम-3 में दिखाए गये आयकर अधिकारी, सेंट्रल सिकिल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों या व्यक्तियों या आय या अर्थ के वर्गों के बारे में निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त के सभी कार्य करेंगे।

अनुसूची

क्र० सं०	निरी० के रेंज प्रोमूक्वालय का नाम	सहा० आय०	आयु०	सिकिल का नाम
1	2	3		
1.	निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, (सेंट्रल) रेंज-1, नई दिल्ली	(1)	आयकर अधिकारी सेंट्रल सिकिल-1, नई दिल्ली	
		(2)	आयकर अधिकारी सेंट्रल सिकिल-2, नई दिल्ली	
		(3)	आयकर अधिकारी, सेंट्रल सिकिल-4, नई दिल्ली	
		(4)	आयकर अधिकारी, सेंट्रल सिकिल-5, नई दिल्ली	
		(5)	आयकर अधिकारी, सेंट्रल सिकिल-6, नई दिल्ली	
		(6)	आयकर अधिकारी, सेंट्रल सिकिल-7, नई दिल्ली	
		(7)	आयकर अधिकारी, सेंट्रल सिकिल-10, नई दिल्ली	
2.	निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, (सेंट्रल) रेंज-मेरठ	(1)	आयकर अधिकारी, सेंट्रल सिकिल-1, मेरठ	
		(2)	आयकर अधिकारी, सेंट्रल सिकिल-2, मेरठ	
		(3)	आयकर अधिकारी, सेंट्रल सिकिल-3, मेरठ	
		(4)	आयकर अधिकारी, सेंट्रल सिकिल-4, मेरठ	

1	2	3
3. निरीक्षीय सहायक (1) आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-3, नई दिल्ली आयकर आयुक्त, (2) आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-8, नई दिल्ली (सेंट्रल) रेंज-4, (3) आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-9, नई दिल्ली नई दिल्ली		

यह अधिसूचना 15-6-1979 से लागू होगी।

नोट:—प्रशासकीय सुविधा के कारण यह अधिसूचना आवश्यक हो गई है।

[एफ० सं० एस० आई०/जूर(1)/सी०/79-80-1183]

एम० जी० शर्मा, आयकर अधिकारी (मुख्यालय-1)

कृते आयकर आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX DELHI (CENTRAL)

New Delhi, the 13th June, 1979

S.O. 3657.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 123 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of previous notification, the Commissioner of Income-tax, Delhi Central-I, New Delhi, hereby directs that the Inspecting Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges mentioned in column 2 of the schedule given below, shall perform all the functions of the I.A.C. of Income-tax in respect of such cases or of such persons or of such incomes or classes of incomes as fall within the jurisdiction of the Income-tax Officers, Central Circles shown in column 3 thereof.

SCHEDULE

S. No.	Name of the I.A.C. Range & H. Qrs.	Name of the Circle
1	2	3
1.	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax (C) Range-I, New Delhi.	(i) Income tax Officer, Central Circle-I, New Delhi. (ii) Income-tax Officer, Central Circle-II, New Delhi. (iii) Income-tax Officer, Central Circle-IV, New Delhi. (iv) Income-tax Officer, Central Circle-V, New Delhi. (v) Income-tax Officer, Central Circle-VI, New Delhi. (vi) Income tax Officer, Central Circle-VII, New Delhi (vii) Income-tax Officer, Central Circle-X, New Delhi.
2.	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax (Central) R-Meerut.	(i) Income-tax Officer, Central Cir.-I, Meerut. (ii) Income-tax Officer, Central Cir.-II, Meerut. (iii) Income-tax Officer, Central Cir.-III, Meerut. (iv) Income-tax Officer, Central Cir.-IV, Meerut.

1	2	3
3. Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, (Central) Range-IV, New Delhi.	(i) Income-tax Officer, Central Cir.-III, New Delhi. (ii) Income-tax Officer, Central Cir.-VIII, New Delhi. (iii) Income-tax Officer, Central Cir.-IX, New Delhi.	

This notification will take effect from 15-6-1979.

Note: This notification has become necessary due to administrative convenience.

[F.No.SI/Jur.(1)/C/79-80/1183]

M.G. SHARMA, Income-tax Officer,

(H. Qrs. II) for Commissioner of Income-tax.

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1979

का०आ० 3658.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सुरेंद्रनगर काटन आयन एण्ड आयलसीड्स एसोसिएशन लि०, सुरेंद्रनगर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समझा हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एन० द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को कपास की अग्रिम संविदाओं के बारे में 23 नवम्बर, 1979 से 22 नवम्बर, 1982 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की तीन वर्षों की अतिरिक्त कालावधि के लिय मान्यता प्रदान करती है।

2. एन० द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशक का अनुपालन करेगी, जो समय-समय पर दिये जायें।

[एफ० सं० 12(3)-आई०टी०/79]

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Civil Supplies)

New Delhi, the 15th October, 1979

S.O. 3658.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Surendranagar Cotton Oil and Oilseeds Association Ltd., Surendranagar, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of three years from the 23rd November, 1979 to the 22nd November, 1982 (both days inclusive), in respect of forward contracts in kapas.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(3)-IT/79]

का०आ० 3659.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन महेंद्र व्यापार संडार कम्पनी लि०, धुरी, द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और

यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कम्पनी को गुड़ की अधिम संविदाओं के बारे में 20 अक्टूबर, 1979 से 19 अक्टूबर 1982 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की तीन वर्षों की अतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त कम्पनी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

[एफ०सं० 12(1)-आई०टी०/79]

S.O. 3659.—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Mahesh Beopar Bhandar Co. Ltd., Dhuri, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Bhandar for a period of three years from the 20th October, 1979 upto the 19th October, 1982 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(1)-IT/79]

का०आ० 3660.—केन्द्रीय सरकार, अधिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 4 के अधीन भटिंडा ओम एंड एक्स्चेंज लि०, भटिंडा द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को गुड़ की अधिम संविदाओं के बारे में 20 अक्टूबर, 1979 से 19 अक्टूबर, 1982 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की तीन वर्षों की अतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

[एफ०सं० 12(1)-आई०टी०/79]

S.O. 3660.—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Bhatinda Om & Oil Exchange Ltd., Bhatinda and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act recognition to the said Company for a period of three years from the 20th October, 1979 to 19th October, 1982 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(1)-IT/79]

का०आ० 3661.—केन्द्रीय सरकार, अधिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन लुधियाना ग्रेन एक्सचेंज लि०, लुधियाना द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और

यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को चिनीले की अधिम संविदाओं के बारे में 12 दिसम्बर, 1979 से 11 दिसम्बर, 1982 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की तीन वर्षों की अतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो समय-समय पर दिये जायें।

[एफ०सं० 12(7)-आई०टी०/79]

S.O. 3661.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Ludhiana Grain Exchange Ltd., Ludhiana, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of three years from the 12th December, 1979 to 11th December, 1982 (both days inclusive) in respect of forward contracts in cottonseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(7)-IT/79]

का०आ० 3662.—केन्द्रीय सरकार, अधिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन इण्डियन एक्सचेंज लि०, अमृतसर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को चिनीले की अधिम संविदाओं के बारे में 11 नवम्बर, 1979 से 10 नवम्बर, 1982 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) का तीन वर्षों की अतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो समय-समय पर दिये जायें।

[एफ०सं० 12(7)-आई०टी०/79]

के०एस० मैथ्यू, उप-सचिव

S.O. 3662.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Indian Exchange Ltd., Amritsar and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of three years from the 11th November, 1979 to the 10th November, 1982 (both days inclusive) in respect of forward contracts in cottonseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions, as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(7)-IT/79]

K. S. MATHEW, Dy. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1979

का०आ० 3663.—केन्द्रीय सरकार, विकास परिचय (प्रक्रिया संबंधी) नियम 1952 के साथ पठित उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को इस आदेश के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये तेल, साबुन तथा प्रक्षालकों के उत्पादन में रत अनुसूचित उद्योग विकास परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है :—

तेल, साबुन तथा प्रक्षालक उद्योग विकास परिषद्

1. अवर सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग
2. श्री एन०बी० गोदरेज,
निदेशक,
मैसर्स गोदरेज सोप्स लिमिटेड,
ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे,
विक्रोली, बम्बई-400079
3. श्री एम०ए० भट्ट,
उत्पादक प्रबन्धक,
मैसर्स स्वास्तिक हाउसहोल्ड एण्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स,
पो०आ० सं० 362, अहमदाबाद हाउस,
13/15, बालचन्द हीराचन्द मार्ग,
बेल्ले इस्टेट, बम्बई-400038.
4. मैसर्स गवर्नमेंट सोप फैक्ट्री,
बंगलौर का प्रतिनिधि।
5. मैसर्स जयन्त आयल मिल्स,
बम्बई का प्रतिनिधि।
6. फैब्रिकेशन आफ एमोसिएशन्स आफ
स्माल स्केल सोप एण्ड डिटर्जेंट मेन्युफैक्चरर्स,
बजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया,
दिल्ली-52 का प्रतिनिधि।
7. फैब्रिकेशन आफ एमोसिएशन्स आफ स्माल
इंडस्ट्रीज आफ इण्डिया (एफ०आई०एस०आई०एल०)
रोहतक रोड, नई दिल्ली का प्रतिनिधि।
8. योजना आयोग,
नई दिल्ली का प्रतिनिधि।
9. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय,
नई दिल्ली का प्रतिनिधि।
10. नागरिक पूर्ति विभाग,
नई दिल्ली का प्रतिनिधि।
11. भारतीय मानक संस्थान,¹
मानक भवन,
9, बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली का प्रतिनिधि।
12. मैसर्स आई०पी०सी०एन०,
प्रतिनिधि

13. विकास आयुक्त, लघु उद्योग,
निमणि भवन नई दिल्ली का प्रतिनिधि।

14. प्रभारी विकास अधिकारी,
साबुन तथा प्रक्षालक उद्योग,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली का प्रतिनिधि।

15. श्री के० कपूर, विपणन प्रबन्धक,
राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली।

16. संयुक्त सचिव,
(विषय के प्रभारी)

सदस्य-सचिव

[का०सं० 15/2/78-एम०आई०]

आर० एन० चोपड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 9th October, 1979

S.O. 3663.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints, for a period of two years with effect from the date of this order, the following persons to be members of the Development Council for the Scheduled Industries engaged in the manufacture of Oils, Soaps and Detergents :—

DEVELOPMENT COUNCIL FOR OILS, SOAPS AND DETERGENTS INDUSTRIES

1. Additional Secretary,
Department of Industrial Development.....Chairman
2. Shri N. B. Godrej,
Director,
M/s. Godrej Soaps Ltd.,
Eastern Express Highway,
Vikhroli, Bombay-400079.
3. Shri M. A. Bhatt,
Production Manager,
M/s. Swastik Household and Industrial Products,
P.B. No. 362, Ahmedabad House,
13/15, Walchand Hirachand Marg,
Ballard Estate, Bombay-400038.
4. A representative of
M/s. Government Soap Factory,
Bangalore.
5. A representative of
M/s. Jayant Oil Mills,
Bombay.
6. Representative of the
Federation of Associations Small Scale Soap and
Detergent Manufacturers of India,
Wazirpur, Industrial Area,
Delhi-52.
7. Representative of the
Federation of Associations of Small Industries
of India (FASIL),
Rohat Road,
New Delhi.
8. Representative of the
Planning Commission,
New Delhi.
9. Representative of the
Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi.

10. Representative of the
Department of Civil Supplies,
New Delhi.
11. Representative of the
Indian Standards Institution,
Manak Bhavan,
9, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi.
12. Representative of
M/s. I.P.C.L.
13. Representative of the
D.C.S.S.I., Nirman Bhavan,
New Delhi.
14. D.O. in-charge, Soap and Detergents Industry,
DGTD, New Delhi.
15. Shri K. Kapoor,
Marketing Manager,
STC, New Delhi.
16. Joint Secretary,
(Incharge of the subject).....Member/Secretary
[F. No. 15(2)/78-M1]
R. N. CHOPRA, Jr. Secy.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय**पेट्रोलियम विभाग**

नई दिल्ली, 29 मिनम्बर, 1979

क्र० प्रा० 3664.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपबन्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाइप लाइन प्रोजेक्ट, बी-18, शिवमार्ग, बनी पार्क जयपुर-6 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तहसील/रायपुर	जिला : पाली	राज्य : राजस्थान			
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल	हेक्टर	ऐयर वर्गमीटर	
जैतपुर	321	0	03	24	
	322	0	06	47	
	327	0	04	05	

[सं० 12020/18/79-प्रोड०]

725 GI/79—2.

MINISTRY OF PETROLEUM CHEMICALS AND FERTILIZER

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 29th September, 1979

S.O. 3664.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, India Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Raipur	District : Pali	State : Rajasthan			
Village	Khasra No.	Area	H.	A.	Sq. M.
Jaitpura	321	0	03	24	
	322	0	06	47	
	327	0	04	05	

[No.12020/18/79-Prod.]

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 1979

क्र० प्रा० 3665.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० सानंद-42 से सानंद-15 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपबन्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और वेखमाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बबोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा धाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सानन्द-42 से सानन्द-15 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : मेहेसना	तालुका : कड़ी		
गांव	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
मेरदा	9/1	0	08	22
	9/2	0	03	15
	544	0	01	86
	373/1	0	11	16
	373/पी	0	09	77

[सं० 12016/44/79-प्रोड०]

New Delhi, the 10th October, 1979

S.O. 3665.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Sanand-42 to Sanand-15 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Sanand 42 to Sanand 15

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Kadi		
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Merda	9/1	0	08	22
	9/2	0	03	15
	544	0	01	86
	373/1	0	11	16
	373/P	0	09	77

[No.12016/44/79-Prod.]

सां० प्रा० 3666.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० डबका-14(डीबीएन) से डबका-4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अधः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के सीजे पाइप लाइन बिछाने के लिए धाक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल का प्राकृतिक गैस तथा प्रायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा धाक्षेप करनेवाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० डबका-14 (डीबीएन) से डबका-4

राज्य— गुजरात	जिला : भसव	तालुका : जंबर		
गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	एटीआई	सेन्टीयर
कानवा	541	0	16	25
	539	0	12	35
	533	0	15	21
	533/2/ए	0	07	80
	533/2/बी	0	07	80
	533/3	0	07	80

[सं० 12016/45/79-प्रोड०]

S.O. 3666.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Dabka-14 (DBN) to Dabka-4 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

New Delhi, the 11th October, 1979

Rou for Flow Line From Dabka Well No. 14 (DBN) to Well No. Dabka-4

State : Gujarat	District : Brauch	Taluka : Jambusar			
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare	
Kanva	541	0	16	25	
	539	0	12	35	
	533	0	15	21	
	533/2/A	0	07	80	
	533/2/B	0	07	80	
	533/3	0	07	80	

[No.12016/45/79-Prod.]

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1979

का० प्रा० 3667.—यतः पेट्रोलियम गौर खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 60) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 970 तारीख 2-3-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सखम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अथ, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० के-127 से जी०जी०एस० III तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाना	तहसील : कड़ी			
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एशरई	सेन्टीयर	
अम्बापुरा	123	0	15	75	
	124	0	17	55	
	126	0	05	85	
	127	0	10	80	

[सं० 12016/12/79-प्रोड०]

S.O. 3667.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 970 dated 2-3-1979 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. K-127 to G.G.S. III

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Kadi			
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare	
Ambavpura.	123	0	15	75	
	124	0	17	55	
	126	0	05	85	
	127	0	10	80	

[No. 12016/12/79/Prod.]

गृहि-पत्र

का० प्रा० 3668. —भारत सरकार के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 29 जनवरी, 1977 के पृष्ठ संख्या 408 पर का० प्रा० संख्या 383 के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, पेट्रोलियम, रसायन और उर्ध्वरक्त मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या 12020/17/76 प्रोडक्शन-I दिनांक 7 जनवरी, 1977 के अधीन निम्नलिखित अनुसूची के स्थान पर नोबे दी गई अनुसूची को पढ़ें।

तहसील : धरतपुर	जिला : धरतपुर	राज्य : राजस्थान			
पढ़ें	के लिए				
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल है० ऐ० बमी०	ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल है० ऐ० बमी०
रंघ सक्तिरा	94	0 14 57	रंघ सक्तिरा	168	0 14 57

[सं० 12020/17/76-प्रो०]

ERRATUM

S.O. 3668.—In the Notification of Government of India Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizer (Department of Petroleum) No. 12020/17/76 Prod. I dated 7-1-77 under S.O. 382 published in the Gazette of India Part II section 3 sub-section (ii) dated January 29, 1977 on page No. 415.

Tehsil : Bharatpur District : Bharatpur State : Rajasthan

Read

Village	Khasra No	Area		
		H.	A.	Sq. M.
Rundh Sakeetra	94	0	14	57

For

Village	Khasra No	Area		
		H.	A.	Sq. M.
Rundh Sakeetra	168	0	14	57

[No. 12020/17/76-Prod.]

का० आ० 3669.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एस० इ० ए० से सी० टी० एफ० सोभासन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार करने अर्जित का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

अर्थात् कि उक्त भूमि में हितवन् कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी सेल तथा प्राकृतिक गैस तथा आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, सडोवरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधी व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस० इ० ए० से सी० टी० एफ० सोभासन

राज्य—गुजरात	जिला—मेहसाणा	तालुका—मेहसाणा		
गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर एअरार्ड सेन्टीभर	1	2
पुनासन	223	0 05	50	
	226	0 08	89	
	227	0 10	00	

1	2	3	4	5
	229	0	05	00
	231	0	07	00
	143	0	00	72
	141	0	00	75
	225	0	02	00
	81	0	19	25

[नं० 12016/47/79-प्र०]

S.O. 3669.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from S.E.A. to C.T.F. Sobhasan in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Rou from S.E.A. to C.T.F. Sobhasan

State : Gujrat	Distt. : Mehsana	Taluka : Mehsana		
Village	Survey No.	Hect. Are	Centiare	
Punasan	223	0 05	50	
	226	0 08	89	
	227	0 10	00	
	229	0 05	00	
	231	0 07	00	
	143	0 00	72	
	141	0 00	75	
	255	0 02	00	
	81	0 19	25	

[No. 12016/47/79-Prod.]

का० आ० 3670.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) का धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1284 तारीख 2-4-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग अनुसूची में विनिश्चित भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजना के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और भागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिर्देश किया।

अब, अतः उक्त अधिनियम का धारा 6 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और भागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, वापसा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

घोषणा— 12 से डब्ल्यू. एच. आई. घोषणा— 1 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात	जिला—खेड़ा	तालुका—मातर			
गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	एअरई	सेन्टीयर	
रसिकपुरा	61	0	07	20	
	63	0	10	05	
	89/2	0	17	40	
	92/3	0	03	75	
	92/2	0	08	25	
	90	0	01	95	
	91	0	15	90	
रडू	757/2	0	09	00	
	757/1/पी	0	09	83	
	757/1/पी	0	02	25	
	758/3	0	11	70	
	758/2	0	02	25	

[सं० 12016/26/79-प्रो०]

S.O. 3670.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1284 dated 2-4-79 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline, (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Dholka—12 to WHI at Dholka-1

State : Gujarat	Distret : Kaira	Taluka : Matar			
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centi-are	
Rasikpura	61	0	07	20	
	63	0	10	05	
	89/2	0	17	40	
	92/3	0	03	75	
	92/2	0	08	25	
	90	0	01	95	
	91	0	15	90	
Radhu	757/2	0	09	00	
	757/1/P	0	09	83	
	757/1/P	0	02	25	
	758/3	0	11	70	
	758,2	0	02	25	

[No. 12016/26/79-Prod.]

का० प्रा० 3671.— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं. जे० एल० क्यू० से जी० जी० एम० कालांरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लक्ष्यों का बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग के अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आशेष मक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस तथा आयोग, निर्माण तथा देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर पर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कबन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जे० एल० क्यू० से जी० जी० एम० कालांरा तक पाइपलाइन बिछाने के लिए राज्य—गुजरात जिला—मेहसाना तालुका—कडो

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	एअरई	सेन्टीयर
मेरडा	130	0	16	00
	131	0	02	00
	132	0	07	65
	136	0	21	00
	137	0	07	00
	142	0	09	00
	80	0	32	70
	193	0	04	50

[सं० 12016/46/79-प्रो०]

S.O. 3671.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from ILQ to G. G. S. Jhalora in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from ILQ to GGS Jhalora

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Kadi		
Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Centiare
Merda	130	0	16	00
	131	0	02	00
	132	0	07	65
	136	0	21	00
	137	0	07	00
	142	0	09	00
	80	0	32	70
	193	0	04	50

[No. 12016/46/79-Prod.]

अनुसूची

घोलका- 6 से डब्ल्यूएचआई० घोलका- 10 के पास तक पाइपलाइन बिछाने के लिए ।

राज्य- गुजरात	जिला- खेड़ा	तालुका- सावर
गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर एघारई सेंटीयर
वरमंग	173/2	0 03 00
	173/1	0 01 00
	181/प	0 11 70
	191/प	0 02 40
	176	0 14 30
	179	0 06 45
	177	0 14 70
	149/1	0 04 65
	149/2	0 01 20
	148	0 03 60
	147	0 18 00
	143/1	0 05 40
	144	0 03 00
	140	0 03 60
	138/प	0 03 00
	145	0 16 15
	238	0 04 65
	233	0 10 65
	232	0 10 35
	231	0 08 10
	229	0 02 00

[मं० 12016/19/79-प्रो०]

क्र० प्र० 3672— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना क्र० प्र० सं० 1172 तारीख 20-3-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों का बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तत्पक्ष और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

S.O. 3672.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1172 dated 20-3-79 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Dholka-6 to WhI at Dholka-10

District : Kaira	Taluka : Matar			
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Warsang	173/2	0	03	00
	173/1	0	01	00
	181/P	0	11	70
	181/P	0	02	40
	176	0	14	30
	179	0	06	45
	177	0	14	70
	149/1	0	04	65
	149/2	0	01	20
	148	0	03	60
	147	0	18	00
	143/1	0	05	40
	144	0	03	00
	140	0	03	60
	138/P	0	03	00
	145	0	16	15
	238	0	04	65
	233	0	10	65
	232	0	10	35
	231	0	08	10
	228	0	02	00

[No. 12016/19/79-Prod.]

क्रा० प्रा० 3673.— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अधिनियम) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना क्र० प्रा० सं० 254 तारीख 1-1-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है ।

और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और प्रागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

के-114 से जी० जी० एम० 7 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात	जिला व तालुका : गांधीनगर			
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एकड़	सेन्टीयर
अनारमद	कार्टेडूक	0	01	10
	906/4	0	08	10
	906/3	0	09	69
	904	0	15	70
	903/1	0	07	96
	902	0	03	64
	901/1	0	06	40
	901/2	0	03	38
	900/1	0	05	02
	989/3	0	09	96
	989/1	0	01	00
	1090	0	11	25
	कार्टेडूक	0	00	78
	1088	0	12	61
	1087	0	06	02
	1089	0	00	30
	1083	0	07	41
	1082	0	19	97
	1100	0	01	40
	1105	0	14	86
	1104	0	06	94
	1107	0	11	70

[सं० 12016/18/79-प्रो०]

S.O. 3673.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 254 dated 1-1-1979 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from K-114 to G.G.S. VII

State : Gujarat	District & Taluka : Gandhinagar			
Village	Survey No.	Hectare	Area	Centiare
Uvarasad	Cart track	0	01	10
	906/4	0	08	10
	906/3	0	09	69
	904	0	15	70
	903/1	0	07	96
	902	0	03	64
	901/1	0	06	40
	901/2	0	03	38
	900/1	0	05	02
	989/3	0	09	96
	989/1	0	01	00
	1090	0	11	25
	Cart track	0	00	78
	1088	0	12	61
	1087	0	06	02
	1089	0	00	30
	1083	0	07	41
	1082	0	19	97
	1100	0	01	40
	1105	0	14	86
	1104	0	06	94
	1107	0	11	70

[No. 12016/18/79-Prod.]

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1979

क्र० आ० 3674.—यत्. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) का धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना क्र० आ० सं० 2605 तारीख 11-8-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को प्राप्त लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत् मक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार प्राप्त लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

अथ, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को विहित होगा।

अनुसूची

के० ई० नम्बर—1 से० जी० जी० एम्० कलोल तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाणा	तालुका : कलोल		
गांव	सर्वे सं०	हेक्टेयर	एकराई	सेन्टीयर
कलोल	593/1	0	02	55
	593/2	0	10	20
	593/3	0	12	90
	594	0	06	33
	595/1	0	06	66
	595/2	0	03	15
	539	0	10	50
	540	0	01	00
	538	0	07	05
	542	0	06	75
	537	0	11	40
	536/1	0	01	00
	कार्ट ट्रैक	0	01	00
	535	0	40	51
	534	0	10	50
	कार्ट ट्रैक	0	01	00
	478	0	06	30
	477	0	10	80
सईज	138	0	08	55
	96	0	23	70
	97/4	0	02	55
	97/5	5	08	70
	97/6	0	04	00
	98/1	0	02	55
	98/2	0	06	00
	ब्लॉक सं०			
बोरीस्त.	132	0	06	00
	कार्ट ट्रैक	0	00	75
	133	0	06	90
	134	0	07	80
	138	0	06	45
	137	0	02	55
	141	0	16	65
	143	0	04	65
	144	0	14	70

[सं० 12016/6/78-प्रोड०]

किरण चड्ढा, अवर सचिव

New Delhi, the 12th October, 1979

S.O. 3674.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 2605 dated 11-8-1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from KEX-1 to G.G.S. Kalol

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Kalol			
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centi-tiare	
Kalol	593/1	0	02	55	
	593/2	0	10	20	
	593/3	0	12	90	
	594	0	06	33	
	595/1	0	06	66	
	595/2	0	03	15	
	539	0	10	50	
	540	0	01	00	
	538	0	07	05	
	542	0	06	75	
	537	0	11	40	
	536/1	0	01	00	
	Cart Track	0	01	00	
	535	0	40	51	
	534	0	10	50	
	Cart track	0	01	00	
	478	0	06	30	
	477	0	10	80	
Saij	138	0	08	55	
	96	0	23	70	
	97/4	0	02	55	
	97/5	0	08	70	
	97/6	0	04	00	
	98/1	0	02	55	
	98/2	0	06	00	
	Block No.				
Borisana	132	0	06	00	
	Cart Track	0	00	75	
	133	0	06	90	
	134	0	07	80	
	138	0	06	45	
	137	0	02	55	
	141	0	16	65	
	143	0	04	65	
	144	0	14	70	

[No. 12016/6/78-Prod.]

KIRAN CHADHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1979

क्र० आ० 3675.—यह संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार अधिसूचना द्वारा इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिये गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक और गुजरात राज्य में विरमगाम से गुजरात मोघनशाला कोयली तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है।

725 GI/79—3

और यह: इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में निविष्ट प्रक्रिया की अनुसूची में निविष्ट गांव के नामके सामने दिखाई गयी तिथि से पर्यवेक्षण कर दिया है।

अन्य बात: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन, सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निविष्ट प्रक्रिया पर्यवेक्षण के रूप में एतद्वारा अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

व्ययन क्षेत्र सलाया से मथुरा तक पाइपलाइन सक्रियता पर्यवेक्षण

संताप्य का नाम	गांव	क्र० आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यवेक्षण की तिथि
पेट्रोलियम रस-यन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	Gauridad	1545	17-5-75	4-1-79
	(Except S. No. 241 और 498 गौरीदाद)	3915	30-10-76	

[सं० 12020/2/79 प्रो० II]

New Delhi, the 29th September, 1979

S.O. 3675.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (ii) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act., 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (i) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

"Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura"

Name of Ministry	Name of Village	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of Termination
Petroleum, Chemicals & Fertilisers (Petroleum Department)	Gauridad	1545	17-5-75	4-1-79
	(Except S.No. 241 & 498)	3915	30-10-76	

[No. 12020/2/79/Prod.-II]

का० प्रा० 3676.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रो-
नियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन)
अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत
सरकार अधिसूचना द्वारा इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के निम्ने
गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मुथरा तक और गुजरात राज्य
में विरमगम से गुजरात शोधनशाला कोयाली तक पेट्रोलेियम के लिए
उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित
कर लिया गया है।

और यतः इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की
धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में निदिष्ट प्रक्रिया की अनुसूची
में निदिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गयी तिथि से पर्यवसान कर दिया
है।

अब यतः पेट्रोलेियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के
अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन, सक्षम
प्राधिकारी उक्त तिथि, को ऊपर निदिष्ट सक्रिय पर्यवसान के रूप में एतद्
द्वारा अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

व्यधन क्षेत्र सलाया से मुथरा तक पाइपलाइन सक्रिय पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	का० प्रा० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	सक्रिय पर्यवसान की तिथि
पेट्रोलेियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलेियम विभाग)	जेपुर	965	29-3-75	27-1-79
	भलगम	"	"	5-2-79

[सं० 12020/2/79-प्र०.]

S.O. 3676.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (ii) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (i) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963 the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura

Name of Ministry	Name of Village	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of Termination
Petroleum, Chemicals & Fertilisers (Petroleum Department)	Jepur	965	29-3-75	27-1-79
	Bhalgam	965	29-3-75	5-2-79

[No. 12020/2/79/Prod.]

का० प्रा० 3677.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलेियम
और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन)
अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत
सरकार अधिसूचना द्वारा इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के लिये
गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मुथरा तक और गुजरात राज्य
में विरमगम से गुजरात शोधनशाला कोयाली तक पेट्रोलेियम के परिवहन
के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार
अर्जित कर लिया गया है।

और यतः इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की
धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में निदिष्ट प्रक्रिया की अनुसूची
में निदिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गयी तिथि से पर्यवसान कर
दिया है।

अब यतः पेट्रोलेियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के
अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन, सक्षम
प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निदिष्ट सक्रिय पर्यवसान के रूप में एतद्
द्वारा अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

व्यधन क्षेत्र सलाया से मुथरा तक पाइपलाइन सक्रिय पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	का० प्रा० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	सक्रिय पर्यवसान की तिथि
पेट्रोलेियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलेियम विभाग)	नाघेडी	1925	21-6-75	2-1-79

[सं० 12020/3/79-प्र०.]

S.O. 3677.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (ii) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And Whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (i) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura

Name of Ministry	Name of Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of Termination
Petroleum, Chemicals & Fertilisers (Petroleum Department)	Naghedi	1925	21-6-75	2-1-79

[No. 12020/3/79/Prod.]

का० आ० 3678—यः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार अधिसूचना द्वारा इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिये गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक और गुजरात राज्य में विरमगम से गुजरात शांवनशाला कोयाली तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है।

और यतः इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया की अनुसूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गयी तिथि से पर्यवसित कर दिया है।

अब अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन, सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में एतद् द्वारा अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

व्ययन क्षेत्र सलाया से मथुरा तक पाइपलाइन संक्रिया पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यवसान की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	धारादुंगरी	962	29-3-75	14-2-79
	सीतागढ़	"	"	"
	हडाला	"	"	"

[सं० 12020/4/79-प्रो०-II]

S.O. 3678.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (ii) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act., 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (i) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura

Name of Ministry	Name of Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of Termination
Petroleum, Chemicals & Fertilisers (Petroleum Department)	Dharadun-gari	962	29-3-75	14-2-79
	Sitagadh	962	29-3-75	14-2-79
	Hadala	962	29-3-75	14-2-79

[No. 12020/4/79/Prod.-II]

का०आ० 3679—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार अधिसूचना द्वारा इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिये गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक और गुजरात राज्य में विरमगम से गुजरात शांवनशाला कोयाली तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है।

और यतः इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया की अनुसूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गयी तिथि से पर्यवसित कर दिया है।

अब अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन, सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में एतद् द्वारा अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

व्ययन क्षेत्र सलाया से मथुरा तक पाइपलाइन संक्रिया पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यवसान की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	दाणावाडा	1759	7-6-75	3-8-78

[सं० 12020/4/79-प्रो०-I]

श्रीकान्त बेडरा,

गुजरात के लिए अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

S.O. 3678.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (ii) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Right of User has been acquired in the land specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (i) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now, therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

(स्वास्थ्य विभाग)

"Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura"

Name of Ministry	Name of Village	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of Termination
Petroleum, Chemicals & Fertilisers (Petroleum Department)	Danavada	1759	7-6-75	3-8-78

[No. 12020/4/79-Prod.-I]

S. D. VADERA.

Competent Authority under the Act, for Gujarat State

आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1979

क्रा० आ० 3681.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की तारीख 23 जुलाई, 1962 की अधिसूचना सं० एफ० 16-44/16-एम० अ ई० द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निवेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए "आर्टसेक्समेन" (यूनिवर्सिटी ऑफ एमस्टर्डम) चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी।

और यतः डा० (कुमारी) एच० अय्यर, जिनके पास उक्त अर्हता है वैश्विक और धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल जालना मिशन अस्पताल, पूना क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन, जालना जिला औरंगाबाद के साथ सम्बद्ध है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा:—

- (1) सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन होने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए

अथवा

- (2) उस अवधि की जब तक डा० (कुमारी) एच० अय्यर, जालना मिशन अस्पताल, पूना क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन, जालना जिला औरंगाबाद के साथ संबद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगी।

[सं० बी० 11016/17/79-एम० ई० (पी०)]

के० एल० भट्टिया, अवर सचिव

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 23rd October, 1979

S.O. 3681.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. F. 16-44/61-MI, dated the 23rd July, 1962, the Central Government has directed that the Medical qualification, "ARTSEXAMEN" (University of Amsterdam), shall be recognised medical qualification for the purpose of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. (Miss) H. Kreuger who possesses the said qualification is for the time being attached to the Jalna Mission Hospital Poona Christian Medical Association, Jalna District Aurangabad for the purposes of teaching and Charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of Section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

- a period of two years from the date of publication of this order in the official Gazette, or
- the period during which Dr. (Miss) H. Kreuger is attached to said Jalna Mission Association, Jalna, District Aurangabad, whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/17/79-M.E.(Policy)]

K. L. BHATIA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1979

क्रा० आ० 3680.—प्रखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर० आर० गुप्ता, संयुक्त सचिव (वित्तीय सहायक) को श्री प्रेम नाथ के स्थान पर प्रखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का सचिव मनोनीत करती है और भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 24 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना सं० बी० 16011/1/76-एम० ई० (पी० जी०) में निम्नलिखित प्रविष्टि-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

- "1. श्री आर० आर० गुप्ता, वित्त मंत्रालय में प्रतिनिधि।
संयुक्त सचिव,
(वित्तीय सहायक)
स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्रालय,
नई दिल्ली।

[सं० बी० 16011/2/78-एम० ई० (पी० जी०)]

पी० जी० जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th October, 1979

S.O. 3680.—In pursuance of clause (d) of section 4 of the All India Institute of Medical Science Act, 1956, (25 of 1956), the Central Government hereby nominates Shri R.R. Gupta, Joint Secretary (Financial Adviser), to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi vice Shri Prem Nath, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. V.16011/1/76-ME(PG), dated the 24th December, 1977.

In the said notification, for entry 1, the following entry shall be substituted, namely:

- "1. Shri R.R. Gupta, Representative of the Ministry of Finance."
Joint Secretary,
(Financial Adviser),
Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.

[No.V.16011/2/78-ME(PG)]
P.C. JAIN, Under Secy.

इस्पात और लौह मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1979

गुडि-पत्र

क्रा० प्रा० 3682.—इस विभाग की दिनांक 18 सितम्बर, 1979 की सम्-
संख्या अधिसूचना के क्रम संख्या 2 पर दिए गए नाम को "श्री दिलीप
कुमार गुप्त" के स्थान पर "दिलीप कुमार गुप्त" पढ़ा जाये।

[सि० सं० 8(108)/76-के० आई०]

ते० बा० नायर, उप सचिव

MINISTRY OF STEEL MINES & COAL

(Department of Steel)

New Delhi, the 19th October, 1979

CORRIGENDUM

S.O. 3682.—The name appearing at S. No. 2 in this De-
partment's Notification of even No. dated 18th September,
1979 is substituted to read as "Shri Dilip Kumar Gupta" in-
stead of Shri Dalip Kumar Gupta.

[File No. 8(108)/76-KI]

T. V. NAYAR, Dy. Secy.

हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के नामने
दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है :—

क्रम सं०	अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी पद	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के अधीन पद	भारतीय खाद्य निगम को स्थानान्तरण की तारीख
1	2	3	4	5
1.	श्री राम प्रकाश खन्ना	उच्च श्रेणी लिपिक	उच्च श्रेणी लिपिक	3-4-1970
2.	श्री ए० एन० राय	—	अवर श्रेणी लिपिक	26-3-1970 (अपराहृत)
3.	श्री पी० के० बैनर्जी	उच्च श्रेणी लिपिक	उच्च श्रेणी लिपिक	7-12-1970
4.	श्री प्रार० एल० त्रिपाठिया	उच्च श्रेणी लिपिक	उच्च श्रेणी लिपिक	1-4-1969 (अपराहृत)

[संख्या 52/5/79-एफ० सी० 3]

एम० एल० कम्बोह, अवर सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1979

क्रा० प्रा० 3683.—अतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा सेवा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भण्डारकरण, संवर्धन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बंद कर दिया है जोकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं।

और यतः खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा सेवा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उपरिपरि कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें जतिविष्ट तारीख के अन्तर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय को उक्त अधिनियम की धारा 12-ए की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है।

अतः अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अद्यतन संशोधित की धारा 12-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 3rd October, 1979

S. O. 3683.—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directors and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under Section 13 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India ;

And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorate of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response to the Circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 intimated, within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-Section (I) of Section 12A of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date the Central Government hereby transfer

the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them

Sl No	Name of the Officer/employee	Permanent post held under the Central Govt	Post held under the Central Govt at the time of transfer	Date of transfer to the F C I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sh Ram Prakash Khanna	U D C	U D C	3 4 1970
2	Sh A N Rai	—	L D C	26-3-1970 (AN)
3	Sh P K Bhatnagar	U D C	U D C	7-12-1970
4	Sh R L Trighatta	U D C	U D C	1-4-1969 (AN)

[No 52/5/79-FC III]

S L KAMBOH Under Secy

निर्माण और आवास मंत्रालय

(सम्पदा निवेशालय)

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1979

का० प्रा० 3684—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकाधिकारी, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, और निर्देश देती है कि उक्त अधिकारी, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन सम्पदा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा—

सारणी

अधिकारी का पद नाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
सहायक सम्पदा प्रबंधक, भारत सरकार, फरीदाबाद।	गाजियाबाद में स्थित केन्द्रीय सरकार के, या उसके द्वारा प्रयत्न इसकी ओर से पट्टे पर लिए गए, या अधिगृहीत, उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थान।

[का० सं० 21011/2/79-नीति-III]

कृष्ण चन्द्र, उपसम्पदा निवेशक

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

(Directorate of Estates)

New Delhi, the 15th October, 1979

S.O. 3684—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being gazetted officer of Government, to be estate officer for the purposes of the said Act, and further directs that the said officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on the estate officer by or under the said Act within the limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table—

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
The Assistant Estate Manager, Government of India Estates Faridabad	Premises belonging to, or taken on lease, or requisitioned by, or on behalf of the Central Government situated within Ghaziabad, under his administrative control.

[F.No. 21011(2)/79-Pol III]

KRISHAN CHANDER, Deputy Director of Estates

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1979

का० प्रा० 3685—अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 3 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एम्.ए.आर. थो एम्. रामनाथन, आई. एं. एस., को तत्काल एवं अग्रिम प्राप्ति तक भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[सं. एं. बी. 24012/2/79-ए. एं.]

चन्द्रमणि चतुर्वेदी, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 22nd October, 1979

S.O. 3685.—In exercise of the powers conferred by Section 3(3) of the International Airports Authority Act, 1971

(43 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri S. Ramanathan, IAS, as Chairman, International Airports Authority of India, with immediate effect and until further orders.

[No. AV. 24012/2/79-AA]

C. M. CHATURVEDI, Jt. Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1979

क्रा० आ० 3686.—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुपालन में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) पूर्वोक्त रेलवे के निम्नलिखित कार्यालयों को जहाँ के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है अधिसूचित करना है :—

1. उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (नार्वाय) का कार्यालय, महेन्द्रघाट।
2. क्षेत्रीय प्रशिक्षण विद्यालय, मुजफ्फरपुर।
3. मण्डल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, गढ़हरा।
4. क्षेत्र अधीक्षक का कार्यालय, गोरखपुर।
5. जिला सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर (निर्माण) का कार्यालय, लखनऊ।
6. मुख्य इंजीनियर बड़ी लाइन (सर्वेक्षण एवं निर्माण) का कार्यालय, लखनऊ।
7. उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (कारखाना) का कार्यालय, इज्जतनगर।
8. जिला विद्युत इंजीनियर (कारखाना) का कार्यालय, इज्जतनगर।
9. जिला मण्डल नियंत्रक का कार्यालय, समस्तीपुर।

[सं० हिन्दी-78/रा० भा०-15/7]

के० बालचन्द्रन, सचिव रेलवे बोर्ड एवं पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 19th October, 1979

S.O. 3686.—In pursuance of Sub-Rules (2) & (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Ministry of Railways (Railway Board) hereby notify the undermentioned offices of North Eastern Railway, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Office of the Dy. Chief Mechanical Engineer (Ferry). Mahendraghat.
2. Zonal Training School, Muzaffarpur.
3. Office of the Divl. Medical Officer, Garhara.
4. Office of Area Supdt., Gorakhpur.
5. Office of the Distt. Signal & Tele. Commn. Engineer (Works), Lucknow.
6. Office of the Chief Engineer B. G. (Survey & Const.), Lucknow.
7. Office of the Dy. Chief Mechanical Engineer (Workshop), Izatnagar.
8. Office of the Distt. Electrical Engineer (Workshop). Izatnagar.
9. Office of the Distt. Controller of Store, Samastipur.

[No. Hindi-78/OI-15/7]

K. BALACHANDRAN, Secy.

Railway Board &
Ex-officio Jt. Secy.

भ्रम मंत्रालय

प्रावेश

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1979

क्रा० आ० 3687.—श्री जेकरा राजन सेंट जोसेफ विला कोलाबेल नियोजक और उनके कर्मचारियों के बीच जिनका प्रतिनिधित्व मिस्टरस बर्कस यूनियन मानावालाकुरीची, तमिलनाडु, करती है एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और उक्त नियोजकों और कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यमस्थ के लिए निर्बंधित करने का करार कर लिया है और उक्त करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त करार को एतद्वारा प्रकाशित करती है।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10-क के अधीन)
पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री जेकब राजन, सेंट जोसेफ विला, कोलाचेल (सैसमें इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड मिनरल्स डिवीजन मानावाला-कुरीची के बैगिंग ट्रामपोर्टिंग, शिपिंग तथा स्टीविङोरिंग के लिए ठेकेदार)।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री जी० फिलिप, अध्यक्ष मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, पंजीकरण संख्या 27/के० के० एम० मानावाला-कुरीची।
2. श्री सी० राजारेतनम, संयुक्त मंत्री, मिनरल्स वर्कर्स यूनियन पंजीकरण संख्या 27/के० के० एम०, मानावाला-कुरीची।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री बी० जोसेफ महापक श्रमयुक्त (केन्द्रीय) अर्नाकुलम के माध्यम से लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

(i) निम्नलिखित विवाद प्रस्तुत विषय :—

(क) निम्नलिखित कार्यों के लिए श्रमिकों को देय मजदूरी को दरे क्या होनी चाहिए :—

मानावाला-कुरीची में लारियों में खनिज पदार्थों की लोडिंग।
कोलाचेल गोदामों में खनिज पदार्थों की अनलोडिंग।
कोलाचेल बीच में खनिज पदार्थों की अनलोडिंग।

(ख) एसी समय-सीमा क्या होनी चाहिए जिसके अन्दर-अन्तर ठेकेदार द्वारा मजदूरी की बकाया राशि यदि कोई हो का भुगतान किया जाना चाहिए।

(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें अंतर्बलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है।

(1) श्री जेकब राजन, सेंट जोसेफ विला, कोलाचेल (ठेकेदार इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मिनरल्स डिवीजन, मानावाला-कुरीची)।

(2) मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, पंजीकरण संख्या 27/के० के० एम०, मानावाला-कुरीची।

प्रतिष्ठान : इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मिनरल्स डिवीजन, मानावाला-कुरीची।

(iii) यदि कोई संघ प्रत्यक्ष कार्यकारी का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम।

मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, पंजीकरण संख्या 27/के० के० एम०, मानावाला-कुरीची।

(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या—57 कर्मकार।

(v) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या—57 कर्मकार

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर बाध्य कर होगा।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री जेकब राजन, सेंट जोसेफ विला, कोलाचेल।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री जी० फिलिप, अध्यक्ष मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, मानावाला, कुरीची।
श्री सी० राजारेतनम, संयुक्त मंत्री, मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, मानावाला-कुरीची।

साक्षी :

1. ह० (एन० कृष्णन नायर)।

2. ह० (बी० स्टीफन)

[सं० एल०-29013/3/79-डी-3बी०]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 12th October, 1979

S. O. 3687.—Whereas an industrial dispute exists between the employer Shri Jacob Rajan, St. Joseph Villa, Colachel and his workmen represented by Minerals Workers' Union, Manavalakurichi, Tamilnadu;

And, whereas the said employers and workmen have, by a written agreement in pursuance of the provisions of the sub-section (1) of section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947 agreed to refer the said dispute to arbitration by the persons specified therein and a copy of the said agreement has been made available to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10-A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement.

AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Names of Parties:

Representing employer : Shri Jacob Rajan, St. Joseph Villa, Colachel (Contractor for Bagging, Transporting, Shipping and Stevedoring for M/s. Indian Rare Earths Ltd., Minerals Division) Manavalakurichi.

Representing workmen : 1. Shri G. Philip, President, Minerals Workers' Union, Reg. No. 27/KKM, Manavalakurichi.

2. Shri C. Rajaretnam, Jt. Secretary, Minerals Workers' Union, Reg. No. 27/KKM, Manavalakurichi.

It is hereby agreed between the parties to refer the following Industrial dispute to the arbitration of Shri V. JOSEPH, Asst. Labour Commissioner (C), Einakulam.

(i) Specific matters in dispute:

(a) What should be the rates of wages payable to the workers for:

Loading Minerals in lorries at Manavalakurichi
Unloading Minerals at Colachel Godowns
Unloading Minerals at Colachel Beach.

(b) What should be the time limit within which arrears of wages if any should be paid by the Contractor.

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved:

1. Shri Jacob Rajan, St. Joseph Villa, Colachel (Contractor, Indian Rare Earths Ltd., Minerals Division Manavalakurichi).

2. Minerals Workers Union, Reg. No. 27/KKM, Manavalakurichi.

ESTABLISHMENT: Indian Rare Earths Ltd., Minerals Division, Manavalakurichi.

(iii) Name of the Union, if any, representing the workmen in question:

Minerals Workers' Union Reg. No. 27/KKM, Manavalakurichi.

(iv) Total No. of Workmen employed in the undertaking affected..... 57 workmen.

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute..... 57 workmen.

We further agree that the decision of the arbitrator shall be binding on us

Signature of the parties.

Representing employer: Shri Jacob Rajan, St. Joseph Villa, Colachel.

Representing workmen: Shri G. Philip, President, Minerals Workers' Union, Manavalakurichi.

Shri C. Rajaretnam, Jt. Secretary, Minerals Workers' Union, Manavalakurichi.

Witnesses:—

1. Sd/- (N. Krishnan Nair)

2. Sd/- (V. Stephen)

[No. L-29013/3/79-D.III.B]

आदेश

नई दिल्ली 16 अक्टूबर 1979

का० आ० 3688 —केन्द्रीय सरकार की राय है कि हममें उपाखण्ड अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री कल्याणरामा माइका काना, 725 GI/79—4

गुदुर के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार उस विवाद को व्यापनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वाछनीय समझती है;

अतः अद्य औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधि-करण गठित करती है जिसके पोंटासीन अधिकारी श्री जी० सदाशिव रेड्डी होंगे जिसका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उस विवाद को उस औद्योगिक अधिकरण का व्यापनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

“क्या कल्याणरामा माइका काना, गुदुर के प्रबंधन द्वारा फिटर-क-वेल्डर, श्री ए० सत्यानारायणा की बख्शिशों व्यापित हैं? यदि नहीं, तो वह किन अनुबोध का हकदार है?”

[संख्या एल-28011/4/79-डी० 3 बी०]

ए० के० राय, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th October, 1979

S.O. 3688.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Sri Kalyanarama Mica Company, Gudur and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. Sadasiva Reddy shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

“Whether the dismissal of Shri A. Satyanarayana, Fitter-cum-Welder by the management of Kalyanarama Mica Company, Gudur is justified? If not what relief is he entitled to?”

A. K. ROY, Under Secy.

[No. L-28011/4/79-D.III.B]

आदेश

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1979

का० आ० 3689.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि हममें उपाखण्ड अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मिगरेसी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड कोथायुडियम (आई० एम० ए०) पावर हाउस, आन्ध्र प्रदेश के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और केन्द्रीय सरकार उस विवाद का व्यापनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वाछनीय समझती है,

अतः अद्य औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० बी० नरसिम्हन होंगे जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद का उक्त औद्योगिक अधिकरण को व्यापारनिर्णय के लिए निर्देशित करना है।

अनुसूची

“कदा संघर्ष सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोथगुडियम पावर हाउस के प्रबंधन के पावर हाउस में श्री एस० सिदानन्दम श्रेणी-II कर्मकार का बायलर पावर के रूप में दिसम्बर, 1978 में प्रोन्नत न करने का कार्यवाही व्यापारित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार, किम अनुलोष के हकदार है ?

[संख्या एन-21012(17)/79-डी० 4(बी)]

शशि भूषण, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 16th October, 1979

S.O. 3689.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem (J.M.A.) Power House, Andhra Pradesh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed:

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. Sadasiva Reddy shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad, and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited Kothagudem Power House in not promoting Shri S. Sivanandam Category II worker in Power House as Boiler Attendant with effect from December, 1978 is justified. If not, to what relief is the concerned workman entitled?

[No. L-21012(17)/79-D. IV(B)]

SHASHI BHUSHAN, Desk Officer

प्रदेश

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 1979

का० आ० 3690.—भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 459, दिनांक 5 फरवरी 1963 द्वारा गठित श्रम व्यापारिक विवाद संस्थानों के अधीन में स्थित है के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है,

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपखंडों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री बी० बी० नरसिम्हन को पूर्वाधिकृत गठित श्रम व्यापारिक का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[सं० ए० 11020/10/78/डी-1(ए)]

ORDER

New Delhi the 18th October, 1979

S.O. 3690.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Labour Court with headquarters at Bangalore constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Employment No. S.O. 459 dated the 5th February, 1963;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri K. Sanjeeva, as the Presiding Officer of the Labour Court constituted as aforesaid.

[No. S. 11020/10/78/DI(A)]

का० आ० 3691.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2, के खण्ड (ड) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1549, तारीख 26 अप्रैल, 1979 द्वारा संघ राज्य के क्षेत्र के अन्दर अस्पतालों और औद्योगिक क्षेत्रों की सेवाओं का उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 26 अप्रैल, 1979 से छ मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि की छ मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग का उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 26 अक्टूबर 1979 से छ मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० ए० 11017/3/79-डी०(ए)]

पी० बी० एल० सखेना, डेस्क अधिकारी

S.O. 3691.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1549 dated the 26th April, 1979, the services in the hospitals and dispensaries within the Union Territory of Delhi, to be public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months from the 26th April, 1979;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said services to be public utility services for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 26th October, 1979.

[No. S. 11017/3/79/DI(A)]

P. B. L. SAXENA, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 मई, 1979

क्र० आ० 3692.—केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 27 के अनुसरण में, उक्त नियम की धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सौदा कोयला खान जिला हजारीबाग बिहार राज्य में 16 सितम्बर, 1976 को हुई दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए नियुक्त, जांच-न्यायालय द्वारा उसे प्रस्तुत की गई निम्नलिखित जांच रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

केन्द्रीय सौदा कोयला खान, जिला हजारीबाग, बिहार राज्य में 16 सितम्बर 1976 को हुई दुर्घटना की बाबत जांच न्यायालय की रिपोर्ट।

सेंट्रल सौदा कोलियरी

में

16 सितम्बर, 1976 को हुई दुर्घटना के संबंध में

जांच अदालत की रिपोर्ट

खंड 1

बिहार की सेंट्रल सौदा कोलियरी में 16 सितम्बर, 1976 को हुई दुर्घटना के संबंध में जांच अदालत की रिपोर्ट

प्रस्तावना :

अदालत का गठन

(1) सेंट्रल सौदा कोलियरी में तारीख 16 सितम्बर, 1976 को एक दुर्घटना हो गई जिसमें हाथीदारीसीम की 13वीं इन्क्लाइन में पानी भर जाने के फलस्वरूप 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मृतकों की सूची इस रिपोर्ट के अनुबंध में 1 दी गई है ;

अतः भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने 25 नवम्बर, 1976 की अपनी अधिसूचना द्वारा जो भारत के राजपत्र भाग-2 खंड 3(ii) दिनांक 11 दिसम्बर, 1976 में प्रकाशित हुई, एक जांच अदालत गठित करने की घोषणा की, जो निम्नलिखित प्रकार थी—

“सां० आ० 4695 चूंकि बिहार राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित सेंट्रल सौदा कोयला खान में 16 सितम्बर, 1976, को एक दुर्घटना हुई है जिसके फलस्वरूप कई जानें गई हैं ;

और चूंकि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि दुर्घटना के कारणों तथा उस समय की परिस्थितियों के बारे में एक औपचारिक जांच होनी चाहिए ;

इसलिए, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35वां) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रयत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन० द्वारा श्री एन० पी० दुबे, सेवा निवृत्त सचिव, भारत सरकार को उक्त जांच करने के लिए नियुक्त करती है तथा निम्नलिखित व्यक्तियों को जांच कार्य में असेसर के रूप में नियुक्त करती है, यथा—

(1) प्रो० एस० एस० सलूजा,

निदेशक

प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी

(2) श्री एस० दासगुप्ता,

महासचिव,

इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन,

धनबाद”

इसके बाद 29 दिसम्बर, 1976 को अनुदेश प्रसारित किए गए जिनमें अदालत के कार्यसंचालन पर होने वाले खर्च तथा 15-1-1977 से जांच

अदालत के लिए एक अंशकालिक सचिव की नियुक्ति का उल्लेख था। इस पद पर नियुक्त श्री सतपाल सिंह को 1 अप्रैल 77 से अदालत का पूर्ण-कालिक सचिव बना दिया गया।

अदालत द्वारा जारी किए नोटिस

(2) अदालत की पहली बैठक 14 फरवरी, 1977 को रांची में हुई और अगले दिन उसने नौ समाचारपत्रों/पत्रिकाओं में एक नोटिस जारी किया जिसके अनुसार जांच में हिस्सा लेने के इच्छुक लोगों को यह हिदायत दी गई थी कि वे अपने लिखित बयान तथा उन गवाहों के नामों की सूची जिन्हें वे अदालत के सामने पेश करना चाहते हैं, अदालत को 8 मार्च तक प्रस्तुत कर दें। इस नोटिस को निम्नलिखित कार्यालयों के परिसरों में भी चिपकवा दिया गया :—

(क) महाप्रबन्धक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० बर्काना ;

(ख) सेंट्रल सोदा कोलियरी ;

(ग) प्रबन्धक निवेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०, रांची ;

(घ) महानिदेशक, खान सुरक्षा, धनबाद ; तथा

(ङ०) निदेशक, खान सुरक्षा, रांची

खान का निरीक्षण

3.1 प्रो० सलूजा तथा श्री दासगुप्ता असेसरों तथा खानों के मुख्य निरीक्षक और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०, बर्काना के महाप्रबन्धक के साथ मई 15 फरवरी, 1977 के पूर्वार्द्ध में सेंट्रल सौदा कोलियरी का निरीक्षण किया। हमने ऊपर की सतह का निरीक्षण किया और उस क्षेत्र की सामान्य स्थलाकृति, छोटे ताले के आर-पार बने उस तटबंध को जो हाथीदारी गौफ को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उस क्षेत्र को जो धंस गया था तथा उस जगह को भी देखा जहां से नकारी नदी (जिसे नलकारी नदी भी कहा जाता है) का पानी खान में घुस गया बताया जाता था। इसके बाद हम हाथीदारी सीम के इन्क्लाइन नं० 13 के नीचे उत्तरकर 23/24वें स्तर तक गए जहां मजदूर 16 सितम्बर, 1976 को पंप को शिफ्ट करते गए थे और इसी काम के दौरान उक्त इन्क्लाइन के जगह पानी घुस आने की वजह से उनमें से दस लोगों ने अपनी जानें गंवा दी।

3.2 15 फरवरी की शाम को हमने नकारी नदी पर बने पतरातु बांध को देखा और 1976 की भारी बाढ़ का जायजा लेने के लिए 16 फरवरी की सुबह मैंने भूरकुंडा कोयला खान की खदान नं० 4, एन० सी० डी० सी० कोयलाखान की अरगदा ‘ए’ इन्क्लाइन, खदान नं० 1—नकारी नदी पर—तथा एसोसिएटेड कर्जपुरा कोलियरी की दामोदर नदी पर इन्क्लाइन 1 तथा 2 का निरीक्षण किया। 16-2-1977 को सेंट्रल सौदा कोलियरी से रांची लौटते समय रास्ते में मैंने रामगढ़—हजारीबाग राजमार्ग पर दामोदर नदी पर बने पुल को भी देखा जो 1976 की बाढ़ में डूब गया बताया जाता है।

जांच की पार्टी नं० 1 तथा पार्टी नं० 2

4.1 12 मार्च, 1977 की रांची में हुई अगली बैठक में अदालत को निम्नलिखित कागजात प्राप्त हुए—

(क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के प्रबंधकों की ओर से 35 पृष्ठों का, जिसमें 5 अनुबंध थे, साइक्लोस्टाइल्ड बयान जिसके साथ उनके गवाहों की सूची भी संलग्न थी ; तथा

(ख) इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन तथा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बन्ध राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ की ओर से चार पृष्ठ का टंकित बयान।

4.2 खान सुरक्षा के महानिदेशक (खा० सु० म० नि०) ने कोई लिखित बयान प्रस्तुत नहीं किया लेकिन अदालत के इस निदेश पर, कि वे दुर्घटना से सम्बद्ध जो भी सामग्री उनके पास हो उसे पेश करें, उन्होंने

13 पृष्ठ की साइक्लोस्टाइल्ड दुर्घटना रिपोर्ट दि० 22-12-76 प्रस्तुत की जिसके साथ उनके द्वारा लिपिबद्ध की गई गवाहियों की प्रतियां रिपोर्ट में दी गई प्लान तथा अन्य द्यौरे भी संलग्न थे।

4.3 बाद में 28-3-77 को अदालत को खा०सु०म०नि० की रिपोर्ट पर प्रबंधकों की टिप्पणियां तथा रा० को० म० सं० द्वारा प्रस्तुत बयान पर प्रबंधकों की टिप्पणियों के रूप में अनुपूरक सूचना भी प्राप्त हुई। अप्रैल, 1977 के दौरान रांची में जब अदालत का सत्र चल रहा था तो प्रबंधकों ने अपनी अनुपूरक सूचना तथा अपने साइक्लोस्टाइल्ड बयान में संशोधन किए। 12-5-77 को अदालत के सामने अपने बयान की साइक्लोस्टाइल्ड प्रति पर हस्ताक्षर करने समय महाप्रबंधक बर्किकाना ने कहा था कि अधिप्रमाणन उपर्युक्त संशोधनों के अधीन ही है।

4.4 प्रबंधकों को प्रथम पक्ष तथा रा० को० म० सं० को द्वितीय पक्ष बनाया गया।

जांच की तीसरी पार्टी

5.1 प्रबंधकों ने अपने बयान तथा अपनी गवाही में यह कहा कि सेंट्रल सीधा कोलियरी के उपरि प्रवाह नकारी नबी के प्रारंभ पर पतरातू बांध से अकस्मात और बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने की वजह से उनकी खानों में पानी भर गया। पतरातू साप बिजलीघर के महाप्रबंधक-न-मुख्य इंजीनियर श्री एन० करकेट्टा का 13 तथा 14 मई, 1977 को अदालत के गवाह के रूप में बयान लिया गया।

5.2 12 जुलाई को श्री करकेट्टा ने एक याचिका प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थना की गई कि पतरातू ताप बिजली घर को इस बाद में अपना बचाव करने और अदालत को सही निष्कर्ष पर पहुंचने तथा 16-9-76 को सेंट्रल सीधा कोलियरी में बाढ़ आ जाने की परिस्थितियों जानकारी देने में सहायता करने के लिए एक पक्ष बनाया जाए। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया और पतरातू ताप बिजलीघर, जो तृतीय पक्ष बन गया, ने 13-7-77 को अपनी और से लिखित बयान पेश किया और 4-8-77 के अपने पत्र द्वारा उन्होंने अपने गवाहों की एक सूची प्रस्तुत की। प्रबंधकों ने 8-8-77 को पतरातू ताप बिजलीघर के बयान का प्रत्युत्तर पेश किया।

खा०सु०म०नि० की भूमिका

6.1 12-3-77 को अदालत के सामने अपनी दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट पेश करते हुए खान सुरक्षा महानिदेशक ने कहा कि वे यह रिपोर्ट एक पक्ष की हैसियत से नहीं प्रेषित जांच के काम में अदालत को सहायता देने के लिए पेश कर रहे हैं। जब प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष अर्थात् प्रबंधक तथा रा० को० म० सं० ने 25-4-77 को यह सुझाव दिया कि खा०सु०म०नि० को भी एक पक्ष बनाया जाए तो अदालत ने कहा कि खा०सु०म०नि० ने पहले ही यह आश्वासन दिया है कि वे जांच में सहायता करेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि वह खा०सु०म०नि० समेत किसी भी गवाह को बुला सकती है और शपथ के साथ उनकी गवाही ले सकती है और कि वह प्रबंधकों तथा रा० को० म० सं० के किसी भी ऐसे सुझाव पर विचार करने को तैयार रहेगी जिसके अनुसार खा०सु०म०नि० तथा/अथवा उनके कब्जे में किसी दस्तावेज की जांच को मांग को जाएगी।

6.2 तत्पश्चात्, अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणी दी:—

“अदालत का कहना है कि खा०सु०म०नि० जांच कार्य में सहायता देने हेतु अभी तक अदालत की सभी बैठकों में उपस्थित रहे हैं और अदालत में बयान दे रहे गवाहों से उन्होंने सवाल भी पूछे हैं। खा०सु०म०नि० की कुछ कमियों की ओर अदालत को संकेत किया गया है तथा उसके ध्यान में लाई गई है जिनका आशय कुछ मामलों में वे उनके विशुद्ध आरोपों की शकल प्रस्तुत कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं; ऐसी परिस्थिति में तथा उन्हें यह प्रीतिव्यक्त बताने के लिए कि उस समय उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, अभी भी यही सलाह दी जाएगी कि खा०सु०म०नि० को भी इस जांच का एक पक्ष बना दिया जाए। अदालत के सामने जो

कुछ आ रहा है उसका खा०सु०म०नि० को गुरु से ही पता है और उन्हें अदालत के आवेदन-पत्र दिए जाते रहे हैं तथा अदालत के सामने पेश किए बयानों तथा याचिकाओं की प्रतियां भी दी जाती रही हैं। उन्हें अदालत में पेश किए दस्तावेजों, रिपोर्टों आदि को देखने और उनकी जांच करने की अनुमति भी दी जाती रही है। इसलिए इस अवस्था में भी यदि खा०सु०म०नि० एक पक्ष बन जाते हैं तो उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि खा०सु०म०नि० एक पक्ष नहीं बनते तो स्पष्टतः उन्हें अदालत में जिरह के वक्त खुद का बचाव करने का मौका नहीं मिल पाएगा। उस अवस्था पर केवल उन्हीं प्रश्नों अथवा वादों के बारे में मौखिक रूप से जिरह होगी जो अदालत के सामने पहले पेश कर दिए गए हैं और अदालत कोई नया प्रश्न मंजूर नहीं करती। खा०सु०म०नि० यदि अब एक पक्ष बन जाते हैं तो उन्हें भी, यदि आवश्यक हो, जिरह से पहले अपने गवाह अदालत के सामने पेश करने की अनुमति होगी। इसलिए अदालत ने खा०सु०म०नि० को यह निवेश दिया कि वे अदालत को तत्काल लिखित रूप में सूचित करें कि वे एक पक्ष बनने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं।

6.3 इस पर खा०सु०म०नि० ने जवाब दिया कि उनके एक पक्ष बनने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता और इसके कारण। स्पष्टीकरण उनके पत्र के साथ संलग्न 4 पृष्ठ के टिप्पण में दिए गए हैं। अदालत की राय थी कि अतीत में घटी कुछ खान दुर्घटनाओं से संबंधित जांचों में खा०सु०म०नि० एक पक्ष रहा है और खान अधिनियम, 1952 में भी ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है जिससे अदालत के इस विवेकाधिकार पर कोई रोक लगी हो कि वह जांच के लिए जरूरी किसी को भी एक पक्ष बना सकती है। अदालत का कहना था कि वह खा०सु०म०नि० को कानूनी रूप से तो इस जांच का एक पक्ष नहीं बनाएगी, लेकिन फिर भी कार्यवाही के दौरान आपा तप्पों के प्रकाश में वह सेंट्रल सीधा कोलियरी की दुर्घटना पर प्रभाव डालने वाली किसी भी परिस्थिति से संबंधित उनके उत्तरदायित्व यदि कोई हो, का निर्धारण अवश्य करेगी।

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स द्वारा याचिका

7. अदालत को सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, कलकत्ता के सचिव की एक याचिका प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने स्वयं को इस जांच के एक पक्ष के रूप में शामिल करने की प्रार्थना की थी। अदालत ने उन्हें सूचित किया कि वे अपने मामले के बारे में एक लिखित बयान अदालत के विचारार्थ जुलाई, 1977 में रांची में होने वाली बैठक के समय प्रस्तुत करें। हालांकि, से०ई०ट्रे०यू० के सचिव बीमार होने के कारण अदालत की 11-7-77 की बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। से०ई०ट्रे०यू० की ओर से 13-7-77 को एक याचिका प्रस्तुत की गई। याचिका पर विचार किया गया तथा दूसरे पक्षों की आपत्तियों की सुनवाई की गई। तत्पश्चात् अदालत ने से०ई०ट्रे०यू० से फिर कहा कि वे स्वयं को एक पक्ष बनाए जाने हेतु अपना लिखित बयान प्रस्तुत करें। से०ई०ट्रे०यू० के सचिव ने अपने 25-7-77 के पत्र के साथ लिखित बयान पेश किया और प्रबंधकों ने 8-8-77 को उसका प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। अदालत के 9-8-77 के अनुसार से०ई०ट्रे०यू० को उनके बयान में उल्लिखित वादों पर अपनी गवाही प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई और उनसे कहा गया कि जो भी उनका प्रतिनिधि होगा उसे अदालत के गवाह का दर्जा दिया जाएगा।

प्रदर्श तथा नकशे

8. खंड-2 में इस रिपोर्ट के अनुबंध हैं। अनुबंध-1 में मृतकों के नामों का उल्लेख है; अनुबंध-2 में अदालत में पेश गवाहों की सूची है; तथा अनुबंध 3 तथा 4 में प्रदर्श तथा गिनावन हेतु निम्नित दस्तावेजों का उल्लेख है। खान तथा जल-प्रवाह के 7 खाके अनुबंध-5 (क) से (5) (छ) में दिए गए हैं।

भाग-1

खाम तथा पतरातू बांध

सेट्रल सोदा कोलियरी की अवस्थिति

9.1 नकारी नदी पर 23' 39 फुट 10 इंच तथा 23' 40 फीट 50 इंच अवकाशों तथा 85' 20 फुट 0 इंच तथा 85' 21 फुट 01 इंच देशान्तर के बीच फैली सेट्रल सोदा कोलियरी विहार के हजारी बाग जिले में दक्षिण करनपुरा कोथला क्षेत्र सोदा अनाक सी में अवस्थित है।

हजारीबाग—रांची राजमार्ग पर 25 कि०मी० की मड़क इस कोलियरी को रामगढ़ से जोड़ती है। यह पतरातू होकर रांची से भी जुड़ी हुई है। कोलियरी से पतरातू मड़क द्वारा 15 कि०मी० है। रामगढ़ से सेट्रल सोदा कोलियरी के रास्ते में कांकीनी तथा मारगढ़ नदिकाओं की दो पुलिया तथा एन०सी०डी०सी० सोदा कोलियरी, जो नकारी तथा दामोदर नदियों के संगम के ऊर्ध्व प्रवाह पर ही अवस्थित है, के समीप एक नियमित पुल को पार करना होता है। पतरातू से सेट्रल सोदा कोलियरी के रास्ते में नकारी नदी को दो बार नियमित पुलों से पार करना पड़ता है।

कोलियरी का निकटवर्ती रेलवे स्टेशन पतरातू है जो पूर्वी रेलवे के देहरी ब्रोनसन—गोमोह की शाखा लाइन पर अवस्थित है।

9.2 सेट्रल सोदा कोलियरी पट्टे की जमीन है जिसका क्षेत्र 325.61 एकड़ अथवा 131.82 हेक्टेयर है और इसकी सीमा इस प्रकार है :—

उत्तर में :	खाम करनपुरा कोलियरी ;
उत्तर पूर्व में :	एन०सी०डी०सी० सोदा कोलियरी ,
पूर्व में :	भूरकुड़ा कोलियरी ;
दक्षिण में :	सोदा 'डी' कोलियरी ; तथा
पश्चिम में :	स्थान 'डी' कोलियरी।

9.3 दामोदर नदी की सहायक नकारी नदी प्रायः दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर तथा दामोदर नदी लगभग पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर और सेट्रल सोदा कोलियरी की उत्तरी सीमा के लगभग समान्तर लगभग 2 कि०मी० दूर बहती है। नकारी नदी, जो सेट्रल सोदा कोलियरी के समीप एक तोखा मोड़ लेती है, उस कोलियरी को भूरकुड़ा कोलियरी से घेरना करती है और फिर दामोदर नदी के संगम की ओर बह जाती है, यह संगम सेट्रल सोदा कोलियरी से लगभग 1.5 कि०मी० दूर है।

पतरातू बांध

10.1 नकारी नदी पर बना पतरातू बांध सेट्रल सोदा कोलियरी से 11 कि०मी० दूर ऊर्ध्व प्रवाह पर अवस्थित है। इसका निर्माण 1962 में प्रारंभ होकर 1965 में पूरा हो गया था और अधिप्लव द्वारा 1968 में लगा दिए गए थे। मिट्टी के बने इस बांध की लम्बाई 3.2 कि०मी० है और इसके ऊपर 20 फीट चौड़ी रामर की मड़क बनी हुई है। अधिप्रवाह संकशन के अन्तर्गत नदी संकशन में पत्थरों की चिताई की हुई है। दोनों बाजुओं पर मिट्टी-बांध संकशन है—जो दोनों किनारों पर निर्मित है तथा उपयुक्त द्राजिशन संकशन द्वारा अधिप्लव मार्ग तक बना हुआ है। अधिप्लव मार्ग के लिए ऊपर उठने वाले द्वार लगे हुए हैं। इस मिट्टी के बांध तथा अधिप्लव मार्गों के डिजाइन केन्द्रीय जल तथा विद्युत प्रायोग के मार्गदर्शन में तैयार किए गए थे।

10.2 इस पतरातू (नकारी) बांध के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं :—

(म) जलग्रहण क्षेत्र	81.30 वर्ग मील
(आ) बांध की अधिकतम ऊंचाई	119.5 फुट
(इ) समग्र लम्बाई	10620.0 फुट
(ई) चिताई वाले अधिप्लव मार्ग की लम्बाई	349.0 फुट
(उ) गैर-अधिप्रवाह संकशन की लम्बाई	558.0 फुट
(ऊ) प्रचालन प्लेटफार्म की ऊंचाई	117.0 फुट
(ए) इस्पात द्वारों का आकार	35 फुट × 23½ फुट (कुल संख्या 8)
(ऐ) अधिकतम भंडारण क्षमता	87000.0 एकड़ फुट
(ओ) सक्रिय भंडारण	80800.0 ,, ,,
(ओ) एक० आर० एल का जलाशय विस्तार	2,450.0 ,, ,,
(अं) बांध पर जल की अधिकतम गहराई	109.5 फुट
(अ) जल की प्रयोज्य गहराई	60.5 फुट
(क) अधिप्लव मार्ग पर अधिकतम निकास	1 लाख क्यूसेक
(ख) अधिकतम ड्रेन ऑफ	6 करोड़ गैलन के 110 क्यूसेक प्रति- घंति

10.3 जलाशय से अपरिष्कृत जल एक ग्रहण-ताली द्वारा जल निस्सृ-
क मयूज से जो लगभग एक मील दूर है, जाता है और वहां से ग्रेविटी-
मेंस द्वारा ताप घर की कूलिंग टावरों तक पहुंचता है।

400 मेघा के ताप बिजलीघर के लिए मेकअप तथा सर्विस जल की कुल आवश्यकता 40 क्यूसेक की है जबकि जलाशय से त्रिनियमित प्रवाह 110 क्यूसेक का है। सेट्रल कोलफील्ड्स लि० को पतरातू क्षेत्र में तथा उसके आसपास की कोयलाखानों के लिए 10 क्यूसेक जल की लगातार पूर्ति प्राप्त होती है। पतरातू के 840 मेघा संयंत्र के लिए मेकअप जल की अनुमानित आवश्यकता लगभग 70 क्यूसेक की है। पतरातू ताप बिजलीघर

11. नकारी नदी के बाएं किनारे पर माध्य समुद्र-तल से 372.5 मी० की ऊंचाई पर स्थित पतरातू ताप बिजली घर पतरातू बांध से 3 कि०मी० अनुप्रवाह पर स्थित है। बिजलीघर की पहली सान यूनिटें 1966 और 1977 के दौरान कमिशन की गई थीं। ऐसी आशा है कि इसकी आठवीं इकाई 1978 में काम शुरू कर देगी तथा सोबी तथा दसवीं इकाइयों (110 × 2 मेघा) का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है जिससे इसकी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 840 मेघा हो जाएगी। कोयला खान की कोयला सीम

12.1 इस क्षेत्र की कोयला सीम लोभर गोडवाना की बाराकार क्षेत्र की है। सोदा सीम-समूह को छोड़कर करनपुरा क्षेत्र की सभी सीमें सेट्रल सोदा कोलियरी में हैं। बांसगोडा तक की सभी नई सीमें प्रोपर्टी में ही दृश्यमान होती है। मिरका तथा आरगलदा सीमें दृश्यमान नहीं होतीं अथि 180 मीटर से भी अधिक की गहराई में होती है।

12.2 सेट्रल सोदा कोलियरी की सीमों के नाम, जो एक के बाद एक प्रोपर्टी में हुई, निम्नलिखित हैं :—

- (अ) अपर मायल
- (आ) लोभर मायल
- (इ) अपर बालकुड़ा
- (ई) लोभर बालकुड़ा
- (ऊ) अपर नकारी

- (ए) लोअर नकारा
(ऐ) अपर सीमाना
(आ) लांअर सीमाना
(ओ) हाथीदारी
(अ) बामगोडा
(अः) अपर सिरका
(क) लोअर सिरका
(ख) आरगदा समूह

छह चालू सीमें

12.3 उपर्युक्त 14 सीमें में से केवल छह चालू हैं, ये हैं—कुर्स, अपर नकारी, लोअर नकारी, बामगोडा, अपर सिरका तथा लोअर सिरका। इनका विवरण अगले पांच उप-पैराग्राफों में दिया गया है।

(क) कुर्स सीमः यह सीम 17 फुट मोटी है तथा इन्क्लाइन नं० 11, 12 तथा 15 द्वारा की गई है। यह सीम बोर्ड तथा पिलर विधि पर पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी और तीसरे पैल में खंभे ताँजे जा रहे थे। पहले दो पैलों में खंभे तोड़े जा चुके थे और सीम कर दिए गए थे। इस सीम से 90 टन प्रति पारी उत्पादन हो रहा था और हम पर निम्नलिखित कामगार लगे थेः—

भूमि के नीचे	76 प्रति पारी
धरातल पर	4 प्रति पारी
कर्मचारी	4 प्रति पारी

(ख) अपर तथा लोअर नकारी सीमः—इन सीमों को इन्क्लाइन नं० 6, 9 तथा 10 से विकसित किया गया था। अपर सीम 11 फीट मोटी तथा लोअर सीम 6 फीट मोटी थी। दोनों सीमों का बोर्ड तथा पिलर विधि से विकास 1970 के लगभग पूरा हो चुका था। अपर तथा लोअर सीमों को बहुत से ट्रिप्ट तथा स्टेपल पिट जोड़े हैं। इन दोनों सीमों में खंभे तोड़ने का काम कुर्स सीम के नीचे तबनुरूप लगे कुर्स सीम के पैलों के साथ साथ ही चल रहा था।

इन दोनों सीमों से 100 टन / पारी का उत्पादन हो रहा था और इसमें लगे कामगार इस प्रकार थेः

भूमि के नीचे	81 प्रति पारी
धरातल पर	5 ,, ,,
कर्मचारी, ओवरमैन	2 ,, ,,
सिरदार	2 ,, ,,
शाट फिर्स	2 ,, ,,
मूल्गी	2 ,, ,,

(ग) बामगो सीमः—यह सीम लगभग 14 फीट मोटी है और इसका विकास बोर्ड तथा पिलर विधि से इन्क्लाइन नं० 17, 18 तथा 25 के माध्यम से हो रहा था। डिप माइड पर अछूते टुकड़े को विकसित करने में आने वाले दोष को ठीक करने के लिए दो ट्रिप्ट भी चलाए जा रहे थे।

उत्पादन 140 टन/पारी

नियोजित व्यक्ति

भूमि के नीचे	120
कर्मचारी	9
धरातल पर	10

(घ) अपर सिरका सीमः—यह सीम तथा इसके नीचे की सीम प्रॉपर्टी में दृष्टाश नहीं होती। यह सीम 22 फीट मोटी है और पिट नं० 1 तथा 2 के रूप में पुकारे जाने वाले शीफ्टों के एक युग्म के माध्यम से खनी है। इसका विकास बोर्ड तथा पिलर विधि से लगभग इसकी तट के किनारे-किनारे किया गया है। इसका विकास व्यावहारिक रूप से पूरा हो चुका था केवल दक्षिण-पश्चिम के एक छोटे से हिस्से पर काम अभी चल रहा था।

इसका उत्पादन 50 टन/पारी था।

नियोजित व्यक्ति

भूमि के नीचे	57 प्रति पारी
धरातल पर	6 ,, ,,
कर्मचारी-ओवरमैन	1 ,, ,,
सिरदार	1 ,, ,,
शॉट फायर्स	1 ,, ,,
मूल्गी	1 ,, ,,

(ङ) लोअर सिरका सीमः—यह सीम 11 फीट मोटी और पिट 1 तथा 2 के माध्यम से इस पर काम हो रहा था। यह सीम अपर सीम से ट्रिप्टों के एक युग्म से जुड़ी हुई थी। इस सीम में बोर्ड तथा पिलर विधि से विकास अभी हाल में शुरू हुआ था।

उत्पादन 70 टन/पारी

नियोजित व्यक्ति

भूमि के नीचे	45 प्रति पारी
धरातल पर	4 ,, ,,
कर्मचारी	4 ,, ,,

पांच और चालू सीमें

12.4 पांच सीमों अर्थात् अपर सयाल, लोअर सयाल, लोअर बाल-कुद्रा, अपर सेमाना तथा आरगदा सीम समूह में कोई काम अब या उत्पादन नहीं हो रहा था। इन सीमों में स्थिति इस प्रकार थीः—

(क) अपर सयाल यह सीम हस्त खनन द्वारा निकाशी जा चुकी है।

(ख) लोअर सयालः इस सीम का इन्क्लाइन 22 तथा 23 के माध्यम से पूरी तरह विकास हो चुका था परन्तु इससे कोई उत्पादन नहीं हुआ।

(ग) लोअर बालकुद्राः उन्खनन, विकास तथा खंभे तोड़ने के बाद इसके इन्क्लाइन नं० 19 तथा 20 अप्रैल, 1974 में बंद कर दिए गए।

(घ) अपर सेमानाः इस सीम पर बहुत सी इन्क्लाइनों के माध्यम से काम हो चुका है और दृष्टाशों के छोटे हिस्से उन्खनित हो चुके हैं। 16-9-76 को इस सीम पर कोई काम नहीं हो रहा था लेकिन बाद में एक छोटा सा नया टुकड़ा विकास के लिए ल लिया गया।

(ङ) आरगदा समूहः आरगदा, आरगदा 'ए' तथा आरगदा 'बी' की सीमे सभी अभी नहीं थीं और इनमें प्रवेश अभी नहीं हुआ है।

पंजि केवल तीन सीमों में

12.5 निम्नलिखित सीमों में पंजि के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा थाः—

(क) अपर बालकुद्रा ;

(ख) लोअर सेमाना ; तथा

(ग) हाथीदारी।

हाथीदारी सीम का एक संक्षिप्त वृत्त

13.1 हाथीदारी सीम, जहाँ पर 16 सितम्बर, 1976 को घुँघटना हुई, 12 फीट मोटी है और प्रापटी में दृष्यांश है तथा बोर्ड और पिलर विधि द्वारा इन्क्लाइन नं० 13, 14 तथा 24 के माध्यम से विकसित की गई है। नं० 13 तथा 14 इन्क्लाइनों द्वारा होने वाले काम को पुरानी हाथीदारी तथा इन्क्लाइन नं० 24 के माध्यम से होने वाले काम को नई हाथीदारी कहा जाता है।

13.2 यह बताया जाता है कि पुरानी हाथीदारी का निम्नतम गत तक का विकास 1968 में पूरा हो गया था और केवल एक छोटा स अप्रयुक्त टुकड़ा ही अविकसित रह गया था, जिसे अप्रैल, 1974 से प्रारंभ कर मार्च 1975 में पूरा कर दिया गया था। पुरानी हाथीदारी में सीम में से पानी निकालने के लिए केवल पंपिंग का काम हो रहा था, जिससे कि उसके नीचे की बांसगोड़ा सीम को और विकसित किया जा सके। एक स्ट्राइक फास्ट दोनों सीमों के आर-पार थी और इसलिए यदि हाथीदारी सीम में ऊपर पानी इकट्ठा होता रहता तो बांसगोड़ा सीम को खतरा हो सकता था।

13.3 नई हाथीदारी का विकास 1973 में शुरू किया गया और 1974 के अंत में पूरा हो गया। इस पैच का खुली कोरिंग द्वारा खंभे तोड़ने का प्रबंधकों का प्रस्ताव खाना मु० नं० 13 को अप्रैल, 1974 में भेज दिया गया था और उसकी अनुमति जनवरी, 1975 में मिल गई।

13.4 नया तथा पुराना हाथीदारी हिस्से तीन गलियारों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे तथा नई हाथीदारी को दूसरा मार्ग तथा संवाहन परिपथ पुरानी हाथीदारी में हो कर ही था। अलग करने वाले अवरोधों से तीनों एक दूसरे को जोड़ने वाले गलियारों को धंद कर दिया गया था और यह काम, प्रबंधकों के अनुसार, मार्च, 1976 में खंभे तोड़ने का काम खत्म हो जाने पर पूरा हो गया था।

खान का स्थापित

14 यह खान 1946 में यूनाइटेड कोलियरीज लि० द्वारा खोली गई। 31 जनवरी, 1973 तक, जब कि नोन-कोरिंग कोयला खानों का प्रबंध भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था, यह खान सर्वश्री करम चन्द थापर एण्ड ब्रदर्स (प्रा०) लि० के प्रबंध में थी। अन्य नोन-कोरिंग कोयला खानों के साथ साथ इस खान का भी 1 मई, 1973 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह कोयला खान प्राधिकरण के मध्य प्रभाग के रामगढ़ क्षेत्र की एक इकाई बन गई। बाद में इस क्षेत्र का नाम बदलकर बर्काकाना क्षेत्र कर दिया गया। नियंत्रण कंपनी कोल इंडिया लि० के गठन के बाद बर्काकाना क्षेत्र सेन्ट्रल कोल फील्ड लि०, जो कोल इंडिया लि० की एक नियंत्रित कं० है, की एक इकाई बन गया। नियंत्रित कंपनी का प्रशासन एक पूर्णकालिक अध्यक्ष-व-प्रबंधनिदेशक के हाथ में है, जिसे खान अधिनियम, 1952 के प्रयोजन के लिए स्वामी नामित किया गया है।

16-9-76 को घुँघटना के समय सेन्ट्रल सौदा कोलियरी के प्रमुख पण्योजना अधिकारी श्री एस० के० मुखर्जी थे। उन्होंने 4-8-76 को अपने पूर्ववर्ती श्री मेवाड़ से कार्यभार संभाला था। परियोजना अधिकारी बर्काकाना क्षेत्र के महाप्रबंधक के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है और खान अधिनियम के अधीन कोलियरी का एजेंट कहलाता है।

सेंट्रल सौदा कोलियरी का एक कोलियरी मैनेजर भी है। 9-1-74 से 17-9-76 तक श्री के० दोरेस्वामी कोलियरी के मैनेजर थे और 18-9-76 को उनका बर्काकाना के लिए स्थानांतरण कर दिया गया था। मैनेजर के अधीन प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कोयला खान प्रबंधक प्रमाण-पत्र हासिल किए सहायक होते हैं और साथ ही अन्य कामूनी कार्मिक जैसे सर्वेक्षक, सुरक्षा-अधिकारी, मोबरमैन, सिरदार आदि भी होते हैं।

भाग-2**घुँघटना****खान का विकास**

15.1 सेंट्रल सौदा कोलियरी की हाथीदारी सीम के जनमन हो जाने के फलस्वरूप यह घुँघटना, जिसमें 10 घावमियों की जाने गई (प्रबंध 25), 16 सितम्बर, 1976 को हुई।

धरातल से खान में पानी तभी घुस सकता है जब कि कोयला निकालने के लिए खान का विकास शुरू हो चुका हो और पानी को अन्दर घुसने से रोकने के लिए उपयुक्त बचाव उपाय किए बिना यह काम चालू रखा जाता हो। सुरक्षित प्रचालन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह अपनाया जाता है कि यह देख लिया जाए कि पास में बहती हुई नदी अथवा पानी की कोई धारा, फिर चाहे वह बारहमासी हो अथवा मौसमी, कोयला निकालने के लिए किए जा रहे काम से सुरक्षित दूरी पर हो। इसीलिए कोयला खान विनियमावली 1957 के विनियम 126(2) में यह व्यवस्था है कि किसी भी ऐसी खान में जो लंबमान रूप से निम्नलिखित से नीचे स्तर पर है, कोई भी काम नहीं किया जाएगा:—

- (क) किसी नदी, नहर, झील, तालाब अथवा अन्य धरातली जलाशय के किसी भाग; अथवा
- (ख) किसी नदी अथवा नहर के किसी भी किनारे अथवा किसी झील, तालाब अथवा अन्य धरातली जलाशय की सीमा से 15 मीटर की समस्तरीय दूरी के अन्दर आने वाले किसी स्थल।

15.2 इसका अर्थ है कि कोयला किसी सीम के ऐसे हिस्से से नहीं निकाला जाना चाहिए जो जल की धारा से लंबमान रूप में नीचे है अथवा इसके लिए यहां तक कि वह धरातली जल से 15 मीटर तक की दूरी पर है। लेकिन फिर भी यदि प्रबंधक विश्वासपूर्वक यह महसूस करते हैं कि यह काम निरापद रूप से किया जा सकता है तो उन्हें खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नियुक्त मुख्य खान निरीक्षक से इसकी निश्चित अनुमति प्राप्त करनी होगी और इस संबंध में मुख्य खान निरीक्षक द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन काम करना होगा।

प्रबंधकों ने इन्क्लाइन नं० 13 तथा 14 के माध्यम से काम कराके, जिसे पुरानी हाथीदारी कहा जाता है, हाथीदारी सीम के अधिकतर भाग का 1968 तक विकास पूरा कर लिया था। दक्षिण पूर्वी माइड पर सोप बचे एक छोटे से हिस्से का, 1973-1974 के दौरान विकास इन्क्लाइन नं० 24, जिसे नया हाथीदारी कहा जाता है, के माध्यम से काम कराके किया गया। लेकिन जब यह विकास जिसमें गैलरियां घाबि बनाकर आंशिक रूप से कोयला निकालना शामिल था चालू था तो प्रबंधकों ने इस तथ्य की मुख्य निरीक्षक को कोई सूचना नहीं भेजा कि वे एक ऐसे बड़े नावे की ओर बढ़ रहे हैं, जो 15 मीटर से भी कम दूरी पर है, और वास्तव में उन्होंने नावे के लंबमान स्तर के नीचे में कोयला निकाला लिया है।

बड़ा नावा

15.3 साथ नगी सौदा 'डी' कोलियरी से चलकर यह नावा सेंट्रल सौदा प्रापटी पर होता हुआ नकारी नदी जिसे नलकारी नदी भी कहा जाता है, में मिल जाता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य जांच के दौरान प्रकाश में आया जब अदालत ने यह देखा कि प्रबंधकों द्वारा रखी जाने वाली सांविधिक भूमिगत कार्ययोजना (प्रबंध "डी") यह दर्शाती है कि नई हाथीदारी का विकास उस बड़े नावे के समीप तथा उसके नीचे हुआ है। इसकी पुष्टि श्री के० दोरेस्वामी ने की, जो सेंट्रल सौदा कोलियरी के 9-1-74 से मैनेजर बने आ रहे थे और तब नई हाथीदारी का विकास चल रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी में, खान के विकास से संबंधित प्रबंध "डी" में कोई त्रुटि नहीं है। जब, अदालत ने उससे पछा कि जब

विकास का काम नाले के समीप या उसके नीचे के क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था तो खान सुरक्षा महानिदेशालय की अनुमति क्यों नहीं प्राप्त की गई तो मैनेजर ने कहा कि :—

“विकास अवस्था के दौरान हमने खान सुरक्षा महानिदेशालय की अनुमति नहीं ली थी। ऐसा न करना कोयला खान विनियमावली के विनियम 126 (2) का उल्लंघन माना जा सकता है। तथापि इस प्रश्न पर अदालत जैसा उचित समझे निर्णय ले सकती है।”

खंभे तोड़ने का काम

16.1 किसी खान से कोयला निकालने का काम प्रायः बोर्ड तथा पिलर पद्धति से किया जाता है। मोटे तौर पर इसके अनुसार जहाँ से कोयला निकाला जा रहा है उसकी छत गिरान पड़े इसके लिए बड़े बड़े खंभे अक्षत रूप में तोड़ दिए जाते हैं और उनमें से कोई कोयला नहीं निकाला जाता। विकास के दौरान ये खंभे ही उपरिवर्ती स्तर को सहारा देते हैं और खनन कार्य में सुरक्षा बढ़ाते हैं। हालाँकि विकास प्रक्रिया के अंत में प्रबंधक उन खंभों में से भी कोयला निकालना शुरू कर सकते हैं। खंभे तोड़ने की इस प्रक्रिया की वजह से गोफ बन जाती है और ऊपरी स्तर में गुहा सा बन जाती है। लेकिन खंभे तोड़ने का काम तभी शुरू किया जा सकता है जबकि खान सुरक्षा महानिदेशालय से अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। दूसरे शब्दों में, किसी खान में से कोयला निकालने हेतु उसका विकास करने के लिए जब तक कि उक्त प्रक्रिया में खान अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन न होता हो, प्रबंधकों को सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है किन्तु बाव में खंभे तोड़ने के काम के लिए निश्चित अनुमति प्राप्त करना प्रबंधकों का कानूनी दायित्व है। विनियमों के अधीन खंभे तोड़ने की कार्रवाई के लिए मुख्य निरीक्षक की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रबंधकों को एक विहित प्रार्थना पत्र भरकर पेश करना होता है तथा उसके साथ खंभे तोड़े जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र का एक अद्यतन नक्शा दो प्रतियों में, पेश करना होता है।

बड़े नाले से खतरा

16.2 नई हाथीदारी के खंभे तोड़ने के लिए प्रबंधकों ने एक प्रार्थना पत्र अपने 10 अप्रैल 1974 के पत्र (प्रदर्श बी-2) के साथ प्रस्तुत किया। इसके बाद एक अन्य पत्र 9 अगस्त 1974 (प्रदर्श सी-1) को भेजा गया जिसमें इस विषय पर खा० सु० म० नि० द्वारा उठाए कुछ मुद्दों का स्पष्टीकरण दिया गया था। आवेदन प्रोफार्मा (संशोधित) 1973 (प्रदर्श बी-1) के ऊपर यह लिखा है कि खंभे तोड़ने का आवेदन विनियम 100 (2) 105 (1)/125/127 के अधीन किया जा रहा है जबकि विनियम 105 (1) तथा 127, जिनका संबंध रेल लाइनों तथा सड़कों आदि के नीचे काम करने से है तथा भूमिगत जलमग्नता के खतरे से है, इस मामले से ताल्लुक नहीं रखते। विनियम 100 (1) तथा 125 इस मामले पर लागू होते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक खंभे तोड़ने तथा धरातल के जल से खतरे से है। और इसलिए, यह प्रारण्य की बात है कि सेंट्रल सौदा कोलियरी के प्रबंधक द्वारा भरा गया प्रोफार्मा आवेदन तथा उसके साथ भेजे गए खंभे तोड़े जाने वाले क्षेत्र के अद्यतन नक्शों में और विशेषरूप से नई हाथीदारी के जलमार्ग के समीप तथा उसके नीचे विकास करने के मन्दर्भ में सभी आवश्यक तथा प्रासंगिक सूचनाएं नहीं दी गई हैं जबकि सेंट्रल सौदा कोलियरी के अधीक्षक (खानें) अर्थात् एजेंट श्री वी० मेवाड़ द्वारा हस्ताक्षरित 10-4-74 के पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि खंभे तोड़े जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र का एक हिस्सा अभी भी विकास के अन्तर्गत है। वास्तव में तो प्रबंधकों को इस अवसर से लाभ उठाकर खासुमनि को सूचित कर देना चाहिए था कि उन्होंने शायद गलती से बिना आपकी अनुमति के विकास कार्य नाले तक तथा उसके नीचे तक कर दिया है। उन्होंने ऐसा नहीं किया इससे यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि यह काम गलती से नहीं हुआ था अपितु यह विनियम 126 (2) के उपबन्धों को नजरअन्दा करने का प्रयास था। यह निष्कर्ष इससे भी पुष्ट होता है कि प्रबंधकों ने आवेदन के साथ प्रस्तुत नक्शों में नाले की उपस्थिति

का कोई उल्लेख नहीं किया। 12-3-77 को प्रस्तुत और 12-5-77 को अदालत के सामने हस्ताक्षरित अपने साइकलोस्टाइल बयान के पृष्ठ 12 पर प्रबंधकों ने कहा कि खान में पूर्ण में सटा हुआ नाला अज्ञान में नक्शे में नहीं दिखाया गया था। यदि ऐसा ही था तो प्रश्न उठता है कि कम से कम प्रोफार्मा आवेदन की मद 10(iii) के अन्तर्गत उन्होंने ठीक स्थिति का वर्णन क्यों नहीं किया। इस मद्द के अन्तर्गत प्रबंधकों से ऐसी नहीं, नाले अथवा किसी अन्य जलमार्ग, तालाब अथवा जलाशय का उल्लेख करवाया जाता है, जो खंभे तोड़ने के प्रस्तावित क्षेत्र के ऊपर अथवा 45 मीटर के अन्दर अन्दर आते हैं। प्रबंधकों ने इस मद्द के प्रागे ‘कोई नहीं’ शब्द भर दिया, जबकि उन्हें निश्चिततः यह पता था कि वे उस क्षेत्र के समीपवर्ती बड़े नाले तक तथा उसके नीचे पहुँच गए हैं। इस बारे में प्रबंधकों से जब पूछा गया तो उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि प्रोफार्मा आवेदन की मद सं० 10(iii) का उत्तर “कोई नहीं” की बजाय “हाँ” होना चाहिए था।

16.3 प्रबंधकों का आशय, जो जांच के दौरान अन्तिम रूप से उभर कर सामने आया, यह था कि उनके यहाँ कानूनी नक्शे प्रदर्श “डी”—में गलत दिखाया गया है कि ये बड़ा नाला खंभे गिराए जाने के प्रस्तावित क्षेत्र के 15 मीटर के अन्दर-अन्दर स्थित है। उनके अनुसार दुर्घटना के बाद खा० सु० म० नि० द्वारा वि० प्र० सर्वेक्षण (प्रदर्श “के”) दर्शाता है कि बड़ा नाला खंभे तोड़ने वाले क्षेत्र से बाहर है तथा जांच के दौरान खा० सु० म० नि० तथा प्रबंधकों द्वारा संयुक्त रूप से किया सर्वेक्षण (प्रदर्श “एम”) दर्शाता है कि बड़ा नाला खंभे तोड़े जाने वाले क्षेत्र से 96 से लेकर 120 फीट (लगभग 30 से 36 मीटर) दूर है। इस लिए वास्तव में उन्होंने विनियम 126 के उपबन्धों, जिनके अनुसार खंभे तोड़े जाने वाला क्षेत्र नाले से कम से कम 15 मीटर दूर होना चाहिए, का उल्लंघन नहीं किया है। दुर्घटना हो जाने के बाद होने वाले सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता क्योंकि तब छत घस चुकी होती है और खंभे तोड़े गए क्षेत्र तक जाने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन यदि बाद वाले दोनों सर्वेक्षणों पर भी विचार किया जाए, हालाँकि संयुक्त सर्वेक्षण के नक्शे पर खा० सु० म० नि० ने वस्तुतः नहीं किए—तब भी उनके निष्कर्षों से प्रबंधक अपने इस वायित्व से बरी नहीं हो जाते कि उन्होंने अपने आवेदन प्रोफार्मा की मद सं० 10 (iii) में गलत तस्वीर पेश की है। यद्यपि विनियम 126 में उल्लेख है कि नाला आदि खंभे तोड़ने के क्षेत्र से 15 मीटर अथवा उससे अधिक दूर होना चाहिए लेकिन खंभे तोड़ने संबंधी आवेदन में तो प्रबंधक को 45 मीटर तक की दूरी पर स्थित नालों अथवा अन्य जलमार्गों का उल्लेख करना होता है। इस मामले में प्रबंधकों ने यह नहीं किया। मद सं० 10 (iii) की आवश्यकता के पीछे जो आशय है वह स्पष्ट है। इसके द्वारा खा० सु० म० नि० को एक चेतावनी मिल जाती है कि खंभे तोड़े जाने वाले क्षेत्र के काफी निकट कोई जलमार्ग विद्यमान है, जिससे वे ऐसी स्थिति के गहन अर्थ का बड़ी सावधानी से जांच कर और ऐसे यथोचित रक्षोपाय निर्धारित कर सकें जिससे उस क्षेत्र को जलमग्न होने के खतरों से बचाया जा सके।

जलमग्न होने का खतरा

17. एक अन्य उत्तर, जो प्रोफार्मा आवेदन की मद सं० 13 के जवाब में दिया गया, उतना ही भ्रामक था। उस मद्द में पूछा गया था कि प्रस्तावित खंभे तोड़ने की कार्रवाई के कारण धरातली जल से जलमग्न हो जाने का तो कोई खतरा नहीं है, जिसके उत्तर में प्रबंधकों का जवाब था “नहीं”। आवेदन देते समय प्रबंधकों के पास सिवाय अपने कानूनी नक्शे, प्रदर्श “डी” के अलावा और कोई नक्शा था ही नहीं जिसको वे आधार बनाते और उस नक्शे से प्रकट होता है कि खान का विकास उस नाले के समीप तक ही नहीं अपितु वास्तव में तो उस बड़े नाले के नीचे तक चला गया है, फिर वे कैसे कहते हैं कि उक्त क्षेत्र में खंभे तोड़ने की वजह से धरातली जल के घुस जाने और जलमग्न हो जाने का कोई खतरा नहीं है। यदि प्रबंधकों को वास्तव में यह विश्वास था कि

जलमग्न होने का कोई खतरा नहीं है तो उन्हें अपने इस विश्वास के पक्ष में तर्क देने चाहिए थे और अंतिम निर्णय का काम विनियम 126 के अंतर्गत मुख्य निरीक्षक पर छोड़ देना चाहिए था।

उच्चतम बाढ़ स्तर

18.1 खंभे तोड़ने के काम के लिए खा० सु० म० नि० को भेजे गए धावेदन फार्म में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य का भी उल्लेख नहीं किया गया है। प्रोफार्मा धावेदन की मद सं० 11 में लिखा है:—

उच्चतम बाढ़ स्तर

क्या यह क्षेत्र किसी नदी, नाले आदि के उच्चतम ज्ञात बाढ़ स्तर के नीचे ती नहीं पड़ता?

प्रबन्धकों का उत्तर “नहीं” था। अपने इस कथन की पुष्टि के लिए कम से कम उन्हें धावेदन फार्म की मद संख्या 11 के आगे नकारी नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर के अंक का उल्लेख तो करना ही चाहिए था। लेकिन यदि उन्होंने यह अंक इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनसे ऐसा करने को स्पष्टतः नहीं कहा गया है, तब उन्हें यह अंक अपने धावेदन के साथ संलग्न नक्शे में तो दिखाना चाहिए ही था, विशेष रूप से तब जब कि विनियम 2(28) के अनुसार “नदी” का अर्थ है “जल की कोई धारा, फिर चाहे वह बारहमासी हो या मौसमी, तथा उसमें उच्चतम ज्ञात बाढ़ स्तर तक विस्तृत हो जाने वाले किनारे भी शामिल हैं।” धनबाद के खा० सु० म० नि० को भेजे धावेदन के साथ संलग्न नक्शे की प्रतियां प्रदर्श “बी-6” तथा “बी-7” में देखी जा सकती हैं। प्रदर्श बी-6 में नदी बड़े धंधले रूप में दिखाई गई है तो प्रदर्श बी-7 में नदी का देखना मुश्किल ही है। लेकिन प्रदर्शों में नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। इन प्रिंटों में संतोषजनक ढंग से सभी धरातल-परिरेखाओं को भी नहीं दिखाया गया है जिनका उस क्षेत्र के उच्चतम बाढ़ से सीधा संबंध है, जहां खंभे तोड़ने का प्रस्ताव है।

18.2 यद्यपि नकारी नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर का न तो धावेदन-पत्र में ही उल्लेख है और न उसे संलग्न नक्शे में ही दर्शाया गया है, फिर भी धावेद के दौरान प्रबन्धकों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने नदी के जिस उच्चतम बाढ़ स्तर को माना है वह 1108 फीट है जो 14 अक्तूबर, 1973 को हो गया था। उनका यह भी कहना था कि जिस क्षेत्र में खंभे तोड़ने के लिए धावेदन किया गया है वह 1108 फीट के स्तर से काफी ऊंचा है, इसलिए खंभे तोड़े जाने वाले क्षेत्र की तथा उसके आस पास की सभी परिरेखाओं को विखाने की जरूरत नहीं थी, जबकि परिरेखाओं द्वारा दिखाए जाने वाले क्षेत्र की ऊंचाई 1973 के उच्चतम बाढ़ स्तर के अंक से अधिक थी। उनके द्वारा नक्शे में दिखाई 295.56 मीटर की एक परिरेखा, नदी के 1973 के उच्चतम बाढ़ स्तर के संबंध में, प्रस्तावित खंभे तोड़े जाने वाले क्षेत्र की उच्च संमिति को दर्शाती है।

1973 के स्तर को उच्चतम बाढ़ स्तर मान लेना

18.3 नकारी नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर के लिए 1108 फीट के अंक को मान लेने के विषय में प्रबन्धकों ने अदालत के समक्ष 12-3-77 को पेश किए अपने बयान में कहा कि 16-9-76 (दुर्घटना की तारीख) से पहले उच्चतम बाढ़ स्तर बिन्दु 1108 फुट ही था। लेकिन बयान के साथ संलग्न अनुबन्ध “ग” में दिए नक्शे (प्रदर्श-2 बी) में 1108 फुट के अंक को हाथीदारी सीम पर नहीं दिखाया गया है, अपितु नक्शे के कोने पर एक अंकन के रूप में दिखाया गया है, जो इस प्रकार है:—

एन० सी० डी० सी० सौदा द्वारा 1973 में अभिलेखित पुराना उच्चतम बाढ़ स्तर 337.71 मीटर (1108 फीट) था।

इसके बारे में जब एन० सी० डी० सी० सौदा कोलियरी के प्रबन्धक श्री एस० एन० चटर्जी से पूछा गया तो उन्होंने अदालत को बताया कि जहाँ तक उन्हें याद पड़ता है, उनका उच्चतम बाढ़ स्तर उनकी कोयला खान के कानूनी नक्शे में अंकित था, लेकिन उच्चतम बाढ़ स्तर के बर्थ का किसी

भी नक्शे में उल्लेख नहीं था। इस संबंध में प्रस्तुत प्रदर्श सी० धार०-10 तथा सी० धार०-11 में दिखाया गया है कि 1108 फीट का स्तर 1966 तथा 1964 के वर्षों में पहुंच गया था, लेकिन प्रबन्धक ने कहा कि 1108 फीट का स्तर 1966 में पहुंच गया था और उससे पहले तथा बाद में भी यही अंक प्राप्त हुआ। यदि यह मान भी लिया जाए कि एन० सी० डी० सी० सौदा का बाढ़ स्तर 1973 में भी 1108 फीट ही था, तब भी अदालत को संदेह है कि उससे बिपटी सेंद्रल सौदा कोलियरी का, जो एन० सी० डी० सी० सौदा के ऊर्ध्व प्रवाह पर है, स्तर भी वही होगा। इस संदेह की बाव में तब पुष्टि हो गई जब अदालत ने प्रबन्धकों की ओर से पेश किए गवाह श्री बी० पी० बालिगा से इस संबंध में प्रश्न पूछे। श्री बालिगा, जिन्होंने इसका अध्ययन किया था, ने 1-11-77 को अदालत को बताया कि यदि एन० सी० डी० सी० सौदा पर उच्चतम बाढ़ स्तर 1108 फीट है तो सेंद्रल सौदा पर तदनुसार यह स्तर 1110.20 फीट बनेगा क्योंकि नकारी का प्रवाह बामोवर की तरफ है। इसलिए सेंद्रल सौदा कोलियरी पर भी 1973 में उच्चतम बाढ़ स्तर 1108 फीट ही था, जैसा कि अदालत में पेश प्रबन्धकों के बयान में कहा गया है, यह विश्वास करना कठिन है।

1973 के जल स्तर का आपत

18.4 12-3-77 को प्रस्तुत किए प्रबन्धकों के बयान में यह कहीं उल्लेख नहीं है कि उन्होंने 1973 में अपनी खान में बाढ़-स्तर को खुद कहीं नापा है, लेकिन उनके सर्वेक्षण श्री पी० के० मजूमदार ने 12-5-77 को अपनी गवाही के दौरान बताया कि उन्होंने 18-10-73 को सेंद्रल सौदा में 14-10-73 को आर्द्र ऊंची बाढ़ का सर्वेक्षण किया और उसका स्तर 1108 फीट पाया, जैसा कि उसकी स्तर-पुस्तिका में दर्ज है। बाव में इस पुस्तिका को प्रबन्धकों ने अदालत को दे दिया जो प्रदर्श 1 अंकित की गई है। इस प्रदर्श में सेंद्रल सौदा तथा एन० सी० डी० सी० सौदा खानों की शामलात सीमा के पास जो स्तर नापा गया उसे पैसिल से 932.30, 932.31 तथा 932.28 फीट दिखाया गया है। उसमें 175.70 फीट का बीचमार्क जोड़ा गया है तो माध्य उच्चतम बाढ़ स्तर 1108 फीट बनता है। सर्वेक्षक ने अदालत को यह बताना टाल दिया कि जब शामलात सीमा पर स्तर 1108 फीट है तो सेंद्रल सौदा कोलियरी पर तो, जो एन० सी० डी० सी० कोलियरी के ऊर्ध्व प्रवाह पर है, स्तर ज्यादा होना चाहिए। इसका उत्तर न दे पाने का कारण, उसके मतानुसार, यह था कि उसे जन-विज्ञान का काफी ज्ञान नहीं है तथापि, उन्होंने कहा कि उन्होंने सेंद्रल सौदा के किसी भी नक्शे में इस अंक को उच्चतम बाढ़ स्तर के रूप में नहीं दर्शाया है क्योंकि 1108 फीट का अंक इस कोलियरी में कभी भी मापा गया उच्चतम स्तर नहीं है। उनके अनुसार जैसा कि कोलियरी के नक्शे प्रदर्श डी तथा प्रदर्श 3 को दर्शाते हैं कि उच्चतम बाढ़ स्तर 1958 में पहुंचा था और कानूनी धरातल नक्शे प्रदर्श 3 में दिखाया 1958 का 288.748 मीटर का स्तर भी 1128 फीट बनता है। यदि ऐसा ही था तो यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने नकारी नदी के किनारे पर बने ढूँटों के स्तंभ पर उच्चतम बाढ़ स्तर के रूप में 1108 फीट दिखाए जाने पर अपनी मौन स्वीकृति कैसे दे दी। उन्होंने 12-5-77 को अपनी गवाही के दौरान कहा कि यह स्तंभ उस समय विद्यमान नहीं था तथा 10-8-77 को प्रबन्धक ने कहा कि 1976 की बाढ़ में यह स्तंभ बह गया था। 31-10-77 तथा 18-11-77 को सर्वेक्षक से जिन्हें से-यह गंभीर संदेह पैदा हो जाता है कि सेंद्रल सौदा कोलियरी पर बाढ़ स्तर को नापने के लिए वास्तव में अथवा प्रभावी ढंग से कोई सर्वेक्षण भी किया गया था अथवा नहीं।

यदि उन्होंने 18-10-73 को सर्वेक्षण किया था और जल स्तर 1108 फीट पाया था, तो अदालत यह जानना चाहती थी कि फिर प्रदर्श सी० धार०-1 (अदालत द्वारा जन्त वस्तावेज, जिसमें हाथीदारी सीम की कार्य योजना दिखाई गई है) में उन्होंने यह क्यों लिखा है कि “एन० सी० डी० सी० सौदा द्वारा 1973 में रिकार्ड किया पुराना उच्चतम बाढ़ स्तर (337.71 मीटर) (1108.00 फीट) था।”

उनका प्रविश्वनीय उत्तर तथा जो पूछे गए प्रश्न का जवाब नहीं था यह था कि सेंद्रल सौदा कोलियरी की कार्य योजना पर यह इसलिए लिख दिया गया था क्योंकि यह एन० सी० डी० सी० सौदा से चिपकी हुई है।

लेकिन यदि यह मान लिया जाए कि सर्वेक्षण किया गया और स्तर 1108 फीट ही आया, तब भी प्रश्न यह उठता है कि प्रबंधकों ने उस उच्चतम बाढ़-स्तर की व्यवस्था कैसे कर दी जो 1958 में 1128 फीट तक पहुंच गया था और जिसे स्पष्ट रूप से उनके सांविधिक नक्शों में दिखाया गया है।

1958 के उच्चतम बाढ़ स्तर की उपेक्षा

19.1 1123 फुट के स्तर की अपेक्षा कर देने के प्रबंधकों के दो तर्क थे। 9 तथा 10 अगस्त, 1977 को अपनी गवाही के दौरान, प्रबंधक ने कहा कि जब सेंद्रल सौदा कोलियरी (एक निजी मालिक से) को लिया गया तो 1958 के उच्चतम बाढ़-स्तर, जो संभवतः ऊर्ध्व प्रवाह वाली किसी कोयला खान से मांगा लिया गया था के सही होने के सर्वेक्षण के लिए कोई रिकार्ड प्राप्य नहीं थे। भेद-पुस्तिका प्रथम अन्य रिकार्डों के अभाव में उनके सांविधिक नक्शों में दिखाए 1958 के उच्चतम बाढ़-स्तर के सही होने का स्थापन करना कठिन था और इसलिए 1958 के अंक पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अदालत इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकती। यदि प्रबंधकों को 1958 के उच्चतम बाढ़-स्तर के बारे में वास्तव में कोई संदेह था तो वे अपने सर्वेक्षक, श्री पी० के० मजूमदार से इसके बारे में पूछ सकते थे क्योंकि यह सर्वेक्षक सेंद्रल सौदा कोलियरी में 1961 से प्रयत्न इस खान के राष्ट्रीयकरण तथा अपने हाथ में ले लेने के काफी पहले से ही, कार्य कर रहे थे और प्रदर्श "डी" में शुरू से आखिर तक उनके हस्ताक्षर हैं। खा० सु० म० नि० ने 15-9-77 को अदालत का ध्यान आकर्षित किया कि 1958 के पांच वर्ष बाद भी तत्कालीन प्रबंधकों (करमचन्द थापर एण्ड ब्रदर्स लि०) ने नवम्बर, 1963 में हाथीचारी सीम पर काम करने की अनुमति के लिए प्रार्थना की थी, जो नाने के अंदर तथा 15 मीटर की दूरी पर है और यह उक्त नक्शे में दिखाया गया है और उस पर श्री पी० के० मजूमदार के हस्ताक्षर हैं जिस पर 23-7-1958 का उच्चतम बाढ़-स्तर अंकित है। उक्त नक्शे का भी प्रदर्श "डी" में उल्लेख है। इसलिए प्रबंधकों के कानूनी नक्शे-प्रदर्श "डी" में दिखाए 1958 के उच्चतम बाढ़-स्तर की प्रामाणिकता पर संदेह करने की कोई संभावना नहीं है।

19.2 1123 फुट के उच्चतम बाढ़-स्तर की उपेक्षा करने का प्रबंधकों का दूसरा तर्क यह है कि सेंद्रल सौदा के ऊर्ध्व-प्रवाह पर 11 कि० मी० दूर नकारी नदी पर पतरातू बांध का निर्माण हो गया है। उनके अनुसार, 1968 के बाद बांध चालू हो जाने से 1958 की 1123 फुट का स्तर अब उस सभी खानों के लिए महत्वहीन हो गया है, जो नकारी के किनारे स्थित हैं। प्रबंधकों का कहना यह है कि जब नदी के आर-पार कोई बांध बनाया जाता है तो अनुप्रवाह की ओर बांध-पूर्व का उच्चतम बाढ़-स्तर बांध के निर्माण के बाद कम हो जाता है। लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि पतरातू बांध बन जाने के बाद बांध पूर्व स्तर में कितने फुट की गिरावट आ गई, स्पष्टतः क्योंकि न तो उन्होंने ही और न अन्य किसी ने घटे हुए स्तर को नापने की कोई कोशिश की, जबकि दामोदर के किनारे की कुछ खानों का उच्चतम बाढ़-स्तर मीठों/पणछेट बांधों के बन जाने के बाद कम हो गया था। प्रबंधकों ने मात्र यह मान लिया प्रतीत होता है कि नकारी के आर-पार ऊर्ध्व प्रवाह पर बांध बन जाने से पतरातू ताप बिजलीघर के अधिकारियों द्वारा जलाशय से समुचित तथा उपयुक्त मात्रा में जल की निकासी की जाएगी जिसमें सेंद्रल सौदा के किनारे नकारी का स्तर 1128 फुट तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा और इसलिए उन्हें उनकी खानों के जलमग्न होने का कोई खतरा नहीं था। यह तर्क माना नहीं जा सकता। क्योंकि, यदि यह मान भी लिया जाए कि बांध बन जाने से 1128 फुट का स्तर कभी नहीं पहुंच पाएगा तब भी क्या उससे नीचे का स्तर प्रयत्न 1122 फुट से लेकर

1116 फुट प्रथम यहाँ तक कि 1100 फुट का स्तर खान को जलमग्न नहीं कर देगा ?

19.3 यदि सेंद्रल सौदा कोलियरी के प्रबंधकों ने 1958 में पतरातू बांध बन जाने के बाद 1968 के उच्चतम बाढ़-स्तर की उपेक्षा कर दी तो अदालत यह जानना चाहती थी कि क्या नकारी के किनारे की अन्य सभी कोयला खानों ने भी इसी आधार पर ऐसा ही किया। खा० सु० म० नि०, जिसे यह देखने का काम सौंपा गया, ने अदालत के सामने कुछ मामले पेश किए जिनमें दिखाया गया कि उन खानों में 1958 के उच्चतम बाढ़ स्तर को ही माना जाता है। भूरकुंडा कोलियरी में, सेंद्रल सौदा के नीचे अनुप्रवाह पर है, प्रबंधकों ने 1130 फुट का उच्चतम बाढ़-स्तर, जो 1958 में खान पर पहुंच गया था, अपने 1975 में पेश किए नक्शे में दिखाया था। यह नक्शा उनकी लोअर नकारी सीम के विकास जो नाने के नीचे तथा 15 मीटर के अंदर थी, के लिए खा० सु० म० नि० को प्रस्तुत किया गया था। जहाँ तक सेंद्रल सौदा के ऊपर ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित सौदा "डी" कोलियरियों का संबंध है, खा० सु० म० नि० के प्रतिनिधि ने कहा कि जहाँ तक उसे जानकारी है, वहाँ के प्रबंधक अपने नक्शों में 1976 की बाढ़ के बाद भी 1958 के उच्चतम बाढ़-स्तर को 1129.39 फीट ही दिखा रहे हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि सेंद्रल सौदा कोलियरी के प्रबंधक अपने प्रोफार्मा आवेदन की मव सं० 11 के जवाब में, जिसमें उनसे यह जवाब मांगा गया कि क्या वह क्षेत्र जिसमें खम्बे तोड़े जाने हैं, नदी के उच्चतम ज्ञात बाढ़-स्तर से नीचे स्थित है, उच्चतम बाढ़-स्तर 1123 फुट की, जो 1958 में उनकी खान पर हो गया था, उपेक्षा कर दें। मव 11 में "ज्ञात" उच्चतम बाढ़-स्तर शब्द प्रयुक्त किया गया है, प्रबंधकों द्वारा स्वीकार कर लिया प्रथम मान लिया गया उच्चतम बाढ़-स्तर प्रयुक्त नहीं हुआ है। प्रबंधकों को यह "ज्ञात" है कि उनकी खान पर सर्वाधिक उच्चतम स्तर 1123 फीट है और उन्हें यह भी ज्ञात है कि वह क्षेत्र जिनमें कि खम्बे तोड़े जाने हैं, उस स्तर से नीचे स्थित है। इसलिए उन्हें मव सं० 11 के आगे वही "ज्ञात" अंक निश्चय चाहिए था, वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं थे। यदि वे ऐसा करते तो खा० सु० म० नि० उसकी जांच करके या तो उस क्षेत्र में खम्बे तोड़ने की कार्यवाही की अनुमति ही नहीं देता और यदि अनुमति देता भी तो इस संबंध में यथोचित रक्षोपाय भी बतलाता।

परिरेखाएं

20. इस रिपोर्ट के पैरा 18.2 में संबंधित परिरेखाओं संबंधी प्रबंधकों के दूसरे अभिमत के विषय में तथ्य यह है कि खम्बे तोड़ने के उनके आवेदन के साथ नक्शे नक्शे में सभी परिरेखाएं नहीं दर्शायी गई हैं। अदालत के समक्ष अपनी गवाही में सर्वेक्षक ने यह स्वीकार किया है कि उसे 5 मीटर की दूसरी परलंबमान अंतरों से परिरेखाओं को दिखाना चाहिए था किन्तु वह प्रदर्श 3 पर फैले लगभग 400 मीटर के क्षेत्र पर ऐसा नहीं दिखा पाया। हालांकि उसने प्रदर्श 3 में कानूनी घरातल नक्शा, 295.56, 289.56 तथा 286.50 मीटरों की तीन परिरेखाएं दिखाई हैं और कि वह प्रदर्श "डी" में ऐसा नहीं दिखाया पाया, यह उसकी शूक है। यह पूछे जाने पर कि, खम्बे तोड़े जाने के आवेदन के साथ नक्शे नक्शे में उसने 3 परिरेखाओं में से केवल उच्चतम परिरेखा को ही क्यों दर्शाया और उन दोनों को जो क्यों नहीं दिखाया, उसने कहा, प्रदर्श "डी" में जिस पर संभवतः नक्शा आधारित है, इन दोनों निम्नतर परिरेखाओं को नहीं दिखाया गया है। उसका कहना है कि यह अनजाने में हो गया है कि उन्होंने प्रदर्श "डी" में ही गई सूचना के अभाव में अन्य उपलब्ध सूचना का उपयोग नहीं किया। स्थल स्तर के बारे में, उसका कहना है कि उसने उसे मुख्य ड्रान के सम्बन्ध में दिखाया है। खम्बे तोड़े जाने वाले क्षेत्र के ग्रेड बच्चे हिस्से के बारे में उसका कहना है कि ग्रेड कार्मों में स्तर लेने का उसे समय नहीं मिला होगा। यदि सभी परिरेखाओं और विशेष रूप से 286.50 मीटर वाली परिरेखा को नक्शे में दिखाया गया होता तो सा० सु० म० नि० निश्चिततः खम्बे तोड़ने के प्रस्तावित क्षेत्र

में तथा उसके आसपास में स्तर के निहितार्थों के बारे में अधिक मावधानी से ध्यान देता क्योंकि फिर वह उसके स्तर को 1958 के 288.74 मीटर के उच्चतम बाढ़ स्तर के संदर्भ में देखते। 1958 के इस स्तर की उन्हें सूचना थी क्योंकि 1958 के बाढ़ के सैल मीदा कोनियरी के कई स्तर नक्शों में जिनकी प्रतियां उनके पास हैं यह स्तरों को दिखाए गए हैं।

21. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हाथीदारी सीम के विकास तथा खम्भे तोड़ने की कार्रवाई से सम्बन्धित प्रबन्धकों के आवेदन के विषय में विचार किया गया है। आंसुमंनि० ने आवेदन पर 2 जनवरी, 1975 को अपनी स्वीकृति दे दी: प्रदर्श "जी"। अब यह देखना जरूरी है कि क्या प्रबन्धकों ने इस मंजूरी को समुचित तथा संतोषजनक ढंग से कार्यरूप दिया। इस विषय पर ध्यान इसलिए जरूरी है कि एक छोटा नाला तथा उसके आर-पार बना एक तटबन्ध अब सामने आता है।

छोटा नाला

22.1 पैरा 16.2 में उल्लेख किया गया है कि प्रबन्धकों ने अपने खम्भे तोड़ने के आवेदन के साथ नत्थी नक्शे में बड़ा नाला नहीं दिखाया था। उक्त नक्शे तथा आवेदन में वह छोटा नाला भी नहीं दिखाया अथवा उल्लेख किया जो खम्भे तोड़ने वाले क्षेत्र के ऊपर से सीधे बहता था और इस क्षेत्र में 1975 की अन्तिम तिमाही में खम्भे तोड़ भी दिए गए थे। जब यह पूछा गया कि खान के जलमग्न होने पर सीधे प्रभाव डालने वाले इस छोटे नाले के बारे में आंसुमंनि० को सूचित क्यों नहीं किया गया तो प्रभावित को परस्पर विरोधी उत्तर प्राप्त हुए। सर्वेक्षक श्री पी० के० मजूमदार ने यह तथ्य पेश किया कि समूचे क्षेत्र पर साड़-झाड़ उगे हुए थे इसलिए छोटे नाले को देख सकना सम्भव नहीं था। खम्भे तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने से पूर्व जब धरती से साड़-झाड़ साफ कर दिए गए तो उसे नाले की जानकारी मिली। तब उसने उसका सर्वेक्षण किया और कोयला खान के कार्यालय में रखे नक्शे में उसे उसने दिखाया है। उसने कहा कि, कानूनी नक्शे पर इस छोटे नाले को 31 दिसम्बर, 1974 से पहले ही दिखा दिया गया था। क्षेत्रपुस्तिका (प्रदर्श-ई) को देखने के बाद उसने स्वीकार किया कि उसे उस नाले की जानकारी 1974 के जुलाई को अन्त में अथवा अगस्त के प्रारम्भ में हो गई थी और उसकी जानकारी मिलने के तत्काल बाद उसने इसकी सूचना कोनियरी के प्रबन्धक अथवा एजेंट को दे दी थी। यद्यपि, उसने विनियम 49, जो सर्वेक्षकों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित है, की अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं किया किन्तु उसने इस नाले के बारे में प्रबन्धक तथा एजेंट को मौखिक रूप से सूचना दे दी थी।

22.2 उक्त स्थिति को स्वीकार करते हुए प्रधान ने प्रबन्धक से पूछा कि शुरु अगस्त, में अर्थात् 9-8-74 को खान सुरक्षा महानिदेशक को खम्भे तोड़ने के लिए दूसरा आवेदन भेजने से पूर्व, जब उन्हें छोटे नाले की मौजूदगी की जानकारी हो गई थी, तो वे हम तथ्य को खान सुरक्षा महानिदेशक के ध्यान में क्यों नहीं लाए। प्रबन्धक ने कहा कि उन्हें इसकी सूचना 9-8-74 के बाद मिली थी। परन्तु जब उनसे यह पूछा गया कि इसकी जानकारी उन्हें खम्भे तोड़ने के कार्य के प्रारम्भ से पूर्व अवश्य ही दी गई होगी और उन्हें चाहिए था कि इस विषय में खान सुरक्षा महानिदेशक को लिख देने तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नवम्बर, 1974 में एजेंट श्री बी० मेवाड़ के साथ विचार-विमर्श किया था तथा यह निर्णय लिया था कि नाले की मौजूदगी तथा इस पर प्रस्तावित बांध के निर्माण की सूचना खान सुरक्षा महानिदेशक को दे दी जाए। परन्तु इस निर्णय के बाद लगभग एक ही मास के अन्दर जब उपनिदेशक, खान सुरक्षा, श्री के०बी० मजूमदार ने 13-12-74 को नई हाथीदारी की 24वीं इन्सलाइन का निरीक्षण कर लिया तो उन्होंने यह सूचना महानिदेशक को नहीं भेजी इस निरीक्षण के दौरान प्रबन्धक उपस्थित थे परन्तु अपने बयान उन्होंने न्यायालय को कहीं भी नहीं बताया कि उन्होंने छोटे नाले की मौजूदगी के बारे में उक्त अधिकारी को जानकारी दी। यह बात और भी आश्चर्यजनक है कि प्रबन्धकों ने खान सुरक्षा महानिदेशक की अनुमति प्राप्त होने से

पहले ही खम्भे तोड़ने का काम प्रारम्भ कर दिया। ये सब तथ्य बाद में प्रदर्श "एफ"-3 के पृष्ठ 1, 7 तथा 8 के माध्यम से, न्यायालय की जानकारी में आए।

खान सुरक्षा महानिदेशक को मौखिक सूचना दी गई

22.3 जब श्री मेवाड़ से पूछा गया कि छोटे नाले की मौजूदगी—जब उन्हें इसका पता चला—तथा इस पर बांध के निर्माण की बात खान सुरक्षा महानिदेशक के ध्यान में क्यों नहीं ल आई, तो उन्होंने कहा कि यद्यपि उन्होंने इन दोनों तथ्यों की सूचना खान विभाग को देने का निर्णय लिया था, किन्तु उन्हें लिखित सूचना भेजने की बात विभाग से उतर गई। उन्होंने ये तथ्य मौखिक रूप से श्री के०बी० मजूमदार के ध्यान में लाए थे जब वह अगस्त, 1975 में खान के निरीक्षण के दौरान उनके साथ थे। चूंकि उनसे उन्होंने कोई पत्रावि प्राप्त नहीं हुआ था, उन्हें संतोष हो गया अथवा विश्वास हो गया कि उनके द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त थे तथा खान सुरक्षा महानिदेशक भी इनसे सन्तुष्ट थे। श्री मेवाड़ ने कहा कि कार्य की अधिकता तथा नैमी कर्तव्यों के भार के कारण, खान सुरक्षा महानिदेशक की अनुमति न लेना सैद्धान्तिक उल्लंघन हो सकता है, परन्तु उन्हें इत्मीनान था कि खम्भे तोड़ने से कामगारों को कोई खतरा न था, और इसलिए उन्होंने यह कार्य बन्द नहीं किया।

खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा प्रतिवाद

22.4 जब अखिल ने उनके बयान लिए, श्री के०बी० मजूमदार उपनिदेशक, खान सुरक्षा, ने निश्चयपूर्वक कहा कि नालों को उस धराल नक्शे में नहीं दिखाया गया था जो कि दिसम्बर, 1974 तथा मई, 1975 में उनके द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान उन्हें दिए गए थे, और न ही प्रबन्धकों ने उन्हें बताया कि खम्भे तोड़ने के स्थल के ऊपर अथवा निकट ही कोई नाला बह रहा था। श्री मेवाड़ की बात का खण्डन करते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त, 1975 में उनके द्वारा हाथीदारी सीमा के निरीक्षण के दौरान श्री मेवाड़ उनके साथ नहीं गए थे और न ही वे छोटे अथवा बड़े नाले की मौजूदगी तथा बांध की बात उनके ध्यान में लाए।

छोटे नाले के नीचे खम्भे तोड़ना

22.5 पिछले उपपैराग्राफों के कथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रबन्धक छोटे नाले की मौजूदगी तथा खानों में पानी के भरव को रोकने के लिए उस पर उनके द्वारा बनाए गए बांध की जानकारी खान सुरक्षा महानिदेशक को लिखित रूप में दिए बिना ही खम्भे तोड़ने का काम करवाते रहे। प्रबन्धकों ने खान सुरक्षा महानिदेशालय के उन अधिकारियों को मौखिक रूप से भी नहीं बताया जो कि प्रबन्धकों को छोटे नाले की जानकारी होने के तुरन्त बाय ही खान में आए थे। पिछले उपपैरा से यह स्पष्ट है कि प्रबन्धक ने यह जानकारी नहीं दी। इस मामले में एजेंट ने भी कोताही की क्योंकि जब 12-2-75 को श्री एस०डी० प्रसाद, निदेशक, खान सुरक्षा खान सुरक्षा महानिदेशालय ने खान में खम्भे तोड़ने का प्रश्न निरीक्षण किया तो एजेंट ने उनके साथ छोटे नाले के विषय में कोई चर्चा नहीं की, बल्कि दो ऐसे मामलों के सम्बन्ध में चर्चा की जिनका विषय से कोई सम्बन्ध नहीं था। प्रदर्श "एफ" से यह स्पष्ट है।

प्रबन्धकों को छोटे नाले तथा बांध की बात खान सुरक्षा महानिदेशालय के ध्यान में लानी चाहिए थी—यह स्पष्ट हो जाता है एक तो खम्भे तोड़ने के कार्य की स्वीकृति प्रदान करने वाले खान सुरक्षा महानिदेशालय के दिनांक 2-1-75 के मंजूरीपत्र प्रदर्श "जी" से, और दूसरे कोयला खान विनियमावली के विनियम 198(2) के उपबन्धों से। इस सम्बन्ध में प्रबन्धकों के प्रतिवाद पर कि उन्होंने मंजूरी पत्र अथवा विनियम 198(2) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं किया, अगले दो उपपैराग्राफों में गौर किया जाता है।

22.6 खम्भे तोड़ने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय की मंजूरी प्रबन्धकों के उम आवेदन-पत्र पर आधारित थी जिसके साथ संलग्न, अन्य काजजात के अतिरिक्त, पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख था कि खम्भे

तोड़ने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के धरातल पर तथा उससे 4.5 मीटर के अंदर-अंदर कोई नदी, नाला अथवा जलमार्ग, तालाब अथवा जलाशय नहीं था। खंभे तोड़ने के कार्य की अनुमति देते हुए खान सुरक्षा महा-निदेशालय ने लिखा था कि उन्होंने प्रबंधकों के आवेदन पत्र तथा संलग्न नक्शों की जांच कर ली है तथा यह शर्त लगाई है कि, "इस अनुमति से संबंध परिस्थितियों में यदि कोई ऐसा परिवर्तन आ जाता है जिससे कि कामगारों, खान अथवा धरातल को कोई खतरा हो, तो खंभे तोड़ने का कार्य तुरन्त बंद कर दिया जाए तथा उसकी सूचना खान सुरक्षा के संयुक्त निदेशक को दी जाए। खंभे तोड़ने का कार्य इस महानिदेशालय की लिखित अनुमति के बिना दोबारा चालू नहीं किया जाएगा। मंजूरी पत्र की मर 10 में इस बात पर पुनः बल दिया गया जिसमें उल्लेख था कि, "यदि किसी भी समय इस अनुमति की आधारभूत शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन किया गया अथवा उसे पूरा न किया गया तो इस अनुमति को तत्काल रद्द माना जाएगा।"

प्रबंधकों के आवेदन-पत्र तथा संलग्न नक्शों में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि खंभे तोड़ने के क्षेत्र के ठीक ऊपर वास्तव में कोई नाला बह रहा था। इसका जो कारण उन्होंने दिया है वह यह है कि नाले के संबंध में उन्हें उस समय पता चला जब कि वे अपना आवेदन पत्र दे चुके थे। यदि उनके इस कथन को सही मान भी लिया जाए तो भी मंजूरीपत्र की शर्तों के अनुसार प्रबंधकों को चाहिए था कि वे उस छोटे नाले के बारे में पता चलने ही खान सुरक्षा महानिदेशालय को सूचित करते तथा इस बात की प्रतीक्षा करने कि उन्हें नाले के नीचे के क्षेत्र में उद्घाटन रूप से विस्तृत कार्य की अनुमति दी जाती है अथवा नहीं। अदालत के समक्ष श्री मेवाड़ का स्पष्टीकरण यह था कि उनके मतानुसार नाले की मौजूदगी की जानकारी से परिस्थितियों में आए परिवर्तन से चूँकि कामगारों के लिए किसी खतरे की आशंका नहीं थी उतने खंभे तोड़ने का कार्य बंद नहीं किया। अदालत का मत यह है कि प्रबंधकों का यह बिलक्षण बलि कल्पनाशून्य, रवीय प्रति अथवा यह, जबकि विनियम 198(2) में बड़े स्पष्ट शब्दों में इस शर्त का उल्लेख है कि किसी नदी, नहर, झील तालाब अथवा अन्य सतही जलाशय के किसी भाग के नीचे किसी खान में उद्घाटन रूप से खंभे तोड़ने का कार्य नहीं किया जाएगा।

22. प्रबंधकों को ज्ञात था कि वे छोटे नाले के ठीक सीधे खंभे तोड़ने का कार्य कर रहे थे और इस के लिए अदालत के समक्ष उन्होंने यह औचित्य दिया कि उनके अनुमान नुसार तत्कालीन नाला मात्र "बर्षा कटाव" था—एक साधारण सी स्थलाकृति—जोकि मानसून में वस्तुतः सभी खानों में पाई जाती है। अतः इसे खान सुरक्षा महानिदेशालय के ध्यान में लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती उन्हें इस बात में भी संदेह था कि प्राया यह "बर्षा कटाव" जिसके नीचे खंभे तोड़ने का कार्य हो रहा था, "नाला" की परिभाषा के अंतर्गत आता भी है या नहीं इनका तर्क कि "बर्षा कटाव" कोयला खान विनियमावली के अधीन नहीं आ सकता, सर्वथा प्रामाण्य है, क्योंकि विनियम - 2(28) के अंतर्गत "नदी" की परिभाषा के अंतर्गत कोई भी नाला अथवा जलधारा आ जाती है तथा आवेदन प्रोफार्मा की मर 10 में किसी भी नाला अथवा जलमार्ग का उल्लेख है। और फिर प्रबंधक एक 200 फुट (लगभग 61 मीटर लम्बे) जल मार्ग अथवा बर्षा कटाव को, जो कि श्री मेवाड़ के अनुसार 6 से 12 मीटर चौड़ा था, एक सामूची स्थलाकृति कैसे मान सकते हैं जबकि यह बड़े नाले तथा नकारी नदी से जुड़ा हुआ था। यदि प्रबंधक इसे खान सुरक्षा महानिदेशालय के ध्यान में लाए होते तो हो सकता है वे खंभे तोड़ने के कार्य की अनुमति दे देते लेकिन पूर्ण निर्वातन विधि द्वारा नहीं जैसा कि उनके मंजूरी पत्र में है, बल्कि किसी अन्य विधि द्वारा जिसे कि वे तत्कालीन परिस्थितियों में उपयुक्त समझते। वे इसे बीच बीच में खंभे छोड़ कर तथा उपरी सतह के आश्रय के लिए पीछे पर्याप्त क्षेत्र छोड़ कर कोयला निकालने की सलाह दे सकते थे अथवा इसे नोक की भराई करने की सलाह दे सकते थे और या फिर स्थिति को ध्यान में रखते हुए खंभे तोड़ने के कार्य की ही मनाही कर देते।

नक्शों में छोटे नालों का संकेत

23.1 अश्वतथ यह जानना चाहती थी कि प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्र के ठीक ऊपर बहने वाला छोटा नाला परिनियत नक्शों में वस्तुतः दिखाया भी गया था अथवा नहीं, और, यदि हां तो खानों का निरीक्षण करते समय खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों ने इसे कोई महत्व क्यों नहीं दिया और खंभे तोड़ने के कार्य के लिए अपनी मंजूरी पर पुनर्विचार क्यों नहीं किया था। इस संबंध में दस्तावेजों तथा नक्शों की जांच एवं अध्ययन से कुछ बड़े रोचक तथ्य सामने आए हैं। 21-9-76 को, अर्थात् दुर्घटना के पांच दिन बाद, खान सुरक्षा महानिदेशक के समक्ष अपने बयान में सर्वेक्षक श्री पी० के० मजूमदार ने कहा कि अगस्त, 1974 के अन्त में किसी समय उन्होंने छोटे नाले का सर्वेक्षण किया था तथा खान के प्रबंधक और एजेंट को कच्चा नक्शा दिखाया था। वे अप्रैल, मई, 1975 तक मुख्य कार्यवाहन नक्शे अथवा विभिन्न खाकों अथवा हाथ से बनाए गए नक्शों पर इस नाले (मौसमी जल-मार्ग) के स्थान का अंकेन न कर सके क्योंकि वे खान में घकेले सर्वेक्षक थे तथा उन्हें कई अन्य असांविधिक कार्य भी करने पड़ते थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनमें किसी भी नक्शे अथवा खाकों पर नाले के स्थानांकन की विधि का उल्लेख नहीं किया था। अतः सर्वेक्षक के बयान का भाव यह था कि अप्रैल, मई, 1975 के बाद खान सुरक्षा महानिदेशालय यदि खान तथा नक्शों का निरीक्षण करता तो छोटे नाले की मौजूदगी का उसे पता चम जाता।

दो दिन बाद, अर्थात् 23-9-76 को प्रबंधक ने खान सुरक्षा महानिदेशक के समक्ष जो बयान दिया वह सर्वेक्षक के तर्क का खण्डन करता है। प्रबंधक का कथन था कि नाले का स्थानांकन दैनिक प्रयोग के लिए बनाए गए दस्ती नक्शों में तो था परन्तु सांविधिक नक्शों में नहीं था। उनमें कहा कि मुख्य भूमिगत नक्शों में नाला दुर्घटना के समय तक नहीं दिखाया गया था जो कि 16 सितम्बर की दोपहर को हुई थी। 16-9-76 की रात को जब मुख्य भूमिगत नक्शा खान सुरक्षा के संयुक्त निदेशक को दिखाया गया, केवल तभी उनमें देखा कि नाले की नक्शे में दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्य भूमिगत नक्शा दुर्घटना के बाद उसी दिन देखा था, तब उन्होंने नक्शे में नाला नहीं देखा था। 23-9-77 को अर्थात् अदालत के खान सुरक्षा महानिदेशालय की रिपोर्ट प्राप्त होने के चारह दिन बाद, वाचिन किए गए अपने अनुपूर्व लिखित बयान में प्रबंधकों ने यह भी कहा कि तंग विकास (छोटा नाला) न तो खंभे तोड़ने की अनुमति के लिए प्रस्तुत नक्शों में और न ही दुर्घटना की विधि से पूर्व के दूसरे नक्शों में दिखाया गया था। प्रबंधकों के कथनानुसार यह बुरा स्वाभाविक भी और उसमें उनका कोई कदाशय नहीं था। श्री दोरेस्वामी तथा प्रबंधकों के इन बयानों का अर्थ यह भी हो सकता है कि नक्शों में छोटा नाला इसलिए न दिखाया गया हो कि इस प्रकार खान सुरक्षा महानिदेशालय के निरीक्षक अधिकारियों को हाथीवारी सीम में पानी भर जाने से उत्पन्न खतरों के बारे में आपत्ति उठाने से रोका जा सके।

23.2 पिछले पैरे में उल्लिखित खान सुरक्षा महानिदेशालय की रिपोर्ट, जिसमें सर्वेक्षक तथा प्रबंधक का बयान भी था, अदालत ने 12-3-77 को प्रबंधकों को दी, तथा तत्पश्चात् इस विषय पर शपथ लेकर हुई जिरह के दौरान प्रबंधकों के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों ने नया मोड़ लिया।

सर्वेक्षक का बयान था कि छोटे नाले का स्थानांकन अवश्य ही 31 दिसम्बर, 1974 से पूर्व खान कार्यालय में रखे सांविधिक मड़े हुए नक्शे में अन्तर्लिखित किया जा चुका होगा; उस सांविधिक नक्शे के सर्वेक्षण में नाला नहीं दिखाया गया था और यह कि ट्रैसिंग कपड़े पर बना नक्शा तब अद्यतन किया गया जब 16 सितम्बर, की रात को प्रबंधक, एजेंट, खान के महा प्रबंधक तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के साथ चर्चा के लिए ले जाया गया।

प्रबंधक का भी यही बयान था कि 16-9-76 को दुर्घटना के पश्चात् खान सुरक्षा के संयुक्त निदेशक को चर्चा के लिए जो नक्शा दिखाया गया

था वह ट्रेसिंग कपड़े पर बना नक्शा था जिस पर दुर्घटना होने के समय तक नाला नहीं दिखाया गया था। परंतु सांविधिक नक्शा प्रदर्श—“डी”—जहाँ तक खान सुरक्षा के उपनिदेशक श्री के० बी० मजूमदार को याद है, उनके द्वारा खान के निरीक्षण के समय अद्यतन था। उन्होंने कहा कि जैसे यह स्मरण रखना कठिन है कि किसी विशिष्ट तिथि को किसी नक्शे में कोई विशिष्ट स्थलाकृति दिखाई गई थी अथवा नहीं। उनके अनुसार इसका अर्थ यह हुआ कि प्रदर्श “डी” में हो सकता है छोटा नाला दिखाया गया हो अथवा प्रदर्श “डी” में न भी दिखाया गया हो जबकि इन्होंने मई, 1975 में निरीक्षण किया था। अतः प्रबंधक के बयान का अर्थ यह हुआ कि दुर्घटना के उपरान्त सांविधिक नक्शा नहीं बल्कि उसका संरक्षण अद्यतन किया गया था और यह कि उसे पुरा पता नहीं था कि सांविधिक नक्शों में यदि छोटा नाला दिखाया गया था तो कब दिखाया गया था, यद्यपि खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा किए गए निरीक्षणों के समय नक्शे से खान के कार्य की अद्यतन स्थिति प्रकट होती थी। प्रबंधक के लिखित बयान कि किसी भी नक्शे में छोटा नाला नहीं दिखाया गया था, के हवाले से प्रबंधक ने कहा कि मैनेजमेंट को नक्शों की जाँच करने का अवसर नहीं मिला क्योंकि दुर्घटना के तुरंत बाद खान सुरक्षा महानिदेशालय में इन नक्शों और विशेषकर प्रदर्श “डी” सांविधिक नक्शे को जल कर लिया था। यह नहीं है कि 23-3-77 को जब प्रबंधकों ने अपना लिखित बयान दाखिल किया तो उसके पास प्रदर्श “डी” नहीं था जिसे 17-9-76 की खान सुरक्षा महानिदेशालय ने जल कर लिया था। परंतु उनके पास एक और सांविधिक नक्शा था जिससे छोटे नाले का पता चलता था। सेंट्रल सीढ़ा कोलियरी का सतही नक्शा दिखाने वाला यह नक्शा प्रदर्श 3 बाद में प्रबंधकों ने 23-4-77 को अदालत में पेश किया। दूसरे शब्दों में, प्रबंधकों ने अदालत के समक्ष अपना लिखित बयान दाखिल करते समय अपने पास के सभी नक्शों की जाँच करने का कष्ट नहीं उठाया।

23.3 यह मानते हुए कि सांविधिक नक्शे विशेष कर प्रदर्श “डी” तथा 3 में छोटा नाला दिखाया गया था, अदालत ने खान सुरक्षा उपनिदेशक श्री के० बी० मजूमदार से जिरह की जिन्होंने खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा खम्बे तोड़ने के कार्य की अनुमति प्रदान किए जाने के पश्चात् सेंट्रल सीढ़ा कोलियरी का निरीक्षण किया था। जैसा कि पैरा 23.4 में उल्लेख है, श्री मजूमदार ने अदालत को बताया था कि बड़े और छोटे दोनों ही नाले उस सतही नक्शे में नहीं दिखाए गए थे, जो कि दिसम्बर 1974 तथा मई, 1975 में खान के निरीक्षण के दौरान प्रबंधकों ने उनकी प्रस्तुत किए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रबंधकों ने श्री मजूमदार को नहीं हाथीदारी के विकास की कोई जानकारी नहीं दी थी जोकि 1974 के अंत में पूरा हो चुका था तथा बड़े नाले तक अथवा उसके नीचे तक पहुँचा था। इसका यह भी अर्थ हुआ कि प्रबंधकों ने निरीक्षण के लिए जो नक्शा प्रस्तुत किया उसमें छोटा नाला नहीं दिखाया गया था। यदि श्री मजूमदार के कथन को स्वीकार कर दिया जाए तो प्रबंधक के इस बयान के प्रकाश में कि मई, 1975 में श्री मजूमदार के निरीक्षण के दौरान प्रदर्श “डी” में छोटे नाले को हो सकता है दिखाया गया हो अथवा न दिखाया हो इस विषय में संबंधित श्री मजूमदार के अगले बयान से एक विलक्षण सवाल पैदा होता है। उन्होंने कहा कि सांविधिक नक्शे में नाले उनके निरीक्षण के पश्चात् अगस्त, 1975 में रेखांकित किए गए। उन्होंने भागे कहा कि इन नालों को अलग-अलग स्थाहियों में दिखाया गया था और ये स्थाहियाँ फाउण्टेन पेन की स्पाही प्रतीत होती हैं जोकि नियमानुसार मान्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नक्शे में कुछ चिह्न थे जिनसे पता चलता है कि निश्चय ही कुछ मिटाया गया है और बाद में भिन्न स्थाही से कुछ दोबारा रेखांकित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्श “डी” तथा प्रदर्श 3 दोनों ही सांविधिक नक्शे में ऐसा किया गया है उन्होंने खम्बे तोड़ने के लिए आवेदन पत्र की जाँच करते समय जून, 1974 तथा दिसम्बर 1974 में प्रदर्श “डी” को देखा था, मगर प्रदर्श 3 को उन्होंने 1974-75 के सामान्य निरीक्षण के दौरान अवश्य देखा होगा, परन्तु जब उन्होंने ये दोनों प्रदर्श देखे थे, तब मिटाने का कोई चिह्न उन्हें दिखाई नहीं दिया था और ये निश्चय ही निरीक्षण के बाद बने होंगे। इस प्रकार के बयान का अर्थ यह होगा कि जो प्रदर्श उन्हें दिखाए गए

थे उनमें बड़े और छोटे नाले नहीं थे और इसी कारण उन नक्शों में मिटाने का कोई चिह्न नहीं था। यदि प्रदर्शों में नाले दिखाए गए होते तो उनके लिए उसका अर्थ यह होता कि वह हाथीदारी सीम का विकास तथा खम्बे तोड़ने का कार्य बन्द करवा देते। जहाँ तक मिटाने के चिह्नों का संबंध था, श्री मजूमदार से जिरह के दौरान प्रबंधकों ने कहा कि मिटाने के मामले में प्रबंधकों का कोई कदाशय नहीं था और यह कि भूमिगत नक्शा में प्रवर्धित चिह्न हो सकता है स्थानांकन प्रावि में किन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए मिटाने पर बने हों।

नक्शों में मिटाने के चिह्न

23.4 पिछले पैरा में श्री मजूमदार के बयान का सार यह है कि प्रदर्श “डी” अथवा प्रदर्श 3 में प्रबंधकों द्वारा नाले नहीं दिखाए गए थे जब कि उन्होंने इन्हें

(घ) 1974 में अपने निरीक्षण,

(धा) खम्बे तोड़ने के आवेदन-पत्र की जाँच, तथा

(इ) 1975 में अपने निरीक्षण

के दौरान उन्हें देखा था, और यह कि अदालत जिरह के दौरान प्रदर्शों में जो नाले उनके ध्यान में आए, अवश्य ही अगस्त, 1975 के निरीक्षण के बाद प्रबंधकों द्वारा नक्शों में बनाए गए और मिटाए गए।

उपर्युक्त तर्कों को स्वीकार करना कठिन है क्योंकि यदि प्रबंधक हाथीदारी सीम में विकास तथा खम्बे तोड़ने का काम जारी रखने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय से नालों की मौजूदगी का तथ्य छिपाना चाहते थे, तो उन्होंने नाले क्यों रेखांकित किए, क्यों मिटाए और फिर दोबारा क्यों रेखांकित किए, और यह सब कुछ अगस्त, 1975 के बाद ही क्यों। अतः जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि बड़ा नाला, जो कि एक स्पष्ट स्थलाकृति था, सांविधिक नक्शे में दिखाया गया था, परंतु बाद में यह ध्यान में आने पर कि खम्बे तोड़ने के कार्य के प्रारंभ हो जाने के बाद खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा खान तथा नक्शों का निरीक्षण होने पर, वे अनुविभाजनक स्थिति में फँस जायेंगे प्रबंधकों ने इसे बड़ी सफाई से मिटा दिया, ताकि जिससे कि यह पहली वृत्ति में ही निरीक्षक अधिकारियों के ध्यान में स्पष्ट रूप से न आ जाए। असलता, दुर्घटना के तुरंत बाद उस पर जल्दी में स्पाही फेर वेनी पड़ी, क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता तो वह और भी गंभीर स्थिति में फँस जाते। जहाँ तक छोटे नाले का संबंध है हो सकता है यह भी सांविधिक नक्शे में रहा हो, यद्यपि यह तथ्य प्रबंधक के विभिन्न अधिकारियों के बयानों से असंविष्ट रूप से स्थापित नहीं होता। सर्वशक ने प्रारंभ में यह कहा था कि वह अप्रैल अथवा मई, 1975 तक नाले का स्थान अंकित नहीं कर सके थे, परंतु इससे बाद उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने दिसम्बर, 1974 से पूर्व ऐसा अवश्य किया होगा। प्रबंधक के बयान का अर्थ मात्र यही है कि नक्शा खान सुरक्षा महानिदेशालय के निरीक्षणों के समय बूँक अद्यतन होने चाहिए, छोटा नाला सांविधिक नक्शे में अवश्य दिखाया गया होगा, यद्यपि उसे पूरा निश्चय नहीं था कि वास्तव में ऐसा किया गया था या नहीं। एजेंट श्री मेधाड़ ने जो कुछ अदालत को बताया वह यह नहीं था कि खान सुरक्षा उपनिदेशक ने छोटे नाले वाला नक्शा देखा था या उन्हें दिखाया गया था। उसका बयान केवल यही था कि “बांध और नाले का तथा मौखिक रूप से उनके ध्यान में लाया गया था” और श्री मजूमदार ने उससे इनकार किया। अतः छोटा नाला पहली बार दुर्घटना के तुरंत पश्चात् प्रवर्धित किया गया अथवा इस पर दोबारा स्पाही फेरी गई।

23.5 पिछले उप पैराओं में जो कुछ कहा गया है उससे यह संदेह बना रहता है कि क्या छोटा नाला सांविधिक नक्शों में स्पष्टतः दिखाया गया था। कारण यह कि यदि यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया होता तो यह असंभव प्रतीत होता है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के किसी अधिकारी ने खान के अपने निरीक्षण के दौरान इससे उन्मत्त होने वाली

समस्याओं को नज़र-अंदाज़ कर दिया हो। श्री जे० सी० अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, खान सुरक्षा, ने भी मई, 1975 में खान का निरीक्षण किया था, और यद्यपि इस संबंध में सांविधिक नकशों की जांच का कोई अवसर नहीं था, फिर भी जो अन्य नक्शे उन्होंने देखे, उनके अनुसार, उनमें किसी नदी प्रवाह नाले का स्थानांकन नहीं था।

छोटे नाले पर बांध

24.1 खान सुरक्षा महानिदेशालय की जानकारी में छोटे नाले की मौजूदगी न खाने का जो अन्य कारण प्रबंधकों ने दिया वह यह था कि उस पर बांध का निर्माण करके भूकंप सुरक्षा-उपाय कर लिया गया था, खान सुरक्षा महानिदेशालय को इसकी सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी। श्री मेवाड़ के अनुसार खम्भे लोड़ने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र पर्याप्त ऊंचा था तथा धड़े नाले और नकारी नदी के साथ-साथ ऊंची भूमि से चिरा हुआ था एवं नकारी प्रवाह पास के गड्ढे से सतही जल के रेले से कोई खतरा प्रतीत नहीं होता था। परंतु जब उन्होंने बाढ़-झंझाड़ को साफ किया और वहां ऊंची भूमि के थोड़े से भाग को काटता हुआ वर्षा-कटाव देखा, तो वहां उन्होंने मिट्टी का बांध बना कर भूमिगत फिर ऊंचा कर दिया ताकि बाहर का पानी उस क्षेत्र में प्रवेश न पा सके जब तक कि वह ऊंची भूमि में सम्पूर्ण क्षेत्र तक न पहुंच जाए अथवा उसे पार न कर जाए। बांध-निर्माण का काम 1974 के अंत में शुरू किया गया तथा संभवतः अप्रैल अथवा मई, 1975 तक पूरा हो गया। बांध उच्च समुद्र तल से 1105 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया। इसकी ऊंचाई 10 फुट थी जो कि चोटी पर 1115 फुट के उभार के अनुरूप थी। शिखर पर यह 2 मीटर चौड़ा तथा तल पर 11 मीटर चौड़ा था। पार्श्व ढलान 1.5 में 1 थी तथा प्रयुक्त सामग्री घासपास के क्षेत्र से ली गई मिट्टी थी जिससे परत के ऊपर परत बना कर मजदूरों ने बांध बनाया था। प्रबंधकर्ता द्वारा दी गई इन विशिष्टियों के आधार पर छोटे नाले की गहराई को मामूली बात नहीं माना जा सकता तथा खान में पानी भरने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में बनाए जाने वाले बांध के संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशालय से परामर्श करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित व्यय तथा प्रयोगार्थ सामग्री के बारे में खान सुरक्षा महानिदेशालय सुझाव दे सकता था क्योंकि खानों पर बने ऐसे बांधों का विकलता के उदाहरण उनके पास थे। बांध के विषय में परामर्श देने समय महानिदेशालय उच्च बाढ़ स्तर के प्रश्न पर सम्पर्क करने से विचार करता तथा कामगारों को बाढ़ से बचाने के उद्देश्य से उन्हें वहां से हटा लेने का निर्देश दे सकता था। एक सामान्य निर्देश के अनुसार खान सुरक्षा महानिदेशालय ही यह बात उनके ध्यान में ला देगा कि परावर्तन-बिंदु उच्च बाढ़ स्तर के अनुसार निश्चित किया जाए और यह कि कामगारों के काम से वापस बुलाने के उद्देश्य से नदी के प्राकृतिक सट को ही ध्यान में रखा जाए न कि बांध को।

24.2 इस संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशालय से परामर्श न करने का जो सब प्रबंधकों ने किया वह यह था कि विनियम 126(1)(क) के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करना उनका अपना काम है; उन उपायों के संबंध में मुख्य निरीक्षक को सूचित करना उनके लिए अनिवार्य नहीं तथा ऐसी सुरक्षा पर्याप्त है अथवा नहीं, इस बात का निश्चय करना मुख्य निरीक्षक का अपना काम है।

विनियम 126(क) निम्न प्रकार है :—

“जब कोई खान प्रवाह उमका कोई भाग ऐसी जगह स्थित हो कि खान प्रवाह उसके भाग में सतही जल के प्रवेश का खतरा हो, तो जल के ऐसे प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। ऐसी सुरक्षा पर्याप्त है अथवा नहीं, इसका निश्चय मुख्य निरीक्षक द्वारा किया जा सकता है जिसका निर्णय अंतिम होगा।”

इस संदर्भ में विनियम 126(1)(क) की चर्चा असंगत है, क्योंकि इस विनियम का संबंध मात्र उन सामान्य सुरक्षा उपायों से है जो कि प्रबंधकों खान की अवस्थिति की दृष्टि से करते हैं। इसका संबंध खान के कार्य से नहीं जो कि जांच का विषय है। खान का कार्य विनियम 126(क) के अधीन आता है जो यह शर्त लगाता है कि मुख्य निरीक्षक को

लिखित अनुमति तथा उसके द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा किए बिना, किसी नदी के किसी भाग अथवा नदी के तट से 15 मीटर की क्षैतिज दूरी के अंदर-अंदर किसी स्थान के नीचे ऊर्ध्वाधर रूप से खनन-कार्य नहीं किया जाएगा।

उच्च बाढ़ स्तर तथा बांध-शीर्ष

24.3 किसी गोफ में पानी के प्रवेश को रोकने के लिए बचाये जाने वाले बांध की ऊंचाई सदैव उस नदी के उच्च बाढ़ स्तर से संबंधित होती है जिससे कि पानी के सीधे बांध से ऊपर तथा संयोजक नालों में से बहने की संभावना होती है। अपनी गवाही में सर्वेक्षक श्री पी० के० मजूमदार ने अदालत को जानकारी दी कि यद्यपि नकशों में केवल 1958 बाढ़ स्तर को दर्शाया गया था, तथापि बांध की ऊंचाई नियत करते समय निम्न 1973 स्तर पर विचार किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि बांध के डिजाइन के संबंध में निर्णय उन्होंने नहीं लिया था। उनके बयान का अर्थ स्पष्ट है। इसका अर्थ यह है कि जहां तक उनका संबंध है, बांध डिजाइन करने समय कोयला खान में अग्रिमलिखित 1958 उच्च बाढ़ स्तर को वह नज़र-अंदाज़ नहीं कर सकता था। वास्तव में, उन्होंने अदालत के समक्ष यह माना है कि बांध का शीर्ष 1958 के उच्च बाढ़ स्तर से 8 फुट नीचे था। प्रबंधक ने सर्वेक्षक के बयान का खण्डन करते हुए कहा कि मिट्टी के बांध का काम एजेंट श्री बी० मेवाड़ तथा सर्वेक्षक श्री पी० के० मजूमदार के संयुक्त परामर्श से किया गया था। जहां तक श्री दोरे-स्वामी का संबंध है, उनका कहना है कि 1108 फुट उच्च बाढ़ स्तर संबंधी जानकारी उन्हें सर्वेक्षक की स्तर पुस्तिका, प्रदर्शनी 1 तथा नकारी के तट पर ईंटों के स्तम्भ से, जिस पर 1973 का उच्च बाढ़ स्तर 1108 फुट था, प्राप्त हुई थी। श्री मेवाड़ ने भी कहा कि उच्च बाढ़ स्तर प्रस्तावित विस्तृत क्षेत्र के समीप नकारी नदी के तट पर स्थित स्तम्भ पर अंकित था। हो सकता है कि सर्वेक्षक को जनविज्ञान का कोई ज्ञान न हो परंतु वरिष्ठतम दोनों अधिकारियों—एजेंट तथा प्रबंधक को तो यह समझ लेना चाहिए था कि सर्वेक्षक की स्तर पुस्तिका जो 1108 फुट के आंकड़े दर्शा रही थी वह एन० सी० डी० सी० सी० मीदा के साथ उनकी खान की सीमा पर थी और यदि प्रस्तावित विस्तृत क्षेत्र के समीप ईंटों का एक स्तम्भ बनाया जाता उस स्थल पर जन स्तर का ऊंचाई निर्धारण हो 1108 फुट से अधिक होती। बिजली सहायक श्री के० एम० तिबारी, जो दुर्घटना के दिन दोपहर को 12 और 1 बजे के बीच गोफ के पास ही थे, ने अपनी गवाही में अदालत को बताया कि उन्हें यह याद नहीं कि उन्होंने ईंटों का बना स्तम्भ देखा था और यह कि 18-9-76 से पहले भी उन्हें ईंटों के कालम के होने के विषय में पता नहीं था क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उसे कभी भी नहीं देखा जब प्रबंधकवार सुरक्षा उपाय के रूप में मिट्टी का बांध बनवा ही रहा था तो इस तथ्य को, कि प्रस्तावित विस्तृत क्षेत्र के नमन पार्श्व पर विकास कार्य पहले ही हो चुका था, ध्यान में रखते हुए वह गोफ के नीचे पृथक्करण भराई के स्थान पर जन बांधों का निर्माण कर सकता था। पृथक्करण भराई का प्रयोजन होता है खान में प्राय के खतरों से बचाव करना जो कि गोफ में अचानक गर्मियों के कारण भड़क सकती है। ये भराइयां पानी के भारी भार को रोकने के लिए नहीं होती और इसी लिए इन में जल सीलों की व्यवस्था रहती है ताकि गोफ में रिसता हुआ पानी उन पम्पों की तरफ बह जाए जो कि पानी का खींचने के लिए इनक्लाइन में नमन पार्श्व पर लगाए जाते हैं। सीलों के बंद हो जाने का खतरा सदा बना रहता है जिसके परिणामस्वरूप वर्षा ऋतु में गोफ के अंदर पानी भारी मात्रा में एकत्र हो जाता है। इससे पृथक्करण भराइयां टूट सकती हैं और पानी का रेला गोफ के ऊंचे पार्श्व में नमन पार्श्व की ओर जा सकता है जिनसे कि वहां काम कर रहे कामगारों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इस संबंध में प्रबंधक ने अदालत को बताया कि संभव है यदि जन बांध संभावित जल भार को सहने के उपाय बनाए जाते तो दुर्घटना टल जाती। यह खेद की बात है कि किसी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए बांध नहीं बनाए गए और दुर्घटना हो जाने के बाद ही प्रबंधकों ने मोबाइल हाथीदारी इनक्लाइन पर भूमिगत चार बांध बनाए गए जिससे कि विस्तृत क्षेत्र में खान से अलग हो जाए और भविष्य में किसी होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके।

1958 उच्च बाढ़ स्तर की उपेक्षा

24.4 प्रबंधकों ने जिस प्रकार कार्य किया उसमें निकलने वाला निष्कर्ष पर्याप्त स्पष्ट है। जब उन्होंने बांध बनवाया इसने इसकी ऊंचाई को किसी वास्तविक उच्च बाढ़ स्तर के अंक से नहीं जोड़ा। उन्होंने केवल इतना ही किया कि आस-पास की ऊंची भूमि के अंदर-अंदर छोटे ताले पर बांध बना कर इसे बंद कर दिया। इसका स्तर ऊंची भूमि का स्तर ही रहा जो 1115 फुट था। 1115 फुट के अंक को गणित की दृष्टि से 1973 के बाढ़ स्तर से जोड़ा जा सकता है जिसे प्रबंधकों ने 1108 फुट माना। इसने 1115 फुट के अंक को 1108 फुट के अंक से जोड़ा ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह यह तर्क दे सके कि बांध उच्च बाढ़ स्तर से 7 फुट ऊंचा बनाया गया जबकि विनियम 126(1)(क) में निर्धारित ऊंचाई लगभग 5 फुट (अर्थात् 1.5 मीटर) थी। यदि 1958 के अंक अपनाए जाते तो विस्तृत कार्य का प्रश्न ही न उठता जब तक कि वह बांध तथा आस-पास की भूमि को बहुत ऊंचे स्तर तक ऊपर उठाने एवं पर्याप्त प्रकार के भण्डार छोड़ने अथवा विस्तृत क्षेत्र के पश्चात् गोफ की भरवाई करने को तैयार न होते। चूंकि इस सब पर भारी खर्च पड़ता, संभवतः प्रबंधकों ने सोचा कि 1958 उच्च बाढ़ स्तर की उपेक्षा करना ही ठीक है। उनका ऐसा सोचने का आधार यह था कि 1958 में पतरातू बांध बन जाने के बाद पानी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा अथवा उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। 1108 फुट बाढ़ स्तर को अपनाना—तथा 1958 के उच्च बाढ़ स्तर की उपेक्षा करना—स्पष्टतः सही कार्यवाई नहीं थी, विशेषकर जबकि 1108 फुट का अंक वर्ष 1975 में पार किया जा चुका था। खान सुरक्षा महानिदेशालय के समक्ष प्रबंधक के 17-9-76 के बयान के अनुसार उन्हें याद था कि 1975 में पानी मिट्टी के बांध के साथ चोटी से 4-5 फुट नीचे था। इसका यह अर्थ है कि वर्ष 1975 में उच्च बाढ़ स्तर-वाले बांधों पर बांधों के लिए ही सही—1110 फुट तथा 1111 फुट के बीच था, और इससे प्रबंधकों की यह धारणा गलत सिद्ध हो जाती है कि 1973 का 1108 फुट का अंक पतरातू बांध के निर्माण के बाद कभी भी पार नहीं हो सकता। क्या उन्हें सेंट्रल सोदा कोलियरी में 1108 फुट के उच्च बाढ़ स्तर पर निर्भर होने के विषय में दोबारा सोच-विचार नहीं करना चाहिए था।

16 सितम्बर की दुर्घटना

25.1 अब हम इस बात पर विचार करें कि 16 सितम्बर, 1976 की दुर्घटना कैसे हुई।

मानभूत के दौरान अधोभूमि रखाव तथा गोफ पर वर्षा के परिणामस्वरूप भूमिगत खानों में पानी के स्तर में प्रायः वृद्धि हो जाती है और यह पानी विस्तृत कार्य द्वारा भूमिगत में बरारों से हो कर खानों में पहुंच जाता है।

15 सितम्बर, 1976 की रात को काफी भारी वर्षा हुई थी और 16 सितम्बर, के प्रातः भी बूँदा-बूँदा ही रही थी, जब यह पता चला कि सेंट्रल सोदा कोलियरी में लगभग सभी इनक्लाइनों यथा समाना, हाथीदारी तथा बांभगोड़ा, में भूमिगत पानी की मात्रा में वृद्धि हो रही थी 16 सितम्बर को प्रातः 6.30 बजे वरिष्ठ कार्यपालक अभियंता (ई० एण्ड एम०) की ए० कुण्ड को सूचना मिली कि समाना इनक्लाइन में पानी का स्तर बढ़ रहा है। अतः उन्होंने दो टिण्डल गैंग लेकर उस इनक्लाइन में दो पम्पों के परावर्तन की व्यवस्था करने के लिये बिजली पर्यवेक्षक श्री ए०के० सैन गुप्ता को कहा। जब पर्यवेक्षक दो गैंगों के साथ लगभग 8.30 बजे प्रातः इनक्लाइन पर गया तो उन्होंने देखा कि पम्प पहले ही बूझ चुका था, परन्तु स्विचगियर को निकालने के लिये अभी भी दो गैंगों की आवश्यकता थी।

25.2 पुरानी हाथीदारी में खान से कोयला नहीं निकाला जा रहा था। परन्तु नीचे बांसगोड़ा सीमा में कामगारों की सुरक्षा हेतु पानी

निकालने तथा निकले पानी की कालोनी में पूर्ति के लिये मुख्य नमन में 24वीं स्तर के समीप इनक्लाइन में एक उच्च क्षमता पम्प लगाया गया था। 16 सितम्बर की प्रातः 8 बजे अपनी पारी की समाप्ति पर पम्प खलासी श्री विलजान मियां तथा उसके सहायक ने पम्प का काम श्री रामनाथ तथा बिरजू पासी को सौंपा तो विलजान मियां ने सहायक प्रबन्धक श्री सुखदेव राज शर्मा को बताया कि इनक्लाइन में पानी बढ़ रहा है और पम्प को उस स्थान से हटाने की आवश्यकता है। सहायक प्रबन्धक ने विलजान मियां से प्रभारी फोरमैन (बिजली) श्री ए०एन० शर्मा, को मामले की रिपोर्ट करने को कहा और उसने सुबह 8.15 बजे के लगभग रिपोर्ट कर दी। जब फोरमैन ने इस स्थिति की सूचना कार्यपालक अभियंता (ई०एण्ड एम०) श्री ए० नायक को दी तो श्री नायक ने सुबह 8-30 बजे के करीब उससे कहा कि कामगारों को हाथीदारी इनक्लाइन को भेजा जाये। उसने कहा कि उसने स्थिति का जायजा लेने के लिये फोरमैन प्रशिक्षु (श्री कामेश्वर पाण्डेय) तथा मैकेनिकल फिटर (श्री इवरीस मुहम्मद) को इनक्लाइन में जाने की हिदायत की है। प्रबन्धक के अनुसार वे संभवतः पूर्वाह्न 11 बजे इनक्लाइन में गये। जब श्री ए० एन० शर्मा ने कहा कि कुशल कामगार पर्याप्त संख्या में नहीं हैं तो श्री नायक ने कहा कि श्री इवरीस मुहम्मद तथा श्री पाण्डेय से रिपोर्ट मिलने पर वह इनक्लाइन में कामगार भेजने की व्यवस्था करेगा। जब बिजली पर्यवेक्षक श्री ए०एन० सैन गुप्ता श्री बलबिंदर सिंह के साथ प्रातः 9.30 बजे समाना इनक्लाइन से ऊपर आया तो वह श्री इवरीस मुहम्मद से मिला जिसने उसे बताया कि प्रबन्धक तथा श्री नायक ने उसे श्रीलक्ष्मी हाथीदारी से पम्प ऊपर लाने के लिये नीचे जाने को कहा था। प्रातः उसने इनक्लाइन में शोध टिण्डल भेजने की प्रार्थना श्री सैन गुप्ता से की। जब श्री सैनगुप्ता गोफ की चोटी पर आये तो प्रबन्धक ने भी समाना टिण्डलों को हाथीदारी इनक्लाइन की तरफ लगाने को कहा जिस पर श्री सैनगुप्ता ने बलबिंदर सिंह को समाना सीम वापिस जा कर वहां से टिण्डल ले आने को हिदायत की। इसके बाद प्रबन्धक ने बिजली मिस्री इशार्थ को हाथीदारी में जाने को कहा। रास्ता न जानने के कारण इशार्थ चूंकि वहां न जा सका बिजली पर्यवेक्षक ने श्री सीताराम साहू को सहायक त्रिभुवन लाल के साथ वहां जाने को कहा।

इनक्लाइन में गये व्यक्ति

25.3 श्री कुंवन सिंह के अनुसार वह तथा अन्य टिण्डल समाना सीम से स्विचगियर बाहर निकालने के बाद प्रातः 10.45 बजे वहां से ऊपर आ गये तथा दोपहर 12.30 बजे पुरानी हाथीदारी में अपनी हाजिरी लगाई। वे यह नहीं बता सके कि हाजिरी रजिस्टर में उनकी हाजिरी प्रातः 11.15 बजे की क्यों लगी हुई थी। हाथीदारी इनक्लाइन पर दोपहर 12.30 बजे पहुंचने के पहले के सामान लेने के लिये स्टोर में गये थे और उन्होंने चाय भी पी थी। इनक्लाइन में जाने वाले सात व्यक्ति थे :—

सर्वश्री (1) कुंदन सिंह	टिण्डल
(2) प्रबिलाख	"
(3) रामदेव	"
(4) बलबिंदर सिंह	"
(5) राजदेव	"
(6) किशुन	"
(7) भूरे कुमार	"

पहले तीनों व्यक्ति जिन्होंने प्रीजार और साजसामान उठाया दुपरा पर इनक्लाइन के 15वें स्तर के आस-पास धीरे-धीरे गये जबकि शेष चारों

लगभग 12 से 20 मिनट में प्रत्यक्ष बोपहर 12.45 बजे 23वें स्तर तक पहुँच गये। निम्नलिखित व्यक्ति पहले ही पम्पस्थल के समीप थे:—

सर्वश्री (8) मुहम्मद इदरीस	मैकेनिकल फिटर
(9) फकीर मुहम्मद	फिटर हैल्वर
(10) सीताराम साहू	इलेक्ट्रीशियन
(11) त्रिभुवन प्रसाद लाल	बिजली हैल्वर
(12) राम नाथ	पम्प खतासी
(13) बिरजूपासी	पम्प हैल्वर
(14) के० पाण्डेय	फोरमैन प्रशिक्षु

इन्क्लाइन में पानी का घुसना

25.4 बलबिंदर सिंह ने कहा कि 23वें स्तर पर पम्पस्थल पर पहुँचने पर मैकेनिकल फिटर मुहम्मद इदरीस ने उन्हें बताया कि वे बेरी से पहुँचे थे और पम्प बूब रहा था। बलबिंदर सिंह को 23वें स्तर पर पहुँचे 5 से 10 मिनट तक हुए थे कि उनसे भन्दर हवा आती देखी जिनके साथ ही एक आवाज भी सुनाई देने लगी। तब उसने मुहम्मद इदरीस को बताया कि वह वहाँ से भाग रहा है क्योंकि पानी भन्दर आ रहा है। वह चिल्लाया "भागो, भागो, ऊपर से पानी आ रहा है" और वह इन्क्लाइन पर चढ़ने लगा। शुरू में पानी की मात्रा कम थी परन्तु बाद में इसने जोर पकड़ लिया। उसने एक सिगनल तार को पकड़ा और उस स्थल पर चढ़ आया जहाँ से पानी भन्दर आ रहा था। जब वह 15वें स्तर के पास उस स्थान पर पहुँचा पानी का रेला बड़ गया और उसके चढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया। सिगनल लाइन छोड़कर वह नीचे झुका और रेलवे लाइन पकड़ कर ऊपर आ गया। कुंवर सिंह जोकि 15वें स्तर पर था जहाँ कि भराई में एक रास्ता बना हुआ था ने बलबिंदर सिंह को यह कहते सुना कि वह नहीं बचेगा। इस पर उसने उसे अपना हाथ बढ़ाने को कहा ताकि उसे पकड़ कर पानी से बाहर निकाल सके। वह बलबिंदर सिंह को ऊपर खींचने तथा उसकी जान बचाने में सफल हो गया। दूसरे दो टिप्पणियों के साथ मिलकर कुंवर सिंह ने ठेकेदार के प्रावमियों को पानी के रेल में से ऊपर खींच कर जाम बचाने में भी सहायता की। वहाँ ठेकेदार के 6 आदमी काम पर लगे थे जो 19वें तथा 20वें स्तरों के बीच पम्प की वरार में भराई करने के लिये प्रातः 9 बजे के लगभग इन्क्लाइन में उतरे थे। कुंवर सिंह ने प्रविलास के साथ बलबिंदर सिंह को इन्क्लाइन के ऊपर भेजा। ऊपर पहुँचने पर बलबिंदर सिंह बेहोश हो गया तथा बाव में अस्पताल में उसे होश आया। प्रविलास ने बलबिंदर सिंह की इस गवाही की पुष्टि की कि जब वह कुन्वर सिंह के साथ 15वें स्तर पर आरोहण कर रहा था उसने 3x2 1/2 फुट की एक वरार देखी। इसके बाव उसने एक आवाज सुनी और हवा को भन्दर आते देखा। तब उसने उस वरार से पानी भन्दर आते देखा और नीचे काम कर रहे प्रावमियों को चिल्ला कर ऊपर भाग जाने को कहा। ठेकेदार के प्रावमियों के प्रतिरिक्त कोयलाखान का जो आदमी जीवित बचा वह बलबिंदर सिंह था। उपर्युक्त पैरा 25.3 में न०सं० (5) से (14) तक उल्लिखित पम्पस्थल पर काम कर रहे वस आदमी ऊपर न आ सके और सभी पानी के रेल में डूब गये।

कामगारों की बचने का प्रयास

25.5 प्रविलास, श्री दोरेस्वामी, जो हाथीदारी गोट में नदी के पानी के प्रवेश की बात सुनकर खान को दौड़े आये, ने 14वीं स्तर से देखा कि दक्षिण पार्श्व में भराई की वरार में से पानी बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। अपने जीवन को जोखिम में डालकर फंसे हुए लोगों तक पहुँचने के प्रयास में उसने और नीचे जाने का यत्न किया परन्तु अपने पीछे पानी के भारी रेल के कारण वे 15वें स्तर में से

आगे न जा सके। तब वे 14वें स्तर तक लौट आये और उन्होंने रेल के बोरे नीचे डालने का प्रयत्न किया ताकि मुख्य नमन में एक दीवार सी खड़ी हो जाये जिससे पानी ऊपरी पार्श्व के कटाव की ओर मुड़ जाये जहाँ कि पानी के खड़ा होने के लिये कुछ स्थान था। उसने यह हिदायत भी दी कि इन्क्लाइन में खाली टब डाल दिये जायें जिससे कि यदि वे कार्यस्थल पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ फंसे लोग उन्हें पकड़ सकें और ऊपर खींचे जाने का सिगनल दे सकें। दुर्भाग्य से ये सभी प्रयास विफल रहे।

सायं 4.30 बजे के लगभग पानी इन्क्लाइन के दूसरे स्तर तक पहुँच चुका था। खान में से पानी निकालने का प्रबन्ध 16 सितम्बर की शाम को किया गया, परन्तु पानी निकालने का वास्तविक काम 18 तारीख को ही शुरू हो सका जब नकारी का स्तर नीचे आ गया तथा नदी का पानी हाथीदारी इन्क्लाइन के पानी से प्रलग हो गया। इन्क्लाइन के मुँह तक पानी की मात्रा 17.3 करोड़ गैलन थी। चूँकि 34वें स्तर से 24वें स्तर तक पानी की मात्रा सदा 4.8 करोड़ गैलन रहती थी, उसका अर्थ यह हुआ कि इन्क्लाइन में 12.5 करोड़ गैलन पानी घुस आया था जिससे इन्क्लाइन में बाढ़ आ गई और वह पूरी तरह बूब गई। खान में से पानी निकालने तथा शवों (प्रदर्श 25) को बाहर निकालने में लगभग 2 1/2 महीने लगे। पानी की मात्रा में सामान्य वृद्धि हो जाने के कारण हाथीदारी सीम के साव-साव समाना सीम में से भी पानी निकालना पड़ा।

पम्पों की बचाने में बिलम्ब

26.1 प्राप्त साक्ष्य के आधार पर घटना केवल यही निष्कर्ष निकाल सकती है कि यद्यपि मानसून के दौरान खानों के खनन स्थल से पम्पों को हटा लेना एक नियमित प्रायः काम है, तथापि प्रबन्धकों के कथनानुसार सेंट्रल सौरा कोलियरी में 16 सितम्बर को यह काम धीमी गति से किया गया। पम्प खतासी ने बिजली पर्यवेक्षक को प्रातः 6 बजे सूचना दी कि समाना सीम में पानी का स्तर बढ़ रहा था और यह कि सीम से पम्प हटा दिया जाना चाहिये। उस सीम से दो पम्प उठाने के लिये टिप्पणियों के दो गैंगों के साथ उस सीम तक पहुँचने में पर्यवेक्षक को 2 1/2 महीने लगे; वह वहाँ प्रातः 8.30 बजे पहुँचा। इस बिलम्ब का कारण संभवतः यह था कि सीम में उतरने के लिये वरिष्ठ कार्यपालक प्रभियंता से आदेश लेने थे तथा खान के भन्दर जाने से पहले आवश्यक साज-सामान इकट्ठा करना था। परन्तु जब वे पम्प स्थल पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पम्प पहले ही बूब चुके थे। अतः उन्हें स्विचगियर हटाने के काम में जुट जाना पड़ा। यदि प्रबन्धकों ने संभावित बिलम्ब से बचने के लिये निर्धारित किसी प्रक्रिया के अनुसार जल्दी से कार्रवाई की होती तो समाना में लगे पम्प बचाये जा सकते थे।

हाथीदारी इन्क्लाइन के उतरने में बिलम्ब

26.2 हाथीदारी इन्क्लाइन के मामले में, पानी के बढ़ते स्तर की सूचना प्रभारी फोरमैन को लगभग प्रातः 8.15 बजे मिल गई थी और प्रातः 8.30 बजे तक यद्यपि हिदायतें दी जा चुकी थी कि पम्प वहाँ से हटा लिये जायें, टिप्पणियों को इन्क्लाइन में उतरने में चार घंटे लग गये, हालांकि इस बीच प्रातः 10.15 बजे पम्प सहायक बिरजूपासी प्रभारी बिजली फोरमैन को यह सूचित करने के लिये ऊपर आया था कि हाथीदारी इन्क्लाइन में पानी बढ़ता जा रहा है और पम्प की तल-पट्टियों के समीप आता जा रहा है। समाना इन्क्लाइन प्रातः 10.30 तथा 10.45 को ऊपर आने वाले टिप्पणल यदि हाथीदारी इन्क्लाइन में तुरन्त चले गये होते तो वे पम्प स्थल पर पूर्वाह्न 11 बजे तक पहुँच गये होते, और जैसाकि प्रबन्धकों का कहना है कि पम्प को ऊँचे स्तर पर हटाने में 1 1/2 से दो घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिये, वे बोपहर एक बजे से थोड़ी देर पहले यह काम पूरा कर लेते, लगभग वही समय जब पानी खान में भरना शुरू हुआ था। परन्तु प्रतीत ऐसा होता है

कि पम्पों के बचाने के काम में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, संबंधित प्रत्येक व्यक्ति, जोकि वहाँ उपस्थित था, लापरवाह था। संभवतः इसका कारण यह था कि, उनके अनुसार पम्पों को डूबने से बचाना गम्भीर मामला न होकर एक तेजी काम था। प्रातः 10.30 बजे जब समाना से बाहर आये तो वे इस स्थिति में होने चाहिये थे कि सीधे हाथीदारी की ओर चम देने, विशेषकर जब उस समय यह पता चल चुका था कि वहाँ के पम्प को डूबने का खतरा था। हाजिरी रजिस्टर यह दर्शाता है कि उन्होंने हाथीदारी सीम पर पूर्वाह्न 11.15 हाजिरी दी। परन्तु बलाबिबर सिंह तथा कुन्दन सिंह दोनों ने रजिस्टर में उस दिवस का खण्डन किया और कहा कि वे इन्कलाइन में दिन के 12.30 बजे उतरे।

पम्प हटाने में विफल के कारण दुर्घटना हुई

26.3 जिन अधिकारियों को पम्प के प्रति खतरे के बारे में जानकारी है, उन्होंने भी इस बात के निष्पत्ति के लिये कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की कि पम्प को यथार्थ अंश स्तर पर हटा लिया जाता। तब यह दिया गया कि उनके पास टिप्पण पर्याप्त संख्या में नहीं थे कि एक ही समय विभिन्न इन्कलाइनों में उतर सकते। परन्तु यदि ऐसा कि प्रबन्धकों का कहना है, मानसून के दौरान पम्पों का डूब जाने का खतरा बना रहता है, तो क्या सभी पम्पों को चालू रखने तथा बचाने के लिये उसके पास कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं होनी चाहिये। स्पष्ट है कि कोई ऐसी प्रभावी प्रक्रिया नहीं थी, हालांकि कोयला खान मुख्यालय के दिनांक 21-8-75 के निर्देश (प्रदर्श सी०आर०-14ई०) में वर्षा ऋतु कार्रवाई कार्यक्रम की रचना एवं कार्यान्वयन का उल्लेख था और कोयला खान के प्रबन्धकों के लिये आवश्यक था कि प्रतिवर्ष 31 मार्च तक इस बात को प्रमाणित करें कि वर्षा से निपटने के लिये आवश्यक प्रबन्ध कर लिये गये हैं। 18, 19 फरवरी, 1976 (प्रदर्श सी०आर०-14जे) को श्री सी०एल० बडेरा, प्रबन्धक निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०, ने सभी महाप्रबन्धकों, उपक्षेत्र प्रबन्धकों, कोयलाखान प्रबन्धकों तथा अवर प्रबन्धकों एवं सुरक्षा अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से लिखा था कि वे विभिन्न स्तरों पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था और वर्ष 1976 के दौरान अपनी खानों को पूर्णतया सुरक्षित एवं दुर्घटना मुक्त बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उठाये जाने वाले कदमों की जाँच करें। इसके कुछ दिन पश्चात्, वर्षा ऋतु के आरम्भ से पर्याप्त पहले, 20, 24 फरवरी, 1976 को बाढ़ आदि के विषय सुरक्षा उपायों संबंधी सामान्य निर्देश (प्रदर्श सी०एल०-14के) जारी किये गये। इसमें सुझाव दिया गया था कि पम्पों की स्थापना एवं अनुरक्षण का कार्य बड़े ध्यान से तथा विधि-अनुसार किया जाये और पर्याप्त रूप से कुशल व्यक्ति काफी संख्या में लगाये जायें। यह भी कहा गया था कि इस बात का निष्पत्ति करने के लिये कुल हासंभाव्य अथवा पम्पों की संख्या अथवा खान के विस्तार के आधार पर कार्यभार तथा पम्पों के लगाने और उनकी ठीक देखभाल के लिये आवश्यक हाजिरी/पर्यवेक्षकों तथा कर्मचारियों की संख्या के बीच कुछ संबंध स्थापित कर लिया जाना चाहिये। कि जाने वाले सुरक्षा उपायों के इस संबंध में कोयला खान के प्रबन्धक टिप्पणों तथा अन्य कर्मचारियों को रिजर्व में रख सकते थे, ऐसा आकारण नहीं होता, अथवा वर्तमान कर्मचारियों की इगूटिया इस प्रकार लगा सकते थे कि वर्षा ऋतु के दौरान खानों में लगे पम्पों को बाढ़ से बचाया जा सके। यदि सेंट्रल सौरा में ऐसा किया गया होता, तो वेगमैन, फिटर, बिजली मिस्त्री तथा पर्यवेक्षक को पम्प बचाने के लिये तुरन्त और यदि आवश्यक होता तो एक साथ, सभी इन्कलाइनों में भी भेजा जा सकता था। तब कामगार हाथीदारी में पम्प को ऊँचे स्तर पर हटा कर ले जाते तथा इन्कलाइन में पानी का घुसना आरम्भ होने से पहले बाहर आ गये होते। ऐसी स्थिति में पानी के रेतने में पम्प तो डूब जाते, परन्तु उन इन्कलाइन में वम व्यक्तियों की जान ना जाती।

मृतकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति

27. बकायाना क्षेत्र के महाप्रबन्धक श्री ए०के० जटर्जी अपने अधिकारियों के साथ संचार-व्यवस्था भंग हो जाने के कारण बड़ी कठिना

से 16 सितम्बर की शाम को सेंट्रल सौरा कोलियरी में पहुँचे। 17 तारीख को सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के प्रबन्ध निदेशक श्री बी०एल० बडेरा, खान सुरक्षा महानिदेशक श्री एम०एस० प्रसाद, जिलाधाय, हाजारी-बाग, श्री डी०एस० मुखोपाध्याय तथा उनके अधिकारी कोयलाखान गये। श्री बिदेसरी दुबे, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार, श्री के०एस० आर० चारी, सचिव, कोयला विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार तथा श्री ए०यू० शर्मा, संयुक्त सचिव, अम मंत्रालय, भारत सरकार भी मध्य सौरा कोयला खान तथा बाढ़ से प्रभावित अन्य कोयला खानों को देखने गये। वे जतरण के०एस० ग्रेवाल, अध्यक्ष, कोल इण्डिया, लि० ने, जो कोयला खान में 18 सितम्बर को पहुँचे, विपत्तिग्रस्त परिवारों को सभी संभव एवं तुरन्त सहायता का आश्वासन दिया। श्री एस०दाम गुप्ता, महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय खान कामगार संघ, श्री दामोदर पाण्डेय तथा श्री जतुनाम मिश्र, विधान सभा सदस्य भी कोयला खान में गये। जो सहायता दी गई वह निम्न प्रकार थी :—

- (अ) मैनेजमेंट द्वारा विपत्तिग्रस्त प्रत्येक परिवार को एक माह के मुक्त राशन के अतिरिक्त रु० 500 तकाल दिये गये।
- (आ) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को एक सप्ताह में मुक्त राशन के अतिरिक्त रु० 500 तकाल दिए गए;
- (इ) मैनेजमेंट द्वारा अन्तिम संस्कार के लिए प्रत्येक परिवार को रु० 200 दिए गए;
- (ई) सी०जी०एल० हितकारी निधि से विपत्तिग्रस्त प्रत्येक परिवार को रु० 2,000 दिए गए;
- (उ) प्रत्येक परिवार को कोयला खान कल्याण संगठन (अम संसालय, भारत सरकार की ओर से रु० 250) तथा विधवाओं को रु० 75) मासिक पेंशन एवं उनके बच्चों को छात्रवृत्तियाँ दी गईं;
- (ऊ) मृतकों के निकटतम संबंधियों को सी०जी०एल० द्वारा नौकरी का प्रस्ताव।

कर्मचारियों को अन्य देय राशियाँ तथा मजदूरी, शेष मजदूरी हाजिरी बोनस' ए०ई० (सी०जी०) राशियों की वापसी तथा उपदान के मामले तय कर दिए गए तथा दुर्घटना के एक माह के घन्वर-घन्वर सब की अदायगी कर दी गई। कोयला खान भविष्य निधि जमा वापसी संबंधी कार्यवाही तुरन्त की गई तथा कर्मचारी अतिपूर्ति अधिनियम के अधीन मृतक के लिए रु० 21,000 तथा रु० 23,000 के बीच देय राशियों को कर्मचारी क्षति-पूर्ति आयुक्त धनबाद के पास जमा करवा दिया गया।

इस विपत्ति से बच निकलने वाले एक मात्र व्यक्ति टिप्पण बलाबिबर सिंह को रु० 3,000 का तकद पुरस्कार दिया गया।

18 सितम्बर को जलस्तर में वृद्धि

28.1 पिछले पैंनाओं में सतही नदी जल के गौफ के रास्ते हाथीदारी सीमा में भर जाने के परिणामस्वरूप 16 सितम्बर, 1976 को होने वाली दुर्घटना पर चर्चा की गई है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रबन्धकों के पास खान में बाढ़ के किसी खतरे की पूर्वचेतावनी देने की उपयुक्त व्यवस्था थी और क्या 13वीं इन्कलाइन में काम कर रहे व्यक्तियों को निकालने तथा उस दिन एक बजे दोपहर को हुई दुर्घटना से उन्हें बचाने के लिए, बड़े जल-स्तर के प्रकाश में, यह कोई उपयुक्त सुरक्षा पूर्वोपाय कर सकती थी और क्या इसने ऐसा किया।

प्रातः 9.15 तथा 10.30 बजे के बीच

28.2 16 सितम्बर को जिन व्यक्तियों ने जलस्तर देखा था, अखिलत के समक्ष उनके साथ में से श्री कुण्डू की गवाही से पता चलता है कि उस दिन प्रातः 9.15 तथा 10.30 बजे के बीच जलस्तर नकारी पर बने आर० सी० सी० पुल के ऊपर तक बढ़ गया था। श्री ए०कुंडू वरिष्ठ कार्यपालक अभियंता (ई०एंडएम०) जिन्हें पिछले 2 में बाढ़ 3 के नियंत्रक रेग्युलेशन बाल्व की मरम्मत करवाने के उद्देश्य से सेंट्रल सौरा कोलियरी से बाहर जाना पड़ा था, को नकारी पर बने आर० सी० सी० पुल को, दामोदर-नकारी संगम के निकट, आने जाने के लिए पार करने के अमसर

ये। जब वह मरम्मत के लिए वर्कशॉप को अपनी कार में जा रहे थे, प्रातः 10.15 बजे के करीब पुल पर घटने तक पानी था और उन्होंने इसे पार नहीं किया। पूर्वाह्न 11 बजे जब एजेंट श्री एस० एन० मुखर्जी बाहर निकले तो उसने भी पुल के ऊपर उनके अनुमान के अनुसार 8 फुट ऊंचा बहुता पानी देखा। खान सुरक्षा महानिदेशक के समक्ष सुरक्षाधिकारी श्री एस० के० दत्त, चौधरी तथा अवर प्रबन्धक श्री के० के० गुप्ता की गवाही के अनुसार जलस्तर दिन के 10-30 अथवा 11 बजे के पहले भी बढ़ रहा था। सुरक्षा अधिकारी ने 17-9-76 को अपने हस्ताक्षरित बयान में खान सुरक्षा महानिदेशक को बताया कि उसने 16 सितम्बर को प्रातः 8-30 बजे 300 फुट की दूरी से पानी की स्थिति देखी तो नाथे में पानी बांध की चोटी से लगभग 5 फुट नीचे अर्थात् उच्चस्तर 1110 फुट पर था। इसके पश्चात् खान सुरक्षा महानिदेशक, प्रबन्ध निदेशक तथा खान सुरक्षा निदेशक के साथ मौखिक चर्चा के दौरान जब यह प्रश्न उठा कि क्या पानी मिट्टी के बांध की चोटी से 2 फुट नीचे था, सुरक्षा अधिकारी ने फिर दोहराया कि पानी बांध की चोटी से 5 फुट नीचे प्रतीत होता था। यह कथन, प्रवेश "ए"-9 उसके अपने हाथ का लिखा हुआ है तथा उसने इस पर उसी दिन, अर्थात् 17-9-76 को हस्ताक्षर किए। श्री के० के० गुप्ता ने 22-9-76 को खान सुरक्षा महानिदेशक को यह भी बताया कि उसने देखा था कि न्यू हाथीवारी खुदाई क्षेत्र के समीप जलस्तर बांध से लगभग 3 फुट नीचे था। परन्तु जब अवगत के समक्ष गवाही देने का समय आया तो इन दोनों ने बात बदल ली और कहा कि जो स्तर उन्होंने देखा था वह बांध की चोटी के संदर्भ में नहीं था बल्कि उसके आधार अथवा तल के संदर्भ में था। श्री एस० के० दत्त ने 14-7-77 को अदालत को बताया कि जब उन्होंने प्रातः 8-30 बजे के करीब निरीक्षण किया तो उनके अनुमानानुसार जल स्तर बांध के आधार से लगभग 3 से 5 फुट नीचे था। और इसलिए उन्होंने प्रबन्धक को सूचना दी कि उस समय खतरे की कोई बात नहीं है। 24-7-77 को भी के० के० गुप्ता ने अपने बयान में अदालत को बताया कि उन्होंने बांसगोडा इन्साइटन को चोटी के समीप से, जो कि हाथीवारी सीम के खुदाई क्षेत्र से 300 फुट अथवा उससे अधिक दूर था, प्रातः 9 बजे पानी का स्तर देखा और अनुमान लगाया था कि स्तर बांध आधार से लगभग 3 फुट नीचे था। जब उन्होंने यह कहा कि बांध आधार तो बांसगोडा इन्साइटन की चोटी के पास से दिखाई नहीं देता होगा, उन्होंने कहा कि ऐसा ही था और यह कि यह उनका अनुमान मात्र था कि जल स्तर बांध के आधार से लगभग 3 फुट नीचे होगा।

28.3 यदि वह तर्क दिया जाए कि बांध अदालत के समक्ष शपथ लेकर दिए गए गवाहों के बयान खान सुरक्षा महानिदेशक के समक्ष दिए गए बयानों—जो खान अधिनियम, 1958 की धारा 23(2) के अधीन कुर्बतना बटने के पश्चात् सांख्यिक जांच करता है—से अधिक महत्व अथवा मान्यता रखते हैं, तो भी खान सुरक्षा महानिदेशक के समक्ष गवाहों के हर बयान की पूर्णरूप से उपेक्षा ही करना व्यावहारिक नहीं, विशेषकर जबकि बांध में अदालत के समक्ष उनके बयान स्पष्टरूप से न तो संपुष्ट किए जाते हैं और न ही अदालत के समक्ष तथ्यों से सिद्ध हो होते हैं। सुरक्षा अधिकारी तथा अवर प्रबन्धक के बयानों को मान कर चलना कठिन है, विशेषकर जब प्रबन्धकों ने स्वयं अदालत को प्रस्तुत अपने लिखित बयानों में 16 सितम्बर को प्रातः जल-स्तर के काफी ऊपर बढ़ जाने की बात स्पष्ट रूप से कही है। 28-3-77 को अदालत को प्राप्त खान सुरक्षा महानिदेशक की रिपोर्ट पर अपनी लिखित टिप्पणी के पृष्ठ 3 पर प्रबन्धकों ने कहा है कि श्री एस० के० दत्त चौधरी द्वारा 16-9-76 की प्रातः 8 बजे नकारी जलस्तर का अनुमान सही नहीं हो सकता और यह कि उपलब्ध बाढ़कारी के आधार पर उस समय जलस्तर 1108 फुट से अधिक नहीं हो सकता अर्थात् बांध की चोटी से 7 फुट। इस प्रकार 1108 फुट का अधिकतम खान सुरक्षा महानिदेशक के समक्ष दो अधिकारियों द्वारा बताया गया कि 1108 फुट तथा 1112 फुट के अंकों से कम है, 1100 फुट तथा 1102 फुट के अंकों के आसपास नहीं है जो कि अदालत के समक्ष उन के बयान के अनुसार है। राष्ट्रीय कोयला खान मजदूर संघ (आर० सी०

एम० एस०) द्वारा दायित्व तथा 25-4-77 को संशोधित बयान पर अपनी टिप्पणी के रूप में दी गई अनुपूरक जानकारी में प्रबंधकों ने कहा कि यह सही था कि भूकंप तथा सौदा के बीच आर० सी० सी० पुल दिन के ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तक बूब चुका था। यह बात अंतिम रूप से ज्ञात उच्चतम बाढ़ स्तर के 1108 फुट के अंक से मेल खाती है। अतः यदि एन० सी० डी० सी० सौदा के समीप उस पुल पर निम्न धारा का जल-स्तर, उनके अपने कथनानुसार, 1108 फुट तक पहुंच चुका था तो क्या उनकी अपनी खान में स्तर बांध आधार से कम से कम 3 फुट ऊपर 1105 फुट तक नहीं होगा। श्री एस० एन० बटजी प्रबंधक एन० सी० डी० सी०—सौदा कोयला खान ने भी इस बात की पुष्टि की कि सेंट्रल सौदा कोलियरी के निकट नकारी का स्तर सदा ही एन० सी० डी० सी०—सौदा के स्तर से ऊंचा ही रहेगा। इस दृष्टि से निम्न धारा पर आर० सी० सी० पुल पर ग्यारह तथा साढ़े ग्यारह बजे के बीच का जलस्तर प्रबंधकों के लिए पूर्व-चेतावनी के रूप में माना जाना चाहिए था। इस रिपोर्ट के भाग-तीन से जैसे कि स्पष्ट हो जाता है कि पुल दिन के ग्यारह बजे ही बूब चुका था। दिन के ग्यारह बजे

28.4 खान सुरक्षा महानिदेशालय की रिपोर्ट पर टिप्पणी करत हुए प्रबंधकों ने कहा कि विभिन्न व्यक्तियों के नियमानुसार दिन के ग्यारह बजे पानी बांध की चोटी से 5 फुट नीचे था। पानी का उस स्तर पर पहुंचना कोई असामान्य बात नहीं थी। एजेंट श्री बी० मेवाड़ ने 21-9-76 को खान सुरक्षा महानिदेशक के समक्ष अपने बयान में कहा कि 1975 में नकारी में उच्चतम बाढ़ के दौरान जल स्तर बांध की चोटी से 5 फुट नीचे तक पहुंचा था। उन्होंने 12-8-77 को अदालत के समक्ष अपने बयान का खण्डन यह कहते हुए किया कि 5 फुट का अभिलिखित अंक 5 मीटर होना चाहिए था क्योंकि 1975 में नकारी नदी में उच्च बाढ़ नहीं आई थी। प्रबंधक ने 17-9-76 को खान सुरक्षा महानिदेशक के समक्ष अपने बयान में कहा था कि पिछले वर्ष भी पानी नकारी पुल से ऊपर आ गया था और मिट्टी के बांध के साथ पानी चोटी से 4-5 फुट ही नीचे था। तब यह जानते हुए भी 1108 फुट का उच्च बाढ़ स्तर जिसे उन्होंने मिट्टी का बांध बनाने के लिए आधार माना 1975 में पार हो चुका था। प्रबंधकों को यह बात क्यों न सूझी कि वह 1976 में वर्षा ऋतु के दौरान जल-स्तर तक पर लगातार और निर्बाध रूप से नज़र रखने के लिए खान में उपयुक्त स्थानों पर बाढ़ भ्रमों लगाने तथा प्रेक्षण स्थल बनाने जैसे विशेष उपाय करते। यह कुछ करने के लिए उनके पास साल भर का समय था परन्तु उन संबंध में कुछ न किया गया। प्रबंधकों के लिखित बयान के अनुसार जब उन्हें पता चल गया था कि 16 सितम्बर को दिन में ग्यारह बजे जल स्तर 1110 फुट तक पहुंच चुका था क्या प्रबंधकों को नहीं चाहिए था कि दिन के ग्यारह बजे (वास्तव में उससे भी पहले) के आस-पास वे हाथीवारी से लोगों को निकालने का काम शुरू कर देते तथा लोगों को उस सीम में उतरने से रोकते जबकि पानी खतरे के बिन्दु से अर्थात् बांध की चोटी से 5 फुट नीचे तक पहुंच चुका था।

खान से लोगों को वापस बुलाना

29.1 उन्हें निश्चय ही यह कार्रवाई करनी चाहिए थी क्योंकि वे नियम 126 के अनुसार (1) (ब) से अनुमति नहीं होने जिसके अनुसार प्रत्येक खान में प्रत्येक प्रवेश इस प्रकार होना चाहिए कि इसका निम्नतम बिन्दु—जहाँ स्थान जहाँ से पानी सतह से खान में प्रवेश करता है—उच्चतम बाढ़ स्तर के ऊपर 1.5 मीटर (लगभग 4.92 फुट) से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जब पानी 1115 फुट की ऊंचाई पर बांध की चोटी से पांच फुट नीचे तक पहुंच गया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बाढ़ 1110 फुट तथा 1112 फुट के बीच के स्तर को छू चुकी थी, और यह स्तर 1973 के उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊंचा था जो कि प्रबंधकों के अनुसार 1108 फुट था। इसका यह अर्थ था हुआ कि 1115 फुट के स्तर, जिसके ऊपर जल खान में प्रवेश कर सकता था, तथा 16 सितम्बर, 1976 की दोपहर को पानी के स्तर के बीच अंतर नियम में निर्धारित 4.92 फुट के अंतर से कम था।

30.1 सुरक्षा अधिकारी भी सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.03 12.20 बजे के बीच खान के घरातल पर नहीं था बल्कि वह इस दौरान नए बासंगो डा० इनक्लाइन के अंदर था और उसने प्रबंधक को संदेश दिया था कि 18 सितम्बर को सुबह 9 बजे के पास पास कोई घसाधारण घटना नहीं थी लेकिन यह भी एक घसामान्य बात थी कि एक सुरक्षा अधिकारी बरसात के मौसम में पूरे 3 घंटे के लिए खान के घरातल पर उपस्थित नहीं था जबकि मकरी नदी भी कोई दूर नहीं थी और एक नाला भी हाथीदार के पास बह रहा था और एक छोटा नाला भी वास्तव में गोक के ऊपर बह रहा था। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि प्रबंधकों ने श्री एस० के० दत्त चौधरी को बोहरा कार्यभार सौंप रखा था। जैसा कि एस० के० दत्त चौधरी ने बताया है कि नया बासंगो डा० इनक्लाइन के उत्पादन प्रबंधक के रूप में उनकी मुख्य जिम्मेदारी खान के उत्पादन में वृद्धि करना था और सुरक्षा अधिकारी के रूप में वे सुरक्षा संबंधी मामलों पर मात्र कागजी कार्रवाई करते थे। सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्यों का सविस्तार और बारीक उल्लेख विनियम 414 में किया गया है। इस विनियम में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि यदि किसी सुरक्षा अधिकारी को इस विनियम में विहित कर्तव्यों के अलावा अन्य कर्तव्य भी सौंपे जाएं तो इस आशय की एक लिखित सूचना उक्त इयटी के सौंपे जाने के 3 दिन के भीतर क्षेत्रीय निरीक्षक अर्थात्

खान सुरक्षा महानिदेशक को भी दी जानी चाहिए। इस संबंध में श्री चौधरी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है लेकिन जहाँ तक उनका विचार है, ऐसी कोई लिखित सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने भ्रवालत को यह भी बताया कि जब उन्होंने दोहरे कार्यभार के बारे में आपत्ति प्रकट की थी तब प्रबंधकों ने कुछ समय के लिए दोनों कार्यभार संभालने के लिए उनसे आग्रह किया था। कुछ दिनों तक दोनों कार्यभार संभालने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि दोनों कार्यभार एक साथ संभालना व्यवहारतः संभव नहीं है अतः उन्होंने प्रबंधकों से निवेदन किया था कि वे उन्हें केवल एक ही जिम्मेदारी सौंपें। उसके बाद एक सहमति हुई कि श्री चौधरी नया बांसगोड़ा इनक्लाइन के प्रभारी सहायक कोयलाखान प्रबंधक के रूप में काम करें और कागजों पर सुरक्षा संबंधी मामलों की देखभाल करें। लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि श्री चौधरी को दोहरा कार्यभार सौंपा गया था फिर भी इस बात की सूचना खान सुरक्षा महानिदेशक को नहीं दी गई थी, जैसा कि प्रवर्ग-19 से प्रकट होता है भ्रवालत को इससे भी अधिक आश्चर्य तो प्रबंधकों वर्ग के कार्यालय आदेश तारीख 7-4-78 पर हुआ जो भ्रदालत के पिछले निदेशानुसार उसमें 9-8-77 को प्रस्तुत किया गया था और उस पर प्रवर्ग 18 अंकित किया गया था।

दोहरे कर्तव्यों सहित प्रबंधक के प्रधीन

30.2 जिम कार्यालय आदेश में इस बात का उल्लेख था कि श्री चौधरी सुरक्षा अधिकारी और नया बांसगोड़ा इनक्लाइन के कार्य-भारी के रूप में काम करेंगे, उससे भ्रदालत को एक और इस तथ्य का पता चला जो उसे पहले मालूम नहीं था कि 27-4-77 को श्री के० के० गुप्ता के बारे में जांच की जा रही थी कार्यालय आदेश में यह लिखा था कि प्रबंधक के अधीन श्री के० के० गुप्ता न्यू बांसगोड़ा इनक्लाइन की देखभाल करेंगे और सुरक्षा अधिकारी के रूप में श्री चौधरी के कार्य में सहायता भी करेंगे। यह तथ्य 27-4-77 को श्री गुप्ता की जांच के दौरान नहीं बताया गया था। उस समय उन्होंने यही बताया था कि उनकी ब्यूटी केवल नया बांसगोड़ा इनक्लाइन के उत्पादन की देखभाल करना है। यदि यह बात मान ली जाय कि अप्रैल 1977 में भ्रवालत के समक्ष बयान देते समय वे खान के सुरक्षा संगठन से सम्बद्ध नहीं थे फिर भी यह तथ्य कि वे दुर्घटना के दौरान इससे सम्बद्ध भ्रदालत के समक्ष विशिष्ट रूप से पेश किया जाना चाहिए था।

श्री गुप्ता ने जब सुबह 8.30 बजे नकारी नदी की स्थिति देखी थी, उसके आधा घंटे बाद वे सुरक्षा अधिकारी को बता सकते थे कि इस मामले में कुछ आवश्यक पूर्वापार किए जाएं और विशेष रूप से उस स्थिति में जब उनका विचार था कि नकारी नदी में सुबह 9 बजे पानी बढ़ गया था, उन्हें ऐसे पूर्वा उपाय करने के लिए कहना चाहिए था। तारीख 27-4-77 को उनसे यह पूछे जाने पर कि जब उनका कयाल था कि नदी के पानी का स्तर बढ़ रहा है तब उन्होंने नकारी नदी पर बराबर निगरानी रखने के लिए किसी व्यक्ति को तैनात क्यों नहीं किया और वे स्वयं भी स्थिति का सही जायजा लेने के लिए नदी के किनारे क्यों नहीं गए तो इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जलस्तर बहुत अधिक नहीं था और उनका अनुमान था कि श्री चौधरी ने इस संबंध में कोई कार्यवाई कर ली होगी। जब उन्होंने 27-4-77 को भ्रदालत की यह बताया कि उनका अनुमान था कि जब पानी का स्तर 1105 फुट के ऊपर पहुँच जाता है तब कामगार काम से वापस बुला लिए जाने चाहिए, तब उनसे पूछा गया कि क्या नदी के 1105 फुट के स्तर की विधाने के लिए कोई बैच मार्क था। उनका जवाब था कि उन्हें मालूम नहीं है कि खान में ऐसा बैच मार्क है। उन्होंने और सुरक्षा अधिकारी ने इस प्रकार का कोई प्रबंध कराने का कष्ट नहीं उठाया जिससे कि जब जलस्तर 1105 फुट या उससे ऊपर के निशानों को छू रहा था तब पहरेदार और सुरक्षा कर्मचारी जल स्तर का निगरानी कर सकते। उनके उस स्थिति में और भी आवश्यक था जब कि वे दोनों सरकारी तौर पर खान की सुरक्षा के काम से संबद्ध थे हालांकि उनमें से एक सुरक्षा संबंधी मामलों पर मात्र कागजी कार्यवाई करता था। अनुमान लगाया जाता है कि नकारी पर खंभे तोड़ने के क्षेत्र के पास जल-स्तर

मालूम करने के लिए ईंटों का एक स्तंभ होना चाहिए था। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यह स्तंभ सन् 1976 की बाढ़ में बह गया जब कि ऐसे स्तंभ सेंट्रल सीढा के दोनों ओर सीढा "डी" और एन० सी० डी० सी० सीढा कोलियरी में बाढ़ में बच गए थे। जब उनसे पूछा गया कि जब वे सुरक्षा अधिकारी के साथ बमिंगोड़ा इनक्लाइन के नीचे जा रहे थे और वे वहाँ, कुछ घंटे बाद साथ-साथ बाहर निकलने के समय तक उनके साथ थे तब क्या उन्होंने श्री चौधरी से उनके द्वारा की गई सुरक्षा संबंधी कार्यवाई के बारे में पूछा था। इस प्रश्न के उत्तर में श्री गुप्ता ने केवल यही कहा कि सुरक्षा अधिकारी ने मुझ से यह कहा था कि जलस्तर को वृद्धि से कोई खतरा नहीं है।

बाढ़ चेतावनी के कोई उपाय नहीं

30.3 यह बड़े आश्चर्य की बात है कि कोयला खान में सुरक्षा मामलों के संबंध में, खासतौर पर उस स्थिति में भी ऐसी शिथिलता बरती गई है जबकि मुख्यालय अर्थात् सी० सी० लिमिटेड से जैसा कि प्रबंध निदेशक ने बताया है, ऐसे बराबर निर्देश मिलने रहे थे कि सभी खानों में सुरक्षा का सर्वोपरि महत्व है और खानों से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सुरक्षा कार्य की बलि नहीं देनी चाहिए। यदि सुरक्षा अधिकारी या के० के० गुप्ता खान के भ्रवालत पर होते और वे सुरक्षा संबंधी मामलों पर अनन्य रूप से कार्यवाई करते तो उस दिन हाथोदारी गोफ के बढ़ते हुए जल-स्तर पर अधिक ध्यान दिया जाता। चूंकि वे वहाँ नहीं थे। अतः कोयला खान ने यह मान रखा था कि खानों में किसी का समय पानी आने का कोई खतरा नहीं था।

सुरक्षा उपाय

30.4 यह पूछे जाने पर कि क्या बाढ़ से बचने के लिए कोई सुरक्षा उपाय किया गया था, एजेंट श्री एस० के० मुखर्जी ने कहा चूंकि सेंट्रल या सीढा समीपस्थ कोयला खानों में बाढ़ भ्रलाम लगे थे, अतः ऐसा कोई सुरक्षा उपाय करना आवश्यक नहीं था। लेकिन भ्रवालत यह महसूस करती है कि यदि कोई प्लव चेतावनी व्यवस्था (फ्लोट एलार्म सिस्टम) या इनक्लाइंस में अंधेरे में आने जाने की सुविधा के लिए पूर-बतिया होती और बरसात के मौसम में बढ़ते हुए जल स्तर को देखने के लिए गश्त अधिकारी के अधीन एक साथ कम से कम 2 पहरेदार होते तो 16 सितम्बर को यह दुर्घटना नहीं होती। भाग्य की बिम्बना है कि नकारी नदी के तट स्थिति खानों में आजकन ऐसे सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

एजेंट की हाथोदारी गोफ की कोई जानकारी नहीं

30.5 कोयला खान के एजेंट श्री एस० के० मुखर्जी ने, जिन्होंने 16 सितम्बर को पूर्वाह्न 11 बजे के आसपास नकारी नदी के पुल के ऊपर से पानी बहते हुए देखा था, मात्र यह सोचा था कि चूंकि पीछे भी ऐसा हुआ है और खान को कोई क्षति नहीं पहुँची है अतः इस बार भी सेंट्रल कोलियरी के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन, यह बिचित्र बात लगती है क्योंकि पिछले वर्षों में जब पानी पुल के ऊपर से बहा था तब वे सेंट्रल सीढा कोलियरी की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं थे। जब उन्होंने 3 अगस्त, 1976 को अर्थात् दुर्घटना के छह सप्ताह पूर्व कोयला खान का कार्यभार संभाला था और 16 अगस्त के पुल के ऊपर से पानी गुजरते हुए देखा था तब उन्हें अपने आपकी इस बात से संतुष्ट होने के लिए कि उस दिन खान के लिए वस्तुतः कोई खतरा नहीं था, पानी के वास्तविक खतरे के बारे में अपने जनिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए था। स्पष्ट है कि 16 सितम्बर के अक्षय सुबह वे स्टीम घातक की ग्रीष्म मरम्मत कराने के लिए चितित थे जो खराब हो गया था और उसके कारण सिरकार सीम से उत्पादन बंद हो गया था। जैसा कि वे वास्तव की मरम्मत के लिए भूकूड़ा वर्कगाय जाता चाहते थे और उन्होंने पूर्वाह्न 11 बजे के आस पास नकारी पुल के ऊपर से पानी गुजरते हुए देखा था तब उन्हें खान के उत्पादन के बजाय खान में काम कर रहे कामगारों की सुरक्षा का तत्पर ध्यान देना चाहिए था।

दूबरे शब्दों में स्टीम बायल की सम्मन करने के बजाय उन्हें जमीन के भीतर, विशेषता हार्थीदारी मोम में जिसकी गोफ नकारी नदी के निकटवर्त, काम करने वाले कामगारों के जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले चढ़ते हुए पानी का तरफ अधिक देना चाहिए था।

खेद की बात है कि एजेंट को कोयला खान की हार्थीदारी गोफ, उसके ऊपर बहते हुए पानी छोटे नाले या उसके पूर्ववर्ती एजेंट द्वारा उच्च बाढ़ स्तर का ध्यान रखने हुए नाले के आर-पार बनाए गए बाध के भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने खान का कार्यभार लिया था तब उसे हा बातों की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन कार्यभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति ने यह आशा की जाती है कि वह सबसे पहले कोयला खान के सभी संबंधित मानचित्र और नक्शों का अध्ययन करे। एजेंट बनने के बाद छह सप्ताह के दौरान वे यह काम निश्चित रूप से कर सकते थे और यदि वे ऐसा करते तो वे हार्थीदारी गोफ और उससे संबंधित प्रत्येक तथ्य की जानकारी हासिल कर सकते थे और उसकी समीक्षा कर सकते थे। लेकिन यदि उन्होंने यह काम पहले नहीं भी किया था फिर भी, वे जब उन्होंने 16 तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे के आर-पास नकारी पुन के ऊपर से पानी गुजरते देखा था प्रबंधक से कुछ विचार-विमर्श कर सकते थे और प्रबंधक और मित्र को हार्थीदारी गोफ और बांध के निकट पहुँचने हुए पानी के बारे में विशेष हिदायत दे सकते थे। उसके बाद बांध, उच्च बाढ़ स्तर आदि सभी विषयों पर उनके संबंधित पूरा विचार-विमर्श किया जाता जो हार्थीदारी इनकाइन की सुरक्षा के बारे में प्रबंधकों के ध्यान में थे। यह भी प्रभाव होता है कि छह सप्ताह के दौरान एजेंट ने यह भी नहीं देखा कि खान के सभी अधिकारियों को क्या-क्या झूठी मीपी गई है क्योंकि यदि वे सभी अधिकारियों की झूठी के बारे में मात्तुमकर लेते तो वे निश्चय ही खान के सुरक्षा संगठन की अर्थगत की जानकारी प्राप्त कर लेते। अपने बयान में उन्होंने अदालत को बताया कि उसके कार्यभार सभानने और दुर्घटना वाले दिन के बीच आपसप्रसिद्ध में अन्य बातों के अलावा उन्होंने खानों में काम करने वाले अनेक व्यक्तियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया था लेकिन यह बात उनकी जानकारी में प्रवेश नहीं जानी चाहिए थी कि बोहरा कार्यभार सभानने वाले सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा संबंधी मामलों पर केवल कागजी कार्यवाही कर रहा था और सुरक्षा संगठन सुरक्षा के संबंध में मुख्यालय से प्राप्त होने वाले सभी निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था।

भाग-3

परचलन का प्रभाव

क्या परचलन के कारण दुर्घटना हुई थी ?

31.1 इस रिपोर्ट के भाग 2 में खान में पानी घुस जाने से संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार किया गया है। अब जिस प्रश्न पर विचार किया जाएगा वह यह है कि क्या पानी सोडा नकारी से आया था या क्या वह हम नकारी और दामोदर के संगम के परचलन का प्रभाव था जिसके कारण सेंट्रल सोडा कॉलियरी के हार्थीदारी गोफ के निकट नदी स्तर 1115 फुट तक बढ़ गया और फलस्वरूप खान में बाढ़ आ गई थी।

खान सुरक्षा महानिदेशालय की रिपोर्ट

31.2 नकारी नदी के बाएँ किनारे जब कोयला खान में दुर्घटना हुई तब उस समय और उसके समय बाद तक लोगों का सामान्य अनुमान व विचार यह था कि 16 सितम्बर, 1976 को दामोदर नदी में भारी बाढ़ आने के कारण उसकी सहायक नदी नकारी का प्रवाह संगम में गिरने से रुक गया और इस प्रकार सेंट्रल सोडा के सटबथ का जलस्तर 1115 फुट से अधिक हो गया। खान सुरक्षा महानिदेशालय की तारीख 22 दिसम्बर 1976 की रिपोर्ट में यही निष्कर्ष दिया गया है।

दुर्घटना की जांच के बाद तैयार की गई इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारी वर्षा के कारण 16 सितम्बर को दामोदर और नकारी नदी में भारी बाढ़ आ गई थी और सामान्यतः नकारी नदी में गिरने वाले छोटे नाले से पानी वापस आ रहा था। इस जांच के दौरान सिवाय के इसके

कि दामोदर नदी की द्वारा और नकारी नदी के पूष्ठ प्रवेश में पानी वापस आ रहा था अन्य किसी प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था। इसका स्पष्ट कारण यह था कि 17 से 23 सितम्बर, 1976 के दौरान खान सुरक्षा महानिदेशक के समक्ष दिए गए किसी बयान में इस बात का कोई संकेत और सुभाव नहीं दिया गया था कि कोयला खान के ऊर्ध्व प्रवाह स्थित नकारी जलाशय में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया था जिसके कारण खान में बाढ़ आई थी। हम जलाशय पर बने पतरातू बांध का अनुगमन और संचालन पतरातू ताप बिजनी घर के प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है जिन्हें इस रिपोर्ट में पी०टी०पी०एस० कहा गया है।

प्रबंधक वर्ग द्वारा इस समस्या का किया गया अध्ययन

31.3 मैट्रण कोनसीन्डम लि० के प्रबंध निदेशक श्री बी०एल० कडेरा ने अदालत के समक्ष अपने बयान में यह कहा कि हालांकि 17 सितम्बर को अर्थात् दुर्घटना के एक दिन बाद सामान्य विचार यह था कि नकारी नदी का पानी दामोदर में जाने से रुक गया था। लेकिन बाद में और जैसे-जैसे समय बीतता गया तब प्रबंध वर्ग द्वारा आदिष्ट विभागीय जांच के दौरान अंतर्निवारिक रूप से अनेक बाद विचारार्थ सामने आए। कुछ अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ का कारण या तो यह हो सकता है कि नकारी नदी का पूरा पानी दामोदर में नहीं गिर सका अथवा पतरातू बांध के जलाशय से इतनी मात्रा में पानी छोड़ा गया था जिसे नकारी नदी संभाल नहीं सकी थी और फलस्वरूप खान जलमग्न हो गई। जब हमें संदेह व्यक्त किए गए तब प्रबंध निदेशक ने अपने सहयोगी संगठन-सेंट्रल खान प्लानिंग तथा डिजाइन संस्थान (सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टिट्यूट) से निवेदन किया कि वे इस प्रश्न पर विचार करें क्या पतरातू बांध से पानी छोड़ा गया था जिसके कारण खान में दुर्घटना हुई। प्रबंध निदेशक के अपने अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि वे दुर्घटना के बारे में बेतुके अनुमान या संदेह व्यक्त न करें क्योंकि पतरातू प्राधिकारियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। वे हमें केवल बिजली सप्लाई ही नहीं करते अपितु वे हमारे कार्यों के अच्छे प्राहक भी हैं। अतः प्रबंध निदेशक ने अपने अधिकारियों से कहा था कि दुर्घटना कारणों के अध्ययन के निष्कर्ष जांच अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

प्रबंधक वर्ग को इस दुर्घटना की विभागीय जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था लेकिन स्मरणपत्र भेजने के बावजूद अदालत को उक्त रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। उसका कारण यह बताया गया कि उन्हें उक्त रिपोर्ट मिला नहीं रही है।

प्रबंधक वर्ग का निष्कर्ष

31.4 प्रबंधकों ने 12-3-77 को अदालत के समक्ष जो बयान दिया था उसका आधार उन्होंने यह बताया था कि वह दामोदर नदी का परचलन नहीं था जो अवतलन गोफ क्षेत्र में घुस गया था और जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। प्रबंधकों के अनुसार दामोदर नदी का जल-स्तर 16 सितम्बर के अगस्त सुबह से ही बढ़ना शुरू हो गया था और नदी के तटों पर लगे चेतावनी-संकेत (अलार्म सिस्टम) द्वारा उक्त नदी के तटवर्ती कोयलाखानों को विधिपूर्वक चेतावनी दे दी गई थी। अतः उन खानों से व्यक्तियों को रात के 12 बजे तक वापस घुसा लिया गया था। प्रबंधकों ने बताया कि 16 सितम्बर के पूर्वाह्न में नकारी नदी की स्थिति में कोई असाधारण परिवर्तन नहीं देखा गया था। लेकिन उसी दिन दोपहर 12 बजे के आस-पास सेंट्रल सोडा के ऊर्ध्व प्रवाह स्थित सोडा-डी कोयलाखान के प्रबंधक को यह सूचना दी गई कि नकारी नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है। अतः वे भूरकुंडा और अपनी खान के बीच बने मड़क के पुल पर गए और उन्होंने देखा कि अपराह्न 12.30 बजे के आसपास नकारी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रबंधकों के अनुसार नदी का जल-स्तर इसलिए तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि सोडा कॉलियरी के ऊर्ध्वप्रवाह पर लगभग 11 कि०मी० की दूरी पर स्थित पतरातू बांध ने नकारी नदी का भारी मात्रा में पानी अमानक छोड़ा दिया गया था।

पानी के इस अचानक प्रवाह से नकारी नदी और सेंट्रल सौदा को मिलाने वाले नाले का जल स्तर 1115 फुट से अधिक बढ़ गया जिसका परिणाम यह हुआ कि हाथीचारी खान जलमग्न हो गई। उनकी दलील यह है कि बामोदर नदी के कारण उन खानों में बाढ़ नहीं आई थी और न ही आ सकती थी। इस संबंध में उनका मुख्य तर्क यह है कि यदि दामोदर का पानी नकारी नदी के माध्यम से उक्त खानों में प्रवेश करता तो सबसे पहले सेंट्रल सौदा के अनुप्रवाह पर स्थित एन०सी०डी०सी० सौदा कोलियरी के सतही सिरका इन्फ्लाइट पर नदी स्तर 1115 फुट होता। सिरका इन्फ्लाइट सेंट्रल सौदा कोलियरी के अपेक्षाकृत संगम के अधिक निकट है और वहां नदी का तट भी 1115 फुट से नीचा है। प्रबंधकों के अनुसार उस समय भी जब हाथीचारी खान जलमग्न हो चुकी थी, एन०सी०डी०सी० सौदा के सतही सिरका इन्फ्लाइट के निकटवर्ती क्षेत्र का नदी स्तर 1115 फुट से बहुत नीचा था।

31.5 प्रबंधक कहते हैं कि खान में भारी मात्रा में जो पानी धुस गया था उसकी उन्हें कभी संभावना या अनुमान नहीं था। यह केवल दुर्घटना मात्र थी जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। यद्यपि उन्होंने सभी सुरक्षा उपाय कर लिए थे फिर भी, बिना किसी पूर्व चेतावनी के पतरातू बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण हाथादारी सीमा में पानी धुस गया। प्रबंधकों का कथन है कि वे कितना ही प्रयत्न क्यों न करते फिर भी दुर्घटना से नहीं बच सकते थे क्योंकि उन्हें दुर्घटना से बचने हेतु यथेष्ट कदम उठाने का कोई अवसर ही नहीं मिला। यदि उन्हें पतरातू बांध से पानी छोड़े जाने का तलिक भी संकेत मिल जाता तो वे खान से व्यक्तियों को बाहर वापस बुलाने के लिए निश्चित रूप से सभी कार्रवाहियाँ करते।

प्रबंधकों के निष्कर्ष का आधार :

32.1 अपनी इस दलील की पुष्टि में कि दुर्घटना का कारण दामोदर का पणजल नहीं था बल्कि बिना किसी पूर्व चेतावनी के पतरातू बांध से भारी मात्रा में और एकदम पानी का छोड़ा जाना था, प्रबंधक-बर्ग ने अपने अध्ययन अदालत के समक्ष पेश किए। ये अध्ययन इस संबंध में सी०एम्०पी०डी०आई० के अध्यक्षक इंजीनियर (पी०एच०ई०) श्री बी०पी० बालिगा द्वारा किए गए थे।

32.2 अन्य बातों के अलावा श्री बालिगा के अध्ययनों का आधार था—भारत सरकार के सीमम विभाग में रखे जाने वाले समवर्षी मानचित्र दामोदर घाटी निगम (दामोदर वैली कांफोरमेशन) के रिकार्ड जिनमें रामगढ़ सड़क पुल के दामोदर के बाढ़ स्तर में जलबद्धि के घंटेवार अंक दिखाए गए थे; वार्षिक उच्चतम बाढ़ स्तर और 1945 से 1976 तक का जल-विसर्जन, 1976 के उच्चतम बाढ़ के स्टेज वेग विसर्जन ग्राफ और हाइड्रोग्राफी, जिसमें दिन के विभिन्न समय पर क्यूसेक में जल-विसर्जन दिखाया गया था। उन्होंने दामोदर और नकारी नदियों के विभिन्न जलग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा और पतरातू नाप बिजली घर के प्राधिकारियों द्वारा प्रेषित आंकड़ों को भी ध्यान में रखा। उन्होंने अदालत के समक्ष अन्य दस्तावेजों के अलावा एक 54 पारोक्ष वाला एलबम (प्रदर्श-4) भी पेश किया जिसमें वे अध्ययन दर्शाए गए थे जो उन्होंने पतरातू बर्काकाना-रामगढ़ क्षेत्र में नकारी और दामोदर नदियों के बारे में किए थे। प्रदर्श-4ए में श्री बालिगा द्वारा किए गए अध्ययनों का सारांश दिया गया है।

32.3 उपर्युक्त अध्ययनों और अदालत के समक्ष पेश किए गए गवाहों की गवाही के आधार पर प्रबंधकों की दलील यह है कि नकारी नदी के 71,962 क्यूसेक जल-विसर्जन के कारण ही सेंट्रल सौदा कोलियरी का जलस्तर 1115 फुट से ऊंचा हो गया था और हाथीचारी सीमा में बाढ़ आ गई थी। प्रबंधकों के प्रदर्श-4 के पृष्ठ 46 पर पारोक्ष सं०पी०एच०ई०/843-21-77-8 में दी गई स्टेज विसर्जन दर में इन अंकों का उल्लेख किया गया है। इसकी एक प्रति इस रिपोर्ट के बॉक्स-2 में अनुबन्ध-5ए के रूप में दी गई है।

प्रबंधकों के अनुसार भारी मात्रा में जल-विसर्जन के कारण ये थे :—

- (क) भारी वर्षा के कारण पतरातू बांध पर अधिव्यव मार्ग के द्वारों से नकारी जलाशय का अत्यधिक मात्रा में पानी का छोड़ा जाना;
- (ख) पतरातू बांध और सेंट्रल सौदा कोलियरी के बीच अवरोधित जलग्रहण क्षेत्र के जल का प्रवाह; और
- (ग) जलाशय से भारी मात्रा में पानी के छोड़े जाने के परिणाम-स्वरूप पतरातू बांध और कोयलाखान के बीच नकारी नदी पर सेचुमार्ग और/या काफ़रबांध नं० 2 के टूट जाने पर जल का प्रवाह।

32.4 अधिव्यव-मार्ग से जल-विसर्जन के प्रश्न पर परवर्ती उपपैरा में विचार किया गया है। जहाँ तक उपर्युक्त (ख) का संबंध है डिकिन्स सूत्र या किसी अन्य गानक सूत्र के अनुसार प्रबंधकों के हिसाब से 26.97 वर्गमील के अवरोधित जलग्रहण क्षेत्र से, उक्त क्षेत्र में हुई वर्षा के आधार पर अधिक से अधिक 11,830 क्यूसेक पानी आ सकता है।

जहाँ तक उपर्युक्त (ग) का संबंध है, प्रबंधकों का कथन है कि जब नकारी नदी का जल काफ़र बांध के निकटस्थ पंपघर के मिरबल स्तर तक पहुँच गया था तब 16 सितम्बर को पतरातू बांध के अनुप्रवाह पर 2.4 कि०मी० की दूरी पर बना काफ़र बांध क्षतिग्रस्त हो गया था। इसका अर्थ यह था कि उक्त क्षेत्र में नकारी जलाशय से यदि ज्यादा नहीं गो जो 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसके कारण ही काफ़र बांध पर 18 फुट से ऊपर पानी बह रहा था। अतः इस बांध में पड़ी दरार के कारण काफ़र बांध के ऊर्ध्व-प्रवाह क्षेत्र में रहे पानी का अचानक विसर्जन हुआ और फणस्वरूप नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र में भी जन प्रवाह में अचानक वृद्धि हो गई और पानी सेंट्रल सौदा कोलियरी में पहुँच गया।

पतरातू अधिव्यव-मार्ग से पानी का छोड़ा जाना :

32.5 प्रबंधकों के कथनानुसार बिहार में 10 सितम्बर से चक्रवाती सीमम बना रहा और उसके कारण नकारी और दामोदर नदी के संगम के निकट बर्काकाना-गिदी क्षेत्र की तुलना में 81.32 वर्गमील के नकारी जलग्रहण क्षेत्र में असाधारण रूप से अधिक वर्षा हुई। अतः इस भारी वर्षा के कारण 15 सितम्बर की राखी रात के पतरातू बांध की स्थिति खतरनाक हो गई। नकारी जलाशय के खतरे का निशान 1332' 50 फुट है। इस निशान पर जल का स्तर 16 सितम्बर के सुबह पहुँच गया था और पानी का यह स्तर उस दिन 11 घंटे से भी अधिक समय के लिए बना रहा। उक्त अवधि के दौरान लगातार 7 घंटे से भी अधिक समय तक पानी का स्तर खतरे के निशान से 2.10 फुट तक ऊंचा बना रहा। अतः बांध को बचाने के लिए पतरातू ताप बिजलीघर को अधिव्यव-मार्ग से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रबंधकों के अनुमान के अनुसार सुबह 7 बजे जल का विसर्जन, यदि अधिक नहीं तो 50,000 क्यूसेक और सुबह 10.30 बजे से 11 बजे तक वही विसर्जन 48,000 क्यूसेक और पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक 45,000 क्यूसेक से कम नहीं होता। इसकी रेंज 45,000 से 50,000 क्यूसेक तक होती।

जैसे ही पानी अवरोधित जलग्रहण क्षेत्र से गुजरा, अधिव्यव-मार्ग से इसके प्रवाह में भारी वृद्धि हो गई। इसका वेग 12 से 18 प्रतिसेकंड था अतः इसे पतरातू बांध से सेंट्रल सौदा कोलियरी तक पहुँचने में एक घंटा लगा। प्रबंधकों के अनुसार इसका अर्थ यह है कि जैसा कि अदालत के चरमवीद गवाह के श्री डी०एन० माजी ने बयान दिया है यदि पूर्वाह्न 11.30 बजे तक आस-पास अधिव्यव-मार्ग से 50,000 से 55,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जाता तो पानी सेंट्रल सौदा कोलियरी तक दोपहर 12.30 के आस-पास पहुँच जाता। 15 से 16 फुट प्रति सेकंड पानी का वेग बहुत अधिक है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नकारी तट के सबसे ऊँचे स्थान पर खड़ा होता और बढ़ते हुए जल प्रवाह को देख रहा होता तो उसे कोयला खान से सुरक्षित स्थान तक पहुँचने के लिए केवल 27 सेकंड

मिलते इसका अर्थ है वह निश्चित रूप से बह जाता और कोयला खान में अचानक जलम्बर बढ़ जाने के बारे में किसी भी व्यक्ति को सूचना नहीं दे पाता।

पतरातू से जल विसर्जन का हिसाब लगाते समय प्रबंधकों ने पतरातू ताप बिजलीघर द्वारा अवालयत को पेश किए गए कम्पाउन्सों का अध्ययन किया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पतरातू ताप बिजलीघर द्वारा अधिप्लव-मार्ग के खुले द्वारों के अनुरूप पेश किए (वेबें प्रदर्श सी० नं० 2ए) और प्रदर्श सी० नं० 3 ई० में दिए गए जलाशय के प्रांशिक रूप से खुले द्वार के अनुरूप जल विसर्जन के अंकों में किसी भी प्रकार का सह-संबंध नहीं था। नकारी जलग्रहण क्षेत्र से जल प्रवाह का हिसाब लगाने के लिए उन्होंने पतरातू ताप बिजली घर द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रांकड़ों का भी अध्ययन किया था। प्रबंधकों के अनुसार उक्त प्रांकड़ों के आधार पर 16 सितम्बर को सुबह 8 बजे जलाशय का जलस्तर 1341.50 फुट अर्थात् पतरातू बांध की चोटी से 1 फुट नीचे और छतरे के निशान से 11 फुट ऊंचा होना चाहिए। यह तब होता जब 15 सितम्बर, के सुबह 8 बजे से 16 सितम्बर के सुबह 8 बजे तक 6 इंच वर्षा होती और यदि यह मान भी लिया जाए कि अधिकतम 2½ इंच वर्षा हुई थी तब भी जलाशय का स्तर 1334.00 फुट होता न कि 1330.50 फुट जैसा कि सी० नं० 58 में पतरातू ताप बिजली घर द्वारा दिखाया गया है।

32.6 इस पैरा में जो भी कहा गया है उससे प्रबंधकों का यह तर्क जान पड़ता है बूकि हाथीवारी सीमा में बाढ़ लाने के लिए सेंट्रल सौदा पर 71,962 क्यूसेक जल विसर्जन होना चाहिए अतः भारी जल विसर्जन की भारीकी में जाना आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि अवरोधित जलग्रहण क्षेत्र का प्रवाह और काफ़र बांध नं० 2 को क्षतिग्रस्त होने के कारण जल प्रवाह भी 11,830 क्यूसेक से कम था तो अधिप्लव मार्ग से जलविसर्जन अधिक होता। दूसरी ओर यदि उनके हिसाब से अवरोधित जलग्रहण क्षेत्र और काफ़र बांध से अधिकतम जल विसर्जित हो रहा था तो अधिप्लव मार्ग से जल विसर्जन कम होता। लेकिन उनके अनुसार पतरातू बांध से लगभग 45,000 क्यूसेक से कम मात्रा में जल-विसर्जन नहीं हो रहा था।

32.7 प्रबंधक इस बात से विश्वस्त हैं कि कुर्बटना के समय 16 सितम्बर को दामोदर के संगम की स्थिति ऐसी नहीं थी जिसके कारण नकारी नदी के माध्यम से पानी सेंट्रल सौदा कोलियरी की गोफ में घुस गया था क्योंकि उनके अध्ययन के अनुसार दामोदर नदी के तट प्रोफाइल इतना अच्छा है कि यदि नकारी से लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी विसर्जित हो तब भी पानी उसके तटों के भीतर ही रहेगा। 16 सितम्बर को अपराह्न 1 बजे के आस-पास दामोदर नदी का जलस्तर 1108 फुट से नीचे था जैसे कि श्री बालिगा ने संगम से दामोदर के उपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी केन्द्रों द्वारा रिकार्ड की गई वर्षा के प्रांकड़ों से जाहिर होता है। प्रबंधकों के अनुसार पतरातू ताप बिजलीघर ने संगम पर अधिक जलस्तर का निष्कर्ष निकालते समय वर्षा की वास्तविक मात्रा का संकेत नहीं दिया जिसके कारण दामोदर संगम का जलस्तर बढ़ गया था और न ही उन्होंने भारी वर्षा का कोई आधार बताया है। यदि पानी वास्तव में पीछे वापस आया होता तो सेंट्रल सौदा कोलियरी के ठीक नीचे और संगम के निकट, जैसा कि उन्होंने कहा है, एन०सी०डी० सी० सौदा खान का जल स्तर 1115 फुट से अधिक होता जिसके कारण हाथीवारी गोफ में पानी घुस गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि एन०सी०डी०सी० सौदा के प्रबंधक की गवाही के अनुसार 16 सितम्बर को अपराह्न 1 बजे के आस-पास उनकी खान में पानी अचानक केवल 1108 फुट नवी-स्तर तक बढ़ा था लेकिन नकारी नदी का पानी उस समय भी संगम की तरफ बह रहा था। एन०सी०डी०सी० सौदा के सिरका इन्क्लाइन में पानी घुसने का निम्नतम बिन्दु नदी स्तर 1117 फुट है और उक्त इन्क्लाइन में पानी 16 सितम्बर को नहीं आया था बल्कि अगले दिन आया था।

गवाहों के बयान :

33.1 प्रबंधक वर्ग ने अपने अध्ययनों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले थे उनकी पुष्टि उनके द्वारा अवालयत में पेश किए गवाहों ने की। पतरातू स्थित बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग के सहायक इंजीनियर (मिजिल) श्री जे०एन० माजी को अवालयती गवाह के रूप में बुलाया गया था और 28 अप्रैल और 19 नवम्बर, 1977 को उनके बयान लिए गए थे उन्होंने भी अपने बयान में ऐसी अनेक बातें बताई जिनकी संपुष्टि प्रबंधकों द्वारा किए गए अध्ययनों से होती थी। श्री माजी और दूसरे अवालयती गवाह बांध विकास अधिकारी श्री जे०एन० प्रसाद ने बयान दिया कि पतरातू में भारी वर्षा हुई थी और नकारी जलाशय की स्थिति चौंका देने वाली थी। श्री माजी ने 14 सितम्बर को जलाशय स्तर का निरीक्षण किया था और वह 1332 फुट था। उन्होंने देखा था कि नकारी जलग्रहण क्षेत्र में पानी के अवधारण उच्च प्रवाह के कारण 16 सितम्बर के सुबह जल स्तर 1336 फुट हो गया था और पानी अधिप्लव मार्ग के द्वारों के ऊपर हांकर बह रहा था। उनके अनुसार उस दिन पूर्वाह्न 11.30 बजे के आस-पास पतरातू बांध से जब सभी अधिप्लव मार्ग के द्वार खोल दिए गए थे, 50,000 से 55,000 क्यूसेक पानी विसर्जित हुआ था। उन्होंने और प्रबंधक वर्ग के गवाह सेंट्रल सौदा कोलियरी के यांत्रिक फ़िटर—श्री नागेश्वर साहू ने कहा कि वे काफ़र बांध नं० 2 के निकट स्थित पंपघर पर थे और उन्होंने बांध के शीर्ष से 12 फुट ऊपर पानी बहते हुए देखा था जो पंपघर के सिरदल स्तर को छू रहा था। प्रबंधकों के अनुसार इससे उनके कथन की संपुष्टि होती है कि नकारी अधिप्लव-मार्ग से अत्यधिक मात्रा में पानी विसर्जित हो रहा था और अधिक नहीं तो जल की मात्रा 50,000 क्यूसेक तो भी थी।

33.2 प्रबंधक, जिन्होंने पतरातू ताप बिजलीघर द्वारा पेश किए गए गवाहों के बयान लिए थे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गवाह नं० 1 से 5 और 7 और 8 के बयान परस्पर विरोधी हैं और वे पतरातू ताप बिजली घर संबंधित प्रदर्शों के इवराजों के भी अनुरूप नहीं थे। प्रबंधकों की शिकायत यह है कि पतरातू ताप बिजली घर का एक भी गवाह इनके अपने संगठन से नहीं है बल्कि राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग से हैं और पतरातू ताप बिजली घर को अपने अधिकारियों, जैसे गेजबांधक, कनिष्ठ इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, कार्यपालक या अधीक्षक इंजीनियर को अवालयत में आने और बयान देने के लिए अवश्य पूछ लेना चाहिए था जो नकारी जलाशय के प्रचालन, उसके स्तर को रिकार्ड करने और अधिप्लव मार्ग के द्वारों से पानी विसर्जन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। बूकि पतरातू ताप बिजलीघर के महाप्रबंधक व मुख्य इंजीनियर श्री एन० करकट्टा 16 सितम्बर के सुबह को हुए अधिप्लवमार्ग से जल विसर्जन के चरमवीच गवाह नहीं थे और उनके कार्यपालक इंजीनियर और अधीक्षक इंजीनियर ने जल विसर्जन का पर्यवेक्षण किया था अतः प्रबंधकों को इस बात पर आश्चर्य था कि उनको अवालयत में हाजिर होने के बावजूब भी उन्हें कुर्बटना वाले दिन को पतरातू बांध की सही स्थिति के बारे में शपथ लेकर गवाह के रूप में बयान देने के लिए अवालयत में पेश नहीं किया गया। वे उन्हें श्री माजी का दूसरा बयान भी पसंद नहीं था। जब श्री माजी ने अपने बयान का आधार यह बनाया था कि उन्होंने पहले जो कुछ भी कहा था वह 16 सितम्बर से संबंधित नहीं बल्कि विश्वकर्मा पूजा दिवस से हो सकता है जो प्रायः प्रतिवर्ष 17 सितम्बर का होता है। उनके अनुसार यह कि उन्हें पतरातू ताप बिजलीघर अधिकारियों द्वारा फुसलाया गया हो। प्रबंधकों के अनुसार स्वयं माजी के अलावा पतरातू ताप बिजलीघर के श्री रामाधर प्रसाद और श्री सतीश प्रसाद जैसे गवाहों की गवाही से यह निष्कर्ष निकलता है कि 17 सितम्बर को नहीं बल्कि 16 सितम्बर को पतरातू अधिप्लवमार्ग से भारी मात्रा में जल विसर्जन के कारण पंपघर में पानी घुस गया था और पंप जल में डूब गए।

पतरातू ताप बिजली घर के निष्कर्ष

34. अपने गवाहों की गवाही और अपने द्वारा किए गए अवरोधक अध्ययनों के आधार पर पतरातू ताप बिजली घर के निष्कर्ष, जिनका

उल्लेख प्रवर्षी पी० 4 से पी० 13 में किया गया है, प्रबंधकों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के नितांत विपरीत थे। ये अध्ययन प्रबंधकों द्वारा प्रत्याशित प्रायः प्रत्येक उद्देश्य के विपरीत थे। पतरातू ताप बिजलीघर के निष्कर्ष सक्षेप में इस प्रकार हैं:—

(क) दामोदर बाटी निगम के समवर्षी मानचित्र के अनुसार 15 और 16 सितम्बर को पतरातू बांध के नकारी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम वर्षा हुई थी,

(ख) यदि बांध से जल विसर्जन नहीं किया गया होता तो उर्ध्वत (ग) के अनुसार 16 सितम्बर को सुबह 8 बजे जलाशय का नदी स्तर केवल 1331 फुट होता लेकिन चूंकि उनके अनुसार जलाशय का वास्तविक नदी स्तर 1330.5 फुट था अतः इसका आशय यह था कि उस दिन के सुबह बहुत कम मात्रा में पानी छोड़ा जाना चाहिए था। सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच केवल 768 क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया था और सुबह 10 बजे से सायं 7 बजे के बीच 3560 क्यूसेक। पतरातू ताप बिजलीघर ने प्रबंधकों के नकारी स्तर के हिसाब का भी बंढन किया क्योंकि उनके अनुसार यह गलत अनुमान के आधार पर लगाया गया था। बांध के अनुप्रवाह क्षेत्र में विभिन्न दूरियों पर अधिप्लव मार्गों से जल विसर्जन का हिसाब लगाने के बाद उनका निष्कर्ष यह है कि प्रबंधकों द्वारा उल्लिखित 50,000 क्यूसेक जल विसर्जन की मात्रा नितांत काल्पनिक है और यह बात प्रवर्षी 4 में उल्लिखित अपने ही सर्वेक्षण और आरेख के आधार पर गलत सिद्ध होगी। पतरातू ताप बिजलीघर का कथन है कि पतरातू बांध से जल विसर्जन के बारे में अपने दावे को सिद्ध करने के लिए प्रबंधकों ने अपने परिकलन भी पेश नहीं किए।

(ग) अधिप्लव मार्गों से अचानक और इतनी मात्रा में जल विसर्जन नहीं हो सकता कि उससे बाढ़ आ जाए लेकिन यदि यह मान भी लिया जाए कि इतना जल विसर्जित हुआ था तो ऊर्जा अधिसूचक इस धक्के को अवशित कर लेता क्योंकि वह इसी प्रयोजन के लिए ही बनाया गया था। उसके बाद पानी सामान्य गति से कोयलाखान की तरफ बहने लगता। पतरातू ताप बिजली घर का विचार है, हालांकि उन्होंने वास्तविक परिकलन नहीं किया था, कि अधिप्लव मार्ग के द्वारों के अनुसार प्रवाह पर 1,000 से 1,500 फुट की दूरी पर पतरातू बांध से विसर्जित जल का प्रवाह सामान्य हो जाना चाहिए था।

(घ) समवर्षी मानचित्र के अनुसार नदी के जलग्रहण क्षेत्र में होने वाली वर्षा के पैटर्न के अनुसार दामोदर नदी के उपरी क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई थी। पतरातू ताप बिजलीघर ने तर्क पेश किया कि यदि बांध और सेंट्रल सौदा कोलियरी के बीच 27 वर्गमील के अवरोधित जलग्रहण क्षेत्र की वर्षा का घनत्व प्रतिघंटा 1 इंच के आस-पास होता जैसा कि प्रबंधक वर्ग ने कहा है तो संगम के ऊर्ध्वप्रवाह स्थित दामोदर नदी के 1040 वर्गमील के जलग्रहण क्षेत्र के लिए वर्षा की इसी दर को स्वीकारा जाए तो संगम पर जलग्रहण क्षेत्र से अधिकतम 4,62,000 क्यूसेक पानी विसर्जित होगा। पतरातू ताप बिजली घर के अनुसार प्रबंधक वर्ग ने संगम के ऊर्ध्वप्रवाह दामोदर का कोई अध्ययन नहीं किया था और न ही उसने इसका हिसाब लगाया था कि दामोदर और नकारी नदी का कितना पानी संगम पर आता है और कितना पानी संगम से आगे जाता है।

(ङ) पतरातू बांध के ठीक नीचे वाला काजवे में 16 तारीख को सायं 7.15 बजे के आसपास दरार पड़ गई थी और 17

सितम्बर को दोपहर बाद काफ़र बांध नं० 2 टूट गया था। अतः 16 सितम्बर को दोपहर 12.30 बजे के आस-पास सेंट्रल सौदा कोलियरी में दुर्घटना होने से पहले सारी चीजें सामान्य थी। उस दिन 3 से 4 घंटे तक अधिकतम वर्षा होने के कारण सुबह 9 बजे के आसपास कोयलाखान के जलविसर्जन की अधिकतम मात्रा केवल 12,568 क्यूसेक थी। 17 सितम्बर को अपराह्न 1 बजे कोयलाखान पर नकारी नदी के जल-विसर्जन की अधिकतम मात्रा 38,086 क्यूसेक थी। इस प्रकार दोनों दिन कोयलाखान पर नकारी नदी का प्रवाह 71,962 क्यूसेक से बहुत कम था और उसके कारण वहाँ जल स्तर 1115 फुट नहीं हो सकता था। पतरातू ताप बिजलीघर का कथन है कि प्रवर्षी 4 में शीट नं० 46 पर प्रबंधक वर्ग द्वारा प्रदर्शित स्टेशन विसर्जन कर्व के अनुसार 16 तारीख को 12,568 क्यूसेक जल विसर्जन के कारण सेंट्रल सौदा कोलियरी का नदी स्तर केवल 1100 फुट हो सकता था। इसलिए, यदि जलस्तर 1100 फुट से 1115 फुट था तो इसका कारण दामोदर की बाढ़ थी। इससे नकारी नदी की तत्कालीन स्थिति में परिवर्तन होगा और उसका प्रवाह वेग काफी हद तक कम हो जाता।

(च) 17 सितम्बर को दामोदर और नकारी नदी के संगम पर अधिकतम बाढ़ स्तर 1125 फुट से कम नहीं था। उनका कथन था कि इस तथ्य की संयुष्टि स० सी० एल० बर्काकाना के महाप्रबंधक के लिखित बयान द्वारा भी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि 17 सितम्बर को संगम के निकट दोनों नदियों के किनारों पर बने रिहायशी मकानों की छतों पानी में डूब गई थीं। इन मकानों की छतों का स्तर 1125 फुट नदी स्तर से कम नहीं था।

(छ) उनकी दलील यह है कि 16 सितम्बर को संगम पर बाढ़ स्तर 1114 फुट से कम नहीं था। अनुप्रवाह पर बने मूला पुल का स्तर भी इतना ही है जो उस दिन 12 बजे के आस-पास बढ़ गया था। यदि नकारी नदी का पानी न आता तो चूंकि संगम पर जलस्तर 1114 फुट था अतः यही जलस्तर सेंट्रल सौदा कोलियरी पर भी होता। लेकिन चूंकि पतरातू बांध से बहाव की ओर नकारी नदी का पानी धाया था अतः कोयलाखान पर जलस्तर 1114 फुट से अधिक हो गया। दूसरे शब्दों में संगम पर दामोदर नदी के स्तर में वृद्धि होने के कारण ही खान दुर्घटना हुई थी।

दोनों पार्टियों के अध्ययनों की विम्वसनीयता

35. प्रबंधक वर्ग और पतरातू ताप बिजलीघर—दोनों ने अनेक उद्घोष-वार और तकनीकी अध्ययन किए। उन्होंने ये अध्ययन अन्य बातों के अलावा दामोदर नदी के विभिन्न जलग्रहण क्षेत्रों में 16 सितम्बर और उससे एकाधिक दिन पहले हुई वर्षा का हिसाब लगाने के संबंध में किए थे। इसके अलावा उन्होंने पतरातू बांध के ऊर्ध्वप्रवाह पर नकारी जल-ग्रहण क्षेत्र में, बांध और सेंट्रल सौदा तथा कोयलाखान और दोनों नदियों के संगम के बीच हुई वर्षा का भी अधिकतम किया। दोनों ने पतरातू बांध के अधिप्लव मार्ग से जलविसर्जन पर जोर दिया है। वर्षा का हिसाब लगाने समय उन्होंने दोनों नदियों के संस्तर और बाढ़ ढलानों और अन्य प्राचलों के महत्व को ध्यान में रखा और प्रोफाइल और जलस्थिति का अधिकतम किया। उन्होंने उक्त दोनों नदियों के विभिन्न फैलावों और अनेक आस-संक्षेपों पर जल-विसर्जन का भी परिकलन किया है। लेकिन किसी भी मुख्य विषय पर दोनों पक्षों का मतभेद नहीं है बल्कि दोनों पक्ष एक दूसरे के अध्ययनों को सचवाई पर शक करते हैं। प्रबंधक वर्ग का कथन है कि उन्होंने मई, 1977 में अपने अध्ययनों के संबंध में वास्तविक सर्वेक्षण किया था और उन्होंने मात्र दृश्य-मूल्यांकन और संगत कारणों

के निर्धारण के लिए दामोदर और नकारी के जल स्तरों की टोह ली थी। पतरातू ताप बिजली घर का तर्क था कि विश्व में कहीं भी जलविसर्जन के परिकलन के लिए जल विसर्जन का दृश्य-अनुमान नहीं लगाया जाता है। नदी के त्रास सेक्शन जल उठाने के संस्तर 100 उष्ण बाढ़ संस्तर, बलिलता का गुणांक और नदी के विभिन्न सैक्शनों के माध्यम से जल विसर्जन का निर्धारण करने हेतु धारा-मापी द्वारा बेग का पता लगाने के लिए एक सुसंगठित टीम को काम करना पड़ता है। उनका कथन है कि प्रायः सभी मानक पुस्तकों में यह सुझाव दिया गया है कि सैद्धांतिक परिकलन करने के बाद अनेक बार प्रेक्षणों के अनुसार वास्तविक घटनाओं का स्थापन करना पड़ता है ताकि जिन गुणों कारकों के आधार पर परिकलन किया जाता है, उनमें वास्तविकता दिखाने के लिए आवश्यक संशोधन किए जा सकें। अतः जब एक तरफ पतरातू ताप बिजलीघर की दलील यह है कि प्रबंधकवर्ग के सैद्धांतिक परिकलनों का कोई आधार और आंकड़े नहीं हैं, दूसरी तरफ प्रबंधकवर्ग को पतरातू ताप बिजलीघर द्वारा किए गए प्रक्षयनों के बारे में संवेह है। प्रबंधकवर्ग के अनुसार पतरातू ताप बिजलीघर ने अक्टूबर, 1977 में किसी समय जो सर्वेक्षण किया था उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सर्वेक्षण उस अवधि के दौरान किया गया था जब दामोदर नदी के उपरि रोषों से काफी मात्रा में जल प्रवाहित हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों में उचित सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता और इसलिए प्रबंधकवर्ग ने उक्त सर्वेक्षण और उससे निकाले गए निष्कर्षों पर आपत्ति प्रकट की।

चरमदीय गवाहों की गवाहियों की विषयसनीयता

36.1 जब उक्त अध्ययनों की प्रामाणिकता के बारे में संवेह प्रकट किया गया है तब क्या उस स्थिति में गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है जिन्होंने यह बयान दिया था कि आसधारण वर्षों के कारण नकारी नदी के जल स्तर में वृद्धि हो गई थी और उसके परिणामस्वरूप अधिप्लव मार्ग के द्वारों से भारी मात्रा में जल विसर्जित किया गया, जिसके कारण काफ़र बांध नं० 2 टूट गया और अत्यंत बेग के साथ पानी का प्रबलनक रैला सेंट्रल सौदा कोलियरी तक पहुंच और हापीवारी गोफ का बचाव करने वाले मिट्टी के बांध के ऊपर से बहने लगा। प्रबंधकवर्ग के अनेक गवाहों ने यह भी कहा कि कम से कम 16 सितम्बर को दोपहर 1 बजे के आसपास संगम से होने वाले पञ्चजल का कोई प्रभाव नहीं था।

36.2 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध करना कठिन है कि नकारी जलाशय में जल प्रवाह बस्तुतः कितना था क्योंकि जलग्रहण क्षेत्र में कोई वर्षामापी नहीं थे। हां, पतरातू बांध के नीचे एक वर्षामापी अवश्य लगा था लेकिन इसके अनुसार संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा की जो माप निकाली गई वह विश्वासस्पद है और उसके विषय में प्रबंधकवर्ग और पतरातू ताप बिजलीघर के बीच काफी मतभेद है। लेकिन, बांध के पास लगे वर्षामापी के अनुसार निकाले गए अंक स्पष्टतः कुछ विश्वसनीय हैं। यदि पतरातू ताप बिजलीघर के इस बयान को सही माना जाए कि 16 सितम्बर को सुबह 7 बजे तक अधिप्लव मार्ग के द्वारों को नहीं खोला गया था तो जैसा कि प्रबंधकवर्ग ने तर्क दिया है, इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्षामापी के अनुसार अंकित की गई वर्षा से 14 सितम्बर के सुबह से 16 सितम्बर के सुबह तक बांध के पंचर इतना पानी भर जाता कि 14 और 15 सितम्बर को जलाशय से उपयोग्य पानी निकालने के बाद भी, उसका स्तर 1330 फुट से अधिक होता। वृत्ति इसका यह अर्थ होता कि जल स्तर बाढ़ नदी स्तर से भी अधिक था जिसे बांध की सुरक्षा की दृष्टि से सामान्यतः वहाँ नहीं टिकने दिया जाता अतः जल स्तर को 1332.5 फुट से नीचे लाने के लिए और पतरातू ताप बिजलीघर द्वारा बताए गए जल से भी अधिक जल के विसर्जन हेतु 16 सितम्बर को सुबह 7 बजे अधिप्लव मार्ग के द्वारों को खोल दिया जाता। तत्पश्चात् नदी स्तर को 1332.5 फुट से नीचे लाने के बाद अपेक्षाकृत कम मात्रा में जल-विसर्जन होता।

725 GI/79-7

पतरातू बांध से; असामान्य मात्रा में जल विसर्जन

36.3 इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिप्लव मार्ग के द्वारों से अत्यधिक मात्रा में जल विसर्जित हुआ था। जैसा कि पैरा 31.4 में उल्लेख किया गया है, सौदा-डी कोलियरी के प्रबंधक श्री पी० के० दास ने सेंट्रल सौदा के ऊर्ध्वप्रवाह पर अपनी खान के निकट अत्यधिक मात्रा में नकारी नदी का पानी धाते देखा था। उन्होंने अवालत के समक्ष बयान दिया कि उन्होंने दोपहर 12.30 बजे के आस-पास श्री करकेट्टा से टेलीफोन पर बात की थी और उनसे कहा था कि नकारी नदी के जलस्तर में असामान्य रूप से वृद्धि हो रही है। उन्होंने उनसे यह भी पूछा था कि क्या पतरातू बांध में भारी मात्रा में छोड़े गए पानी के कारण नकारी नदी के स्तर में वृद्धि हुई है। इसके जवाब में श्री करकेट्टा ने कहा था कि उनके बांध की स्थिति नाजुक है और उन्होंने पहले ही जल विसर्जित कर दिया है तथा और अधिक पानी छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने श्री पी० के० दास को चेतावनी दी थी कि यदि हम पानी नहीं छोड़ेंगे तो बांध टूट जाएगा और उसका परिणाम यह होगा कि अमु-प्रवाह पर स्थित प्रत्येक वस्तु बह जाएगी। श्री दास ने कहा कि नकारी के स्तर में बराबर वृद्धि होते देख उसी दिन शाम को उन्होंने अपने वरिष्ठ कार्यपालक इंजीनियर श्री प्रार० चौबे को पतरातू ताप बिजली घर के प्राधिकारियों के पास इसलिए भेजा कि वे पता लगाएं कि वे रात तक कितना और जल विसर्जन करेंगे ताकि वे तबनुसार अपनी खान में कार्रवाई कर सकें। श्री करकेट्टा ने श्री चौबे से कहा था, 'क्योंकि उनके बांध की हालत बहुत ही खस्ता है अतः वे जलविसर्जन की मात्रा में कमी नहीं कर सकते। हालांकि श्री करकेट्टा ने यह बात स्वीकार करने से इनकार किया कि उन्हें अपराह्न 12.30 बजे के आस-पास श्री पी० के० दास का टेलीफोन मिला था क्योंकि उस समय वे कार्यालय में नहीं थे बल्कि परामर्श बोर्ड के उन सदस्यों के साथ थे जिनके साथ वे उस दिन पूर्वाह्न 10.40 बजे से सायं 4.30 बजे तक बिजलीघर के निरीक्षण के लिए गए थे। उन्होंने यह स्वीकारा कि वे सायं 5 बजे के आस-पास सौदा-डी कोलियरी के प्रतिनिधि से मिले थे और उन्होंने सूचित किया था कि बांध में अनुमत्त अधिकतम जल स्तर बनाए रखने के लिए नकारी जलाशय से न्यूनतम जल विसर्जन दिया जा रहा है। लगातार वर्षा होने की वृद्धि से उन्हें सूचित किया गया कि फाटकों को और अधिक खोलना पड़ेगा।

इन सभी बयानों से जो निष्कर्ष निकलता है वह स्पष्ट है। मतलब यह है कि पतरातू बांध से बहुत अधिक पानी छोड़ा गया था और जैसा कि पतरातू ताप बिजलीघर के प्राधिकारियों ने कहा कि सुबह वह 7 बजे से 10 बजे तक केवल 800 क्यूसेक के लगभग नहीं था अथवा सुबह 10 बजे से सायं 7 बजे तक केवल 2500 क्यूसेक के आसपास नहीं था—अन्यथा जैसा कि उसका तर्क है, सौदा-डी कोलियरी का प्रबंधक-वर्ग 16 सितम्बर को अपराह्न 12.30 बजे और 5 बजे—दोनों समय पतरातू ताप बिजलीघर के प्राधिकारियों के पास इस मामले को क्यों ले जाते। लेकिन जैसा कि चरमदीय गवाहों ने बयान दिया है, उनके इस अनुमान को मानना संभव नहीं है कि अधिक छोड़े गए पानी की सही-सही मात्रा क्या थी। प्रबंधकवर्ग ने पतरातू ताप बिजली घर द्वारा प्रबल जल विसर्जन की मात्रा के संबंध अनेकों पर मात्र यही आपत्ति प्रकट नहीं की है कि वे सैद्धांतिक परिकलन के आधार पर निकाले गए थे अपितु उसे उनकी लौग-जुक में दिखाए गए अंकों के बारे में भी गम्भीर संवेह था। प्रबंधकवर्ग ने यह भी कहा था कि उनके रिकार्डों—विशेषकर काफ़र बांध के निकटस्थ पंचघर के रिकार्डों में अनेक क्षेपक थे। लेकिन इस सारी बातों के बावजूद अधिप्लवमार्गों या काफ़र बांध से हुए वास्तविक जल विसर्जन के बारे में चरमदीय गवाहों के अनुमान को स्वीकार करना कठिन है। अवालत को पंचघर पर जाने और वहाँ जलचिह्न देखने का मौका भी मिला। इस तथ्य के बावजूद कि पानी सिरबल स्तर तक पहुंचा था अथवा नहीं, इस बात कि वहाँ भी जल स्तर नीचा था, अर्थ यह है कि पानी पंचघर में बस गया था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि काफ़र बांध के शीर्ष पर जल के स्तर में वृद्धि हो गई थी। अवालत के लिए पतरातू ताप

बिजली घर के इस कथन को स्वीकार करना भी कठिन है कि बांध 16 सितम्बर को नहीं बल्कि 17 सितम्बर को टूटा था।

हालांकि पतरातू प्रविष्टिबन्धन से असामान्य रूप से जल प्रवाहित हो रहा था फिर भी, प्रवालत एन० सी० डी० सी० सौदा और सेंट्रल सौदा कोलियरी के प्रबंधक-वर्ग के चरमवीद गवाहों के बयान से विश्वस्त नहीं है जिसका निहितार्थ यह है कि केवल नकारी के जलविसर्जन के कारण हाथीदारी गोफ के निकट नदी स्तर 1115 फुट से ऊपर हो गया था।

36.4 प्रबंधकवर्ग या पतरातू ताप बिजलीघर की ओर से कोई भी ऐसे चरमवीद गवाह नहीं हैं जो 16 सितम्बर को दामोदर और नकारी के संगम के पास-पास जल स्थिति के बारे में बता सकें और न ही संगम के उपांत में जल विसर्जन या गेज माप केन्द्र हैं जो उस दिन का जल स्तर रिकार्ड कर सकते थे। चूंकि पाटियों द्वारा किए गए अध्ययन परस्पर विरोधी हैं और इस विषय पर उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में महान भ्रंतर है, अतः प्रवालत को यह जांच करनी पड़ेगी और इस बात को निश्चित करना पड़ेगा कि खान दुर्घटना संगम पर दामोदर के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण हुई थी अथवा नहीं। प्रबंधक-वर्ग के अनुसार 16 सितम्बर को खासतौर पर दुर्घटना के समय संगम का जलस्तर 1102 फुट था। चूंकि इस बात का खंडन पतरातू ताप बिजली घर के प्राधिकारियों द्वारा किया गया है जिनके अनुसार उस दिन संगम पर बाढ़ स्तर 1114 फुट से कम नहीं था, इसलिए प्रवालत के लिए यह निश्चित करना आवश्यक है कि 16 सितम्बर को संगम पर जलस्तर क्या रहा होगा।

दामोदर और नकारी के जल स्तर

37.1 संगम पर स्तर निर्धारित करने के संबंध में प्रवालत की राय है कि यह बात तर्कपूर्ण जान पड़ती है कि जब कोई सहायक नदी मुख्य नदी में मिलती है तब यदि संगम पर मुख्य नदी का जल स्तर सहायक नदी के तब स्तर से अधिक होता है तो संगम पर सहायक नदी के मुख्य प्रवाह में बाधा होगी।

प्रबंधकवर्ग के अनुसार संगम के निकट नकारी का तल स्तर 1083 फुट है जैसा कि उनके प्रदर्श संख्या 4 के रेखाचित्र 48 में दिखाया गया है और उनके रेखाचित्र सं० 28 के अनुसार दामोदर का औसत तलस्तर लगभग 1070 फुट है। पतरातू ताप बिजलीघर ने भी प्रदर्श पी-5 के पृष्ठ 11 पर 1070 फुट का अंक दिखाया है और हालांकि उनके द्वारा दिया गया नकारी के तलस्तर का अंक 1083 फुट से एकाधिक फुट अधिक हो सकता है फिर भी प्रवालत उस तथ्य को निश्चित करने के लिए प्रबंधकवर्ग के निर्धारण को मान लेगी कि क्या उनके परिकल्पन के आधार पर कोई पश्च प्रवाह हुआ था अथवा नहीं।

यदि संगम के निकट नदी और सहायक नदी के स्तर क्रमशः 1070 फुट और 1083 फुट होंगे तो नदी में गिरने वाले नकारी के प्रवाह में बाधा पड़ी होगी और दामोदर का जलस्तर 1083 फुट से अधिक हो गया होगा।

स्तरित प्रवाह

37.2 अगला प्रश्न जिस पर विचार करना है, यह है कि क्या दामोदर का स्तर 1083 फुट था और यह कब हुआ था जिसके कारण नकारी नदी के मुक्त प्रवाह में बाधा पड़ी और पश्चजल प्रवाह के कारण सेंट्रल सौदा की तरफ इसके स्तर में वृद्धि हुई।

प्रबंधकवर्ग ने दो अध्ययन किए हैं, उनमें से एक स्तरित प्रवाह के बारे में है जिसके अनुसार, जैसा कि प्रदर्श 4 के पृष्ठ 46 पर उनके रेखाचित्र में दिखाया गया है, हाथीदारी गोफ के मिट्टी के बांध (जिसका नदीस्तर 1115 फुट था) में पानी—चाहे उसका स्त्रोत कोई भी रहा हो—तब तक नहीं घुस सकता था जब तक कि ऊर्ध्वप्रवाह से लगभग 72,000 क्यूसेक पानी विसर्जित न हो रहा होता जिसमें से अधिक से अधिक 12,000 क्यूसेक पानी पतरातू बांध और सेंट्रल सौदा कोलियरी के मध्यवर्ती जलग्रहण क्षेत्र का प्रवाह हो सकता था। अतः उनका कथन

यह था कि 16 सितम्बर को अपराह्न 1 बजे के पासपास दामोदर नदी की स्थिति ऐसी नहीं थी जिसके कारण हाथीदारी गोफ में पानी घुस जाता बशर्ते पतरातू बांध से एकदम पानी न छोड़ दिया जाता जैसा उन्होंने अपने अध्ययनों में दिखाया है। रेखाचित्र में सेंट्रल सौदा पर 1115 फुट जल स्तर के अनुरूप स्टेज विसर्जन दर दिखाई गई है। कार्मिक सूच (मैनिंग फार्मुला) को अपनाते हुए और .03 बलितता के गुणांक और तल ढलान को ध्यान में रखते हुए खान पर जल विसर्जन की मात्रा 71,962 क्यूसेक के पास-पास निकाली गई थी और दुर्घटना के समय दामोदर का स्तर 1102 फुट था। दामोदर घाटी निगम द्वारा किए गए 16 सितम्बर को रामगढ़ सड़क पुल पर दामोदर नदी के अधिकतम जल विसर्जन के आंकड़ों के अनुसार जब दामोदर का स्तर 1102 फुट होता है तब उसमें 3 लाख क्यूसेक पानी विसर्जित होता है। हालांकि रामगढ़ सड़क पुल पर अनुप्रवाह की ओर जल विसर्जन की मात्रा संगम से अधिक हो सकती है फिर भी, प्रबंधकवर्ग इसकी भूरी तस्वीर पेश करने के लिए यह मान सकता है कि संगम और रामगढ़ पुल पर जल विसर्जन की मात्रा समान थी।

नकारी के प्रोफाइल

37.3 प्रबंधकवर्ग का अन्य अध्ययन प्रदर्श 4 के पृष्ठ 48 पर रेखाचित्र सं० पी० ए० एच० ई०/843-4/77-8 प्लेट नं० 4 में दर्शाया गया है इसकी एक प्रति इस रिपोर्ट के खंड-2 में अनुबंध 5-छ में देवी जा सकती है। इस अध्ययन से यह भी प्रकट होता है कि सेंट्रल सौदा कोलियरी का 1115 फुट का जल स्तर दामोदर नदी के संगम के स्तर के बराबर पहुँच जाता जो इतना ऊँचा था कि जिसके पश्चजल प्रभाव से नकारी नदी का स्तर भी काफी ऊँचा उठ जाता। इस रेखाचित्र में दामोदर नदी की स्थिति के अनुसार संगम, सेंट्रल सौदा और उसके पारे नकारी के प्रोफाइल दिखाए गए हैं। ये प्रोफाइल मानक सोपानी विधि (स्टैंडर्ड स्टेप मीथड), जो ऐसे परिवर्तनों की एक स्वीकृति विधि है, के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। इसमें 16 सितम्बर को दुर्घटना के कुछ घंटे बाद प्रसंगाधीन अवधि के दौरान दामोदर नदी की स्थिति का पता चलता है।

पतरातू ताप बिजलीघर ने वस्तुतः यह वही पेश की कि प्रबंधक वर्ग ने संगम के 1102.5 फुट के स्तर और नकारी नदी के 45,000 क्यूसेक जल-विसर्जन के आधार पर जो प्रोफाइल निकाले हैं, वे सही नहीं हैं। पतरातू ताप बिजली घर के अनुसार यह प्रोफाइल संगम पर दामोदर के 1125 फुट के जल-स्तर और नकारी नदी से 1.40 लाख क्यूसेक जल विसर्जन के आधार पर अभिकल्पित किया जाना चाहिये था जैसा कि प्रबंधकवर्ग का स्वयं का अनुमान है। पतरातू ताप बिजली घर के अनुसार प्रबंधकवर्ग द्वारा दिए गए नकारी नदी के जल प्रोफाइल के रेखाचित्र को कब्स की मात्रा परिभाषा माना जाना चाहिए न कि 17 सितम्बर को उच्चबाढ़ स्तर के वास्तविक कब्स के सूचक। बहरहाल प्रवालत को इस बात की जांच करनी है कि 16 सितम्बर को स्थिति क्या थी। पतरातू ताप बिजलीघर के संगम के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र के सर्वेक्षण और कार्मिक सूच (मैनिंग फार्मुला) के आधार पर तैयार किए गए उसके रेडिंग चार्ट के अनुसार 3.10 लाख क्यूसेक जल विसर्जन पर संगम का जल स्तर 1114 फुट था जिससे संगम के अनुप्रवाह पर झूला-मुल बह गया था, नकारी का जल स्तर 1114 फुट से ऊपर हो गया था और हाथीदारी गोफ में पानी घुस गया था। हालांकि पतरातू ताप बिजली घर को प्रबंधकवर्ग द्वारा बनाए गए नकारी जल के प्रोफाइल के बारे में संदेह तो हो सकता है लेकिन फिर भी, प्रवालत प्रबंधकवर्ग के जल प्रोफाइल को सही मानते हुए यह निश्चित करना चाहेगी कि क्या 16 सितम्बर को पश्च-जल के प्रभाव के कारण नकारी नदी में जल स्तर वृद्धि हुई थी।

आर०सी० सी० पुल का डूब जाना

38. अब प्रवालत प्रबंधक वर्ग द्वारा निर्धारित प्रदर्श 4 के पृष्ठ 48 पर नकारी के जल प्रोफाइल और नकारी तथा दामोदर के तल-स्तरों को ध्यान में रखते हुए इस बात की जांच करेगी कि संगम का जल स्तर किस

समय और किस हद तक नकारी के जलस्तर -1083 फुट से अधिक हुआ जिसके कारण सेंट्रल सौदा कोलियरी की ओर पानी वापस आया।

इस रिपोर्ट के पैरा 28.2 में एन० सी० डी० सी० सौदा कोलियरी के अनुप्रवाह और संगम के निकट नकारी के पास आर० सी० सी० पुल के बूझ जाने का उल्लेख किया गया है, उससे दो मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, 16 सितम्बर को सुबह लगभग 9.15 बजे से 10.30 बजे के बीच नकारी नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई थी जो पुल से भी ऊंचा था। दूसरी, ऐसा होने पर संगम पर दामोदर का जल स्तर नकारी सहायक नदी के जलस्तर -1083 फुट से अधिक हो गया था और परिणामतः आर० सी० सी० पुल बूझ गया था। वरिष्ठ कार्यपालक इंजीनियर श्री कुंभू और सेंट्रल सौदा कोलियरी के एजेंट श्री एस० के० मुखर्जी ने जो कुछ कहा है, उसके अनुसार पुल के ऊपर लगभग 2 फुट पानी बह रहा था। पतरातू ताप बिजलीघर के प्राधिकारियों ने, जिन्होंने इस पुल के शीर्ष तल का अवलोकन किया था, इसे 1110 फुट पाया था, अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पुल पर 1112 फुट के जल स्तर की वृद्धि दामोदर में बाढ़ आने के कारण हुई थी।

चूँकि पानी पुलों से ऊपर बह रहा था और आर० सी० सी० पुल पर 3-4 फुट तक पानी था, जैसा कि श्री बालिगा ने बताया है अतः वास्तविक स्तरजल 1112 फुट 4 फुट अर्थात् 1108 फुट होगा। प्रबंधकवर्ग ने भी अपने लिखित बयान में यह स्वीकार किया है कि पुल 1108 फुट के अधिकतम बाढ़ स्तर पर बूझ गया था। इस प्रकार यदि संगम पर जल-स्तर 1108 फुट था या इससे कुछ कम भी था तब भी यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रवर्ष 4 के पृष्ठ 48 पर दिए गए पानी के प्रोफाइल के संदर्भ में पानी वापस प्रवश्य आया था और परिणामतः सेंट्रल सौदा पर नकारी नदी के जल विसर्जन की मात्रा उक्त रेखाचित्र में दिखाए गए अंकों से कम था।

16 सितम्बर को जल स्तर का निर्धारण

39. प्रबंधकवर्ग द्वारा किए गए वर्णन और दामोदर घाटी निगम के विषयगत आंकड़ों के अनुसार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रातः 9 बजे से पहले ही संगम पर दामोदर का जलस्तर नकारी के जल स्तर से ऊंचा था। 16 सितम्बर को जो असाधारण घटना घटी उसका उल्लेख प्रबंधकवर्ग के लिखित बयान में किया गया है। यह बयान इस प्रकार है "16 तारीख को सुबह से ही दामोदर नदी के जलस्तर में वृद्धि होने लगी थी। उसका प्रत्यक्ष कारण यह था कि पालामऊ जिले में नदी के स्रोत के निकट उपरि जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा हुई थी। 16 सितम्बर के अलस सुबह दामोदर नदी का जलस्तर एसोसिएटेड करनपुरा कोलियरी पर खतरे के निशान को पार कर गया था और दामोदर नदी के निकटवर्ती इन्फ्लाहनों अर्थात् सिरका 1 और 2, सौदा 1 और 2, बांसगोड़ा 4 और 5 और सिरका 3 और 4 से कामगारों को वापस बुला लिया गया था।

एसोसिएटेड करनपुरा कोलियरी संगम के सही उपरि भाग में स्थित है और यह पता लगाने के लिए कि स्वयं संगम के निकट स्थिति क्या रही होगी, अवालत के समक्ष दामोदर घाटी निगम के आंकड़ों से कुछ निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। अतः धात यह है कि स्वयं प्रबंधकवर्ग को अवालत के समक्ष बयान देने का मौका मिला था अतः रामगढ़ सड़क पुल के गेज विसर्जन केंद्र के दामोदर से संबंधित प्रेक्षणों पर निर्भर करना और उसके बाद संगम को आधार मानकर उसकी स्थिति का दोबारा जायजा लेना बुद्धिमानों का काम होगा। अतः अवालत 16 सितम्बर के उस ठीक समय को स्पष्टरूप से जान करने के लिए जब संगम पर जलस्तर में वृद्धि होने लगी थी, दामोदर घाटी निगम तथा अन्य संगत आंकड़ों के आधार पर जांच करना चाहिये:

रामगढ़ सड़क पुल पर जलस्तर

39.2 अवालत ने दामोदर घाटी निगम से निम्नलिखित सामग्री प्राप्त की है:—

- (क) संगम के पास ऊंचाई पर स्थित दामोदर जलग्रहण डेल के चार वर्षामापी केंद्रों—चंडवा, सिल्लाचक, सिलारी और बड़का गांव पर 1 सितम्बर, 1976 से लेकर 21 सितम्बर, 1976 तक प्रतिदिन रिकार्ड किए गए वर्षा के आंकड़े; और
- (ख) दामोदर नदी के रामगढ़ पुल पर 1 सितम्बर, 1976 से लेकर 21 सितम्बर, 1976 तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक बह रहे पानी का अधिकतम जलस्तर और विसर्जित हो रहे पानी की क्यूसेक में मात्रा। सेंट्रल सौदा कोलियरी के सबसे नजदीक जो दामोदर घाटी निगम का गेज और विसर्जन केंद्र है वह नदी के अनुप्रवाह की ओर कोलियरी से 15 मील दूर रामगढ़ पुल पर है।

39.3 अवालत के सामने प्रबंधकवर्ग ने निम्नलिखित तथ्य भी प्रस्तुत किए:—

- (अ) दामोदर घाटी निगम के हाइड्रालिक आंकड़ा प्रभाग की नवी-गेज-रिपोर्ट जिसमें रामगढ़ केंद्र पर 12 सितम्बर, 1976 से लेकर 20 सितम्बर, 1976 तक हर घंटे पर ली गई गेज-रीडिंग और जलस्तर रीडिंग का रिकार्ड है जिसे प्रवर्ष-8 के रूप में अंकित किया गया है।
- (आ) दामोदर घाटी निगम का एक विवरण जिसने दामोदर नदी के रामगढ़ केंद्र पर हर साल में अधिकतम विसर्जन और आर० एल० में गेज दिखाया गया है, जिसे प्रवर्ष-9 के रूप में अंकित किया गया है।

39.4 उपर्युक्त रिकार्डों से निम्नलिखित बातों का पता चलता है:

- (क) 1976 में बाढ़ का सबसे अधिक जोर 17 सितम्बर को था क्योंकि उस दिन रामगढ़ केंद्र पर नदी का जल-स्तर 1040.00 फुट था अर्थात् सबसे अधिक था। रिकार्डों को देखने से पता चलता है कि इतना अधिक जलस्तर 1945 के बाद कभी नहीं हुआ था।
- (ख) हालांकि अधिक बाढ़ के कारण 16 सितम्बर को 12 बजे रात से 17 सितम्बर, 1976 को 10 बजे सुबह तक सभी गेज पानी में डूबे हुए थे, फिर भी रामगढ़ पुल पर 16 सितम्बर को 9 बजे सुबह जल स्तर 1025.49 फुट था।

39.5 जहाँ प्रवर्ष-9 से यह पता चलता है कि रामगढ़ पुल पर 17 सितम्बर को उच्चतम जल स्तर 1040.09 फुट था, वही पृष्ठ 11 पर दिए गए पतरातू ताप बिजलीघर प्रवर्ष पी-5 के रेखाचित्र के अनुसार जल स्तर 3.45 फुट और अधिक था, अर्थात् 1043.54 फुट था जो कि प्रबंधकों द्वारा दिये गये 1043.42 फुट के जल स्तर से काफी मिलता जुलता है जिसे प्रवर्ष 4 पृष्ठ 38 पर दिये गए रेखाचित्र में दिखाया गया है? दामोदर घाटी निगम के बाढ़ के सभी जल स्तर मापी द्वारा अभिलेखित जल स्तर 1040.09 फुट का संबंध दामोदर तल स्तर के 1003 फुट से है, जैसा कि पृष्ठ 51 प्रवर्ष 4 में दिखाया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पुल पर पानी की गहराई 1040.09 फुट—1003 फुट—37.09 फुट थी। यदि 37.09 फुट को दामोदर के उस तल स्तर यानी 1006.63 फुट में जोड़ दिया जाए, जिसे प्रवर्ष 4 पृष्ठ 38 पर में प्रबंधक द्वारा दिखाया गया है, तो पुल पर अधिकतम जलस्तर 1043.72 फुट होगा जो कि लगभग वही होगा जो कि पतरातू ताप बिजलीघर द्वारा मापा गया जलस्तर अर्थात् 1043.54 फुट था। अतः रामगढ़ पुल पर 17 सितम्बर को दामोदर नदी का उच्चतम जलस्तर 1043.54 था। इस

बात को उस स्थिति में सही मान लेना उचित होगा जबकि इस धंक के खिलाफ प्रबंधकों ने कुछ नहीं कहा है और विशेष रूप से तब जबकि यह धंक पतरातू बांध और रामगढ़ पुल के सहसंबंध सर्वेक्षण को निरूपित करता है।

अब भवालत इस अधिकतम जलस्तर और संगम पर इसी दिन के जलस्तर में मिलान करना चाहेंगे।

संगम पर जलस्तर

39.6 प्रबंधकों के अनुसार संगम पर जलस्तर 1123.53 फुट था, जैसा कि प्रदर्श-4 में पृष्ठ 28 पर दिखाया है, जबकि पतरातू ताप बिजलीघर के रेखाचित्र खंड एल० में दिए गए के अनुसार संगम पर जलस्तर 1125 फुट था। प्रबंधकों के लिखित बयान के अनुसार बाढ़ उस समय अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गई थी जबकि बामोदर नदी और नकारी नदी के किनारों पर बने हुए अनेक रिहायशी क्वार्टर 17 सितम्बर के जलस्तर तक पूरी तरह से डूब गए थे और यही वह दिन था जिस दिन बामोदर नदी का जलस्तर अधिकतम था। पतरातू ताप बिजलीघर के अनुसार पूरी तरह डूबे हुए क्वार्टरों और मंदिरों की छतों की समुद्र तल से ऊंचाई 1125 फुट थी, अतः उस दिन जलस्तर भी 1125 फुट होना चाहिये। पर, क्योंकि क्वार्टरों की छतों की ऊंचाईयों के ठीक-ठीक माप भवालत के सामने नहीं प्रस्तुत किये गए हैं और संगम के घास-पास के सभी क्वार्टर और मंदिर समान ऊंचाई के नहीं थे, इसलिए प्रबंधकों द्वारा बताए गए 1123.53 फुट की, जो कि पतरातू ताप बिजली घर द्वारा बताए गए जलस्तर से 1.47 फुट कम है, सही मान लेने में भवालत को कोई आपत्ति नहीं है।

ऊपर दिये गए धंको को देखने से यह पता चलता है कि 17 सितम्बर को संगम पर के और रामगढ़ पुल पर के अधिकतम जलस्तरों में 1123.53 फुट—1043.54 फुट=79.99 फुट का अंतर था।

16 सितम्बर को संगम पर जलस्तर

40. यदि यह मान लिया जाए कि 16 सितम्बर को रामगढ़ पुल पर जलस्तर और संगम पर के जलस्तर में 79.99 फुट का अंतर था, तो रामगढ़ पुल पर के जलस्तर में 79.99 फुट जोड़ देने पर संगम पर का जलस्तर मालूम हो जायेगा।

	रामगढ़ पुल पर जलस्तर, प्रदर्श-8	संगम पर संभावनी जलस्तर
6 बजे सुबह	1021.38 फुट	1101.37 फुट
7 बजे सुबह	1022.38 फुट	1102.37 फुट
8 बजे सुबह	1022.79 फुट	1102.78 फुट
9 बजे सुबह	1025.40 फुट	1106.48 फुट

यदि रामगढ़ पुल पर जलस्तर वह नहीं माना जाए जो कि इस सारणी में दिया गया है बल्कि 3.45 फुट और अधिक माना जाए, जैसा कि 17 सितम्बर के दिन बाढ़ का उच्चतम बाढ़स्तर मालूम करने के लिए प्रबंधकों और पतरातू ताप बिजली घर ने किया है, तो संगम पर भी जलस्तर अधिक होगा यानी 6 बजे सुबह 1104.82 फुट से बढ़ कर 9 बजे सुबह 1108.93 फुट हो जाएगा और इस तरह आर० सी० सी० पुल पर भी 9 बजे सुबह जलस्तर में इतनी ही अपवा इससे भी अधिक वृद्धि हो जाएगी। अतः आर० सी० सी० पुल पर इस स्तर तक पानी 11 बजे और 11.30 बजे पूर्वाह्न के बीच नहीं होगा जैसा कि प्रबंधकों ने प्रस्तुत किया है और जिसका उल्लेख पैरा 28.3 में किया गया है, बल्कि प्रातः 9 बजे के घास-पास ही पानी इस स्तर तक पहुंच गया होगा।

यों तो यह मान लेना कि 16 सितम्बर का जलस्तर का अंतर वही था जो 17 सितम्बर को था, बिल्कुल सही नहीं हो सकता, पर इस से इस बात का पता तो चल ही जाता है कि संगम पर जलस्तर 1105.42 फुट या 1108.93 फुट था जो कि लगभग वही जलस्तर था जिससे

बाढ़ में आर० सी० सी० पुल डूब गया था जिसका उल्लेख पैरा 38 में किया गया है। इस तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि नकारी नदी के जलस्तर की अपेक्षा संगम पर नदी का जलस्तर काफी अधिक था और इस तथ्य से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिम जल का प्रभाव 16 सितम्बर की 6 बजे सुबह के बाद ही शुरू हुआ होगा, इससे पहले नहीं—इस बात की पुष्टि प्रदर्श-4 के पृष्ठ 48 पर भी की गई है।

प्रबन्धक द्वारा प्रदर्श-4 के पृष्ठ 52 पर दिए गए रेखाचित्र से इस बात की पुष्टि होने पर कि 9 बजे के बाद भी संगम पर नदी के जलस्तर में निरन्तर वृद्धि हो रही थी, इस बात का पता चलता है कि बामोदर घाटी निगम, रामगढ़ में किए गए प्रेक्षणों के आधार पर बामोदर नदी के जलस्तर में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। प्रबन्धक के अनुसार भी 11 बजे पूर्वाह्न के लगभग केन्द्रीय सौदा कोलियरी पर जलस्तर पूर्वी तटबन्ध शीर्ष से कम से कम 5 फुट नीचे था अर्थात् जलस्तर 1110 फुट था जिससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि संगम पर नदी के जलस्तर में निरन्तर वृद्धि हो रही थी।

दुर्घटना में पश्चिम जल का प्रभाव

41. पिछले पैराग्राफों से जो कुछ भी पता चलता है उससे प्रबंधकों के इस दलील को मान लेना सम्भव नहीं है कि 16 सितम्बर को दोपहर के 1 बजे घास-पास संगम पर नदी की जो स्थिति थी, वह वर्षा के परिणामस्वरूप उपरी जलग्रहण क्षेत्र से प्राप्त हुए पानी की वजह से नहीं हो सकता बल्कि यह स्थिति केवल तभी हो सकती थी जबकि नकारी नदी से 63,000 क्यूसेक पानी बामोदर नदी में आ रहा होता। अन्यथा, उनके अनुसार बामोदर नदी का जलस्तर 1108 फुट से कम होता। पर यह तो स्पष्ट है कि उपरि जलग्रहण क्षेत्र से आ रहे पानी के कारण बामोदर नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही थी जिसकी वजह से नकारी नदी के मुक्त प्रवाह में बाधा पड़ गई। नतीजा यह हुआ कि पश्चिम जल के कारण नकारी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई और यही वृद्धि दुर्घटना का कारण बनी। पतरातू ताप बिजली घर के अनुसार संगम पर नदी का जलस्तर 1114 फुट या 1115 फुट था। यदि इस बात को सही मान लिया जाए तो तर्कसंगत निष्कर्ष यही निकलेगा कि सेंट्रल सौदा कोलियरी नकारी नदी से बहुत ही कम अर्थात् 12,568 क्यूसेक या इससे भी कम मात्रा में पानी विसर्जित होता, जिसका उल्लेख पतरातू ताप बिजलीघर में किया है और ऐसी स्थिति में पश्चिम जल ही केवल एक कारण होता जिसकी वजह से दुर्घटना हुई, भवालत को इस बात की तहत में जाने की आवश्यकता नहीं है कि संगम नदी का जलस्तर 1115 फुट था कि नहीं क्योंकि प्राथमिक रूप में इसका काम प्रबन्धक द्वारा दी गई इस दलील को परखना है कि नकारी नदी से बहुत अधिक मात्रा में पानी विसर्जित होने के कारण ही दुर्घटना घटी। स्वयं प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत किए गए धंकों से यह स्पष्ट हो जाता है कि नकारी नदी से विसर्जित हो रहे पानी, जो कि 71,962 क्यूसेक से काफी कम था, के साथ-साथ बामोदर नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि के फलस्वरूप पश्चिम जल की वजह से नकारी के जलस्तर में वृद्धि हो गई जिसकी वजह से दुर्घटना हुई।

एन० सी० डी० सी० सौदा पर जलस्तर

42.1 प्रबंधकों की ओर से यह तर्क दिया गया कि यदि सेंट्रल सौदा के हाथीवारी गोफ में बामोदर नदी का पानी फुस जाने के कारण 16 सितम्बर को लगभग 1 बजे दोपहर में जलस्तर 1115 फुट हो गया होता तो इस पानी की वजह से पहले एन० सी० डी० सी० सौदा में 1115 फुट के जलस्तर तक पानी आ गया होता। नकारी नदी के किनारे पर स्थित एन० सी० डी० सी० सौदा कोलियरी सेंट्रल सौदा के उस ओर है जिस ओर नदी का बहाव है और क्योंकि प्रबन्धक के अनुसार नदी के पश्चिमप्रवाह के कारण नदी के अनुप्रवाह की ओर कोलियरी पर का जलस्तर नदी के ऊर्ध्व-प्रवाह की ओर कोलियरी पर के जलस्तर की अपेक्षा अधिक होगा, अतः एन० सी० डी० सी० सौदा के सिरपा इन्कलाइन पर अपराह्न 1 बजे के घास-पास पानी 1117 फुट के जलस्तर तक पहुंच जाता। लेकिन क्योंकि 16 सितम्बर को ऐसी बात नहीं हुई थी अर्थात् उस

दिन एन० सी० डी० सी० सौदा पर अपराह्न 1 बजे के आस-पास जलस्तर 1108 फुट तक ही पहुँच पाया था, अतः बुर्बंटना घटने का कारण पश्चिम-प्रवाह को नहीं माना जा सकता।

42.2 पतरातू ताप बिजलीघर के प्राधिकारियों ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि दामोदर नदी का ही पानी था जो पश्चिम-प्रवाह के कारण सेंट्रल सौदा की गोफ में घुस गया था—और सम्भवतः मुख्य नदी से मिलने वाली सहायक नदी में पश्चिम-प्रवाह तभी हो सकता है जबकि उसमें मिलने वाली सहायक नदी के प्रवाह की धोर या तो बहाव बिल्कुल न हो या बहुत कम हो। पतरातू ताप बिजली घर के प्राधिकारियों ने जो दलील दी है—जिसे भ्रमालत ने सिद्धान्त रूप में तो स्वीकार कर लिया है पर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अंकों के बारे में भ्रमालत ने अपना कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया है कि संगम पर दामोदर नदी के जलस्तर में वृद्धि हो जाने के कारण नकारी नदी के बहाव में काफी बाधा पड़ गई थी। फलस्वरूप सेंट्रल सौदा में नकारी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया जिसकी वजह से सेंट्रल सौदा के हाथीवारी गोफ में पानी घुस गया। चूंकि दामोदर नदी के जलस्तर में वृद्धि होना और नकारी नदी के पानी में विसर्जन में कमी होना दोनों ही बातें घटित हो रही थीं, इसलिए भ्रमालत इस बात का पता लगाना जरूरी नहीं समझती कि सेंट्रल सौदा कोलियरी में घुसने वाला पानी दामोदर नदी का पानी था या नकारी नदी का पानी था अथवा इन दोनों नदियों का पानी था। यह तो स्पष्ट है कि पश्चिम-प्रवाह की वजह से भयानक बुर्बंटना घटी थी अतः, यह पश्चिम-प्रवाह से आया—इस बात का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है—हालांकि यह तो स्पष्ट है कि नकारी नदी का ही पानी अत्यधिक मात्रा में गोफ में घुस आया था।

42.3 एन० सी० डी० सी० सौदा कोलियरी के प्रबंधक वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए गए इस अंक से कि 1 बजे दोपहर तक कोलियरी में पानी 1108 फुट के जलस्तर तक भर गया था, जिसे प्रबंधकों ने स्वीकार कर लिया है, एक अत्यंत रोचक निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

हालांकि 14-7-77 को भ्रमालत के सामने दिए गए अपने बयान में एन० सी० डी० सी० कोलियरी के प्रबंधक श्री एस० एन० चटर्जी ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि उनकी खान में नकारी नदी के जलस्तर का कहीं भी लिखित रिकार्ड नहीं है, फिर भी उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए जलस्तर के अंकों को सेंट्रल सौदा के प्रबंधकों ने प्रमाणित मान लिया है और जलस्तरों से संबंध ग्रहस्थाधारित प्रलेख से अपनी सहमति जाहिर कर दी है। एन० सी० डी० सी० सौदा से लिए गए इस प्रलेख को डी० सी० एन० एस० ने 13-11-77 के दिन भ्रमालत के सामने प्रस्तुत किया जिसे शिनाख्त के लिए एक्स-9 के रूप में अंकित कर दिया गया है।

श्री चटर्जी ने भ्रमालत को बताया कि 16 सितम्बर को 9.30 बजे सुबह से लेकर 2.00 बजे दोपहर तक नकारी नदी को देखने का मौका उन्हें मिला था जिसे वे अपने दफ्तर के बरांडे में खड़े होकर देखते थे और वहीं से हर घंटे पुर के खंभे पर बने हुए जलस्तर के निशान को पढ़ लेते थे। जलस्तर के निशान को पढ़ने पर उन्हें कोई खास बात नजर नहीं आई। उनके अनुसार 2 बजे दोपहर तक नकारी नदी का बहाव संगम की ओर था और दामोदर नदी से कोई पश्चिम-प्रवाह नहीं हो रहा था। 9.30 बजे जलस्तर लगभग 1102 फुट था और 1 बजे दोपहर से थोड़ा पहले जलस्तर 1104 फुट और 1105 फुट के बीच था। 1 बजे दोपहर के आस-पास उन्होंने जलस्तर में यकायक वृद्धि देखी जो कि 1108 फुट था। एक्स-9 में दिए गए अंकों और इन अंकों में थोड़ा बहुत अंतर है। प्रलेख के अनुसार दामोदर नदी के जलस्तर में वृद्धि 4 बजे सुबह शुरू हो गई थी जो 2 बजे दोपहर तक 1108 फुट तक पहुँच गया था। यह पूछे जाने पर कि सेंट्रल सौदा पर 1 बजे दोपहर के लगभग नकारी नदी का जलस्तर कितना था—अपने जवाब में श्री चटर्जी ने यह बताया कि एन० सी० डी० सी० सौदा पर नदी के जलस्तर की अपेक्षा सेंट्रल सौदा पर नदी का जलस्तर हमेशा अधिक रहता था। जब भ्रमालत ने सेंट्रल सौदा पर नदी के अधिकतम जलस्तर के बारे में बताने के लिए प्रबंधकों को आदेश दिया जबकि यह ज्ञात था कि 16 सितम्बर से 1 बजे दोपहर

में एन० सी० डी० सी० सौदा पर नदी का जलस्तर 1108 फुट था तो 1-11-77 को श्री डी० पी० बालिगा द्वारा भेजी गई सूचना हब हस प्रकार थी :

‘आपके आदेश का अनुपालन करते हुए ग्रहोहस्ताक्षरी ने आवश्यक आंकड़े प्राप्त किए हैं। एन० सी० डी० सी० सौदा के एक उपयुक्त स्थल पर नकारी नदी का एक स्टेज विसर्जन-वर कर्व बना लिया गया है। एन० सी० डी० सी० सौदा नकारी नदी के जलस्तर 1108 फुट से (गोफ के नजदीक) सेंट्रल सौदा पर समान मात्रा में विसर्जित नकारी नदी के जलस्तर से और इस स्थल पर स्टेज-विसर्जन दर-कर्व से निर्धारित जलस्तर से नकारी नदी से दामोदर नदी की ओर बहने वाले पानी का नदीस्तर 1110.20 फुट होगा।’

42.4 श्री चटर्जी और श्री बालिगा द्वारा भ्रमालत को दिए गए बयानों से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह बिल्कुल स्पष्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 बजे दोपहर में जब पानी हाथीवारी गोफ में घुस आया उस समय नकारी नदी का जलस्तर 1110.20 फुट था न कि 1115 फुट जैसा कि प्रबंधकों ने अपनी दलील में हर जगह कहा है। इससे इस बात का भी पता चलता है कि उस समय सेंट्रल सौदा पर नकारी नदी से लगभग 48,867 क्यूसेक पानी ही विसर्जित हो रहा था, जैसा कि प्रबंधकों के प्रवेश-4 से प्रकट होता है, न कि लगभग 72,000 क्यूसेक पानी जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा है।

ऊपर जो कुछ भी निष्कर्ष निकाला गया है वह प्रबंधकों के अपने इस बयान पर ही आधारित है कि कम से कम 16 सितम्बर को लगभग 1 बजे दोपहर तक बिना किसी रुकावट के नकारी नदी संगम की ओर बह रही थी। पर, क्योंकि यह बात नहीं मान ली गई है कि संगम पर नदी के जलस्तर में अलग सुबह से ही निरंतर वृद्धि हो रही थी जिसकी वजह से सेंट्रल सौदा पर नकारी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई इसलिए पश्चिम-प्रवाह के कारण ही एन० सी० डी० सी० सौदा पर 1 बजे दोपहर में पानी 1108 फुट के जलस्तर तक पहुँच गया था। चूंकि अनुप्रवाह पर कोलियरी पर नदी का जलस्तर 1108 फुट था, इसलिए ऊर्ध्व-प्रवाह सेंट्रल सौदा पर नदी का जलस्तर थोड़ा बहुत अधिक ही होगा जैसा कि प्रमाण के रूप में प्रदर्श-4 के रेखाचित्र 48 में दिखाए गए प्रबंधकों को जल-प्रोफाइल से स्पष्ट है। एन० सी० डी० सी० सौदा सेंट्रल सौदा की अपेक्षा संगम से अधिक नजदीक है और यदि इसके स्थान को रेखाचित्र में नियत कर दिया जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सेंट्रल सौदा की अपेक्षा एन० सी० डी० सी० सौदा पर जलस्तर थोड़ा बहुत कम ही होगा। चूंकि यह रेखाचित्र संगम पर नकारी नदी से विसर्जित हो रहे पानी की मात्रा और दामोदर नदी के जलस्तर पर आधारित है, जिस पर पतरातू ताप बिजलीघर ने आपत्ति की है, अतः यह किसी भी हालत में इस बात को प्रदर्शित नहीं करता कि पश्चिम-प्रवाह की वजह से एन० सी० डी० सी० सौदा की अपेक्षा सेंट्रल सौदा पर जलस्तर अधिक हो जाता है किसी भी पक्ष ने यह पता नहीं लगाया है कि 1 बजे दोपहर में सेंट्रल सौदा पर जलस्तर ठीक-ठीक क्या हो सकता था जबकि उस समय एन० सी० डी० सी० सौदा पर जलस्तर 1108 फुट था पर यह बात ठीक नहीं जंचती कि दोनों कोयला खानों का आस-पास होने पर वहाँ का जलस्तर सेंट्रल सौदा पर के 1115 फुट तक के जलस्तर तक पहुँच जाता। इसे तथ्य से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि हाथीवारी गोफ में भरने वाला पानी 1115 फुट के स्तर पर नहीं था जैसा कि प्रबंधकों ने कहा है बल्कि इससे कम स्तर पर था अगर यह भी मान लिया जाए कि पश्चिम-प्रवाह के कारण गोफ में पानी नहीं भरा है बल्कि पश्चिम-प्रवाह के कारण भयानक बुर्बंटना घटी है तब भी सेंट्रल सौदा पर के जिस जलस्तर से 1 बजे दोपहर के आस-पास पानी गोफ में आ गया होगा वह एन० सी० डी० सी० सौदा के प्रबंधकों द्वारा स्वीकृत जलस्तर 1108 फुट से कम था।

इस तरह नकारी नदी से, जिसका 1 बजे दोपहर के आस-पास एन० सी० डी० सी० सौदा पर जलस्तर 1108 फुट था, जिसे प्रबंधक भी सही मानते हैं, निकलने वाला पानी ही संभवतः वह पानी था जो कि उस समय सेंट्रल सौदा गोफ में 1115 फुट से कम जलस्तर में घुसा था, चाहे यह

पानी नकारी नदी के मुक्त प्रवाह के कारण हो, चाहे संगम से भाए हुए पक्कजल के कारण हो या चाहे पक्क प्रवाह हो, जिसकी वजह से भ्रष्टाना बुधटना घटी थी।

43.1 यदि 1115 फुट से कम जलस्तर पर पानी हाथीधारी सीम में आया हो तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि बांध में जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1115 फुट थी और जिसे प्रबंधकों ने खान को बचाने के लिए बनवाया था—तेजी से पानी आने के कारण दरार पड़ गई। प्रबंधकों की ओर से यह दलील दी गई है कि तटबंध मिट्टी बहने के कारण नहीं बल्कि उसके ऊपर से पानी निकलने के कारण टूटा था। श्री बी० पी० बालिगा ने जिन्होंने जानकारी प्राप्त करने के संबंध में बांध को देखा था, अपने बयान में प्रचालत को यह बताया कि 16 सितम्बर 1976 से लेकर फरवरी 1977 तक की जबकि वह बांध को देखने गए थे, प्रबंधन में बुधटना के बाव बांध को बनाने का काम नहीं किया गया। जिस समय फरवरी में उन्होंने बांध का निरीक्षण किया था उस समय उन्होंने यह देखा था कि बांध के आधार पर कोई मुकसान नहीं हुआ है, इस तरह उनका निष्कर्ष यह था कि ऊपर से पानी निकलने की वजह से मिट्टी का तटबंध टूट गया। उन्होंने इस आधार पर अपना तर्क दिया था कि दरार पड़ जाने पर मिट्टी का बांध सामान्यतः टूट जाता है। प्रचालत के अनुसार इस बात से यह परिलक्षित होता है कि हालांकि बुधटना के बाद ही बांध को टूटा हुआ पाया गया, और प्रबंधकों के अनुसार बांध 1115 फुट से कम जलस्तर पर तेजी से आने वाले पानी के कारण नहीं टूटा था बल्कि जल स्तर 1115 फुट थी और पानी बांध की चोटी से बह रहा था और बुधटना के बाव पानी उतर गया था। श्री कर्केटा के अनुसार मिट्टी का बांध दरार पड़ने से नहीं टूटा क्योंकि ऐसी स्थिति में बांध के दोनों ओर के भाग के मुकसान पड़ता है, और यह बात सेंट्रल सोदा पर नहीं हुई थी। प्रबंधकों ने अपनी दलील में जिस बात पर अधिक जोर दिया है उसके बारे में प्रचालत का विचार है कि यह एक अनुमान ही है और इस बात की संभावना बिलकुल नहीं है कि 1110 फुट के जलस्तर पर बांध के शीर्ष से 5 फुट कम जलस्तर से आने वाले पानी से बांध टूट जाए। उस समय बांध पर कोई भी ऐसा चपमदीव गवाह मौजूद नहीं था जिस समय पानी गोक के अंदर घुसना शुरू हुआ था। अपने बयान में जीत सिंह ने यह कहा था कि 12.15 बजे दोपहर और 12.45 बजे दोपहर के आस-पास गोक को देखने पर उन्होंने यह पाया कि पानी बांध के ऊपर से बह रहा है पर यह स्पष्ट है कि वे उस स्थान पर यह बात न तो देख सके और न ही यह देख पाए कि क्या पानी बांध के ऊपर से बह रहा था जो उस समय बिलकुल सही सलामत था या पहले ही टूट चुका था।

इस बात के भलावा कि बाढ़ के पानी के टकराने से बांध टूट सकता है तथा बांध का शीर्ष बह सकता है, एक अन्य संभावना भी हो सकती है जिससे इस बात की पुष्टि हो सकती है कि 1115 फुट से भी कम जलस्तर पर पानी गोक में घुस सकता है। चूंकि आस-पास की मिट्टी से ही बांध बनाया गया था जैसा कि पैरा 24.1 में बताया गया है, इसलिए मानसून की वर्षा की वजह से तथा खास तौर से बरबाती अवस्था की वजह से, जो कि बिहार में 16 सितम्बर, 1976 के कुछ दिन पहले हो गई थी, बांध की ऊपरी सतह बहने के बाव 1110 फुट या इसके आस-पास के स्तर तक आ गया हो।

43.2 इसमें तथा पिछले पैरे में जो कुछ कहा है उससे सेंट्रल सोदा के पास बह रही उस नकारी नदी के जलस्तर के बारे में संदेह बना रहता है जिसका पानी गोक में घुस गया था। प्रचालत का सीधा संबंध ठीक-ठीक उस समय के जल स्तर की जानकारी प्राप्त करने का नहीं है जिसकी वजह से हाथीधारी गोक जलमग्न हो गई थी और न ही हम प्रश्न से उसका सीधा संबंध है कि नकारी नदी के मुक्त प्रवाह की वजह से गोक में पानी घुस गया था या दामोदर नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण भयानक बुधटना घटी थी। इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि बुधटना केवल नकारी नदी के जल विसर्जन

के कारण ही नहीं घटी थी बल्कि सहायक नदी के प्रवाह और संगम पर नदी के अलस्तर में वृद्धि होने के कारण भी घटी थी।

भाग-4

मंजूरी और निरीक्षण

खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा मंजूरी

44. हालांकि खान सुरक्षा महानिदेशालय इस जांच का एक पक्ष नहीं था, जैसा कि इस रिपोर्ट के पैरा 6 में उल्लेख किया गया है, पर प्रचालत ने इस बात की ओर उनका ध्यान आकषित किया है कि उन्हें केवल यह नहीं मान लेना चाहिए कि प्रबंधकों के प्रावेदन-पत्र में वे सभी तथ्य और जानकारी मौजूद है जो कि उन्हें खाने तोड़ने से संबंधित मंजूरी देने के लिए संगत है। आमतौर पर उन्हें यह समझना चाहिए कि हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का कोई कदासय न हो, फिर भी अपने प्रावेदन-पत्र को तैयार करने में प्रबंधक वर्ग कुछ गलतियां कर सकता है, या संभवतः लापरवाही में कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत न कर पाए हों जो खाने तोड़ने की अनुमति देने के लिए आवश्यक हो। इस खास मामले में, यदि खान सुरक्षा महानिदेशालय ने इस बात को नहीं मान लिया होता कि प्रावेदन-पत्र तथा संलग्न सनक्चो में दिए गए तथ्य सही थे, तो वे खान में पानी भर जाने की संभावित खतरे की ओर प्रबंधक वर्ग का ध्यान अवश्य आकषित करते। ऐसा करते समय वे स्वयं गोक में पानी भर जाने से संबंध मामलों पर अधिक सावधानी बरतने के लिए अपने निरीक्षण-प्रधिकारियों को सतर्क कर देते। जैसा कि इस मामले में हुआ है, न तो प्रबंधक वर्ग और न ही खान सुरक्षा महानिदेशालय इस बात की तह तक पहुंच पाए थे कि सेंट्रल सोदा कोलियरी में पानी भर जाने की संभावना हो सकती है। यदि यह भी मान लिया जाए कि खान में पानी भरने की संभावना बहुत ही कम थी, तो भी उन्हें इस संभावना की उम्मा नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ऐसा करने का मतलब खान में काम कर रहे लोगों के जीवन को खतरे में डालना था।

अतः पहले पहल तो खान सुरक्षा महानिदेशालय को खान के उन रिफाई और नक्शों के साथ प्रबंधक वर्ग के प्रावेदन-पत्र में दिए गए तथ्यों की जांच करनी चाहिए जिसका उनके पास होना आवश्यक है। पर न तो रांची के कार्यालय में और न ही धनबाद के मुख्यालय में ऐसा किया गया। यदि रांची के कार्यालय में खान का व्यापक विवरण मौजूद नहीं था, जिसे उन्हें रखना चाहिए, तो उनके अधिकारी खाने तोड़ने से संबंध सभी सुसंगत तथ्यों की ठीक-ठीक जांच करने के लिए निरीक्षण कर सकते थे—पर यह कार्य भी संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया। निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रचालत के इन प्रेरणों की विस्तार से उल्लेख किया गया है।

खान का प्रथम इतिवृत्त

45.1 खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा अपने नियंत्रण की जानों के के प्रथम वृत्त पत्र तथा पिछले सभी रिफाई को रखने से संबंध अपने कार्यालयों को दी गई हिरायतें विशिष्ट प्रकार की हैं। इतिवृत्त का होना आवश्यक है क्योंकि इसकी सहायता से सुसंगत नक्शों को देखकर खान के बारे में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। धरातल पर तथा जमीन के नीचे पानी भर जाने, ज्वलनशील गैस तथा भाग, आदि से खान में होने वाले खतरों को नोट कर लेना आवश्यक है और "खतरा-पुस्तिका" के रूप में इसे औद्योगिक कार्यालय में रखना आवश्यक है तथा सुर निरीक्षण अधिकारी को अपने पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन आने वाली जानों की सुरक्षा से संबंध एक अपरिवार नोट तैयार करना आवश्यक है। इस बात के होते हुए भी कि खान के पिछले रिफाई को देखे बिना कोई भी निरीक्षण नहीं किया जा सकता, निरीक्षण अधिकारियों को नदियों, नालों और बड़े तालाबों के आस-पास की जानों में पानी भर जाने के संभावित खतरे की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है और साथ ही हर साल मानसून के आने के पहले सभी पूर्वापार करने आवश्यक हैं।

मई के महीने में प्रबंधक वर्ग को फिर से याद दिला देना, सुरक्षात्मक उपायों की जांच करना तथा यह देखने के लिए पूरे बरसात के मौसम में भ्रमणक जांच करते रहना आवश्यक है कि जो कुछ भी पूर्वापाय निर्धारित किए गए हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसी हिदायत देते रहने का मतलब बिल्कुल साफ है। इसका पहला मतलब तो यह है कि खंभे तोड़ने से संबंधित आवेदन-पत्र की जांच करते समय इस आवेदन-पत्र में दिए गए तथ्यों का मिलान खान के प्रद्यतन वृत्त-पत्र एवं पिछले रिकार्डों कर लेना चाहिए। इसका दूसरा मतलब यह है कि ऐसे रिकार्डों की सहायता से खानों का निरीक्षण करते समय अधिकारी को घरातल तथा जमीन के अंदर के मुख्य लक्षणों से हमेशा अच्छी तरह से परिचित हो जाना चाहिए।

प्रबंधक वर्ग के आवेदन-पत्र पर विचार करते समय पूरी जानकारी के साथ व्यवस्थित ढंग से रखे हुए रिकार्डों को रांची के क्षेत्रीय कार्यालय के ध्यान में लाना चाहिए था—जैसे, खान के बिल्कुल पास एक बड़े नाल का होना और वास्तव में खंभे तोड़ने के स्थान के ठीक ऊपर नाल का होना। अतः खान सुरक्षा के उपनिदेशक श्री के० बी० मजूमदार के इस बयान को सुनकर अदालत को आश्चर्य हुआ कि खंभे तोड़ने से संबंधित आवेदन-पत्र पर विचार करते समय उनके पास खान का इतिवृत्त नहीं था। यदि उनके कार्यालय में इतिवृत्त को रखा नहीं जाता था या आवेदन पत्र पर विचार करते समय खान का इतिवृत्त नहीं था तो मुख्य कार्यालय से वह खान का वृत्त-पत्र भंगा सकते थे। पर यह काम भी नहीं किया गया।

निरीक्षण द्वारा सत्यापन

45.2 तिबूट के न होने पर मजूमदार को चाहिए था कि वे प्रबंधकों के आवेदन-पत्र में दी गई सूचनाओं का निरीक्षण करके ठीक ढंग से जांच कर लेते। पूछे जाने पर उन्होंने अदालत को यह बताया कि 27-6-74 को किए गए अपने निरीक्षण के दौरान प्रबंधक वर्ग के सांविधिक नक्शे (प्रवर्ग-बी) में 1958 के अधिकतम बाढ़ स्तर 288.34 मीटर पर उनका ध्यान गया था, पर इस बात की जांच करने के संबंध में कि क्या कोई ऐसा भी कंटूर था जिसका स्तर खंभे तोड़ने के क्षेत्र के स्तर से कम था, उन्होंने यह बताया कि बहुत अधिक झाड़-झंझड़ होने के कारण वह वहाँ स्वयं जाकर क्षेत्र की ढाल की जांच नहीं कर सके थे। अगले के बयान में उन्होंने यह कहा कि प्रबंधकों द्वारा उन्हें यह बताया गया था कि केवल 295.50 मीटर वाले एक कंटूर में उस मही की धीर, जिसका अधिकतम बाढ़ स्तर 288.34 मीटर था, जमीन की एक समान ढाल थी जिसे उन्होंने नक्शे में नोट कर दिया था। ऐसी स्थिति में वह प्रबंधकों से उनके सांविधिक घरातल नक्शे (प्रवर्ग 3) की मांग कर सकते थे, और यदि ऐसा किया गया होता तो उन्हें खंभे तोड़ने के प्रस्तावित क्षेत्र के अधिकतम जलस्तर से कम स्तर की एक दूर रेखा दिखाई पड़ गई होती। अदालत के सामने उन्होंने यह स्वीकार किया कि विसम्बर, 1974 में किए गए अपने भ्रम निरीक्षण के दौरान उन्होंने घरातल नक्शे को देखा तो था पर उन्होंने कंटूर प्राकृतियों की प्रबंधक वर्ग के आवेदन-पत्र के नक्शे में दिए गए कंटूर-प्राकृतियों के साथ मिलान नहीं किया था। ऐसा न करने का कारण उन्होंने यह बताया कि उन्होंने यह मान लिया था, जैसा कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति करता, कि घरातल नक्शे में दिखाई गई कंटूर रेखाएं प्रबंधकों के आवेदन-पत्र में अवश्य दिखाई गई होंगी। स्पष्टतः यह उनके द्वारा किया गया गलत निर्णय था क्योंकि आवेदन-पत्र की जांच करते पर उन्हें यह देख लेना चाहिए था कि नियम 59 (3) (क) में दिखाई गई कंटूर रेखाओं से नक्शे में दी गई कंटूर रेखाएं मेल नहीं खातीं। उस नियमन के अधीन प्रबंधक वर्ग को ऐसे नक्शे रखना अपेक्षित है जिनमें पांच मीटर से कम के ऊर्ध्वपर अंतरालों पर घरातल कंटूर रेखाएं दिखाई गई हों। अतः यह मान लेना तर्क संगत होगा कि जब भी कोई प्रबंधक वर्ग ऐसे क्षेत्र में खंभे तोड़ने के लिए आवेदन पत्र दे जिसका संबंध किसी मही नाले तथा उसके अधिकतम बाढ़ स्तर से हो, तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ दिए गए नक्शे में सभी कंटूर रेखाएं दिखायाना आवश्यक है।

विसम्बर 1974 में और मई तथा अगस्त, 1975 में श्री मजूमदार द्वारा किए गए निरीक्षण यदि उचित ढंग से किए गए होते तो उनके नज़र में वह छोटा नाला अवश्य आ गया होता जिसके ठीक नीचे खंभे तोड़े गए थे। जिसकी वजह से खान में बुर्बटना हुई थी। बुर्बटना होने के पहले उनके द्वारा किए गए निरीक्षण में नाले के किनारे बने हुए बांध की धीर उनका ध्यान अवश्य आना चाहिए। पर इस प्रसंग में उनकी वलील यह थी कि कभी भी नाला और बांध उनकी जानकारी में नहीं थे। इसका पहला मतलब यह हुआ कि प्रबंधक वर्ग की धीर से न तो मौखिक रूप में और न ही तथ्यों की सहायता से इन तथ्यों के बारे में उन्हें बताया गया था और दूसरा मतलब यह हुआ कि अपने निरीक्षण के दौरान इन तथ्यों की धीर उनका ध्यान कभी भी नहीं गया।

अनुमति मिलने के पहले ही खम्बे तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया था।

46.1 हालांकि अपने पहले ही वलीलों में सम्भवतः अदालत द्वारा न पूछे जाने के कारण यह बात उन्होंने अदालत को नहीं बताई थी, जिसका पता बाद में चला कि 13-12-74 को किए गए अपने निरीक्षण के दौरान वह मैनेजर के साथ हाथीदारी सीम देखने गए थे और वहाँ पर खम्बे तोड़ने के काम का निरीक्षण किया था। यह बात संयुक्त निदेशक श्री जे० सी० अग्रवाल अदालत की जानकारी में आए, जिन्होंने हवाले के लिए 13-12-74 की श्री मजूमदार की निरीक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत किया (प्रवर्ग एक-3 के पृष्ठ 1, 7 और 8 पर) यह बात जानते हुए भी कि खान सुरक्षा महानिदेशालय से अनुमति मिलने के पहले ही प्रबंधक वर्ग ने खम्बे तोड़वाने का काम शुरू कर दिया था—जिसका उल्लेख इस रिपोर्ट के पैरा 22.3 में किया गया है—उपनिदेशक को प्रस्तुत किए गए असांविधिक नक्शों के अनुसार ही केवल काम नहीं करना चाहिए था और इस बात को भी सही नहीं मान लेना चाहिए था कि प्रबंधकों ने आवेदन-पत्र के साथ संलग्न नक्शे में जो कुछ भी तथ्य दिए थे सही ही हैं।

मंजूरी फाइल में उल्लेख नहीं किया गया

46.2 आश्चर्य की बात है कि 13-12-74 को हाथीदारी सीम का निरीक्षण कर लेने के 3 दिन बाद जब उन्होंने सिफारिश के साथ खम्बे तोड़ने के आवेदन-पत्र की मंजूरी की फाइल को संयुक्त निदेशक के पास भेजा, उसमें उन्होंने इस बात का हवाला नहीं दिया था कि प्रबंधक वर्ग द्वारा खम्बे तोड़वाने का काम शुरू किया जा चुका था। जब उनसे यह पूछा गया कि इस बात को फाइल प्रवर्ग आर-9 में क्यों नहीं दर्ज किया था तो वे सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। उनकी वलील यह थी कि इस बात का उल्लेख वे अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में कर चुके थे और उन्होंने इस फाइल से इस बात का पुनः उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा जो खम्बे तोड़ने की मंजूरी से सम्बद्ध थी। यह पूछे जाने पर कि यदि उन परिस्थितियों में उनके वरिष्ठ अधिकारी उस निरीक्षण रिपोर्ट को देख लेते जिसमें अनुमति मिलने के पहले ही खम्बे तोड़ने का काम शुरू हो जाने का हवाला था, तो उनका कहना था कि 26 जून, 1975 को उनके पास रिपोर्ट भेज देने के बाद ही वे उसे देख पाते। जब उन्हें यह कहा गया कि जनवरी, 1975 को आवेदन-पत्र की मंजूरी करते समय संयुक्त निदेशक श्री अग्रवाल और निदेशक श्री एस० बी० प्रसाद को इस बात की जानकारी नहीं थी कि विसम्बर, 1974 से सम्भवतः एक-दो महीने पहले से ही प्रबंधक वर्ग ने खम्बे तोड़वाने का काम शुरू कर दिया था, श्री मजूमदार को यह कबूल करना पड़ा कि वे अपनी रिपोर्ट देर से भेजने के कारण अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रबंधक वर्ग द्वारा किए गए उल्लंघनों को नहीं ला सके। उन्होंने भागे यह कहा कि अधिक काम होने तथा रिपोर्ट को टाइप कराने में देरी होने के कारण ही उन्हें अपनी रिपोर्ट को जमा कराने में देरी हो गई।

मौखिक सूचना

46.3 जब उनसे यह पूछा गया कि जनवरी, 1975 से पहले अनधिकृत रूप से खम्बे तोड़ने का काम शुरू हो जाने की सूचना अपने

वरिष्ठ अधिकारियों को मौखिक रूप से क्यों नहीं बी थी तो श्री मजूमदार ने यह बताया कि ऐसा करने का मौका ही उन्हें नहीं मिल पाया था। जब उनसे यह कहा गया कि श्री भद्रवाल को इस बात की जानकारी थी कि जनवरी, 1975 से पहले ही अनधिकृत रूप से खम्बे तोड़ने का काम शुरू हो गया है और उन्होंने भद्रवाल को यह बताया है कि इस बात की चर्चा वे निदेशक श्री प्रसाद से कर चुके हैं और वे दोनों इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि इस मामले में प्रबन्धक वर्ग पर अभियोग लगाना उचित नहीं है, तो श्री मजूमदार ने इस बात को मानने से इन्कार कर दिया कि अनधिकृत रूप से खम्बे तोड़ने के बारे में उन्होंने श्री भद्रवाल से ग्रथवा श्री प्रसाद को मौखिक सूचना दे दी थी। श्री प्रसाद ने भद्रवाल के सामने अपना बयान देते हुए यह बताया कि श्री भद्रवाल ने न तो मुझे इस बात की सूचना दी थी और न ही मुझसे चर्चा की थी कि प्रबन्धक वर्ग खम्बे तोड़वाने का काम शुरू करवा चुका है।

भद्रवाल ने श्री मजूमदार को उनके द्वारा मौके पर की गई जाँच की बात बतायी जिसकी रिपोर्ट खान के प्रबन्धक द्वारा 20-12-74 को प्राप्त हुई थी। मौके पर की गई जाँच से वो बातों का पता चलता है जिनमें से एक का सम्बन्ध कार्यस्थल पर अग्रप्राप्त हवा के होने और दूसरे का सम्बन्ध फेंकों को स्प्रे करने के लिए किसी व्यवस्था का न होने से था। जब उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया था कि अनुमति मिलने के पहले वे ही प्रबन्धक वर्ग ने खम्बे तोड़वाने का काम शुरू कर दिया था तो इसके जवाब में श्री मजूमदार ने भद्रवाल को यह बताया कि उन्हें यह आशा थी कि खम्बे तोड़ने की अनुमति प्रबन्धक वर्ग को जल्दी ही दे दी जाएगी और इसी कारण से उनका यह विचार था कि ऐसा करने से किसी बात का उल्लेख नहीं हो रहा है। इस प्रसंग में उनकी दलील हमेशा यही रही कि खम्बे तोड़ने की अनुमति से सम्बन्ध फाइनल में, जिसे सितम्बर, 1974 में खोला गया था, केवल गलतियों को ठीक करने से सम्बन्ध प्रणों और विकास में प्रगति न होने के कारणों के बारे में थी। चूंकि वरिष्ठ अधिकारी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई थी और फाइनल में उठाए गए प्रणों पर 16-12-74 को उन्होंने कार्रवाई की थी। अतः इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि खम्बे तोड़ने की मंजूरी शीघ्र ही मिल जाएगी। यह एक ऐसी दलील है जिसे स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि 13-12-74 को हाथीदारी सीम का निरीक्षण करने के तीन दिन के बाद लिखे हुए नोट से इस बात की जानकारी मिल जाती है कि खम्बे तोड़ने का काम शुरू किया जा चुका है तो भद्रवाल केवल यह नहीं मान सकती कि इस सम्बन्ध में उनके वरिष्ठ अधिकारी किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते होते।

46.4 अनधिकृत रूप से खम्बे तोड़ने का काम शुरू करने के सम्बन्ध में खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान परस्पर विरोधी हैं। यदि श्री मजूमदार के बयान को सही मान लिया जाए तो उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वे इस बात को वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक नहीं समझते क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि खम्बे तोड़ने की अनुमति जल्दी ही मिल जाएगी और इस प्रसंग में प्रबन्धक वर्ग द्वारा किए गए उल्लेख को गम्भीर नहीं माना जा सकता। उनका तर्क यह था कि प्रबन्धक वर्ग के आवेदन-पत्र में जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए थे—वे सही थे, अतः खान में पानी भर जाने का कोई खतरा नहीं था। इसके विपरीत यदि श्री भद्रवाल के बयान को सही मान लिया जाए तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे और श्री प्रसाद दोनों ही अनधिकृत रूप से खम्बे तोड़े जाने के काम से अवगत थे लेकिन इस बात को वे गम्भीर उल्लेख नहीं मानते क्योंकि इसकी वजह से खान में पानी भर जाने का खतरा नहीं हो सकता था। वास्तव में श्री भद्रवाल ने भद्रवाल को बताया कि जब अनधिकृत रूप से खम्बे तोड़े जाने का काम शुरू करने के बारे में 15 या 16 दिसम्बर, 1974 को श्री मजूमदार से उन्हें जानकारी मिली थी, उस समय उनका मत यह नहीं था कि एक खम्बे को तोड़ना गम्भीर

मामला है। अपने बयान में उन्होंने भद्रवाल को यह भी बताया कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी सद्भावना में काम करते हैं और प्रबन्धक वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि क्योंकि प्रबन्धक वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर खान में पानी भरने का खतरा नहीं है, इसलिए उन्होंने आंकड़ों को सही मान लिया था। श्री भद्रवाल ने यह भी बताया कि इस मामले की चर्चा उन्होंने श्री प्रसाद से की थी जिन्होंने एक सहृदय व्यक्ति होने की वजह से श्री भद्रवाल से यह कहा कि आवेदन-पत्र पर कार्रवाई तुरन्त कर देनी चाहिए जिससे कि शुरू किए गए खम्बे तोड़ने के काम को नियमित किया जा सके। इस मामले में श्री प्रसाद की दलील यह थी कि प्रबन्धक वर्ग द्वारा दी गई सूचना पर उन लोगों का पूरा विश्वास है और वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि एक राष्ट्रीयकृत प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना में किसी बात की छिपाया गया है।

भद्रवाल यह अनुमान करती है कि ऊपर बताए गए आधार पर ही श्री प्रसाद ने उस समय सांविधिक नक्शों को नहीं देखा था जबकि वे हाथीदारी के कीयला सीम के क्षेत्र में खम्बे तोड़ने के काम का निरीक्षण करने के लिए अग्रवानक गए थे। यह निरीक्षण, प्रदर्श-एफ, 12-2-75 को अर्थात् खम्बे तोड़ने का काम शुरू करने की अनुमति मिलने के लगभग 40 दिन बाद किया गया था जबकि इस दौरान में खम्बे तोड़ने से सम्बन्ध सुसंगत सांविधिक नक्शों का कोई भी अध्ययन कर सकता है। केवल हाथ से बनाए गए नक्शों को देखकर ही वे सन्तुष्ट हो गए थे जिनमें उनके अनुसार कोई भी नाज़ा नहीं दिखाया गया था।

जिस निहितार्थ का वास्तव में महत्व है और जिसे ऊपर कही गई बातों के आधार पर निकाला गया है, यह है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि प्रबन्धक वर्ग के आवेदन-पत्र में जो कुछ भी तथ्य दिए गए हैं वे पूरी तरह से प्रमाणिक एवं सही थे।

आवेदन-पत्र की छानबीन

47.1 प्रबन्धक वर्ग के प्रति ऐसी धारणा न केवल रांची के अधिकारियों की ही थी बल्कि धनबाद के खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों की भी यही भावना थी। धनबाद के खान सुरक्षा महानिदेशालय के उपनिदेशक की श्री एस० भार० सरकार ने, जिन्हें मंजूरी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजने के पहले आवेदन-पत्र का अध्ययन करना था, भद्रवाल को यह बताया कि यदि प्रबन्धक वर्ग के आवेदन-पत्र में किसी असामान्य बात का उल्लेख न हो और नक्शे से किसी बात का पता न चलता हो तो स्वाभाविक है कि मुख्य कार्यालय में बैठकर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आवेदन-पत्र या नक्शे में कोई चीज छूटी हुई है। आगे उन्होंने यह बताया कि स्वयं आवेदन-पत्र में दिए गए तथ्यों के आधार पर आवेदन-पत्र की जाँच की जाती है न कि विनियम 60 के अधीन प्रबन्धक वर्ग द्वारा मुख्यालयों को दिए गए अद्यतन नक्शों के किसी सन्दर्भ के आधार पर। यदि यह मान लिया जाए कि किसी क्षेत्रीय अथवा जोनल कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही के लिए आवेदन-पत्र भेजने का उद्देश्य केवल आवेदन-पत्र और नक्शे का इस दृष्टि से अध्ययन करना है कि देखते ही वे क्रम में नजर आते हैं कि नहीं, तो भी भद्रवाल का यह निश्चित मत है कि मुख्यालय में रखे गए रिकार्डों के किसी सन्दर्भ के बिना आवेदन-पत्र की साधारण छानबीन करने पर भी आवेदन-पत्र और नक्शों में कुछ असंगति मिल सकती है। मिसाल के तौर पर, इस बात की ओर ध्यान जा सकता था कि प्रबन्धक वर्ग के नक्शे में नदी दिखाई गई है पर यह नहीं बताया गया है कि नदी के किनारे की ऊँचाई कितनी है जब जल स्तर से कम है या अधिक और यह भी नहीं बताया गया है कि कन्टूर की ऊँचाई कितनी है जो अधिकतम बाढ़ स्तर है।

मंजूरी की छानबीन

47.2 यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रारम्भ में आवेदन-पत्र की साधारण छानबीन बहुत आवश्यक नहीं समझी जाती, फिर भी खान सुरक्षा महानिदेशालय के अपने अनुदेश के अनुसार और जिसे मुख्यालय के समर्थन से श्री प्रसाद ने भी यह अनुदेश दिया था कि आवेदन-पत्र की मंजूरी से सम्बद्ध पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर इस बात से मुनिश्चित होने के लिए आवेदन-पत्र की जांच क्रम से करना आवश्यक है कि क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से कोई महत्वपूर्ण तथ्य तो नहीं छूट गया है और अनुमति उचित ढंग से दी गई है। अतः विनियम 60 के उपबन्धों का ज्ञान रखते हुए तथा यह जानते हुए भी कि मुख्यालय के पास सेट्टल्य सीदा कोविचरी के प्रदर्श 5, यू-1, यू-2 आदि जैसे नक्शे हैं जिनमें अधिकतम बाड़ स्तर, बड़ा नाला और कन्दूरी को दिखाया गया है, अदालत यह पता लगाना चाहती है कि क्या मुख्यालय ने उसके पान उपनब्ध सूचना के सन्दर्भ में रांची से प्राप्त मंजूरी पत्र की जांच की थी कि नहीं। श्री सरकार के हम उत्तर को सुनकर अदालत को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मंजूरी-पत्र की जांच तो की थी पर खान के वृत्त अथवा नक्शों के सन्दर्भ के बिना ही उन्होंने जांच की थी। यहाँ तक कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के फाइल, प्रदर्श-5 में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि मुख्यालय में अनुमति-पत्र पर किम प्रकार की जांच की गई थी। फाइल में 27 जनवरी और 28 जनवरी, 1975 की टिप्पणियों में केवल इस बात का ही उल्लेख किया गया था कि मंजूरी-पत्र को रजिस्टर में रिकार्ड कर लिया जाए। इन तथ्यों से भी इसी बात का पता चलता है कि मुख्यालय में भी व्यवहारतः यह मान लिया जाता है कि आवेदन-पत्र में दिए गए सभी तथ्य हमेशा सही होते हैं जबकि सारा अनुदेश यह दिया गया है कि मंजूरी पत्रों की जांच करने समय काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

खान सुरक्षा महानिदेशालय में कठिनाइयाँ

47.3 अदालत में बुलाए गए खान सुरक्षा महानिदेशालय के क्षेत्र अधिकारियों की सामान्यतः मुख्य वसील यह थी कि उनके पास काफी संख्या में नक्शे होने के कारण तथा किसी एक खास खान में अनेक कोयला सीमों पर काम होते रहने के कारण प्रत्येक बात की जांच करके किसी आवेदन-पत्र का सही होना निश्चित करना उनके लिए असम्भव है और साथ ही सभी खानों के बारे में सभी स्पौरवार बातों को ध्यान में रखना उनके लिए काफी कठिन होता है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या उन्होंने इस बात से महानिदेशक को परिचित कराया है तो उनका उत्तर था कि उनके काम करने के इस ढंग से महानिदेशक अवगत परिचित हैं। अदालत यह अनुभव करता है कि ऐसी परिस्थितियों में जबकि निरीक्षण संगठन में स्टाफ की कमी है, महानिदेशक को क्षेत्र-अधिकारियों की कार्य-प्रणाली के बारे में व्यावहारिक लिखित अनुदेश तैयार करें। मुख्यालय के स्टाफ के सम्बन्ध में, जिन्हें भी श्री सरकार के अनुसार अत्यधिक संख्या में आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ होती हैं, उनके कार्य करने के बारे में एक व्यावहारिक कार्य-प्रणाली तैयार करें।

विनियम 60 का उल्लंघन

48. अदालत को खान सुरक्षा महानिदेशालय में एक अन्य प्रकार के धारमतोष की भावना भी देखने को मिली। कोयला खान विनियमावली के विनियम 60 के अधीन प्रबन्धक वर्ग की हर साल 31 अक्टूबर तक खान के जमीन के अन्दर के ऐसे नक्शे की दो प्रतियाँ खान सुरक्षा महानिदेशालय को भेजना आवश्यक है जिसमें अन्य बातों के अलावा कार्य-स्थल के किसी भाग से क्षैतिज समतल में 200 मीटर के अन्दर स्थित नदी, सरिता, जलमार्ग आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण धरातल लक्षण दिखाए गए हों। धनबाद के खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्राप्त दो प्रतियों में से एक प्रति उन क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजने के लिए होती है जिनके

कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ये खान आती हैं और इन कार्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे खान के इतिवृत्त के साथ इस प्रति को एक अलग फोल्डर में रखें। विनियम 60 को हटाने का एक प्रस्ताव (प्रदर्श 9) किया गया था, जिसे हटाना खान सुरक्षा महानिदेशालय आवश्यक समझता था, पर अदालत ने यह पाया कि अप्रैल, 1960 में सरकार ने इस प्रस्ताव को तामंजूर कर दिया था। ऐसा हो जाने के बाद प्रबन्धक वर्ग द्वारा नक्शों को न जमा कराने पर उनके प्रति नरम रवैया नहीं अपनाया चाहिए और उन्हें इस बात को मुनिश्चित कराना चाहिए कि प्रतिवर्ष अद्यतन भूमिगत नक्शों की दो प्रतियाँ नियमित रूप से प्राप्त हो रही हैं जिससे कि उनमें से एक प्रति की वे अपने रांची के कार्यालय को भेज सकें। यदि ऐसा किया गया होता तो क्षेत्रीय कार्यालय से कम से कम कागज पर ही एक बड़े नाले की मौजूदगी से हमेशा परिचित रहते और तब ऐसी स्थिति में इस नाले के नीचे तथा आसपास के क्षेत्र में खन्वे तोड़ने की मंजूरी देते समय काफी सतर्क रहते। इस मामले में सम्भवतः 31-10-74 को समाप्त होने वाले वर्ष के भूमिगत नक्शे की एक प्रति को और निश्चित रूप से 31-10-75 को समाप्त होने वाले वर्ष के भूमिगत नक्शे की एक प्रति से इस बात का भी पता चल गया होता कि उस क्षेत्र के ऊपर एक छोटा नाला बह रहा है जिसका विस्तम्भन किया जाता था और विस्तम्भन हो भी रहा था। अथवा भी, खान-क्षेत्र के अन्दर और उसके आस-पास नदी-नाले जैसे महत्वपूर्ण लक्षणों की जानकारी निरीक्षण-अधिकारियों को होनी चाहिए थी जिससे कि वे इनकी जानकारी प्रबन्धक वर्ग द्वारा खन्वे तोड़ने की कार्रवाई के दौरान दे सकते।

खान सुरक्षा महानिदेशालय की दुर्घटना रिपोर्टें

49. यदि खान के इतिवृत्त अथवा उनके द्वारा वर्षों किए गए निरीक्षणों के सन्दर्भ में क्षेत्र अधिकारी तथा क्षेत्र कार्यालय के सन्दर्भ में क्षेत्र अधिकारी तथा क्षेत्र कार्यालय विकसित क्षेत्र तथा खन्वे तोड़ने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास एक बड़ा नाला होने की जानकारी न दे पाए हों, तो भी कम से कम उनकी इस कमी को खान सुरक्षा महानिदेशालय की दुर्घटना रिपोर्टें में दर्ज किया जा सकता था। दुर्घटना से सम्बद्ध परिस्थितियों के बारे में की गई जांच की यह रिपोर्टें 22-12-76 को प्रकाशित हुई।

रिपोर्टें प्रस्तुत करते समय इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के पान जल किया गया खान का सांख्यिक नक्शा (प्रदर्श डी) था जिसमें यह बिखलाया गया था कि खन्वे तोड़ने का काम बड़े नाले के ठीक नीचे तक पहुँच गया है। इसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि खन्वे तोड़ने के काम के अलावा उन वर्षों में प्रबन्धक वर्ग को उस सीमा तक जातीयदारी सीमा को विकसित करने की अनुमति भी खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों को नहीं देनी चाहिए थी लेकिन इस बात का उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया गया है। रिपोर्ट का अनुबन्ध 'ग', जो उस धरातल का नक्शा है जिसमें होकर बाड़ का पानी खान में घुसा था और जिसे प्रदर्श 'क' के रूप में अंकित किया गया है, बड़े नाले को प्रदर्शित करता है लेकिन रिपोर्ट में इस बात का कोई भी प्रतिमन्वर्भ नहीं दिया गया है। रिपोर्टें प्रस्तुत करते समय ऐसे प्रतिमन्वर्भ का दिया जाना अपेक्षित है। हालांकि नक्शा इस बात को प्रदर्शित नहीं करता कि नाले के ठीक नीचे खन्वे तोड़ने का काम किया गया था। इसका उल्लेख न करने का कारण सम्भवतः यह था कि दुर्घटना के तुरन्त बाद भूमिगत सर्वेक्षण करना आसान काम नहीं था, फिर भी नक्शे से इस बात का पता तो चल ही जाता है कि खन्वे तोड़ने वाले क्षेत्र से लगभग 15 मीटर की आसपास की दूरी में नाला है। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया जा सकता था कि खन्वे तोड़ने के काम की अनुमति गलती से दे दी गई है और मंजूरी देने के बाद किसी भी निरीक्षण अधिकारी का ध्यान इस बात की ओर नहीं गया था कि वास्तव में खन्वे तोड़ने का काम बड़े नाले के आस-पास और नीचे बढ़ता जा रहा था और छोटे नाले के तो ठीक नीचे भी हो

रहा है। यह कहना तो काफी कठिन है कि दुर्घटना रिपोर्ट में—जिसे उस समय के खान सुरक्षा महानिदेशालय के निदेशक श्री एम० डी० प्रसाद की देखरेख में तैयार किया गया था—इन दो नालों और खान तौर पर उनके नीचे किए गए खम्बे तोड़ने के काम का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया था ताकि यह साबित हो सके कि खान में घटी दुर्घटना में खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों का हाथ नहीं था। लेकिन यदि यह मान भी लिया जाए कि बात ऐसी नहीं थी तब भी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया जा सकता था कि खम्बे तोड़ने की अनुमति देते समय इस तथ्य की ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं गया था कि सीम पर विकास का काम बड़े नाले के पास तथा उसके नीचे तक पहुंच गया था और खम्बे तोड़ने का काम इस बड़े नाले के आसपास, उसके नीचे तक तथा छोटे नाले के तोड़ीक नीचे हो रहा था। लेकिन निरीक्षण के दौरान कभी भी इन बातों का पता नहीं चल पाया था और यदि पता लग भी जाता तो हालात ऐसे थे कि निरीक्षण अधिकारियों के इस कल्पना के आधार पर सम्भवतः इसकी उपेक्षा कर दी गई होती कि सेन्ट्रल सीधा कोलियरी में बाढ़ का पानी घुसने का कभी भी अन्वेषण नहीं है।

जब उस समय के खान सुरक्षा महानिदेशालय के संयुक्त निवेशक श्री ए०एन० मुखोपाध्याय से, जिन्होंने दुर्घटना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, पूछा गया तो उन्होंने अदालत को यह बताया कि उनके द्वारा की गई जांचों में ग्राम कार्यप्रणाली उन तथ्यों एवं उल्लंघनों का पता लगाना तथा उन पर ही ध्यान केन्द्रित करता होता है जो प्रत्यक्ष रूप से दुर्घटना के कारण होते हैं। दुर्घटना जांच रिपोर्ट में प्रत्येक उल्लंघन का उल्लेख नहीं किया गया है। उनके अनुसार खान में पानी बड़े नाले से बहकर नहीं बलिक छोटे नाले से बह कर घुसा है और रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि खम्बे तोड़ने की अनुमति प्राप्त करने के खान सुरक्षा महानिदेशालय में दिए गए नक्शे में प्रबन्धक वर्ग ने यह नहीं दिखाया है कि खम्बे तोड़े जाने वाले क्षेत्र के ऊपर होकर छोटा नाला बह रहा है।

हालांकि यह बात तो सही है कि छोटे नाले के नीचे खम्बे तोड़े जाने के कारण ही (जिसका उल्लेख लिखित रूप में खान सुरक्षा महानिदेशालय को प्रबन्धक वर्ग ने नहीं किया है) सीम में पानी भर गया था फिर भी दुर्घटना रिपोर्ट में खान सुरक्षा महानिदेशालय के अपने अनुदेशों के अनुसार दुर्घटना से संबंधित खानों में अपनाई जाने वाली कार्य-प्रणाली आधारभूत सूचना का उल्लेख किया जा सकता था। बूँकि खम्बे तोड़ने के काम का सीम के विकास के साथ सीधा संबंध है इसलिए जिस गलत ढंग से इसे विकसित किया गया था निरीक्षण-अधिकारियों द्वारा अवश्य देख लेना चाहिए था, या उस समय मंजूरी मिलने के पहले ही खम्बे तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया था, इन बातों का उल्लेख दुर्घटना रिपोर्ट में नहीं किया गया है जबकि रिपोर्ट में क्रम से उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया जा सकता था जिनकी वजह से वास्तव में खान में दुर्घटना हुई थी।

भाग-5

निष्कर्ष

50. जब कोई दुर्घटना होती है तभी दुर्घटना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध कोयला खान विनियमों के अनेक पिछले उल्लंघन खुलकर सामने आते हैं।

इस मामले में अदालत ने उन घटनाओं का उल्लेख कालानुक्रम में किया गया है जिनकी वजह से सेन्ट्रल सीधा कोलियरी में दुर्घटना हुई थी। पहला, हाथीदारी सीम जिसका विकास पांस के एक बड़ा नाला होने की बात की उपेक्षा करके किया गया था। दूसरा, बड़े नाले के पास तथा सीधे विकसित क्षेत्र में खम्बे तोड़ने का काम करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रबन्धक वर्ग द्वारा दिया गया आवेदन पत्र। तीसरा, बांध में जानकारी मिल जाने के बाव भी कि खम्बे तोड़े जाने वाले क्षेत्र

के ठीक ऊपर एक छोटा नाला बह रहा है, खम्बे तोड़ने का काम जारी रखना और साथ ही इस तथ्य का निम्न रूप में खान सुरक्षा महानिदेशालय को सूचित न करना। चौथा, खान में जात बाढ़ का अधिकतम जलस्तर की उपेक्षा का होना। पाचवां, बरसात के मौसम में चकते हुए पानी के स्तर पर, खामतीर से पानी की भीतर घुसने से बचाव के लिए स्वयं प्रबन्धक वर्ग द्वारा बनाए गए तटबन्ध के पास नियमित रूप से चौकसी न करना और अन्त में, सुसंगत सुरक्षा पूर्वापार्यों को बरतने में शिथिलता दिखाना। बूँकि यदि सुरक्षा पूर्वापार्य किए जाते तो पानी का स्तर बढ़ने देखकर हाथीदारी सीम में आदिमियों को भेजने से रोका जा सकता था तथा उन लोगों को बाहर बुलाया जा सकता था जो सीम में पप चलाने का काम लगासार कर रहे थे।

51. ऊपर उल्लेख की गई विफलताओं के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य आते हैं :—

घरातल के पानी से जलमग्न होने के खतरे से संबद्ध कोयला खान विनियमों का प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया गया उल्लंघन; खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों से संबंधित खान के उचित तथ्यों और सेवकों को उचित ढंग से न रखना और उन नक्शों को नियमित रूप से न चेक करने रहना जो हाथीदारी सीम में भूभौतिक कार्य स्थलों को प्रदर्शित करते हैं।

हालांकि इस बात को तथा अन्य बातों को पूरा करने में प्रबन्धक वर्ग असफल रहा है, लेकिन खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों के मन में यह बात नहीं बैठ जानी चाहिए थी कि खम्बे तोड़ने से संबद्ध आवेदन-पत्र एवं नक्शे में जो कुछ भी उल्लेख किया गया है वह बिल्कुल सही है। खान का खम्बे समय तक परीक्षण करते रहने के साथ-साथ अपने ज्ञान और अनुभव से जल मार्ग तथा बाढ़ का अधिकतम जल स्तर जैसे सुसंगत तथ्यों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए था, और अपने सामान्य एवं विशेष निरीक्षणों के दौरान बड़े और छोटे नाले तथा काम चलाऊ बांध को देखने में तथा हाथीदारी सीम में खम्बे तोड़ने के काम पर इन सखणों के बुरे प्रभावों को समझने में बूझता नहीं चाहिए था। अदालत की नजर में यह बात प्राची है कि अपने कार्यकाल के दौरान जब खान सुरक्षा महानिदेशालय का उपनिदेशक हजारीबाग जिला के कुछ भाग में, पूरे रांची में, पूरे पलामू जिला तथा उत्तरांचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा तक फैले हुए क्षेत्र में स्थित 22-26 कोलियरी तथा 70-110 अन्य खानों को अपने कार्यभार के अधीन रख सकता है तब ऐसी परिस्थिति में निरीक्षण अधिकारियों को उनके लिए निर्धारित सभी ज्यूरिस्डिक्शन अनुदेशों का अवरोध पालन करना पड़ेगा और यह देखने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा कुछ कदम उठाने होंगे कि निरीक्षण संगठन की कार्यप्रणाली इस प्रकार की हो कि वह सभी अनुदेशों का पालन उचित ढंग से कर सके और यह भी देखना होगा कि स्टाफ की कमी तो नहीं है।

52. किसी भी जांच के दौरान विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों से संबंधित प्रबन्धक वर्ग या अन्य किसी व्यक्ति के लिए यह अस्वाभाविक नहीं है कि वह अपने बचाव के लिए अपने विचार से ऐसे तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत करे कि दुर्घटना में उसका कोई हाथ नहीं था। पर इसे सैद्धांतिक रूप से अथवा किसी अन्य ढंग से करने पर इनकी जांच करने में अदालत को काफी समय लग जाता है। उदाहरण के लिए यह तर्क दिया जा सकता है कि पनरातु बांध से अत्यधिक मात्रा में पानी का विसर्जन होने के कारण ही खान में पानी भर गया था। इस प्रकार के अन्य तर्क भी हैं जिनकी जांच करने पर अनेक विरोधात्मक तथ्यों और कमियों का पता चला जो दुर्घटना के साथ अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के बावजूद खान में नहीं पाई जानी चाहिए।

53.1 यद्यपि इस मामले में विभिन्न उल्लंघनों का उल्लेख किया गया है फिर भी यदि प्रबन्धक वर्ग गौफ के निकटवर्ती तटबन्ध पर बढ़ते हुए पानी के स्तर का अज्ञान समय पर से लेता तो हाथीदारी

सीम में काम कर रहे अनेक लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था। लेकिन इस सम्बन्ध में खान की सुरक्षा के बारे में भी प्रबन्धकर्ता ने कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की थी। खान में घुसने वाले घरातली पानी से संबंधित सुरक्षा को वह प्रमुखता एवं महत्व नहीं दिया गया जिसका उल्लेख कोयला खान विनियमों के विनियम 41ए में और 190 में दिया गया है। इन सभी बातों के होते हुए भी संभावित बाढ़ के बारे में स्वयं प्रबन्धकर्ता को अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि विनियमों का स्वरूप व्यापक है और उनमें उन सभी उपायों का उल्लेख नहीं किया जा सकता जो कि विभिन्न विशेष खान में कुछ विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होते हैं।

53. 2 सुरक्षा अधिकारी तथा उसके काम में सहायता देने वाले अधिकारी को खान सुरक्षा महानिदेशालय से अनुमति लिए बिना ही, खान से कोयला उत्पादन से सम्बन्ध कार्य सौंपने का मतलब यह था कि सुरक्षा के महत्व को कम कर दिया गया था और खान में होने वाली दुर्घटना को घटाने के लिए पूरी तरह से उचित कार्रवाई करने में हम अधिकारियों के धांधल को कम कर दिया गया था।

16 सितम्बर को एक बरिष्ठ ओवरमैन से जलस्तर पर नजर रखने के लिए कहा गया था। पर वह इस कार्य को प्रभावी ढंग से कभी भी नहीं कर सका क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था जिससे वह बढ़ते हुए पानी के स्तर को ठीक-ठीक माप सके। यदि बांध के पास कोई बैचमार्क अथवा खंभा होता तो वह प्रबन्धक को 11 घंटे पूर्व ही जल स्तर में हुई ठीक-ठीक वृद्धि के बारे में सूचित कर सकता था—हालांकि उस ओवरमैन के बयान के अनुसार जलस्तर में वृद्धि बहुत ही कम थी। लेकिन जो कुछ भी तथ्य प्राप्त हुए, उनसे प्रबन्धक स्वयं कोई न कोई निष्कर्ष निकाल सकते थे। ओवरमैन हाथीवारी गोफ पर भी जहाँ से पानी घुस जाने का खतरा था लगातार नजर नहीं रख सकता था क्योंकि उसे तीन अन्य गोफों का भी निरीक्षण करना था जिससे कि वह उनके आस-पास के नाले-नालियों की जांच कर सके और यदि आवश्यक हो तो उनकी मरम्मत भी कर दे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बांध पर बढ़ते हुए पानी के स्तर पर निरन्तर नजर रखने के लिए वह हाथीवारी गोफ पर हर समय उपस्थित नहीं रह सकता था। इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि उसको दिए गए अनुप्रेष और जो कुछ उसने देखा और किया सभी टरकाऊ प्रवृत्ति के थे और 16 सितम्बर को बढ़ते हुए पानी के स्तर पर भी किसी रखकर सुरक्षा की दृष्टि से कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। यदि यह देख लिया गया होता कि पानी बांध के आधार से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो गया है और 1108 फुट, 1110 फुट या 1112 फुट के जलस्तर को छू रहा है, और यदि उन जलतलों से सम्बद्ध व्यक्तियों की बाहर बुला लेने के कुछ खास अनुप्रेष दिए गए होते तो वर्कमैनों को हाथीवारी सीम में नहीं भेजा जाता था जो भी उस सीम में काम कर रहे थे उन्हें बाहर बुला लिया गया होता। ऐसी स्थिति में हाथीवारी गोफ से होते हुए पानी सीम में प्रवेश घुस गया होता पर उस सीम में जल-पंप को शिफ्ट करने में लगे हुए व्यक्तियों की जाने नहीं जाती।

54. खान में संभावित बाढ़ से सम्बन्ध विभिन्न प्रकार की सुरक्षा के काम में लगे हुए अनेक व्यक्तियों ने अपनी भूमिका पूरी वक्षता के साथ नहीं निभाई। यदि उन लोगों ने अपने कार्यों को पूरी वक्षता के साथ किया होता तो खंभे तोड़ने के काम में पिछली कमियों तथा दोषों के होते हुए भी खान में दुर्घटना नहीं हो सकती थी। खान सुरक्षा महानिदेशालय का मुख्य काम ही सुरक्षा है, अतः ऐसे मामले में उसे अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। पर इस मामले में जो गलतियाँ हुई हैं उसका मुख्य उत्तरदायित्व प्रबन्धकर्ता पर है, जिसने खान में संभावित बाढ़ से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कोई भी विशिष्ट व्यावहारिक कदम न तो उठाए और न ही कोई खास कार्य-प्रणाली निर्धारित की। चूंकि स्वयं खान-ओवर में छोटे-बड़े नाले हैं, जो पास की एक बड़ी सहायक

नदी में गिरते हैं जो पास ही बह रही दामोदर नदी में जाकर मिलती है, तो ऐसी स्थिति में खान में पानी भर जाने को संभावना जैसे मामले में कोई शिथिलता नहीं होनी चाहिए। नदी के ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित बांध नियमित ढंग से पानी विसर्जित करने के लिए है लेकिन यदि नियमानुसार जल-विसर्जन किया भी जाए फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि दामोदर नदी के जल स्तर में वृद्धि नहीं होगी और उसका पानी लौट कर नहीं आ सकता। हालांकि 16 सितम्बर को पतरातू बांध से नकारी नदी में कुछ अधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया था फिर भी खान में हुई दुर्घटना का मात्र मुख्य कारण यही नहीं था। पतरातू तान बिजगोधर प्राधिकारियों को कभी भी इस बात से नजरअन्दा नहीं करना चाहिए था कि नकारी नदी के किनारे बहुत सी खानें हैं। उन्हें पहले से ही प्रबन्धकर्ता को पतरातू बांध से अधिक मात्रा में पानी छोड़ने के बारे में सावधान कर देना चाहिए।

55. मैं यह निवेश देता हूँ कि सेंट्रल सौदा कोलियरी का प्रबन्धन इस जांच में पूरे खर्चे को वहन करे। खर्च का हिसाब खान सुरक्षा महानिदेशालय लगाए और यह खर्च लेखा परीक्षा के बाव प्रबन्धक से वसूल किया जाए।

56. अमार : मैं जांच अवालत को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा नामित को असेसर प्रोफेसर एस० एस० सलूजा और श्री एस० दास गुप्ता का आभारी हूँ। इन्होंने दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों के निर्धारण करने में काफी सहायता तो की है और रिपोर्ट को तैयार तथा पूरा करने में भी सहयोग दिया है।

अवालत के सचिव श्री सतपाल सिंह ने पूरी जांच के दौरान काफी लगन से काम किया और श्री पी०के० भाटिया ने, जिन्होंने गवाहों के बयान रिकार्ड किए, पूरी सक्षमता के साथ काफी संतोषजनक ढंग से काम किया।

मैं खान सुरक्षा महानिदेशालय और प्रबन्धकर्ता को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने रांची में जांच कार्य करने से संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान कीं।

(एन० पी० बुबे)

भूतपूर्व अम सचिव, भारत सरकार
जांच-अवालत

नई दिल्ली,

22 दिसम्बर, 1978

(प्रो० एस० एस० सलूजा)

निवेशक, इस्टीमेट ग्राफ टैक्नालाजी
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
असेसर,
(एस० दास० गुप्ता), महासचिव
इण्डियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन
असेसर

खण्ड-2

अनुबन्ध-1

मृतकों के नाम

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. श्री के० पांडे | फोरमैन प्रशिक्षु (बिजली तथा मैके०) |
| 2. श्री त्रिभुवन प्रसाद साह | बिजली हैण्डर |
| 3. श्री राजदेव घरीर | टिबल |

4. श्री रामनाथ	पम्प खलासी
5. श्री ईंदरीस	मैकेनिक फिटर
6. श्री सीताराम साहू	इलैक्ट्रिशियन
7. श्री किशुन	टिडल
8. श्री भूले	टिडल
9. श्री शिरजू पासो	पम्प हैल्पर
10. श्री फकीर मुहम्मद	फिटर हैल्पर

अनुबंध 2

पार्टी नं० 1 (प्रबन्धक वर्ग) की ओर से अयान देने वाले गवाहों की सूची

1. श्री बलबिंदर सिंह	पंप क्लीनर
2. श्री अभिलाष यादव	टिडल
3. श्री कुचन सिंह	टिडल
4. श्री पी०के० दास	प्रबन्धक, सौदा "डी" कोलियरी
5. श्री आर० चौबे	वरिष्ठ कार्यपालिका इंजीनियर (ई० एण्ड एम०) सौदा 'डी' कोलियरी
6. श्री एन० नायक	कार्यपालक इंजीनियर (ई० एण्ड एम०) सेंट्रल सौदा कोलियरी ।
7. श्री के० के० गुप्ता	भवन प्रबन्धक, सेंट्रल सौदा कोलियरी
8. श्री ए० कुंडू	वरिष्ठ कार्यपालक, इंजीनियरी, सेंट्रल सौदा कोलियरी
9. श्री ओ० एन० शर्मा	फोरमैन तथा प्रभारी, बिजली, सेंट्रल सौदा कोलियरी
10. श्री ए०के० सेनगुप्ता	बिजली सर्वेक्षक, सेंट्रल सौदा कोलियरी
11. श्री सीताराम रणक	ठेकेदार का मजदूर
12. श्री नागेश्वर साहू	यांत्रिक फिटर, सेंट्रल सौदा कोलियरी
13. श्री प्रताप कुमार मजूमदार	सर्वेक्षक, सेंट्रल सौदा कोलियरी
14. श्री बी० पी० बालिया	अधीक्षक इंजीनियर, सी०एम०पी०डी०आई०
15. श्री एस० के० दत्त चौधरी	सुरक्षा अधिकारी, सेंट्रल सौदा कोलियरी
16. श्री जीत सिंह	ओवरमैन, सेंट्रल सौदा कोलियरी
17. श्री एस० एन० चटर्जी	प्रबन्धक एन०सी०डी०सी० सौदा कोलियरी
18. श्री छत्रधारी	समयपाल, सेंट्रल सौदा कोलियरी
19. श्री दिलजान	पंप खलासी, सेंट्रल सौदा कोलियरी
20. श्री सुखदेव राज शर्मा	सहायक कोलियरी प्रबन्धक, सेंट्रल सौदा कोलियरी
21. श्री के० चोरेस्वामी	प्रबन्धक, सेंट्रल सौदा कोलियरी
22. श्री बी० मेवाड़	एजेंट, सेंट्रल सौदा कोलियरी (17-12-73 से 3-8-76 तक)
23. श्री एस० के० मुखर्जी	एजेंट, सेंट्रल सौदा कोलियरी (3-8-76 से)
24. डा० आर० कुमार	अधीक्षक (खान) सी०एम०पी०डी०आई०

पार्टी नं० 3 (पतरातू ताप बिजलीघर)

1. श्री सतीश चन्द्र	सहायक इंजीनियर, पी०एच०ई०डी०
2. श्री वामुदेव सिंह	पंप खलासी, काफर बांध
3. श्री रामाधर सिंह	सहायक पंप प्रचालक, पी०एच०ई०डी०
4. श्री हीरालाल ठाकुर	पंप प्रचालक पी०एच०ई०डी०, काफर बांध
5. श्री हीरा प्रसाद सिंह	सहायक पंप प्रचालक, पी०एच०ई०डी०, फिल्डेशन प्लांट
6. श्री प्रभाशंकर बाजपेयी	अधीक्षक (बिजली), बी०ए०एस०एल०
7. श्री रामाधर प्रसाद	कनिष्ठ इंजीनियर, पी०एच०ई०डी०, पतरातू
8. श्री एस० एन० बाला	पंप प्रचालक, ग्रेड 2, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

अवालत

1. श्री धीरेन्द्र नाथ माजी	सहायक इंजीनियर, पी०एच०ई०डी०, पतरातू
2. श्री एन० कारकेटा	महाप्रबन्धक-9, मुख्य इंजीनियर, पतरातू ताप बिजलीघर
3. श्री ज्योती नारायण प्रसाद	खंड विकास अधिकारी, पतरातू
4. श्री कृष्णनन्द तिवारी	बिजली हैल्पर, सेंट्रल सौदा कोलियरी
5. श्री के० बी० मजूमदार	खान सुरक्षा उप निदेशक
6. श्री एस० डी० प्रसाद	खान सुरक्षा महानिदेशक
7. श्री एस० के० पुरी	सुरक्षा अधिकारी, सेंट्रल सौदा कोलियरी (फरवरी 74 से मई 75 तक)
8. श्री अवधेश नारायण सिन्हा	सुरक्षा अधिकारी, सेंट्रल सौदा कोलियरी (मई 75 से मार्च 76 तक)
9. श्री वी० एन० बडेरा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स, लिमिटेड
10. श्री ए० के० चटर्जी	महाप्रबन्धक, सेंट्रल कोलफील्ड्स, बर्कानान
11. श्री जे० सी० अग्रवाल	संयुक्त खान सुरक्षा निदेशक, (सेवानिवृत्त)
12. श्री ए० एन० मुखोपाध्याय	खान सुरक्षा निदेशक, रांची
13. श्री एस० आर० सरकार	उपनिदेशक, राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद्, सीतारामपुर

अनुबंध 3

प्रदर्शों की सूची

पार्टी नं० 1 (प्रबंधक वर्ग) द्वारा दाखिल किए गए प्रदर्श

क्रम संख्या	चिह्नित प्रदर्श	दस्तावेजों का वृत्त
1	2	3
1	1	सर्वेक्षक की स्तर-पुस्तिका
2	2	17-9-1976 को बर्कानान का धरातल-नक्शा (स्लू प्रिंट)
3	2 ए	सी० सी० एल०, मास्टर प्लान (स्लू प्रिंट) सर्वेक्षक ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और 12-5-77 तारीख डाली है।

1	2	3	1	2	3
4	2 बी०	मी० सी० एन०, सीमा का मैकेशन (स्केल के लिए नहीं)।	19	13	भारत के महा सर्वेक्षक द्वारा तैयार किया गया रांची जिले में हजारीबाग का स्थलाकृति मानचित्र तथा मैप संदर्भ शीट 73, भार 16 तीसरा परिवर्तन सन् 1943, भी संलग्न है। (34 वर्ष पुराना वस्तावित)।
5	2 सी०	हाथीवारी सीमा का धरातल-नक्शा (ब्लू प्रिंट) हम पर सर्वेक्षक ने 12-5-77 को हस्ताक्षर किए हैं।	20	14	बिहार राज्य बिजली बोर्ड पी० टी० पी० एस० ताप बिजली घर तथा आसपास क्षेत्र की स्थलाकृति का मानचित्र।
6	2 डी०	हाथीवारी सीमा का कार्यकारी नक्शा (ब्लू प्रिंट) इस पर सर्वेक्षक के 12-5-1977 के हस्ताक्षर हैं। पैमाना 1 सें० मी० = 12 मीटर।	21	15	सुरक्षा अधिकारी—श्री दत्त चौधरी की डायरी
7	2 ई०	हाथीवारी सीमा का कार्यकारी नक्शा (ब्लू प्रिंट) हम पर सर्वेक्षक के 12-5-1977 के हस्ताक्षर हैं। पैमाना 1 इंच = 200 फुट। हमने मृतकों के नाम और उनको बरामद करने की तारीख दी गई है।	22	16	पुराना धरातल नक्शा (1956)।
8	3	कपड़ पर मड़ा हुआ मूल धरातल-नक्शा (प्रति, अनुबंध 4ड में है)।	23	17	मोसा सौदा का भूवैज्ञानिक मानचित्र
9	4	नकारी और दामोदर नदी के अध्ययन से संबंधित रेखाचित्र (पतरातू बर्किकाना रामगढ़ रीज)। इसमें 54 रेखाचित्र और विषय सारणी के तीन पृष्ठ हैं।	24	18	प्रबंधक वर्ग द्वारा दाखिल किया गया सेंट्रल सौदा (हाथीवारी) का ड्यूटी आर्बिटन से संबंधित कार्यालय आदेश सं० सी० एस० (सीन) 36/76/1220 तारीख 7-4-76
10	4 ए०	श्री बी० पी० बालिगा द्वारा प्रस्तुत नकारी जलाशय प्रचालन के अध्ययन से संबंधित रिपोर्ट।	25	19	सेंट्रल सौदा का सुरक्षा गठन
11	5	दामोदर घाटी निगम की विनियम दीपिका	26	20	डा० कुमार द्वारा हाथीवारी सीमा के सुरक्षा कारकों और खान के खानों के संबंध में किए गए अभ्यास परिकल्पन।
12	6	श्री पी० के० घोष, अपर मुख्य खान इंजीनियर, सी० आई० एन० के अन्वेषण पत्र सहित 1-9-76 से 18-9-76 तक की अवधि के दामोदर घाटी क्षेत्र का दैनिक समवर्षण मानचित्र (18 मानचित्र)।	27	20 ए०	खाने निकालने के क्षेत्र तथा अवतलन स्वरूप आदि से संबंधित डा० कुमार की रिपोर्ट (रिपोर्ट से संलग्न नक्शे को प्रदर्श के रूप में स्वीकार नहीं किया गया)।
13	7	क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, धलीपुर, कलकत्ता के मौसम विज्ञानी श्री यू० एस० दास से प्राप्त 15-9-76 से दामोदर घाटी क्षेत्र के वर्षा के आंकड़े।	28	21	बर्किकाना कासामिल नक्शा-अनुरक्षण कागज पर धरातल का नक्शा।
14	8	सहायक इंजीनियर, जलविज्ञान के तारीख 8-7-77 के हस्ताक्षर सहित हाइड्रोलिक डेटा डिवाजन, डी० बी० सी० से प्राप्त 12-9-76 से 20-9-76 तक की अवधि के रामगढ़ केन्द्र पर की गई दामोदर नदी की घटेवार गेज रीडिंग।	29	22	विनियम 82 (4) के अधीन क नक्शे आदि की सूची का सूचक रजिस्टर।
15	9	दामोदर घाटी निगम के हाइड्रोलिक डेटा डिवाजन से प्राप्त विवरण, जिसमें 1945 से 1976 तक के दामोदर नदी के रामगढ़ स्थल का अधिकतम वार्षिक जल विसर्जन और नदी स्तर का गेज दिखाया गया है।	30	23	पतरातू ताप बिजली घर तारीख 9 और 14 अगस्त और 13 तथा 14 सितम्बर के पत्रों पर दी गई अपनी टिप्पणियों के संबंध में श्री बालिगा द्वारा किया गया 1-11-77 का नोटिंग।
16	10	जलाशय प्रचालन का खासी प्रोफार्मा अर्थात् दामोदर घाटी द्वारा रखा गया दैनिक प्रवाह तुलन-पत्र।	31	23 ए०	नक्शा—जैनगार रेल पुल और सौदा 'डी' सड़क पुल के बीच की नकारी रीज।
17	11	दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया बाढ़ चेतावनी सेवा जापन सं० डब्ल्यू० 2 (सी०)-20165-1968 तारीख 20 मई, 1975।	33	23 बी०	नक्शा—सी० एच०-2135/28677/ आदि पर क्रास सेक्शन।
18	12	दामोदर घाटी निगम का 1948 का अधिनियम सं० 14 (14 पृष्ठ)।	33	23 सी०	नक्शा—सी० एच० 27677/28677/ आदि पर क्रास सेक्शन।
			34	23 डी०	नक्शा सौदा 'डी' सड़कपुल और सौदा ग्राम सीमा के बीच की नकारी सड़क।
			35	23 ई०	सौदा 'डी' के निकट 'ए०-बी०' सी० एच०-33237 पर सेक्शन सहित नक्शा।
			36	23 एफ०	चैनज 33810 पर क्रास सेक्शन का नक्शा।
			37	24	आदेश पत्रक सं० 35 तारीख 19-11-77 में उल्लिखित तीन खदानों के संबंध में प्रबंधकवर्ग (श्री बालिगा) द्वारा किए गए अध्ययनों के परिणाम।
			38	25	खान सुरक्षा महानिदेशक पार्टी नं० 1 (प्रबंधक-वर्ग) और पार्टी नं० 2 (धार० सी० एम० एस०) द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित मृतकों की सूची।

पार्टी नं० 3 (पतरातू ताप बिजली घर) की ओर से दाखिल किए गए प्रवर्ग			1	2	3
1	2	3			
1	पी०-1	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की लागू पुस्तक	6	ए०-5	श्री ए० कंडू, एम० ई० एन० (ई० एंड एम०) का तारीख 23-9-76 का बयान
2	पी०-2	श्री सतीश चन्द्र की नोट-बुक	7	ए०-6	श्री श्री० एन० शर्मा, फोरमैन प्रभारी (बिजली) का तारीख 22-9-76 का बयान
3	पी०-2 ए०	श्री राधाधार प्रसाद की नोट-बुक	8	ए०-7	बिजली पर्यवेक्षक श्री ए० के० सेनगुप्ता का तारीख 22-9-76 का बयान
4	पी०-3	भाफर बांधपंप घर की लागू-पुस्तक	9	ए०-8	श्री प्रताप कुमार मजूमदार, पर्यवेक्षक का तारीख 21-9-76 का बयान
5	पी०-4	पतरातू ताप बिजलीघर के महाप्रबंधक व मुख्य इंजीनियर श्री एम० करकेट्टा द्वारा किया गया अध्ययन। यह अध्ययन सेंट्रल मौदा खान में बाढ़ के कारणों का पता लगाने के लिए नकारी के जलाशय जलग्रहण क्षेत्र के बारे में किया गया है।	10	ए०-9	सुरक्षा अधिकारी श्री एस० के० दत्त चौधरी का तारीख 17-9-76 का बयान
6	पी०-5	नकारी और वामोवर नदी से संबंधित अटारह रेखाचित्रों का एक सेट	11	ए०-10	श्री छलधारी पांडे, रजिस्टर कीपर का तारीख 21-9-76 का बयान
7	पी०-6	जलाशय स्तर तथा द्वार प्रचालन के लिए रखी गई 1973 की लागू पुस्तक	12	ए०-11	पंप खलासी श्री दिवंगन का तारीख 22-9-76 का बयान
8	पी०-7	श्री बालिगा के साक्ष्य सं० 12/जी० एम० तारीख 9-8-1977 से संबंधित पतरातू ताप बिजली घर का पत्र।	13	ए०-12	सहायक कोयलाखान प्रबंधक श्री एस० आर० शर्मा का 22-9-76 का बयान
9	पी०-8	श्री बालिगा के साक्ष्य सं० 15/जी० एम० तारीख 14-8-77 से संबंधित पतरातू ताप बिजली घर का पत्र	14	ए०-13	प्रबंधक श्री के० दोरेस्वामी का 17-9-76 का बयान
10	पी०-9	श्री बालिगा के साक्ष्य सं० 21/जी० एम० तारीख 10-9-77 से संबंधित पतरातू ताप बिजली घर का पत्र	15	ए०-14	प्रबंधक श्री के० दोरेस्वामी का 23-9-76 का बयान
11	पी०-10	श्री बालिगा के साक्ष्य सं० 23/जी० एम० तारीख 14-9-77 से संबंधित पतरातू ताप बिजली घर का पत्र	16	ए०-15	श्री बी० मेवाड़ का 21-9-76 का बयान
12	पी०-11	श्री बालिगा के साक्ष्य सं० 2150 तारीख 24-10-77 से संबंधित पतरातू ताप बिजली घर का पत्र	17	ए०-16	श्री एस० के० मुखर्जी का 17-9-76 का बयान
13	पी०-12	पतरातू ताप बिजली घर का पत्र सं० 2228 तारीख 8-11-77	18	ए०-17	श्री एस० के० मुखर्जी का 23-9-79 का बयान
14	पी०-13	19-11-77 के आदेश पत्र सं० 35 में उल्लिखित खानों के संबंध में पतरातू ताप बिजली घर (श्री करकेट्टा) द्वारा किए गए अध्ययनों का परिणाम	19	ए०-18	श्री के० एन० तिवारी का 22-9-76 का बयान
अदालत में दाखिल किए गए प्रदर्श (खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा जम्मा या पेश किए गए दस्तावेज)			20	बी०	अंधे तोड़ने की मंजूरी प्राप्त करने का प्रबंधकवर्ग के आवेदन सं० सी० एम०/9468/74 तारीख 10-4-74 से संलग्न नक्शा (खान कार्यालय की फाइल)
1	ए०]	श्री बलबिंदर सिंह, टिडल का तारीख 21-9-1976 का बयान	21	बी०-1	प्रवर्ग बी० से संलग्न प्रोफार्मा
2	ए०-1]	श्री अभिलाष यादव, टिडल का तारीख 18-9-76 का बयान	22	बी०-2	खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा पेश किया गया प्रबंधकवर्ग का तारीख 10-4-74 का आवेदन पत्र सं० सी० एम०/9468/74
3	ए०-2	श्री कुंदन सिंह, टिडल का तारीख 18-9-76 का बयान	23	बी०-3	खान सुरक्षा महानिदेशक का जम्मा किया गया प्रबंधकवर्ग का 10-4-74 का आवेदन-पत्र सं० सी० एम०/9468/74
4	ए०-3	श्री नीलाचल नायक, इंजीनियर का तारीख 18-9-76 का बयान	24	बी०-4	प्रबंधक वर्ग के आवेदन-पत्र सं० सी० एम०/9468/74 तारीख 10-4-74 के संलग्न नक्शा (आ० सु० म० नि० द्वारा जम्मा किया गया)
5	ए०-4]	अध्वर प्रबंधक श्री के० के० मुफ्ता का तारीख 22-9-76 का बयान	25	बी०-5	प्रवर्ग बी०-4 से संलग्न प्रोफार्मा
			26	बी०-6	प्रबंधकवर्ग के तारीख 10-4-77 के पत्र से संलग्न तारीख 5-4-77 का नक्शा (इसमें मदियां अस्पष्ट दिखाई गई हैं) मुख्यालय की फाइल
			27	बी०-7	प्रबंधकवर्ग के तारीख 10-4-77 के आवेदन पत्र से संलग्न तारीख 5-4-77 का नक्शा जिसमें नकारी नदी नहीं दिखाई गई है मुख्यालय की फाइल (प्रति अनुबंध 4-बी० में है)
			28	सी०	सी० एम० आर० के नियम 101 के अधीन अंधे तोड़ने की मंजूरी देने से संबंधित प्रबंधकवर्ग के तारीख 9-8-74 के आवेदन-पत्र से संलग्न नक्शा (प्रति, अनुबंध 4-गं में है)

1	2	3	1	2	3
29	सी-1	प्रदर्श सी० सहित प्रबंधकवर्ग का 9-8-74 का पत्र।	46	एल	प्रबंधक श्री वीरेन्द्रासी की साविधिक शायरी।
30	डी	हाथीदारी सीम का कपड़े पर मढ़ा मूल कार्यकारी नक्शा (प्रति, अनुबध 4-घ में है)।	47	एम	श्री एम० आर० शर्मा की शायरी।
31	ई	सर्वेक्षक की फोटो शायरी।	48	एन	पर्यवेक्षक श्री मजूमदार की रिपोर्ट पुस्तक [सी० एम० आर०, 1957 का विनियम 49(2)]
32	ई-1	सर्वेक्षक की पैमाइश पुस्तक।	49	ओ	कंप के० मैम्प रजिस्टर (जिम पर शिनाख्त के लिए एक्शन-2 अंकित है)।
33	एफ	न्यू हाथीगोडा इन क्वाइन से हाथीदारी सीम के क्षेत्र में खंभे तोड़ने के निरीक्षण से संबंधित खान सुरक्षा महानिदेशालय की तारीख 12-2-75 की निरीक्षण रिपोर्ट।	50	क्यू	10 मर्दान्ता 17-9-1976 की अभियन्तण सूची।
34	एफ-1	हाथीदारी क्षेत्र में खंभे तोड़ने से संबंधित खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रबंधकवर्ग द्वारा भेजा गया पत्र सं० आर० आर० एल० /3762/ राची तारीख 30-8-75।	51	क्यू-1	केवल 2 मर्दान्ता 23-9-76 की अभियन्तण सूची
35	एफ-2	कोलियरी मजदूर संघ के प्रेसीडेंट से प्राप्त शिकायत के बारे में राची के खान सुरक्षा उप महानिदेशक श्री के० बी० मजूमदार की तारीख 28-8-75 की रिपोर्ट।	52	आर	नक्शा सं० सी० एम० बी०-1/ एन०/8-72 तारीख 15-12-72 में जिसके आधार पर खान सुरक्षा महानिदेशक ने विनियम 100 के अधीन अपर नकारी सीम के नं० 1 ईस्ट पैनल में अंतिम कार्यवाही के रूप में खंभे तोड़ने की अनुमति दी गई थी, उच्च बाढ़ स्तर 1130 फुट दिखाया गया है। लेकिन बाढ़ स्तर की तारीख नहीं दी गई है।
36	एफ-3	खा० सु० म० नि० की 13, 18 और 20 दिसम्बर, 1974 की सामान्य खान निरीक्षण रिपोर्ट। इसमें 13 पृष्ठ हैं।	53	आर-1	खान सुरक्षा महानिदेशक ने अपने पत्र सं० 1512-40 तारीख 20 अगस्त, 1971 के अनुसार विनियम 100 के अधीन अंतिम कार्यवाही के रूप में अपर नकारी के वेस्ट पैनल सं० 1 के खंभे तोड़ने की अनुमति दी थी जैसा कि प्रबंधकवर्ग के पत्र सं० डी० एस० ओ० सी० बी० एच० के०/परमीशन/3956-59 तारीख 26-3-71 भूरकुंडा नं० 1 कोलियरी से संलग्न तारीख 11-3-71 में दिखाया गया है। इस नक्से में उच्च बाढ़ स्तर 1130 फुट दिखाया गया था लेकिन इस स्तर की तारीख नहीं दी गई थी।
37	एफ-4	खा० सु० म० नि० की 7, 8, 12, 13, 23 और 25 मई, 1975 की सामान्य खान निरीक्षण रिपोर्ट। इसमें 13 पृष्ठ हैं।	54	आर-2	विनियम 127 के अधीन अनुमति देने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक को भेजे गए प्रबंधक के पत्र सं० सी० एम० बी० 1/1046 से संलग्न नक्शा सं० बी० एच० के० 1(एल) एस० आई० एम० ए०/3 तारीख 28-12-67 में नकारी का उ० खा० स्त० 1130 फुट दिखाया गया था लेकिन उक्त बाढ़ स्तर की तारीख नहीं दी गई थी।
38	एफ-5	श्री जे० सी० अग्रवाल, संयुक्त खान सुरक्षा निदेशक की तारीख 7-5-75 और 12-5-75 की निरीक्षण रिपोर्ट।	55	आर-3	विनियम 122 के अधीन अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रबंधक के पत्र सं० सी० एम० बी० 1/382 तारीख 30-3-68 से संलग्न प्लान सं० बी० एम० के० 1/(एल)/एम० आई० एम० ए०/3 तारीख 29-3-68 में नकारी का उच्च बाढ़ स्तर 1130 फुट दिखाया गया था लेकिन उसकी तारीख नहीं दी गई थी।
39	एफ-6	खा० सु० म० नि० द्वारा 7, 8, 12, 13, 23 और 26 मई, 1975 'कोई किए गए' सामान्य 'निरीक्षण' के संबंध में प्रबंधकवर्ग को बतए गए संलग्न जिनकी सूचना खा० सु० म० नि० के पत्र सं० आर० आर० एल०/3312/राची तारीख 3 सितम्बर, 1975 के अनुसार सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को दी गई थी।	56	आर-4	सिरका सीम खान में खंभे तोड़ने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रबंधक वर्ग के पत्र सं० डी० एम० ओ० सी०/बी० एच० के०/डिप-सिरका/571 तारीख 18/20 जनवरी, 1966 के साथ मुख्य खान निरीक्षक को भेजे गए अपर सेमाना सीम के तारीख 20-1-66 के नक्शा सं० 69 में तारीख 23-7-58 को 1130.09 फुट दिखाया गया है।
40	एफ-7	कोलियरी मजदूर संघ की तारीख 18-3-75 की शिकायत के संबंध में खा० सु० म० नि० से सेंट्रल सोवा कोलियरी के एजेंट को भेजा गया पत्र सं० आर० आर०/4444 तारीख 17 अक्टूबर, 1975।			
41	जी	सी० एम० आर०, 1957 के विनियम 60 के संबंध में खा० सु० म० नि० और श्रम मंत्रालय के बीच हुआ पत्राचार।			
42	एच	सेंट्रल सोवा कोलियरी का हाथिरी रजिस्टर (फार्म सी०)।			
43	आई	जल खतरा नक्शा।			
44	जे	खंभे तोड़ने की मंजूरी के अनुसार खा० सु० म० नि० का पत्र सं० एस० ई० जेड०/25 (कोल) तारीख 2-1-75।			
45	के	अपनी जांच रिपोर्ट के संलग्नक के रूप में खा० सु० म० नि० द्वारा दाखिल किया गया धरातल नक्शा।			

1	2	3
57	आर-5	भूरकुंडा की खान सं० 1 की नोअर नकारी सीम का 15 मीटर के भीतर और नाले के नीचे विकास करने के लिए विनियम 126 (2) के अधीन अनुमति प्राप्त करने हेतु उप मुख्य इंजीनियर के पत्र सं० डी० सी० एम० ई०/बी० एन० के०/डी० जी० एम० एस० परमीशन/1356-59 तारीख 14/19 जनवरी, 1976 से संलग्न तारीख 23-1-76 के नक्शा सं० सी० एम० बी-1(एल० एन०) 8 में नकारी का स्तर 1130 फुट दिखाया गया है। अनुमति निदेशक के पत्र सं० डी० आई० आर०/एम० ई० जेड०/आर० आर० (2955) तारीख 24-6-76 के अनुसार भी गई थी।
58	आर-6	प्रबंधक वर्ग के पत्र सं० एम० ए० यू० एन०/आर० आरगद/साउथ/70/14030-32 तारीख 24-7-71—क्षेत्रीय कार्यालय डायरी सं० 4759 तारीख 28-7-1970 से संलग्न सीम के दक्षिणी ओर सीम की उठान की ओर आरगव "बी" सीम की प्रस्तावित खदान—नक्शा सं० एस० एन० जी०/एस०/ए० आर० जी० बी०/ले आउट/बी-एम/8170-71 पर पर्यवेक्षक श्री बनर्जी के तारीख 8-7-70 के हस्ताक्षर के ओर उसमें उच्च बाढ़ स्तर 337.7 मीटर दिखाया गया था लेकिन बाढ़ स्तर की तारीख नहीं लिखी गई थी।
59	आर-7	नक्शा सं० एस० ए० 1/63 तारीख 28-6-63 में 23-7-58 को नकारी नदी का उच्च बाढ़ स्तर 1129.39 फुट दिखाया गया था। यह नक्शा विनियम 100 के अधीन खंडे हटाने के अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रबंधक के पत्र सं० एम० बी० ई० पी०/2204 तारीख 25 जुलाई, 1963 को भेजा गया था जो मुख्य खान निरीक्षक के पत्र सं० 416200 तारीख 22 अगस्त, 1963 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।
60	आर-8	21 अगस्त, 1975 की घातक दुर्घटना रिपोर्ट सं० आर आर/4748 से संबंधित तारीख 5 नवम्बर, 1975 की दुर्घटना रिपोर्ट और श्री के० के० बी० मजूमदार द्वारा 22-8-75 को दिया गया स्थल निरीक्षण।
61	आर-9	जोनल कार्यालय के खंडे तोड़ने की मंजूरी से संबंधित टिप्पण और कागजात।
62	आर-9(1)	खंडे तोड़ने की मंजूरी से संबंधित प्रबन्धकवर्ग के आवेदनपत्र पर खा० सु० म० नि० के जोनल कार्यालय में किए गए टिप्पण।
63	आर-10	श्री मजूमदार के पत्रातू ताप बिजलीघर के दौर के मिलसिले में विजयनगरम से खान मुरआ, रांची को दिया गया तारीख 10 मई, 1977 का तार।
64	एस	खा० सु० म० नि० द्वारा पेश किया गया संयुक्त सर्वेक्षण नक्शा।
65	टी	सेंट्रल सोदा खान की इतिवृत्त फाइल।

1	2	3
66	टी-1	सेंट्रल सोदा की इतिवृत्त फाइल की मद 1.7।
67	यू	सेंट्रल सोदा खान, नकारी सीम का कार्यकारी नक्शा तारीख 29-10-64।
68	यू-1	सेंट्रल सोदा कोलियरी—हाथीदारी का कार्यकारी नक्शा तारीख 29-1-64।
69	यू-2	सेंट्रल सोदा कोलियरी—हाथीदारी सीम का कार्यकारी नक्शा तारीख 20-10-70।
70	बी	खा० सु० म० नि० मुख्यालय फाइल सं० एम० आई० 590 (बी 1)-74 खंड-1 (सेंट्रल सोदा कोलियरी)।
71	बी-1	फाइल पर श्री एस० आर० सरकार के 28-1-75 के हस्ताक्षर, प्रवर्धनी।
गवाहों द्वारा अदालत में दाखिल किए गए या अदालत द्वारा जम्न किए गए प्रदर्श		
1	2	3
1	सी आर-1	हाथीदारी सीम का कार्यकारी नक्शा (न्यूप्रिंट)।
2	सी आर-2	बांध से पानी छोड़े जाने के संबंध में महाप्रबंधक—व मुख्य इंजीनियर, पतरातू ताप बिजलीघर का पत्र सं० 660 तारीख 28-29 मार्च, 1977।
3	सी आर-2ए	प्रदर्श सी आर-2 के संलग्नक।
4	सी आर-3	वर्षा, वर्षा माप रिकार्ड आदि से संबंधित दस्तावेजों का संलग्नक पतरातू ताप बिजली घर का पत्र सं० 52 तारीख 13-5-1977।
5	सी आर-3ए	प्रदर्श सी आर-3 से संबंध सूचना और दस्तावेजों की सूची।
6	सी आर-3बी	वर्षा गैज रिकार्ड—पतरातू, 15-8-76 से 10-9-76।
7	सी आर-3सी	क्षेत्र क्षमता कर्ष—नकारी जलाशय।
8	सी आर-3डी	अधिप्लव मार्ग द्वार का विमर्जन दर चार्ट।
9	सी आर-3ई	आणिक रूप से द्वार खोलने के लिए विस्तर्जन चार्ट।
10	सी आर 3एफ	1-8-74 से आगे की द्वार लाग पुस्तक।
11	सी आर 3जी	नकारी बांध में पानी के प्रदेश से संबंधित विवरण।
12	सी आर 3एच	1972 का गेज रजिस्टर।
13	सी आर 3आई	नकारी का जलाशय स्तर—1968-75।
14	सी आर 3जे	19-9-76 को पतरातू के प्राधिकारियों द्वारा बिहार स्टेट बिजली बोर्ड, पटना के अध्यक्ष को भेजा गया टेलिक्स संदेश।
15	सी आर-4	पतरातू ताप बिजलीघर का पत्र सं० 1345 तारीख 24-6-77।
16	सी आर 4ए	बलबिंदर सिंह की प्रथम सूचना रिपोर्ट। बाद में इसे शिनाखत के लिए दस्तावेज निर्धारित किया और आदेश पत्र सं० 16 (बी) तारीख 8-8-1977 के अनुसार इस पर 'जिड' चिह्नित किया गया।
17	सी आर-5	पतरातू ताप बिजलीघर का पत्र सं० 1346 तारीख 24-6-77।
18	सी आर-5ए	नकारी बांध और अधिप्लव मार्ग, प० ता० बि० घ० की द्वार प्रचालन तथा निरीक्षण अनुसूची।

- 19 सी धार-5बी 10 से 20 मिनट, 1976 तक द्वार का प्रचालन और जल विमर्जन।
- 20 सी धार-6 पतरातू ताप बिजली घर के प्राधिकारियों द्वारा भरा गया और मूलतः शिनाखत के लिए चिह्नित मय 'बाई'—पी टी पी एम का प्लान स्पलाकृति मानचित्र अब अधिग्रहणित है।
- 21 सी धार-7 श्री एन० करकेट्टा द्वारा प्रचालन के सचिव श्री सतपाल सिंह को तारीख 14-6-1977 के संलग्न मोट के 4 पृष्ठों सहित भेजा गया पत्र सं० 1273 तारीख 15-6-1977।
- 22 सी धार-7ए श्री डी० एन० मेहता, अधीक्षक इंजीनियर तेजुघाट बांध मंडल संख्या-1 द्वारा पतरातू ताप बिजली घर के प्रतिरिक्त मुख्य इंजीनियर को भेजा गया पत्र सं० 2238 तारीख 9-7-70।
- 23 सी धार-7बी श्री एन० धार० कृष्णामूर्ति अधीक्षक इंजीनियर (सी), पतरातू सिविल मंडल (बिजलीघर) द्वारा श्री डी० एन० मेहता अधीक्षक इंजीनियर (सी) तेजुघाट बांध मंडल सं० 1 को भेजा गया पत्र सं० 1796 तारीख 23-8-70।
- 24 सी धार-7सी प्रबंधक निदेशक, एन० सी० डी० सी० लिमि०, रोबी द्वारा श्री सहाय जी० एस०, पी० टी० पी० एस०, पतरातू को भेजा गया आपन सं० 3655 तारीख 24-1-73।
- 25 सी धार-7डी श्री एन० करकेट्टा प्रधान अधीक्षक, द्वारा उप-मुख्य खान इंजीनियर, भूरकुंडा कोलियरी को भेजा गया आपन सं० 2172 तारीख 18-7-76।
- 26 सी धार-7ई श्री जे० पी० वर्मा, कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)-1 पतरातू द्वारा श्री के०एन० प्रधान, कार्यपालक इंजीनियर (सिविल), सिविल प्रभाग नं० 11, पतरातू ताप बिजलीघर को भेजा गया आपन सं० 1686 तारीख 24-9-76।
- 27 सी धार-8 श्री एन० करकेट्टा द्वारा प्रचालन के सचिव श्री सतपाल सिंह को भेजा गया पत्र सं० 1129 तारीख 31-5-77।
- 28 सी धार-8ए अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग, हजारीबाग रोड सिविल द्वारा मुख्य इंजीनियर (सिविल) पतरातू ताप बिजलीघर को भेजा गया पत्र सं० 970 तारीख 9-3-70।
- 29 सी धार-8बी श्री एन० करकेट्टा, महाप्रबंधक व मुख्य इंजीनियर, पतरातू ताप बिजलीघर द्वारा अधीक्षक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, हजारीबाग को भेजा गया पत्र सं० 136 तारीख 22-4-76।
- 30 सी धार-8सी संलग्न रेखाचित्र सहित काफ़र बांध के बारे में रिपोर्ट।
- 31 सी धार-9 नकारी बांध का निरीक्षण अनुसूची रजिस्टर-104 पृष्ठ।
- 32 सी धार-10 श्री धार० पी० सिंह, उप-मुख्य खान इंजीनियर, सौदा/बांसगोड़ा कोलियरी द्वारा बाढ़ के खतरे के संबंध में संयुक्त खान सुरक्षा निदेशक को भेजा गया पत्र सं० एस० ए० यू० एन०/पी० ई० ई० एन०/एच० ई० एल०/पी० धार० ई० सी०/77-78/7711-17 तारीख 23-6-77।

- 33 सी धार-10ए न्यू धारगवा इन्फ्लेशन का सौदा कोलियरी कार्यकारी नक्शा-नक्शा सं० एस० एन० आई०/एन० ई०/एच०/ए० जी० डी०-एच० ई० एन०/2-बी० 77-78 तारीख 13 जून, 1977।
- 34 सी धार-10बी सौदा कोलियरी नक्शा जिसमें उच्च बाढ़ स्तर रेखाओं और धरातल स्थिति एवं मुख्य वीथ सहित सभी वर्तमान चालू सीमा खदानों के सीमांत दिखाए गए हैं। नक्शा सं० एस० एन० डी०/जी० ई० एन०/एच० एफ० एन०/2177-78 तारीख 23-6-1977।
- 35 सी धार-10सी सिरका सीमा कार्यकारी नक्शा सं० एस० एन० डी०/एन० आई० धार०/आफसेट/24/77-78 तारीख 12-6-77 का सौदा कोलियरी पार्ट आफसेट प्लान।
- 36 सी धार-11 एन० सी० डी० सी० सौदा कोलियरी की स्तर पुस्तिका।
- 37 सी धार-11ए प्रदर्शनी सी धार-11 के अनुसार और अनुसंधान कागज पर किए गए 1064 फुट के उ० बा० स्त० के संबंध में बाढ़-स्तर अंकन।
- 38 सी धार-11बी 1966 में अनुसंधान कागज पर दिखाया गया एन० सी० डी० सी० सौदा का 1064 उ० बा० स्त० का परिकल्पन। उस पर सर्वेक्षक के तारीख 27-8-1966 के हस्ताक्षर हैं।
- 39 सी धार-12 दामोदर घाटी और हजारीबाग क्षेत्र के हवाई सर्वेक्षण से संबंधित भारत सर्वेक्षण विभाग का नक्शा—संदर्भ शीट सं० 48 ब्यू।
- 40 सी धार-13 गिरी 'ए' प्रायोगिक खान की दैनिक पागो प्रभारी रिपोर्ट पुस्तक से संबंधित अधिवृत्त आपन सं० तारीख 29-8-1977।
- 41 सी धार-13ए प्रदर्शनी 13 में उल्लिखित रजिस्टर खा० सु० म० नि० से प्राप्त हुआ था। रजिस्टर में 16-9-76 से संबंधित इंदराज संगत है। इस इंदराज का उद्घरण प्रचालन अपने पास रखेगी।
- 42 सी धार-14 15-12-77 को श्री जी० एल० खेरा ने मोनहू और वस्तावेज दाखिल किए और वे समूचे रूप में सी धार-14ए चिह्नित किए गए। ये वस्तावेज श्री खेरा से सी धार-14ओ द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुसंधान से संबंधित हैं।

अनुबंध-4

शिनाखत के लिए चिह्नित वस्तावेजों की सूची

क्रम संख्या	चिह्नित	वस्तावेज का बृत्त
1	2	3
1	जेड	श्री बलबिंदर सिंह की प्रथम सूचना रिपोर्ट को मूलतः सी धार-4 ए के रूप में स्वीकार किया गया था लेकिन बाद में उस पर शिनाखत के लिए 'जेड' चिह्नित किया गया है। आदेश पत्र सं० 16 (बी) तारीख 8-8-77 देखें।

1	2	3	1	2	3
2	एक्स-7	भारगदा क्षेत्र की विभिन्न खानों में बाढ़ के पानी के घुसने से संबंधित ग्रहस्ताक्षरित रिपोर्ट को एक्स-7 चिह्नित किया गया है।	5	एक्स-10	भूमिगत खानों में सूतही जल के फूट निकलने के खतरे और अपनाई जाने वाली आवश्यक सुरक्षा उपायों के संबंध में खा० सु० म० नि० द्वारा वाखिल किया गया नोट (ग्रहस्ताक्षरित) एक्स-10 चिह्नित किया गया है।
3	एक्स-8	करनपुरा क्षेत्र की विभिन्न खानों में बाढ़ के पानी के घुसने से संबंधित ग्रहस्ताक्षरित रिपोर्ट को एक्स-8 चिह्नित किया गया है।	6	एक्स-11	छह खानों में उच्च बाढ़ स्तर उभाने वाली सारणी (ग्रहस्ताक्षरित) को एक्स-11 चिह्नित किया गया है।
4	एक्स-9	सौंदा कोलियरी के जल-स्तर की प्रगति और विभिन्न इम्प्लाइमेंटों की स्थिति की ग्रहस्ताक्षरित प्रगति को एक्स-9 चिह्नित किया गया है।			[म० एन-11015/5/79-एम 1] मीना गुप्ता, प्रवर सचिव

New Delhi, the 16th May, 1979

S.O. 3692.—In pursuance of section 27 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby publishes the following report submitted to it under sub-section (4) of section 24 of the said Act by the Court of Inquiry appointed to hold an inquiry into the causes of and circumstances attending the accident which occurred on the 16th September, 1976, in the Central Saunda Colliery in Hazaribagh District, State of Bihar.

Report of the Court of Inquiry on the accident which occurred on the 16th September, 1976 at Central Saunda Colliery in District Hazaribagh, State of Bihar.

REPORT OF THE COURT OF INQUIRY

on the accident which occurred on

16th September, 1976

at the

CENTRAL SAUNDA COLLIERY, BIHAR

VOLUME I

INTRODUCTION

Setting up of the Court

1. An accident took place at the Central Saunda Colliery on 16th September, 1976 involving the lives of 10 persons as a result of the inundation of the 13th Incline of the Hathidari Seam. The names of the deceased are given in Annexure 1 to this Report.

In its Notification dated the 25th November, 1976, which appeared in the Gazette of India, Part II Section 3(ii), dated 11th December, 1976, the Government of India in the Ministry of Labour therefore announced the setting up of a Court of Inquiry as follows :—

"S.O. 4695. Whereas an accident occurred in the Central Saunda Colliery in Hazaribagh District, State of Bihar, on the 16th September, 1976, causing loss of lives;

And whereas the Central Government is of opinion that a formal inquiry into the causes and circumstances attending the accident ought to be held;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 24 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri N. P. Dube, retired Secretary to the Government of India, to hold such inquiry and also appoints the following persons as assessors in holding the inquiry, namely :—

1. Prof. S. S. Saluja,
Director,
Institute of Technology,
Banaras Hindu University, Varanasi.

2. Shri S. Das Gupta,
General Secretary,
Indian National Mine Workers' Federation,
Dhanbad."

This was followed on 29th December, 1976 by instructions on the expenditure to be incurred on the workings of the Court and the appointment with effect from 15th January, 1977 of a part-time Secretary to the Court of Inquiry. Shri Satpal Singh, so appointed, was made a full-time Secretary to the Court with effect from 1st April, 1977.

Notices issued by the Court

2. The Court held its first sitting at Ranchi on 14th February, 1977 and issued next day a Notice in nine newspapers/weeklies asking the intending participants in the Inquiry to submit their written statements to the Court by 8th March, along with the names of the witnesses whom they would like to produce before the Court. The Notice was also pasted in the office premises of :

- (i) The General Manager, Central Coalfields Ltd., Barkakana;
- (ii) The Central Saunda Colliery;
- (iii) The Managing Director, Central Coalfields Ltd., Ranchi;
- (iv) The Director General, Mines Safety, Dhanbad; and
- (v) The Director of Mines Safety, Ranchi.

Visit to the mine

3.1 With the assessors Prof. Saluja and Shri Das Gupta, I along with the Chief Inspector of Mines and the General Manager, Central Coalfields Ltd., Barkakana visited the Central Saunda Colliery on the forenoon of 15th February, 1977. We went round the surface to see the general topography of the area, the embankment across the small nullah which used to traverse the Hathidari goaf, the area where the subsidence had taken place and the spot where the water from River Nakari (also known as River Nalkari) was reported to have gushed into the mine. We then went down Incline No. 13 of the Hathidari Seam to the 23rd/24th level, to which the workers had gone on 16th September, 1976 to shift the pump, and during which process ten of them lost their lives by the water which rushed through that Incline.

3.2 On the evening of 15th February we had a view of the Patratu Dam on the Nakari river and on the morning of 16th February, in order to get some idea of the heavy floods of 1976, I visited Quarry No. 4 of the Bhurkunda Colliery; incline of Argada 'A' of the NCDC Colliery, Quarry No. 1—on the Nakari river—and Inclines 1 and 2 of the Associated Karanpura Colliery on the Damodar river. On my way from the Central Saunda Colliery to Ranchi, I

also saw on 16th February, 1977 the road bridge over the Damodar on the Ramgarh-Hazaribagh Highway which was reported to have been submerged during the 1976 flood.

Party No. 1 and 2 to the Inquiry

4.1 At its next sitting at Ranchi on 12th March, 1977, the Court received :

- (i) the cyclostyled statement of the Management of the Central Coalfields Ltd., consisting of 35 pages, with 5 annexures, together with a list of their witnesses ; and
- (ii) a four-paged typed statement from the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh (RCMS), an affiliate of the Indian National Mine Workers' Federation and the Indian National Trade Union Congress.

4.2 The Director General of Mines Safety (DGMS) did not give any written statement, but when directed by the Court to present the material with them which was relevant to the accident, they submitted their 13-paged cyclostyled Accident Report dated the 22nd December, 1976, along with the copies of the evidence recorded by them, plans and other details referred to in the Report.

4.3 Later on, on 28th March, 1977, the Court received from the Management their comments on the Report of the DGMS and also supplementary information by way of their comments on the statement submitted by RCMS. When the Court held its session at Ranchi during April, 1977, the Management made a correction to the Supplementary Information and a correction to their cyclostyled statement. While signing the cyclostyled copy of their statement before the Court on 12th May, 1977, the General Manager, Barkakana said that the authentication was subject to the corrections mentioned above.

4.4 The Management were made Party No. 1, and the RCMS were made Party No. 2.

Party No. 3 to the Inquiry

5.1 In their statement and in their deposition the Management asserted that it was the sudden and massive discharge of water from the Patratu Dam—across the River Nakari upstream of the Central Saunda Colliery—that caused inundation of their mine. Shri N. Kerketta, General Manager-cum-Chief Engineer, Patratu Thermal Power Station (PTPS) was examined as a Court witness on 13th and 14th May, 1977.

5.2 On 12th July, Shri Kerketta filed a petition praying that the PTPS should be made a Party to the case to defend themselves and to assist the Court in arriving at the correct conclusion and circumstances which led to the flooding of the Central Saunda Colliery on 16th September, 1976. This was accepted by the Court and the PTPS, who became Party No. 3 filed their written statement on 13th July, 1977 and presented a list of their witnesses in their letter dated 4th August, 1977. The Management filed a rejoinder to the PTPS statement on 8th August, 1977.

Role of DGMS

6.1 While submitting their Report on the accident before the Court on 12th March, 1977, the DGMS said that they were doing so, not in the capacity of a Party, but to assist the Court in its Inquiry. When the Management and the RCMS, Party numbers 1 and 2 suggested on 25th April, 1977 that the DGMS should also be made a Party, the Court stated that the DGMS had already given an assurance to assist the Inquiry. It added that the Court could also call in any witnesses, including the DGMS and take their evidence on oath and that it would be prepared to consider any suggestions of the Management and RCMS to examine the DGMS and/or the documents in their possession.

6.2 The Court, later on, had occasion to make the following observation :

"The Court said that the DGMS have so far attended every sitting of the Court in order to assist it to make the Inquiry and have questioned the witnesses

under examination through the Court. Some shortcomings of the DGMS have been hinted at or brought to the notice of the Court with an implication that could or could not be of the nature of allegations against them on certain points. In these circumstances and in order to enable them to justify what they may or may not have done, it would be advisable even at this stage to make the DGMS a party to this Inquiry. The DGMS know right from the beginning what has come to light before the Court and they have been given the Order Sheets of the Court and copies of the Depositions and petitions made before the Court. They have also been allowed to inspect and examine the documents, reports etc. filed before the Court. So becoming a party at this stage should not be difficult matter for the DGMS. If the DGMS do not become a party then they would obviously not have an opportunity to defend themselves at the arguments stage in the Court. At that stage arguments are orally made on points or issues arising from what has already been brought to the notice of the Court and no new points are entertained by the Court. By becoming a Party now, the DGMS would also, if necessary, be allowed to produce their witnesses before the Court prior to the argument stage. The Court, therefore, directed the DGMS to inform the Court immediately in writing as to whether or not they would like to be made a party."

6.3 The DGMS reply was to the effect that the question of their becoming a party did not arise for the reasons/ explanations given in a 4-page note enclosed with their letter. The Court observed that the DGMS had been a party in the inquiries made in respect of some mine accidents in the past and there had been no amendment of the Mines Act, 1952 ruling out the discretion of the Court to make anyone it considered necessary a party to the inquiry. The Court stated that it would technically not treat the DGMS a party as such in its inquiry, but would still have to—in the light of what came out in the proceedings—assess their responsibility, if any, connected with anything that had a bearing on the accident in the Central Saunda Colliery.

Petition from CITU

7. The Court received a petition dated 21st May, 1977 from the Secretary, Centre of Indian Trade Unions (CITU), Calcutta for inclusion in the Inquiry as a party and informed them to send in a written statement of their case for the consideration of the Court which would hold its sittings in Ranchi in July, 1977. Secretary, CITU, could not, however, be present at the Court sitting on 11th July, 1977 due to his indisposition. A petition was filed on 13th July, 1977 on behalf of CITU for being made a party. The petition was considered and the objections of the other parties were heard, upon which the Court again asked CITU to file their written statement for considering their request to be made a party. The written statement was filed by Secretary, CITU, with his letter dated 25th July, 1977 to which the Management filed a rejoinder on 8th August, 1977. According to the Court's order of 9th August, 1977, CITU were allowed to lead evidence on the points contained in their statement and were told that their representatives who would do so, would be treated as witnesses of the Court.

Exhibits and Plans

8. Volume II contains the Annexures to this Report. Annexure I shows the names of the deceased ; Annexure II the names of the witnesses who appeared before the Court ; and Annexures III and IV the list of Exhibits, and Documents marked for identification. Seven plans of the mine and of the flow of water are shown in Annexure V(a) to V(g).

PART-I

THE MINE & THE PATRATU DAM

Location of the Central Saunda Colliery

9.1 The Central Saunda Colliery on the River Nakari lying between latitudes 23° 39'40" and 23° 40'50" and by longitude

85° 20'0" and 85° 21'01"—is situated in the South Karanpura Coalfield, Saunda Block C, in the district of Hazaribagh, Bihar.

A 25 Kms. road connects the Colliery to Ramgarh on the Hazaribagh-Ranchi highway. It is also connected with Ranchi via Patraru, with Patraru being about 15 kms. by road from the Colliery. Coming from Ramgarh to the Central Saunda Colliery, one has to cross the two cause-ways over the rivulets of Kankani and Marangarha and the regular bridge near the NCDC Saunda Colliery which is just upstream of the confluence of the Nakari and Damodar rivers. On the route from Patraru to the Central Saunda Colliery, the Nakari river has to be crossed twice by regular bridges.

The railway station, Eastern Railway, which is nearest to the Colliery is at Patraru on the branch line from Dehri-on-Sone to Gomoh.

9.2 The Central Saunda Colliery with a leasehold area of 325.61 acres or 131.82 hectares, is bounded :

- on the north-east by : the Khas Karanpura Colliery;
- on the north by : the Khas Karanpura Colliery;
- on the north-east by : the NCDC Saunda Colliery;
- on the east by : the Bhurkunda Colliery;
- on the south by : the Saunda 'D' Colliery; and
- on the west by : the Syal 'D' Colliery.

9.3 The Nakari which is a tributary of the Damodar river run generally on a south to north direction and the Damodar flows more or less in a east to west direction and almost parallel to the northern boundary of the Central Saunda Colliery at an approximate distance of 2 kilometres. The Nakari, which takes a sharp bend near the Central Saunda Colliery, separates that Colliery from the Bhurkunda Colliery and then flows to its confluence with the Damodar river, which is about 1.5 km. from the Central Saunda property.

The Patraru Dam :

10.1 The Patraru Dam, across the River Nakari, is about 11 kilometres upstream of the Central Saunda Colliery. Its construction was started in 1962 and was over in 1965 and the spillway gates were fitted in 1968. The length of this earthen dam is 3.2 kms. and it has 20' wide metalled road on the top. The overflow section consists of masonry construction in the river section which is flanked by the earth dam section on either bank constructed to the spillway by suitable transition section. The spillway is provided with vertical lift-gates. The designs of this earth dam and its spillways were worked out under the guidance of the Central Water and Power Commission.

10.2 The salient features of this Patraru (Nakari) dam are as follows :

(i) Catchment area	81.30 sq. miles
(ii) Maximum height of the dam.	119.5 ft.
(iii) Overall length	10620 ft.
(iv) Length of the masonry spillway	349 ft.
(v) Length of the non-overflow section	558 ft.
(vi) Height of operating platform	147 ft.
(vii) Size of steel gates	35' x 23-1/2' (8 nos.)
(viii) Max. storage capacity	87,000 acre ft.
(ix) Live storage	80,800 acre ft.
(x) Reservoir spread of FRL	2,450 acre ft.
(xi) Max. depth of water at dam	109.5 ft.
(xii) Usable depth of water	60.5 ft.
(xiii) Max. discharge over spillway	1 lac cusecs
(xiv) Max. drain off	110 cusecs of 60 million gallons per day.

10.3 Raw water from the reservoir is carried by CI mains by gravity to the water filtration plant about a mile away and from there by gravity mains to the cooling towers of the thermal station.

The requirement of make up and service water for the thermal power station of 400 MW is 40 cusecs, whereas the regulated flow from the reservoir is 110 cusecs. The Central Coalfields Ltd. receive 10 cusecs of continuous supply for the collieries in and around the Patraru area. The requirement of make up water for 840 MW installation at Patraru is estimated to be approximately 70 cusecs.

Patraru Thermal Power Station :

11. The Patraru Thermal Power Station (PTPS) on the left bank of the river Nakari at a mean sea level of 372.5 m. is three kilometres downstream from the Patraru Dam. The first seven units of the Power Station were commissioned between the years 1966 and 1977. The eighth unit is expected to start operating in 1978 and the construction work of the ninth and tenth units (110 x 2 MW) is to be taken up to raise the generating capacity to 840 MW.

Coal Seams of the Colliery :

12.1 The coal seams of the field belong to the Barakar series of the Lower Gondwanas. All the coal seams of the Karanpura field, except the Saunda group of seams, are found in the Central Saunda Colliery. All the younger seams upto Bangora outcrop within the property. The Sirka and Argada seams do not outcrop but occur at depth of more than 180 metres.

12.2 The names of the seams in the Central Saunda Colliery, which occur in the property in sequence, are given below :—

- (i) Upper Sayal
- (ii) Lower Sayal
- (iii) Upper Bakudra
- (iv) Lower Bakudra
- (v) Kurse
- (vi) Upper Nakari
- (vii) Lower Nakari
- (viii) Upper Semana
- (ix) Lower Semana
- (x) Hathidari
- (xi) Bangora
- (xii) Upper Sirka
- (xiii) Lower Sirka
- (xiv) Argada group

The Six Working Seams :

12.3 Of the 14 seams mentioned above, only six are under operations, namely, the Kurse, Upper Nakari, Lower Nakari, Bangora, Upper Sirka and Lower Sirka seams. Their description is given in the following five sub-paragraphs below.

(a) Kurse Seam.—The seam is 17' thick and has been worked through incline Nos. 11, 12 and 15. The seam has been fully developed on Bord and Pillar method and depillaring was going on in the third panel. The first two panels were depillared and sealed. The production from this seam was about 90 tonnes/shift and employment was as follows :

Underground	76 per shift
Surface	4 per shift
Staff	4 per shift

(b) Upper and Lower Nakari Seams.—The seams have been developed through incline Nos. 6, 9 and 10. The Upper seam is 11' thick and the lower 6'. Development in both the seams by Bord-&-Pillar method was completed around 1970. A number of drifts and staple pits connect the upper and lower seams. Depillaring was being done in both the seams simultaneously with Kurse seam in panels lying correspondingly below the Kurse seam.

The production from these two seams was around 100 tonnes/shift and the employment was—

Underground	81 per shift
Surface	5 per shift
Staff; Overman	2 per shift
Sirdar	2 per shift
Shot Firers	2 per shift
Munshies	2 per shift

(c) Bangsora Seam.—This seam is about 14' thick and development was going on Bord-&Pillar method through incline Nos. 17, 18 and 25. Two drifts were also being driven to negotiate the fault for developing the virgin patch on the dip side.

Production	140 tonnes/shift
Employment	
Underground	120
Staff	9
Surface	10

(d) Upper Sirka Seam.—This seam and the seams below do not outcrop in the property. The seam is 22' thick and has been worked through a pair of shafts known as pits Nos. 1 and 2. Development has been done more or less along the floor of the seam on Bord-&Pillar method. The development was practically complete except for a small portion on the south-west where work was going on.

The production was 50 tonnes/shift.

Employment	
Underground	67 per shift
Surface	6 per shift
Staff-Overman	1 per shift
Sirdar	1 per shift
S.F.	1 per shift
Munshi	1 per shift

(e) Lower Sirka Seam.—This seam is 11' thick and was being worked through pits Nos. 1 and 2. The seam is connected to the Upper seam by a pair of drifts. Development on Bord-&Pillar method was started recently in this seam.

Production	70 tonnes/shift
Employment	
Underground	45 per shift
Surface	4 per shift
Staff	4 per shift

The five non-working seams :

12.4 No working or production was taking place in five seams, namely, the Upper Sayal, the Lower Sayal, Lower Balkudra, Upper Semana and the Argada group of seams. The position in these seams was as follows :

(a) Upper Sayal

: The seam had already been extracted by manual quarry.

(b) Lower Sayal

: The seam was fully developed through Inclines 22 & 23 but there was no production from it.

(c) Lower Balkudra

: After quarrying, development and depillaring, its inclines No. 19 and 20 were closed in April 1974.

(d) Upper Semana

: The seam had been worked through a number of inclines and small portions of outcrop

had been quarried out. There was no working in this seam on 16th September, 1976, but a small virgin patch was later taken up for development.

(e) Argada group

: The seams, namely, Argada, Argada, 'A' and Argada 'B' were all virgin and entries to them had not been established.

Pumping only in 3 seams :

12.5 No working, except pumping, was going on in the following seams :

- (a) Upper Balkudra ;
- (b) Lower Semana ; and
- (c) Hathidari

Brief History of the Hathidari Seam :

13.1 The Hathidari Seam, where the accident took place on 16th September, 1976, is 12' thick and outcrops in the property and was developed by the Bord-&Pillar method through Inclines 13, 14 and 24. The workings through No. 13 and 14 Inclines are known as Old Hathidari and through Incline No. 24 as New Hathidari.

13.2 The development of old Hathidari upto its dip-most extent was reportedly completed in 1968 and only a small virgin patch was left undeveloped, which was later taken up in April, 1974 and completed in March, 1975. Only pumping was going on in Old Hathidari to dewater the seam, so that the underlying Bangsora Seam could be developed further. A strike fault traverses both the seams and due to this, there is danger to Bangsora seam if water is allowed to accumulate at the top in the Hathidari Seam.

13.3 The development of new Hathidari was taken up in 1973 and completed towards the end of 1974. The Management's proposal to depillar the patch by open caving was sent to the DGMS in April, 1974 and the permission was granted in January, 1975.

13.4 The new and old Hathidari portions were inter-connected through three galleries and the second access and ventilation circuit to new Hathidari was through old Hathidari. The three interconnecting galleries were sealed off by isolation stoppings, which were completed, according to the Management, after the cessation of the depillaring operations in March, 1976.

Ownership of the mine :

14. The mine was opened in 1946 by the United Collieries Limited. Till January 31, 1973—when the Management of the non-coking coal mines were taken over by the Government of India—the mine was managed by M/s. Karam Chand Thaper & Bros. (Pvt.) Ltd. The ownership of the mine was nationalised from 1st May 1973, along with other non-coking coal mines and it formed a unit of the Ramgarh Area of the Central Division of Coal Mines Authority. Subsequently the name of the area was changed to Barkakana area. With the formation of the Coal India Ltd.—a holding company—the Barkakana Area became a unit of the Central Coalfields Ltd., which is a subsidiary of the Coal India Ltd. The subsidiary company is administered by a full-time Chairman-cum-Managing Director, who is nominated as owner for the purpose of the Mines Act, 1952.

At the time of the accident on 16th September, 1976, the Central Saunda Colliery was headed by the Project Officer, Shri S. K. Mukherjee. He took over charge on 4th August, 1976 from his predecessor, Shri Mewat. The Project Officer is under the administrative control of the General Manager, Parkakana Area and is also the Agent of the Colliery under the Mines Act.

There is one Colliery Manager at the Central Saunda Colliery. Shri K. Doraiswami was the Manager of the Colliery from 9th January, 1974 to 17-9-76 and was transferred to Barkakana on 18th September, 1976. The Manager has assistants under him, holding 1st and 2nd class Coal Mine Manager's Certificates, besides other statutory personnel like Surveyor, Safety Officer, Overman, Sirdars, etc.

PART-II

THE ACCIDENT

Development of a mine :

15.1 The accident involving the lives of 10 persons (Exhibit 25) occurred on 16th September, 1976 as a result of the inundation of the Hathidari Seam of the Central Saunda Colliery.

Water from the surface can enter into the workings if the development of a mine for the extraction of coal has begun and goes on without adopting adequate safety measures to prevent the inflow of water. And one of the important measures to be taken, in order to ensure safe operational conditions, is to see that any river, stream or current of water whether seasonal or perennial, flowing in the neighbourhood, is at a safe distance away from the workings through which the coal is to be extracted. Regulation 126(2) of the Coal Mines Regulations 1957 (CMR), therefore, stipulates that no workings shall be made in any mine vertically below—

- (a) any part of any river, canal, lake, tank or other surface reservoir; or
- (b) any spot lying within a horizontal distance of 15 metres from either bank of a river or canal or from the boundary of a lake, tank or other surface reservoir.

15.2 This means that coal should not be extracted from any part of a seam which is vertically below a current of water or, for that matter, is even within a distance of 15 metres from the surface water. If, however, it is confidently felt that that can still be safely done, the Management must, under the same Regulation, take in writing the permission of the Chief Inspector of Mines appointed under the Mines Act, 1952, and subject the workings to such conditions as may be prescribed by the Chief Inspector for the purpose.

The Management had completed in the year 1968 the development of the greater portion of the Hathidari Seam by the workings through Inclines Nos. 13 and 14, known as Old Hathidari. The development of the remaining small patch of the south-eastern side, during the period from 1973 to 1974, was done by the workings through Incline No. 24, known as New Hathidari. But when this development, which includes partial extraction of coal by farming galleries etc., was under way, the Management did not bring to the notice of the Chief Inspector the fact that they were approaching a big nullah less than 15 metres away and had, in fact, extracted coal lying vertically below that nullah.

The big nullah :

15.3 This nullah, from the adjacent Saunda 'D' Colliery, passes over the Central Saunda property before joining the river Nakari which is also known as river Nalkari. This important fact came to light during the Inquiry when the Court observed that the statutory underground working plan (Exhibit D) maintained by the Management, showed that the development of New Hathidari had taken place near to and below that big nullah. This was confirmed by Shri K. Doraiswami, who was the Manager of the Central Saunda Colliery from 9th January, 1974 onwards when the development of New Hathidari was already under way. He admitted that Exhibit D contained no error, to the best of his knowledge, in respect of the development of the mine. Then asked by the Court why the permission of the Directorate General of Mines Safety (DGMS) was not obtained when the development was proceeding towards the area which was very near or under the nullah, the Manager deposed that :

"We had not sought the permission of the DGMS during the development stage. Not doing so could be termed as a violation of Regulation 126(2) of the CMR. However, the Court may decide on this issue as it deems fit."

Depillaring operations :

16.1 The extraction of coal from a mine is generally done by the Bord-and-Pillar System which broadly means that, in order to prevent the collapse of roofs under which the coal

is being extracted sizeable pillars must be left intact without extracting any coal from those pillars. It is these pillars which support the superincumbent strata during development and add to the safety of the mining operations. At the end of the development process, the Management can, however, embark on the extraction of coal from the pillars also. This depillaring operation results in the formation of a goaf and the caving in of the upper strata. But the depillaring operation can be undertaken only after obtaining a clearance from the DGMS. In other words, while it is not necessary for the Management to seek Government's permission for the development of a mine for the extraction of coal, so long as that process does not violate any provisions of the Mines Act and the Regulations made thereunder, the Management comes under a statutory obligation to obtain a positive permission for the consequential depillaring operations. In seeking the Chief Inspector's clearance for these depillaring operations under the Regulations, the Management has to fill in a prescribed application for that purpose and to submit two copies of an up-to-date plan of the area which is proposed to be depillared.

Danger from the big nullah :

16.2 The Management submitted the application for depillaring New Hathidari with their letter dated 10th April 1974 (Exhibit B-2), followed by another dated 9th August 1974 (Exhibit C-1), which sought to clarify some points raised by the DGMS on the subject. At the top of the application Proforma (revised) 1973 (Exhibit B-1), it is indicated that the application to depillar is being made under Regulations 100(1)/105(1)/126/127. While Regulations 105(1) and 127, which deal with workings under railways and roads, etc. and with danger from underground inundation, are not attracted in this case, Regulations 101(1) and 126 are very much pertinent as they relate to depillaring and danger from surface water. And that being so, it is surprising that the proforma applications filled in by the Manager of the Central Saunda Colliery and accompanied by up-to-date plans of the area to be depillared, did not indicate all the required and relevant information, especially in the context of the development of New Hathidari near and under the water-course, even though the 10th April, 1974 letter signed by the Agent Shri B. Mewar—Superintendent (Mines), Central Saunda Colliery—clearly indicated that a portion of the proposed depillaring area was still under development. The Management should have, in fact, utilised that opportunity to tell the DGMS that they had perhaps made a mistake in carrying on the development upto and under the nullah without their permission. That they did not indicate this could well lead to the inference that it was not a mistake but an attempt to bypass the provisions of Regulation 126(2). This inference is substantiated by the Management totally omitting the nullah from the plan accompanying the application. On page 12 of their cyclostyled statement submitted on 12th March, 1977 and signed by them before the Court on 12th May, 1977, the Management stated that it was through inadvertence that the nullah lying contiguous east of the mine was not shown in the plan. If that was so, when the question arises why against item 10(iii) of the Proforma application, at least, the Management did not depict the correct situation. This item asks the Management to indicate the river, nullah or any other water-course, tank or reservoir lying above or within 45 metres of the proposed depillaring area. The Management in reply just inserted the word 'NIL' against that item, even when they definitely knew that they had gone down to and below the big nullah adjacent to that area. The Management when questioned on this point had to admit that the answer to the item 10(iii) of the proforma application should have been 'YES' and not 'NIL'.

16.3 The Management's contention, as it finally emerged during the Inquiry, was that the statutory plan—Exhibit D—maintained by them had wrongly shown the big nullah as within 15 metres of the proposed depillared area. According to them, the survey made by the DGMS after the accident (Exhibit K) shows the big nullah outside the depillared area and the survey made by the DGMS and the Management jointly (Exhibit S) when the Inquiry was under way, shows the big nullah about 96 to 120 feet (about 30 to 36 metres) away from the depillared area. As such, they had, therefore, in fact not actually violated the provisions of Regulation 126 which requires that the depillared area should be at least 15 metres away from a nullah. It is not always easy to accept the findings of surveys made after the occurrence of an accident when the workings have caved in and there is no access to the depillared area. But even if the two subsequent surveys are to be

taken into consideration,—though the DGMS did not sign the plan in the joint survey—their findings do not still absolve the Management from having given an incorrect picture through item 10(iii) of their application proforma. Though Regulation 126 stipulates that a nullah should be 15 or more metres away from the depillaring area, the application for depillaring requires the Management even then to show any Water course or nullah which is within 45 metres of that area, which was not done by the Management in this case. The intention behind the requirement of item 10(iii) is clear. It is meant to warn the DGMS of the presence of a water-course fairly close in the neighbourhood of the depillaring area, so that they may be able to examine very carefully the implications of such a situation and to prescribe any safeguards that they think are proper to avoid the dangers of inundation of that area.

Danger of inundation

17. Another reply given—in respect of item No. 13 of the proforma application—was equally misleading. That item asks whether there is any danger of inundation from surface water as a result of the proposed depillaring operations, to which the Management's reply was No. When at the time of making their application the Management had nothing else but their own statutory plan, Exhibit D to rely upon, and which showed that the development of the mine had gone very near to and in fact under the big nullah itself, how then could they have said that the depillaring of that area would not lead to any danger of inundation from the surface water. If the Management were really confident that there was no danger of inundation, they should have given their reasons for saying so and should have left it to the Chief Inspector under Regulation 126 to take a final decision in the matter.

Highest flood level

18.1 There is yet another omission of an important fact in the information supplied to the DGMS in the application form for the depillaring operation. Item No. 11 of the proforma application is worded as follows :—

Highest Flood Level.

Does the area lie beneath the highest known flood level of any river, nullah, etc.

The reply by the Management was NO. In order to substantiate that assertion they should have also at least indicated the figure of the highest flood level (HFL) of River Nakari against item 11 of the application form. But if they did not, merely on the ground that that item does not specifically ask them to do so, they should have shown the HFL figure in the plans attached with the application, especially when a "river" according to Regulation 2(28) means "any stream or current of water, whether seasonal or perennial and includes its banks extending upto the highest known flood level". The prints of the plan accompanying the application to the DGMS at Dhanbad, are at Exhibits B-6 and B-7. While Exhibit B-6 shows the river rather faintly, it is difficult to see the river in Exhibit B-7. But the Exhibits do not at all mention the HFL figure of that river. Neither do those prints indicate in a satisfactory manner all the surface contours which have a direct relationship with the HFL in the area proposed to be depillared.

18.2 Though the HFL of River Nakari was not mentioned in the application form or indicated in the accompanying plan, the Management contended during the Inquiry that the HFL figure they had taken into account was 1108' which was attained by the river on 14th October, 1973. They also asserted that the area applied for depillaring was much higher than the 1108' level so that it was not necessary to have shown all the contour lines in or around the depillaring area when the heights represented by the contours were higher than the high flood level figure of 1973. The one contour line of 295.56 metres shown by them in the plan had indicated the high configuration of the proposed depillaring area, in the context of the 1973 HFL of the river.

Adoption of 1973 level as HFL

18.3 Regarding the adoption of the figure of 1108' as the highest flood level of the Nakari river, the Management in their statement submitted to the Court on 12th March, 1977, stated

that the highest flood prior to 16th September, 1976 (the date of the accident) was RL 1108'. But the plan contained in Annexure C attached with the Statement (Exhibit 2-D) showed the figure of 1108' not at the Hathidari Seam but in the form of an inscription on the corner of the plan, which reads as follows :

Old HFL recorded by NCDC Saunda in 1973 was 337.71 mt. (1108.00 feet).

When examined about this, the Manager of the NCDC Saunda Colliery, Shri S. N. Chatterjee, told the Court that so far as he could recollect, their highest flood level was recorded in the statutory plan of their Colliery, but the year of the HFL was not mentioned in any of the plans. Exhibit CR-10 and CR-11, produced in this connection showed that the figure of 1108' was reached in the year 1966 and 1964, but the Manager added that the figure of 1108' was obtained in the year 1966 and earlier and later also. Even assuming that the flood level at NCDC Saunda was known to be 1108' in the year 1973 also, the Court doubted whether the level at the adjacent Central Saunda Colliery, which is upstream of NCDC Saunda, could also be the same. This doubt was confirmed later on when the Court examined the Management's witness Shri B. P. Baliga on this subject. Shri Baliga, who carried out the study, told the Court on 1st November, 1977 that with the HFL at NCDC Saunda being 1108', the corresponding level at Central Saunda would work out to RL 1110.20' for flow of Nakari towards the Damodar. It is, therefore, difficult to rely on the figure of 1108' being the HFL at Central Saunda also in 1973 as indicated in the Management's statement submitted to the Court.

Measurement of 1973 water level

18.4 Though the statement of the Management submitted on 12-3-77 did not anywhere say that they had themselves measured the flood level in their mine in 1973, their Surveyor, Shri P. K. Mazumdar, during his deposition on 12-5-77 stated that he had on 18-10-73 carried out the survey of the high flood on 14-10-73 in Central Saunda and had found it to be at 1108' as mentioned in his Level Book which was then presented by the Management to the Court and is marked as Exhibit 1. This Exhibit shows in pencil the levels recorded near the common boundary of the Central Saunda and NCDC Saunda mines as 932.33; 932.31 and 932.28 feet to which has been added the bench mark of 1975.70' and the mean HFL worked out to 1108 feet. The Surveyor avoided telling the Court whether with the level at the common boundary being 1108', the level would have been higher at the Central Saunda Colliery which is upstream of the NCDC-Saunda. His reason for doing so, according to him, was that he did not have a thorough knowledge of hydrology. He, however, submitted that he had not shown this figure as the HFL in any of the Central Saunda plans, for the reason that the figure of 1108' was not the highest ever-recorded in that Colliery. As the Colliery's plans, Exhibit D and Exhibit 3 reveal, he stated, the highest flood level was attained in 1958 and the 1958 figure of 288.748 metres shown in the statutory surface plan, Exhibit 3, works out to 11023'. If that was so, it is not understandable why he acquiesced in the brick pillar on the side of the Nakari river showing the HFL as 1108'. The pillar, he said, during his deposition on 12-5-77, did not then exist, and the Manager added on 10-8-77 that it was washed away by the September 1976 flood. The examination of the Surveyor on 31-10-77 and on 18-11-77 raise serious doubts about a survey having really or effectively been made at all of the flood level at the Central Saunda Colliery.

If he had made the survey on 18-10-73 and had found the water level at 1108', the Court wanted to know why then in Exhibit CR-1 (seized document by Court, showing the working plan of Hathidari seam) he had written "Old HFL as recorded by NCDC Saunda in 1973 was (337.71 metres) (1108.00 ft.)". His unconvincing reply and which did not answer the question asked was that it was written on the working plan because Central Saunda is adjacent to NCDC Saunda.

But even if it is assumed that the survey was made which showed the level at 1108' the question really pertinent is why the Management ignored the highest flood level of 1123' attained in their Colliery in 1958, as so clearly indicated in their own statutory plans.

Ignoring the 1958 HFL

19.1 The Management's arguments for ignoring the 1123' level were two fold. During his examination on 9th and 10th August 1977, the Manager stated that since the Central Saunda Colliery was taken over (from a private owner), there were no records available with them to survey the correctness of the 1958 HFL, which was probably borrowed from some colliery on the upstream side. In the absence of field book or other records it was difficult, therefore, to verify the correctness of the 1958 HFL shown in their statutory maps and thus the figure of 1958 could not be relied upon. The Court cannot accept this argument. If the Management really had any doubts about the 1958 HFL they could have questioned their surveyor, Shri P.K. Mazumdar about it, as he had been working as surveyor at the Central Saunda Colliery since 1961—that is even prior to the nationalisation and take over of that mine—and since Exhibit D bore his signatures all along. It was brought to the attention of the Court by the DGMS on 15-9-77 that even five years after 1958, the then Management (Karam Chand Thapar & Bros. Ltd.) had in November 1963 applied for permission to work the Hathidari Seam under and within 15 metres of a nullah indicated in the plan signed by Shri P. K. Mazumdar which depicted the HFL of 23-7-1958. That plan also finds mention the Exhibit D. It is, therefore, not at all possible to doubt the authenticity of the 1958 HFL as shown in the Management's statutory plan Exhibit D.

19.2 The second argument advanced by the Management for ignoring the 1123' HFL is related to the construction of the Patratu Dam across the river Nakari about 11 kms. upstream of Central Saunda. According to them, with the Dam's operation from 1968 onwards, the 1123' HFL figure of 1958 loses its significance for all the mines situated along the banks of the Nakari. The Management's assertion is that when a dam is constructed across a river, the pre-dam HFL on the downstream side comes down after the construction of the dam. They could not, however, indicated by how many feet the pre dam HFL would get reduced after the construction of the Patratu dam, evidently because neither they nor anyone else had tried to work out the supposed reduced figure, even though some of the mines along the Damodar had got the reduced HFLs after the construction of the Maithen/Panchet dams. The Management just seem to have simply assumed that with the dam construction upstream across the Nakari, a proper and judicious release of the water from the reservoir by the Patratu Thermal Power Station (PTPS) authorities could have always ensured that the level of the Nakari would never reach the level of 1123' long Central Saunda, and that was why they did not fear inundation of their mines. This is an argument which cannot be sustained. For even if it is assumed that after the construction of the dam, the level of 1123' would have never again been reached, could not a level lower than that when attained—say 1122' down to 1116' or even 1109'—have also resulted in the inundation of the mine?

19.3 If the Management of the Central Saunda Colliery had ignored the 1958 HFL after the completion of the Patratu Dam in 1968, the Court wanted to know whether the other Colliers along the Nakari, adopting that logic, had also done the same. The DGMS, who were asked to go into this, presented a few cases before the Court showing that the 1958 figure persisted in those mines. In the Bhurkunda Colliery, which is downstream below Central Saunda, the Management had shown the HFL of 1139', attained in the mine in 1958, in their plan submitted as late as 1976 for obtaining permission of the DGMS for development under and within 15 metres of a nullah in respect of their Lower Nakari Seam. So far as the Saunda-D Colliery upstream above Central Saunda is concerned, the representative of the DGMS said that, as far as he knew, the 1958 HFL of 1129-30' in Saunda-D was still being shown by the Management in the plans of their mine even after the floods of 1976. It is, therefore, strange that the Management of the Central Saunda Colliery should have ignored the 1123' HFL figure recorded in their mine in 1958 while replying to item No. 11 of the proforma application which required them to say whether the area proposed to be depillared by them lay beneath the highest known flood level of a river. The word used in item 11 is known and not what was accepted or assumed by the Management as the highest flood level of the river. The Management knew the figure of 1123' as the highest ever recorded in their colliery and also knew that the area proposed to be depillared was below that level. They should therefore have, against item 11, indicated why they were not prepared to accept that known figure. If

they had done so, the DGMS after examining their contention would have either not sanctioned the depillaring operation or would have sanctioned it with safeguards that they may have thought were necessary in that connection.

Contour Lines

20. Coming now to the second contention of the Management about the contour lines, referred to in paragraph 18.2 of this report, the fact is that the plan accompanying their application for depillaring did not show all the contour lines. During his deposition before the Court, the Surveyor admitted that he should have shown the contours at a distance of 5 metres vertical intervals but he was not able to do so over an area which was about 400 metres wide on Exhibit 3. He, however, said he had depicted in Exhibit 3, the statutory surface plan, three contour lines of 295.56, 289.56 and 286.50 metres. That he did not do the same in Exhibit D was an act of omission on his part, he said. When asked why only the highest of the 3 contours was shown in the plan which accompanied the depillaring application, and not the two lower ones also he said that Exhibit D on which the plan was probably based had not shown the two lower contours. It was an act of inadvertence, he said, that they did not utilise the information available other than that contained in Exhibit D. About the spot level, he said that he had shown it with regard to the main dip. With regard to the remaining portion of the depillaring area, he added, he might not have found the time to take the levels in the rest of the workings. If all the contour lines and especially the 286.50 metres one had been shown in the plan, the DGMS would certainly have paid greater attention to the implications of the levels in and around the proposed depillaring area with reference to the HFL of 1958 at 288.74 metres of which they must have been aware, since that figure is shown in a number of post-1958 Central Saunda plans of which copies are in their possession.

21. The preceding paragraphs have dealt with the development of the Hathidari Seam and the application made by the Management for depillaring operations. The application was sanctioned by the DGMS on 2nd January 1975, Exhibit J. It is necessary now to see whether the Management implemented that sanction in a proper and satisfactory manner. The reason why this matter deserves attention is that a smaller nullah and an embankment made across it now comes to the fore.

The small nullah

22.1 It has been indicated in paragraph 16.2 that the Management did not show the big nullah in the plan accompanying their depillaring application. That plan and application did not also show or mention a smaller nullah flowing directly over the area to be depillared and which was actually depillared by the Management in the last quarter of 1975. When asked why the small nullah which had a direct bearing on the inundation of the mine was not brought to the notice of the DGMS, the Court received contradictory replies on the subject. The Surveyor, Shri P.K. Mazumdar brought out the fact that the entire area was covered with thick wild growth so that it was not possible easily to see the small nullah. It was only when the overlying surface was cleared of the wild growth, before the commencement of the depillaring operations, that the nullah came to his notice. He then surveyed it and showed it in the statutory plan kept in the Colliery Office. This plotting of the small nullah on the statutory plan must have been done, he said, before 31st December 1974. After going through the Field Book (Exhibit E) he admitted, however, that he came to know of the small nullah by the end of July or the beginning of August 1974 and that, immediately after its discovery, he brought it to the attention of the Manager or the Agent of the Colliery. Though he had not conformed to the requirements of Regulation 49, which deals with the duties and responsibilities of surveyors, he had given the information about the small nullah verbally to the Manager and the Agent.

22.2 That being so, the Court asked the Manager that since he came to know about the existence of the small nullah in early August, i.e. before the second application on depillaring was sent to the DGMS on 9-8-74, why that fact was not brought to the notice of the DGMS. The Manager stated that he was informed about the nullah after 9-8-74, but when told that he must have known about it before the commencement of the depillaring operations and should have, therefore, written to the DGMS about it, he said that he had consulted the Agent, Shri B. Mewar in November 1974 and they had actually decided to inform the DGMS of the existence of the nullah

and the construction of the proposed embankment across it. But they did not do so when just within a month or so after that decision, Shri K. B. Mazumdar, Deputy Director of Mines Safety inspected the 24th Incline of New Hathidari on 13-12-74. The Manager was present during that inspection, but nowhere in his deposition did he tell the Court that he had informed that officer of the existence of the small nullah. This is even more surprising when the Management had commenced the depillaring prior to receiving the DGMS's permission to do so. All this came out before the Court later on through pages, 1, 7 and 8 of Exhibit F-3.

DGMS verbally informed

22.3 When Shri Mewar was asked why the existence of the small nullah—when it came to his knowledge—and the construction of the embankment across it, were not brought to the notice of the DGMS, he said that though they had decided to inform the Mines Department about both the facts, it slipped from his mind to inform them in writing. He did, however, bring those verbally to the notice of Shri K.B. Mazumdar whom he accompanied during his inspection of the mine in August 1975. As no communication was received from that officer he was satisfied or believed that the steps taken by them were adequate and to the satisfaction of the DGMS. Though it may have been a theoretical violation in not obtaining the permission of the DGMS, due to his pressure of work and other day-to-day duties, Shri Mewar said that he was satisfied that depillaring was not likely to endanger the workers, and he did not, therefore, stop that operation.

Contradiction by DGMS

22.4 When the Court examined him, Shri K. B. Mazumdar, Deputy Director of Mines Safety made a definite statement that the nullah were not shown in the surface plan which was presented to him during his inspection in December 1974 and May 1975 and neither did the Management tell him that there was a nullah flowing over or very near to the area of depillaring. Contradicting Shri Mewar, he said that he did not accompany him during his inspection of the Hathidari Seam in August 1975 and Shri Mewar did not either apprise him or bring to his notice the presence of the small or big nullah and the embankment.

Depillaring under the small nullah

22.5 From what has been indicated in the preceding sub-paragraphs, it clearly emerges that the Management carried on with the depillaring operations without bringing to the notice of the DGMS in writing the existence of the small nullah and the embankment built by them across it to prevent an inundation of the mine. Nor did they even verbally inform the DGMS officers who came to the mine soon after the small nullah had come to the knowledge of the Management. The Manager's failure to do so has been brought out in the preceding sub-paragraph. The failure of the Agent was also there, because when Shri S. D. Prasad, Director of Mines Safety, DGMS, made on 12-2-75 a surprise inspection of the depillaring in the Colliery, the Agent discussed with him not the small nullah, but two other points unrelated to the subject, as comes out of Exhibit F.

That the Management should have brought the small nullah and the embankment to the notice of the DGMS is clearly implied, firstly by the sanction letter dated 2-1-75 from the DGMS, Exhibit J, sanctioning the depillaring operations and, secondly, by the provisions of Regulation 126(2) of the Coal Mines Regulations. The rebuttals of the Management in this connection, the effect that they had not violated the provisions of either the sanction letter or the provisions of Regulation 126(2), are, therefore, examined in the two sub-paragraphs below.

22.6 The DGMS's sanction for depillaring was based on the Management's application, the proforma attached to which, among other things, had categorically stated that there was no river, nullah or any other water-course, tank or reservoir on the surface lying above and within 45 metres of the area proposed to be depillared. In permitting the depillaring operations, the DGMS wrote that they had examined the Management's application and the plan enclosed with it and

stipulated that "In the event of any change in the circumstances connected with this permission, which is likely to endanger the workmen, the mine or surface features, depillaring shall be immediately stopped and the Joint Director of Mines Safety intimated. The operation shall not be resumed without a written permission from this Directorate." The point was further emphasised in item 10 of the sanction letter which stated that "If at any time one of the conditions subject to which this permission has been granted is violated or not complied with it, this permission shall be deemed to have been revoked with immediate effect."

The Management's application and the accompanying plans did not indicate that a small nullah was actually flowing directly over the area to be depillared, for the reasons, as put forward by them, that they came to know about that nullah only after they had submitted their applications. Even assuming that that assertion is correct, the Management should have in terms of the sanction letter, informed the DGMS about that small nullah when its existence had come to their attention, and should have waited to see whether they would be permitted to proceed with the depillaring of the area vertically below that nullah. Shri Mewar's explanation to the Court was that since the changed condition, brought about by the knowledge of the existence of the nullah, did not, according to him, present any apprehension about endangering the workers, he did not stop the depillaring operations. That singular and rather unimaginative attitude of the Management, the Court is of the opinion, was highly unrealistic, more so when Regulation 126(2), in very unambiguous words, clearly stipulates that no working shall be made in any mine vertically below any part of any river, canal, lake tank or other surface reservoir.

22.7 The Management knew that they were carrying on the depillaring directly below the small nullah and the justification produced by them before the Court for doing so was that the "so-called nullah", according to their assessment was only a "rain-cut"—a very minor topographical feature—which is common in practically all the mines during the monsoons and which did not, therefore, deserve being brought to the notice of the DGMS. They were doubtful whether the "rain-cut" under which the depillaring was being done actually came under the definition of "nullah" or not. Their argument that a rain-cut may not be covered by anything contained in the Coal Mines Regulations is not at all tenable, since a "river" in Regulation 2(28) covers any stream or current of water and item 10 of the application proforma speaks of a "nullah or any water course". Furthermore, how could the Management have treated a 200 ft. (about 61 metres) water course or rain-cut, which according to Shri Mewar was between 6 to 12 metres in width, as a negligible topographical feature when it was connected with the bigger nullah and the Nakari river. If the Management had brought it to their notice, the DGMS might have allowed the depillaring, not by the total caving method as mentioned in their sanction letter, but by some other method which they might have thought proper in the circumstances. They might have advised them to extract the coal by splitting the pillars and leaving behind stocks of sufficient area to support the superincumbent strata or they might have advised them to go in for the stowing of the goaf. Or they might just have ruled out any depillaring at all considering their assessment of the situation.

Indication of the small nullah in the plans

23. The Court wanted to know whether the small nullah flowing directly over the proposed depillared area was ever actually shown in the statutory plans, and, if so, they why the officials of the DGMS while inspecting the mines did not take that into cognisance and review their sanction for the depillaring operations. The inquiry and the study of the documents and plans in this connection have revealed some very interesting facts. In his statement made before the DGMS on 21-9-76, i.e. 5 days after the accident, the Surveyor Shri P. K. Mazumdar said that he had made a survey of the small nullah sometimes by the end of August 1974 and had shown the rough plan to the Manager and Agent of the mine. He could not, however, plot the position of this nullah (seasonal water-course) on the main Working Plan, or on various tracings or on the hand plans, till April/May 1975, as he was the only Surveyor in the mine and had to attend

to various other non-statutory works as well. He also admitted that he had not mentioned the date of the plotting of the position of the nullah on any of the plans or tracings. The implication of the Surveyor's statement therefore was that any inspection of the mine and the plans carried out by the DGMS after April/May 1975 would have brought to their notice the existence of the small nullah.

The Manager's statement before the DGMS—two days later, i.e. on 23-9-76—however contradicted the Surveyor's contention. What the Manager stated was that the position of the nullah was shown on the hand plans for day to day use, but was not indicated on the statutory plans. He said that the nullah was not shown in the main underground plan upto the time of the accident which took place on the afternoon of the 16th September. It was only at night on 16-9-76, when the main underground plan was brought to the Joint Director of Mines Safety, that he found that the nullah had been shown on the plan. He had seen that main underground plan, he said, after the accident on the same day, when he did not see that nullah on the plan. In their Supplementary written statement, filed on 28-3-1977, i.e. 12 days after receiving the Report of the DGMS from the Court, the Management also stated that the narrow outlet (small nullah) was not shown on the plan asking for depillaring permission, nor in the other plans, prior to the date of the accident. This omission, they added, was absolutely bonafide and without any malafide intention on the part of the Management. These statements of Shri Doraiswami and the Management could, however, also imply that the small nullah was not shown in the plans in order to prevent the inspecting officers of the DGMS from raising questions about the dangers of inundation of the Hathidari Seam.

23.2 The Report of the DGMS, containing the statement of the Surveyor and the Manager, mentioned in the preceding paragraph, was given by the Court to the Management on 12-3-77 and, during the examination of the subject on oath which began thereafter, the deposition of the Management's witnesses took a different direction.

The deposition of the Surveyor was to the effect that the plotting in respect of the small nullah must have been transferred before 31st December 1974 to the statutory mounted plan kept in the Colliery Office; that it was the tracing of that statutory plan that did not earlier show the nullah and that it was that racing cloth plan which was made up to date when it was taken on the night of 16th September for discussion with the Manager, Agent, General Manager of the Colliery and the Director and Joint Director of the DGMS.

The Manager's deposition was also to the effect that the plan which was shown to the Joint Director of Mines Safety for discussion on 16-9-76, after the occurrence of the accident was the tracing cloth plan on which the nullah was not shown upto the time of the accident. But the statutory plan—Exhibit D—as far as he could recollect was up to date at the time of the inspection of the mine by the Deputy Director of Mines Safety, Shri K. B. Mazumdar. It was, of course, difficult to remember whether any particular feature was shown on any plan on any particular date and this would imply, he stated, that the smaller nullah may have been in Exhibit D or may not have been in Exhibit D when the inspection was made by Shri K. B. Mazumdar in May 1975. The Manager's deposition, therefore, implied that while it was not the statutory plan, but its tracing which was up to dated on 16th September, after the accident, he could not be definite about when and whether the small nullah was shown in the statutory plan, though at the time of inspections by the DGMS the plans show the latest position of the workings of the mine. Referring to the Management's written statement that none of the plans showed the small nullah, the Manager said that the Management did not have the opportunity to check up the plans, because those and specially Exhibit D, the statutory plan, had been immediately seized by the DGMS after the accident. It is correct that while filing their written statement on 23-3-77, the Management did not have Exhibit D with them which had been seized by the DGMS on 17-9-76. But they had another statutory plan with them which purported to show the small nullah. This plan Exhibit 3, which showed the surface plan of Central Saunda Colliery, was later on submitted by the Management to the Court on 26-4-77. In other words, the Management had not taken the trouble to check up all the plans with them while filing their written statement before the Court.

23.3 Assuming then that the statutory plans—particularly Exhibits D and 3—did show the small nullah, the Court examined the Deputy Director of Mines Safety, Shri K. B. Mazumdar who inspected the Central Saunda Colliery after the DGMS had permitted the depillaring operations. As mentioned in paragraph 22.4 Shri Mazumdar had told the Court that the nullahs—both the big and smaller ones—were not shown in the surface plan which was presented to him by the Management during his inspection of the mine in December 1974 and May 1975. This meant that Shri Mazumdar was not even made aware by the Management of the development of New Hathidari which was completed towards the end of 1974 and which had gone up to the big nullah or even below it; it also meant that the smaller nullah was also not shown in the plan presented to him by the Management for inspection. While one may perhaps give Shri Mazumdar the benefit of accepting his assertions, in view of the Manager's deposition that the smaller nullah may have been there in Exhibit D or may not have been there during the time of Shri Mazumdar's inspection in May 1975, an interesting question arises from Shri Mazumdar's further statement on the subject. He stated that the nullahs were drawn on the statutory plan after his inspection in August 1975. These nullahs, he continued, have been shown in different inks and they seem to be fountain pen inks, which are statutorily not accepted. There are some impressions, he said, in the plans which show definitely that something has been erased and later on redrawn in different ink. This has been done, he stated, in both the statutory plans—Exhibit D and Exhibit 3. While he had seen Exhibit D in June 1974 and again in December 1974 when he was processing the depillaring application, he must have seen Exhibit 3, he said, during his general inspection of 1974-75, but when he saw those two Exhibits, he did not notice then any erasings which, he added, must have taken place after his inspection. The implication of such a statement would be that the big and small nullahs were not there at all in the exhibits which had been shown to him and hence there were no erasures either in those plans. If the nullahs had been shown in the exhibits, the implication would have been for him to stop the development and the depillaring in the Hathidari Seam. During his cross-examination, so far as the erasures were concerned, the Management put it to Shri Mazumdar that there was no mala fide intention on their part in making the erasures and that the erasings shown in the underground working plan may have been made in order to rectify certain mistakes in plotting, etc.

Erasure in the plans :

23.4 The substance of Shri Mazumdar's deposition in the preceding paragraph is that the nullahs were not shown by the Management in Exhibit D or Exhibit 3 when he had occasion to see them during.

- (i) his inspections in 1974.
- (ii) his processing of the depillaring application, and
- (iii) during his inspections in 1975,

and that the nullahs, which came to his notice in the exhibits during his examination by the Court, must have been drawn and then erased on the plans by the Management after his inspection in August 1975.

It is difficult to accept the above contention, for why should the Management have drawn those nullahs, and then erased them, and later on redrawn them—and all this after August 1975—if it was their intention not to reveal the nullahs at all to the DGMS, in order to get away with the development and depillaring in the Hathidari Seam. A conclusion that could, therefore, be arrived at is that the big nullah, a prominent feature, was shown in the statutory plans, but realising that inspection by the DGMS of the mine and the plans after the commencement of the depillaring operations might place them in a very awkward position, the Management may have very finely erased that feature, so that it may not strikingly, and at first glance, come to the notice of the inspecting officers. That feature had, of course to be hurriedly relinked immediately after the accident, for if that had not been done, it would have placed them in an even more serious position. So far as the small nullah is concerned, it may perhaps also have been there in the statutory plans, though the deposition of various officers from the Management does not clearly establish that beyond doubt. The Surveyor had originally stated that he could not

plot that nullah till April or May 1975 and had thereafter taken the line that he must have done it before the end of December 1974. The Manager's statement only implied that since plans are supposed to be kept up-to-date at the time of DGMS inspections, the small nullah must have been shown in the statutory plans, though he was not quite sure whether that was or was not actually done. And what Shri Mewar, the Agent, told the Court was not that the Deputy Director of Mines Safety had seen or was shown the plan with the small nullah on it. His statement simply was that the "embankment and the nullah was verbally brought to his notice", a fact which was denied by Shri Mazumdar. The small nullah must have, therefore, either been shown for the first time, or re-linked, immediately after the accident.

23.5 From what has been indicated in the preceding subparagraphs, it is doubtful whether the small nullah was distinctly shown in the statutory plans. For if it had been so exhibited, it seems most unlikely that any officer of the DGMS would have ignored its implications during his inspection of the mine. Shri J. C. Aggarwal, Joint Director of Mines Safety also inspected the mine in May 1975 and though he had no occasion to examine the statutory plans in that connection, the other plans which he saw, did not, according to him, show the position of any river or nullah.

Embankment across the small nullah :

24.1 Another reason given by the Management for not bringing the existence of the small nullah to the notice of the DGMS was that since they had taken effective protective measure by constructing an embankment across it, it did not need reporting to the DGMS. The area proposed to be depillared was quite high according to Shri Mewar and was bounded by high ground along the big nullah and Nakari river and there did not appear any danger from inrush of surface water from Nakari or the adjoining jore. But when they cleared the area of wild growth and observed the rain-cut cutting a small portion of the high ground, they restored the high ground level there by building an earthen embankment so that the outside water may not enter that area until it reached or overtopped the high ground all along. The construction of the embankment was taken up in late 1974 and was probably completed by April or May 1975. The bundh was constructed at 1105 ft. above MSL : its height was 10 ft. corresponding to an RL of 1115 ft. at the crest. At top it was 2 metres wide and at the bottom it was 11 metres. The side slope was 1 in 1.5 and the material used was local earth from the surrounding area for the construction of the embankment by manual compaction in layers. With these specifications given by the Management the depth of the small nullah cannot be construed as a negligible factor and they should have consulted the DGMS about the embankment as a protective measure to be taken by them to prevent the inundation of the mine. The DGMS could then have suggested the type of the embankment to be built and the material to be used, for instances were on record with them of the failure of embankments constructed at the mines. While advising them about the embankment, they would obviously then have gone into the whole question of the HFL and could have also reiterated an earlier guideline about the withdrawal of the workers, in order to save them from inundation. According to a general guideline, the DGMS would have again brought to their attention that the withdrawal point should be fixed in relation to the HFL and that for the purpose of the withdrawal of the workers, the natural bank of the river only, rather than the embankment should be taken into consideration.

24.2 The Management's argument for not consulting the DGMS in this connection was that in terms of Regulation 126(1)(a) it is for them to provide and maintain adequate protective measures; that it is not obligatory on their part to inform the Chief Inspector about those measures and whether such protection is adequate or not has to be determined by the Chief Inspector on his own.

Regulation 126(1)(1) is worded as follows :

"Where any mine or part thereof is so situated that there is any danger of inrush of surface water into the mine or part, adequate protection against such

inrush of water shall be provided and maintained. Whether such protection is adequate or not can be determined by the Chief Inspector whose decision shall be final."

Bringing in Regulation 126(1)(a) into the picture is irrelevant, since that regulation deals only with the protective measures in general which a management is required to take in relation to where the mine is situated. It does not deal with the working of the mine, the issue which is under examination. The working of a mine is governed by Regulation 126(2) which stipulates that no working shall be made in any mine vertically below any part of any river or any spot lying within a horizontal distance of 15 metres from the bank of the river, except with the permission in writing of the Chief Inspector and subject to such conditions as may be specified by him.

HFL and crest of embankment :

24.3 The height of an embankment, designed to prevent an inrush of water into a goaf, has a relevance always to the HFL of the river from which the water is likely to overflow the embankment directly and also through the connecting nullahs. In his testimony, the Surveyor, Shri P. K. Mazumdar informed the Court that though the 1958 flood level only was indicated in the plans, yet the lower 1973 level was taken into consideration while fixing the height of the embankment and added that he did not decide on the designing of the embankment. The implication of his statement is clear. It means that at least so far as he was concerned, he could not have ignored the 1958 HFL recorded in the colliery while designing the embankment. In fact, he had admitted before the Court that the crest of the embankment was 8 feet below the HFL of 1958. The Manager, however, refuted the statement of the Surveyor and said that the earthen embankment was constructed under joint consultation with the Agent, Shri B. Mewar and the Surveyor, Shri P. K. Mazumdar. So far as he was concerned, Shri Doraiswami said that he got the information about the 1108/HFL from the Surveyor's level Book, Exhibit land also from the brick pillar on the bank of the Nakari, indicating the HFL of 1973 which was 1108'. Shri Mewar also said that the HFL was marked on the pillar on the bank of the Nakari river, near the area where they had planned the depillaring operations. Though the Surveyor may not have known anything about hydrology, the two senior-most officers—the Agent and the Manager—should at least have realised that the Surveyor's level Book showed the figure of 1108' at the boundary of their mine with NCDC Saunde and that even if a brick column had been put up near the proposed depillaring area, the height of the water level at that point would certainly have been higher than 1108'. In his deposition, the electric helper, Shri K. N. Tewari who was near the goaf between 12 noon and 1 p.m. on the day of the accident told the Court that he did not recollect seeing the brick column, and that even prior to 16-9-76 the existence of that column was not known to him because he had never seen it himself. Furthermore, when the Management was going in for the earthen embankment as a protective measure, they could have constructed water dams instead of the isolation stoppings under the goaf, in view of the fact that development had already taken place on the dip side of the proposed depillaring area. Isolation stoppings are meant primarily to prevent the danger of fire in the mines, due to spontaneous heating taking place in a goaf. These stoppings are not meant to withstand any heavy pressure of water and are, therefore, provided with water seals to permit the passage of percolating water in the goaf to flow towards the pumps installed on the dip side in the Inclines to withdraw that water. There is, however, always the danger of the seals getting blocked, resulting in the accumulation in rainy season of a large quantity of water inside the goaf. This can lead to a breach of the isolation stoppings and to an inrush of water from the rise side goaf to the dip side workings and thus endanger the lives of the workers engaged therein. The Manager, in this connection, admitted before the Court that probably if the water dams were designed and constructed to suit the pressure of water that they would have to withstand the accident might have been averted. It is a pity that dams were not put up to prevent any likely accident and that it was only after the accident had taken place that Management thought of constructing 4 dams underground in the Hathidari Inclines with a view to isolate the depillared area from the rest of the workings and to prevent any other accident in the future.

Ignoring the 1958 HFL

24.4 From the manner in which the Management acted, the inference is fairly clear. When they constructed the embankment they did not relate its height to a realistic high flood level figure. What they simply did was to block the small nullah within the surrounding high ground by raising the embankment built across it, to the level of the high ground which was 1115'. Since that figure of 1115' could arithmetically be related well to flood level of 1973, which they assumed was 1108' they associated the figure of 1115' with the figure of 1108' so that they could, if and when required, argue that the embankment was built 7' higher than the HFL, as against nearly 5' (i.e. 1.5 metres) prescribed in Regulation 126(1)(b). Adopting the 1958 figure would have practically ruled out any depillaring operations, unless they were prepared to raise the embankment and the surrounding ground to a very much higher level and to leave behind stocks of sufficient size or to stow the goaf after the depillaring was over. Since all this would have meant a great expenditure, the Management probably thought it best to ignore the 1958 HFL on the assumption that the water could never reach or surpass that level after the construction of the Patraru dam in 1968. The adoption of the 1108' flood level and ignoring the HFL of 1958—was obviously not a correct line of action taken by the Management, especially with the figure of 1108' having been evidently surpassed in the year 1975. According to the Manager's deposition before DGMS on 17-9-76, his recollection was that in 1975 the water against the earthen embankment was 4-5 feet below the top. This means that the HFL in the year 1975—even if for a short duration was between 1110' 1111feet, and had belied the Management's assumption that the 1108 feet figure of 1973 could never be surpassed after the construction of the Patraru dam. Should they have not then done some rethinking about relying on HFL of 1108 feet in the Central Saunda Colliery.

Accident on 16th September

25.1 Let us now examine how the accident took place on the 16th September 1976.

During the monsoon period there is generally an increase in the water level in underground mines as a result of strata percolation and of rainfall over the goaf area which finds its way down to the workings through cracks on the surface caused by depilaring operations.

On the night of 15th September 1976 it had rained fairly heavily and there was drizzling rain also on the morning of 16th September when it was noticed that the amount of underground water was increasing in almost all the Inclines in the Central Saunda Colliery, like Semana, Hathidari and Bangsora. It was at 6.30 a.m. on 16th September that the Senior Executive Engineer (E&M), Shri A. Kundu received information that the water level was rising in the Semana Incline. He, therefore, instructed the Electrical Supervisor, Shri A. K. Sen Gupta to take two gangs of tyndels and arrange for the withdrawal of the two pumps in that Incline. When the Supervisor, along with the two gangs went down the Incline at about 8.30 a.m., they found that the pump had already been drowned but that it would still require the two gangs to work on the withdrawal of the switchgear.

25.2 In old Hathidari there was no coal raising from the mine. But there was a high capacity pump in the Incline installed near the 24th level in the main dip for a dewatering process in order to ensure safety of the workers in the Bangsora Seam below and to supply the pumped out water in the colony. On the morning of 16th September, when at the end of their shift at 8 a.m., the Pump Khalasi, Shri Diljan Mian and his helper handed over charge of the pump to Shri Ram Nath and, Birju Pasi, Shri Diljan Mian informed the Assistant Manager, Shri Sukh Dev Raj Sharma that water was rising in the Incline and the pump required shifting from the site. Diljan Mian was asked by the Assistant Manager to report the matter to the Foreman-in-charge (Electrical), Shri O. N. Sharma, which he did about 8.15 a.m. After the Foreman informed the Executive Engineer (E&M) Shri N. Nayak about this development, Shri Nayak told him at about 8.30 a.m. that workers should be sent down to the Hathidari Incline. He said that he had also instructed the Foreman trainee (Shri

Kameshwar Pandey) and mechanical fitter (Shri Idris Mohammad) to go down the Incline to assess the situation. They probably went down the Incline, according to the Manager, at about 11 a.m. When told by Shri O. N. Sharma that there were not enough skilled workers, Shri Nayak said that he would arrange for the sending down of workers to the Incline on the receipt of a report from Shri Idris Mohammad and Shri Pandey. When the Electrical Supervisor, Shri A. K. Sen Gupta, along with Shri Balbinder Singh, came up from the Semana Incline at 9.30 a.m., he met Shri Idris Mohammad who told him that the Manager and Shri Nayak had asked him to go down to lift the pump from Old Hathidari. He, therefore, requested Shri Sen Gupta to quickly send down the tyndels to the Incline. When Shri Sen Gupta came back to the pit top, the Manager also asked him to divert the Semana tyndels to Hathidari Incline, upon which Shri Sen Gupta instructed Balbinder Singh to go back to the Semana seam and get the tyndels from there. Thereafter the Manager asked the electrician, Irshad, to go down to Hathidari. Since Irshad could not do that, as he did not know the way, the electrical supervisor instructed Shri Sitaram Sahu to go there, along with the helper Shri Tribhuvan Lal.

Persons who went down the Incline

25.3 According to Shri Kundan Singh, he and the other tyndels came up from the Semana seam, after getting the switchgear out from there at about 10.45 a.m. and recorded their attendance at the Old Hathidari Incline at 12.30 p.m. He could not say why their attendance was marked at 11.15 a.m. in the attendance register. They went to the stores to collect materials from the godown and also had tea before going down the Hathidari Incline at 12.30 p.m. The seven persons who went down the Incline were:

Sarvashri

- (i) Kundan Singh—Tyndel
- (ii) Abilakh—Tyndel
- (iii) Ramdeo—Tyndel
- (iv) Balbinder Singh—Tyndel
- (v) Rajdeo—Tyndel
- (vi) Kishun—Tyndel
- (vii) Bhulai Kumar—Tyndel.

The first three who were carrying tools and equipment went rather slowly down to about the 15th level of the Incline, while the other four reached the 23rd level in about 15 to 20 minutes, i.e. at about 12.45 p.m. The following were already there near the pump site:

S/Shri	(viii) Modh. Idris	Mechanical Fitter
	(ix) Fakir Mohammad	Fitter Helper
	(x) Sitaram Sahu	Electrician
	(xi) Tribhuban Prasad Lal	Electric Helper
	(xii) Ramnath	Pump Khalasi
	(xiii) Birju Pasi	Pump Helper
	(xiv) K. Pandey	Foreman Trainee

Inrush of water in the Incline

25.4 Balbinder Singh said that on reaching the pump-site at 23rd level, Mohd. Idris, the Mechanical Fitter told them that they had come late and the pump was getting drowned. Balbinder Singh was 5 to 10 minutes at the 23rd level when he noticed air coming in, followed by a sound. He then told Mohd. Idris that he was running away because water was coming in. He shouted "Bhago bhago, uper se pani a raha hai" and rushed up the Incline. At first the volume of water was less and then its force increased. He caught hold of a signal wire and came up to the spot from where the water was rushing in. When he reached that spot near the 15th level, the rush of water had increased and there was danger of his being swept away. After leaving the signal line, he bent

down and caught hold of the railway line and came up. Kundan Singh who was at the 15th level, where the stopping was provided with an opening, heard Balbinder Singh saying that he would not be able to survive, upon which he asked him to stretch out his hand so that he could pull him out of the water. He succeeded in pulling up Balbinder Singh and saving his life. Kundan Singh, along with the other two tyndels also helped to save the life of the contractor's men by pulling them up from the inrush of water. There were 6 workers employed by a contractor who had gone down the Incline at about 9 a.m. to construct a new stopping in the stone drift between the 19th and 20th level. Kundan Singh sent Balbinder Singh up the Incline with Abilakh. Balbinder Singh fainted on coming to the surface and recovered in the hospital thereafter. Abilakh confirmed the testimony of Balbinder Singh that while he, along with Kundan Singh was resting at the 15th level, he saw an opening of the size of $3' \times 2\frac{1}{2}'$, after which he heard a sound and saw the air coming in. Then he saw the water gushing in from the opening when they shouted to the workers down below to rush up. Apart from the contractor's man the only person belonging to the colliery who survived was Balbinder Singh. The other ten at the pump site-mentioned at serial nos. (v) to (xiv) in paragraph 25.3 above could not come up and were all drowned by the gushing water.

Attempts to rescue the workers

25.5 The Manager, Shri Doraiswami who rushed to the Incline on getting word about the entry of the river water into the Hathidari goaf, saw from the 14th level that the water was pouring in with great fury through a breached ventilation stopping on the south side. In an attempt to reach the entrapped persons, at a great personal risk to himself, he tried to go down further but could not proceed beyond the 15th level due to the great force of water behind him. He then retreated to the 14th level and ordered sand-bags to be lowered so that a barricade could be erected in the main dip to divert the water to the north side cross-out area where there was some standage for water. He also instructed that a set of empty tubs be lowered down the Incline so that if they reached the work-site, the persons there could catch hold of them and signal to be hauled upto safety. Unfortunately all those efforts proved infructuous.

By about 4.30 p.m. the water had reached the 2nd level of the Incline. Arrangements for dewatering the mine were made on the evening of 16th September, but the actual dewatering could start only the 18th after the level of the Nakari had come down and the river water got separated from the water of the Hathidari Incline. Up to the mouth of the Incline, the quantum of water was 173 million gallons: since 48 million gallons were always there from the 34th level upto the 24th level, it meant that 125 million gallons of water had gushed in to completely inundate and submerge the Incline. It took nearly 2 1/2 months to dewater the mine and to recover the dead bodies (Exhibit 25). Due to the general increase in the make of water, the Semana Seam had also to be dewatered simultaneously with the Hathidari Seam.

Delay in saving the Pumps

26.1 From the testimony received by it, the Court cannot help but coming to the conclusion that though the removal of pumps from the workings of the mine is almost a regular activity during the monsoons, as stated by the Management, this activity in the Central-Saunda Colliery on 16th September was carried out in a slow and belated manner. The Electrical Supervisor was informed at 6 a.m. by the Pump Khalasi that the level of water was rising in the Semana Seam and that the pump should be withdrawn from that seam. It, however, took 2 1/2 hours for the Supervisor to go down that seam at 8.30 a.m. along with two gangs of tyndels for lifting the two pumps from that seam. This delay was probably due to the fact that orders to go down the seam had to be obtained from the Senior Executive Engineer and the necessary equipment and material had to be collected before going down the mine. But when they reached the pump site, they found that the pumps were already drowned so they had to engage themselves only on the task of withdrawing the switchgears. If the Management had acted quickly according to some prescribed procedure which must always rule out all possible delays - the pumps in the Semana could have been saved.

Delay in going down the Hathidari Incline

26.2 In the case of the Hathidari Incline, word about the rising level of water there was received at about 8.15 p.m. by the Foreman-in-charge and though instructions had been issued by 8.30 a.m. that the pump should be shifted, it took the tyndels four hours to go down to the Incline, even though in between at about 10.15 a.m., Birju Pasi, the pump helper had come up to inform the electrical foreman-in-charge that the water in the Hathidari incline was continuing to rise and was nearing the bed plates of the pump. If the tyndels who had come up from the Semana incline between 10.30 and 10.45 a.m. had immediately gone into the Hathidari Incline, they could have reached the pump site by 11 a.m. and since according to the Management, it should not take more than 1 1/2 to 2 hours to shift the pump to a higher level, they could have completed that work slightly before 1 p.m., round about when water started rushing into the mine. But there seemed to have been complacency all round amongst everyone directly or even indirectly connected with the saving of the pumps for the reason perhaps that saving the pumps from drowning, according to them, is a routine and not serious matter. The tyndels on coming out of Semana at about 10.30 a.m. should have been in a position directly to proceed to Hathidari, especially when it was known at about that time that the pump there was in danger of being drowned. The Attendance Register however showed that they reported at the Hathidari seam at 11.15 a.m. But both Balbinder Singh and Kundan Singh contradicted that entry in the Register and asserted that they went down the Incline at 12.30 p.m.

Delay in shifting the pump leading to the accident

26.3 The Officers who knew about the danger to the pump also did not take any effective steps to ensure that the pump was shifted to a higher level as soon as possible. The argument was that they did not have enough tyndels to go down to the different inclines at the same time. But if, as asserted by the Management, there is a danger always during the monsoons about the drowning of the pumps, should they not have had a prescribed procedure to deal with such a contingency in order to maintain and save all the pumps. Evidently such an effective procedure was not there, even though the directive from the Colliery' headquarter dated 21-8-75 (Exhibit CR-14E) spoke about the formulation and implementation of a rainy season action programme and required the Colliery managements to certify by 31st March every year that all necessary arrangements for dealing with rains had been made. On 18, 19th February 1978 (Exhibit CR-141) Shri B. L. Wadhwa, Managing Director, Central Coalfields Ltd. had written to all the General Managers, sub-area Managers, Colliery Managers and Under Managers and the Safety Officers personally to check up their safety organisation at different levels and the steps required to be taken to achieve the objective of making their mines absolutely Safe and accident-free during the year 1976. This was followed a few days later by the issue of general guide lines dated 20/24th February 1976 (Exhibit CR-14K) on the precautions to be taken against inundation, etc. well before the rainy season. It suggested that installation and maintenance should be done carefully and systematically and persons adequately skilled and insufficient number must be provided. To ensure that, it was stated, some relationship should be worked out between the work-load based on the total HP or the number of equipment or the extent of the mine and the number of engineers/supervisors, personnel needed to instal and maintain them well. In this context of the safety measures to be taken, the Colliery management could have with good reason kept a small number of tyndels and other staff in reserve, or could have rearranged the duties of the existing staff in such a manner as to save the pumps in the mines from inundation during the rainy season. If this had been done at Central Saunda, gangmen, fitters, electricians and supervisors could have been sent down immediately, and simultaneously, if so required, to all inclines to save the pumps. The workman would then have shifted the pump in Hathidari to a higher level and would have come out before the water started rushing into the Incline. The gush of water would then have resulted in drowning the pump, but not in taking the life of as many as ten persons in that Incline.

Compensation to families of the deceased

27. With great difficulty, due to the disruption of the communications, Shri A. K. Chatterjee, General Manager, Barkakana area, along with his officers managed to reach the Central Saunda Colliery on the evening of 16th September. On the

17th, the Managing Director of the Central Coalfields Ltd., Shri B. L. Wadhwa; the Director General of Mines Safety, Shri S. S. Prasad; the Deputy Commissioner, Hazaribagh Shri D. S. Mukhopadhyay and his officers visited the Colliery Shri Bindeshwari Dubey, Minister of Health, Government of Bihar; Shri K.S.R. Chari, Secretary, Department of Coal Ministry of Energy, Government of India; and Shri A. U. Sarma, Joint Secretary, Ministry of Labour, Government of India also visited the Central Saunda Colliery and other collieries which were affected by the flood. Lt. General K. S. Garewal, Chairman, Coal India Limited, who reached the Colliery on 18th September assured all possible and speedy relief to the families of the victims. Shri S. Das Gupta, General Secretary, Indian National Mine Workers Federation; Shri Damodar Pandey and Shri Chautranan Misra, MLA also visited the Colliery. The relief provided was as follows :—

- (i) Rs. 500 on the spot by the Management to the family of each victim, in addition to one month's free ration;
- (ii) Rs. 500 on the spot by the State Government to each of the families in addition to one week free ration;
- (iii) Rs. 200 by the Management towards funeral expenses to each family;
- (iv) Rs. 2000 to each bereaved family from the CCL Benevolent Fund;
- (v) Rs. 250 by the Coal Mines Welfare Organisation (Ministry of Labour, Government of India) to each of the families, with monthly pension of Rs. 75 to the widows and scholarships for their children;
- (vi) Employment offer by CCL to the nearest relatives of the victims.

Other dues of the workers like wages, arrear wage, attendance bonus refund of AE(CD) claims and gratuity were settled and the payments made within one month of the accident. Refunds of Coal Mines Provident Fund accumulations were immediately processed and payments of dues under the workman Compensation Act, between Rs. 21,000 and Rs. 23,100 for each of the victims, was deposited with the workmen Compensation, Commissioner Dhanbad.

A cash award of Rs. 3,000 was given to the tyndel, Balbinder Singh, the only person who managed to escape from the disaster.

Water level rise on 16th September

28.1 The preceding paragraphs have dealt with the accident that took place on 16th September 1976 as a result of the surface river water gushing through the goaf into the Hathidari Seam. It has now to be examined whether the Management had a proper system of forewarning about any danger of inundation of their mine and whether they could have, and did take proper precautionary safety measures in the light of the rising water level, to withdraw the persons working in the 13th incline and save them from the disaster that occurred round about 1 p.m. on that day.

Between 9.15 to 10.30 a.m.

28.2 From the depositions made before the Court by those who had witnessed the water level on 16th September, it emerges from the testimony of Shri Kundu that it was between 9.15 to 10.30 a.m. on that day that the level had increased to be above the RCC bridge over the Nakari. Shri A. Kundu, the Senior Executive Engineer (E & M) who had to go out of the Central Saunda Colliery for the Purpose of getting repaired the regulating valve controlling the winder No. 2 in Pit No. 2, had occasions to cross the RCC bridge over the Nakari, near its confluence with the Damodar. When he was going in his car for the repair to the workshop, there was knee-deep water over the bridge at about 10.15 a.m. and he did not cross it. At 11 a.m. when the Agent, Shri S. N. Mukherjee went out, he also saw the water flowing 2' above the bridge, according to his estimation. According, however, to the testimony before the DGMS by the Safety Officer, Shri S. K. Dutta Choudhary and the Under Manager, Shri K. K. Gupta, the water level even prior to 10.30 a.m. or 11.00 a.m. was on the increase. At 8.30 a.m. on 16th September, when from a distance of 300' away, the Safety Officer saw the water situation, he told the DGMS in his signed statement on 17-9-76 that the water

in the nullah was about 5' below the top of the embankment, i.e. at RL 1110'. Thereafter during a verbal discussion with the DGMS, the Managing Director and the Director of Mines Safety—when a question arose whether the water appeared to be 2' below the top of the earthen embankment—the Safety Officer asserted once again that the water appeared to be 5' below the top of the embankment. This reassertion, Exhibit A-9, was made in his own hand-writing and signed the same day, i.e. 17-9-76. Shri K. K. Gupta also told the DGMS, on 22-9-76, that he had found that the water level was about 3' below the embankment near the New Hathidari goaf area. But when it came for them to depose before the Court, both of them took another line and said that the level they had seen was not with reference to the top of the embankment but to its base or toe. What Shri S. K. Dutta Choudhary told the Court on 14-7-77 was that when he made the inspection at about 8.30 a.m., he guessed that the water level was about 3' to 5' below the base of the embankment and so he sent word to the manager that there was nothing alarming at that time. In his deposition, Shri K. K. Gupta told the Court on 27-4-77 that he saw the level of the water at 9 a.m. from a place near the top of the Bangsora Incline which was 300' or more from the goaf area of the Hathidari Seam and had assessed the level as being about 3' below the toe of the embankment. When it was suggested to him that the toe of the embankment would not be visible from near the top of the Bangsora Incline, he said that that was so and that it was only his assessment that the water level would be about 3' below the toe of the embankment.

28.3 Even if it is contended that the deposition made by the witnesses on oath before the Court of Inquiry have a greater weightage or veracity than their statements before the DGMS—who also conduct a statutory inquiry very soon after the occurrence of an accident under Section 23(2) of the Mines Act, 1952—it is not practicable always to totally ignore everything that the witnesses tell the DGMS, especially when their depositions later on before the Court are not clearly substantiated or even completely borne out by what is brought out before the Court. It is difficult to go by the depositions of the Safety Officer and the Under Manager, particularly when the Management in its two written statements filed before the Court said something quite positive about the water level having gone up fairly high on the morning of 16th September. On page 3 of its written comments on the Report of the DGMS, received by the Court on 28-3-77, the Management stated that the assessment of the Nakari water level at 8 a.m. on 16-9-76 by Shri S. K. Dutta Choudhary could not be correct and that from the available informations, the water level at that time could not be more than 1108', i.e. 7' below the top of the embankment. The figure of 1108' thus given by the Management, though somewhat lower than 1110 feet and 1112 feet stated by the 2 officers before the DGMS, is still nowhere near the figures of 1100 feet and 1102 feet which work out according to their deposition before the Court.

Then in the Supplementary information, by way of its comments on the Statement filed by the Rahtriya Colliery Mazdoor Sangh (RCMS) and amended on 25-4-77, the Management said that it was a fact that the RCC bridge between Bhurkunda and Saunda got submerged by about 11 to 11.30 a.m. which corresponded to the last known highest flood level of 1108 feet. So if the water level downstream at that bridge near NCDC-Saunda, as implied by their statement, had reached RL 1108 feet, would not the level at their own mine have become at least 3 feet above the toe of the embankment at 1105 feet. Even Shri S. N. Chatterjee, Manager NCDC-Saunda Colliery confirmed that the level of the Nakari adjoining the Central Saunda Colliery would always have been higher at any point of time than the level at NCDC Saunda. The level reached between 11 and 11.30 a.m. at the RCC bridge downstream should thus have acted as forewarning to the Management. The bridge got submerged even earlier than 11 a.m. as comes out later in Part III of this Report.

At 11 A.M.

28.4 In its comments on the Report of the DGMS, the Management said that from the observations of the various persons, the water level was at least 5 feet below the top of the embankment at 11 a.m. That water could reach that level was something not unusual; the Agent, Shri B. Mewar, in his statement before the DGMS on 21-9-76 had said that in 1975, during the highest flood in Nakari, the level of the water had reached 5 ft. below the top of the embankment.

He, however, contradicted this statement before the Court on 12-8-77 by saying that actually what was recorded as 5 ft. should be 5 metres because in 1975 there was no high flood in the river Nakari. The Manager in his statement before the DGMS on 17-9-76 had said that in the previous year also, water had risen above the Nakari bridge and that the water against the earthen embankment was about 4-5 feet below the top. Knowing then that the H.F.L. of 1108 feet, which they had assumed for the construction of their earthen embankment had been surpassed in 1975, why were the Management not alerted about taking some special measures like the installation of flood alarms and the setting up of observation points at suitable places in the mine for a constant and uninterrupted watch of the water level during the rainy season in 1976. They had almost a year to do all this but nothing at all was done in that connection. Knowing, however, that the water level at 11 a.m. on 16th September had touched the figure of about 1110 feet, as indicated in their written statement, should not the Management round about 11 a.m. and in fact even earlier have started withdrawing the persons from Hathidari and prevented persons going down that Seam, when water had reached at least 5 ft. below the danger point, i.e. the crest of the embankment.

Withdrawal of persons from the mine

29.1 They should have certainly done so because they could not have been unaware of Regulation 126(1)(b) which states that every entrance into a mine should be so that its lowest point—which means the point at which a body of rising water on surface can enter the mine—shall not be less than 1.5 metres (about 4.92 feet) above the highest flood level at that point. So, when the water came up to 3 to 5 ft. below the crest of the embankment which was at height of 1115 feet, it meant that the flood had touched the level between 1110 and 1112 feet, i.e. a level higher than H.F.L. of 1973 which according to the Management was 1108 feet. It also meant that the difference between the level of 1115 feet over which the water could enter the mine and the level touched on the forenoon of 16th September 1976 was less than 4.92 feet as prescribed in the Regulation.

Regulation 126(1)(b) apart, the Management in their own interest should on their own have prescribed a definite figure, known to all, of the water level at which persons would be withdrawn from the mine, even if the DGMS had not stipulated a specific figure in that connection. This would not have been an unusual act on their part. The Manager of the neighbouring NCDC Saunda Colliery, Shri S. N. Chatterjee evidently had such a procedure for his mine and implemented it on the day of the accident. He told the Court that since the lowest point at which the water could enter his Sirka Incline was at the level of 1117 feet, he withdrew his men from there when he observed that water had reached the level of 1108 feet. This he had done, according to a convention mentioned by him, that persons should be withdrawn when the water is 9 ft. below the danger point. Shri K. K. Gupta of the Central Saunda Colliery told the Court that it was his impression also that workers should withdraw when the water level reaches about 1105 feet, i.e. about 10 feet below the crest of the earthen embankment, though he did not know that there was an official stipulation to that effect.

No prescribed level for withdrawal of persons

29.2 That the Central Saunda Colliery did not have such a procedure comes out fairly clearly by the manner in which the depositions on this point were made before the Court. The Safety Officer—when shown his Diary (Exhibit 15) and asked whether he had issued any instructions—could not say whether there was anything specific recorded about the water level.

When questioned on the same subject, the Manager also said that there were no written instructions, but as a part of the normal precautions to be taken during the monsoon period, the Senior Overman, Shri Jit Singh, had been instructed to inspect all the goafs—of Balkudra, Kurse, Nakari and New Hathidari—to check the garland drains around them and, if necessary, to repair them to ensure that surface water did not find its way to the goaf. Regarding the withdrawal of persons from the mine, the Manager said that Jit Singh had been instructed that if, during his inspection of the New Hathidari goaf, he found the water touching the toe of the embankment, he should report the matter to him or any other officer of the

mine. This was an instruction to Jit Singh in addition to the normal practice for the respective overmen in charge of the inclines to inspect the goafs and the working of their respective mines. When asked what necessitated on 16-9-76 the particular instructions that were given to Jit Singh with regard to the level of the water reaching the toe of the embankment, the Manager said that though there was no particular necessity in view of the Safety Officer having reported the conditions as normal on the morning of the 16th, it was just a precaution so that the supervisory person would not be confused with a situation in which he would have to decide on the course of the action himself.

It is difficult to accept such assertions in the absence of anything in writing about the withdrawal of persons from the mine on water reaching a specific level. If the persons concerned with the watching of the water level during the rainy season, and more especially so the Safety Officer, had been instructed about the specific flood level at which persons should be withdrawn from the mine or prevented from going into it, the accident might not have taken place on 16th September, 1976.

Incorrect water level appraisal

29.3 The Senior Overman, Jit Singh was the only person whom the Management had specifically asked on the morning of 16th to keep a watch on the water level. He was to keep a constant watch and he reported to the Manager at 9 a.m. that the condition of the river was normal. At 11 a.m. he reported that there was slight increase in the level of the water, but gave no indication to what level the water had risen by then. It is difficult to imagine that at that time the level was still below the toe of the embankment, for the bridge over the Nakari downstream of NCDC Saunda had already been submerged. Even assuming that the level at the bridge was 1108 feet as admitted by the Management—and not between 1110 and 1112 feet as implied by the water running over that bridge—the level at NCDC Saunda itself, near the Sirka Incline would have been .50 feet higher, due to Nakari carrying a discharge from the upper reaches, according to Shri B. P. Baliga's study in Exhibit 24. This belies the deposition of the Manager, NCDC Saunda who mentioned before the Court that the level of the Nakari, at his Colliery shortly before 1 p.m. the RL was about 1104 to 1105 or like that. This is not convincing for with the submergence of the RCC Nakari bridge downstream, the level at NCDC Saunda Colliery would have touched the figure around 1108.5 feet near about 11 a.m. if not even earlier. One has to rely on the implications of the submergence of the RCC Nakari bridge. Thus with the level at NCDC Saunda being 1108.5 feet, the level at Central Saunda, according to what Shri Baliga had told the Court earlier, would have been 2.20 feet higher. This means that the water level at Central Saunda around 11 a.m. would have been at least 1110.70 feet, i.e. nearly 6 feet above the toe of the embankment. In this context it is doubtful whether Jit Singh had really been instructed to inform the Manager or any other officer when the level had touched the toe of the embankment. But if he had actually been given that instruction, his assessment of the water level at about 11 a.m. was not at all correct. Then the next time at which Jit Singh appeared at the goaf was round about 12.15 and 12.45 hrs., when he saw the water overtopping the embankment, after which he rushed to reach the Manager at about 1 p.m. to inform him of what was taking place. Jit Singh was nowhere near the Hathidari goaf between 11 a.m. and 12.15 p.m. He was probably around the Balkudra, Kurse and Nakari Seams, even though the working there were not so such in danger of being inundated by the water rushing in from the river, as admitted by the Manager.

Safety Officer with dual charge

30.1 The Safety Officer was also not on the surface between 9.30 a.m. and 12.20 p.m., but was during those hours underground in the New Bangsora Incline, after having sent word to the Manager that things were not abnormal round about 9 in the morning of 16th September. That was rather unusual—a Safety Officer in the rainy season being away for 3 hours at a stretch from the surface of the mine, when the river Nakari was not very far away, a nullah was flowing in close proximity to Hathidari and a smaller nullah was actually flowing over its goaf. But that was so because surprisingly enough, the Management had given Shri S. K. Dutta Choudhary a dual charge. As production manager of New Bangsora Incline, his main responsibility, according to him, was to boost production from that mine and as Safety Officer he dealt with safety matters only on paper. The duties of, Safety Officers are spelt out in great and minute

detail in Regulation 41A, which also stipulates that if any duties other than those so prescribed in the Regulation are assigned to the Safety Officer, a written notice to that effect should also be sent to the Regional Inspector—i.e. of the DGMS within 3 days of such assignment. When asked whether he knew that that had been done, Shri Choudhary said that he was not aware of that but as far as he could think, that was not done. He, however, told the Court that when he objected to the dual charge, the Management requested him to continue with both the works for some time. Having done that for a few days, he found it physically impossible to continue on like that and so he requested the Management to give him only one responsibility. An agreement was then reached that he should function as Assistant Colliery Manager in charge of the New Bangsora Incline but should also look after safety matters on paper. It is surprising that he was assigned a dual charge and the matter not reported to the DGMS, as comes out in Exhibit 19. But what surprised the Court even more was the Management's Office Order dated 7-4-76 which, according to the Court's earlier direction, was presented to it and marked as Exhibit 18 on 9-8-77.

Under Manager with dual duties

30.2 The Office Order while indicating that Shri Chaudhary would work as Safety Officer as well as in-charge of the New Bangsora Incline, brought to the notice of the Court another factor of which it was not aware when Shri K. K. Gupta's examination was under way on 27-4-77. The Office Order said that Under Manager, Shri K. K. Gupta would look after the New Bangsora Incline and assist Shri Choudhary in his job as Safety Officer also. This was not brought to light in the examination of Shri Gupta on 27-4-77 when he only indicated that his duties were to see the production of the New Bangsora Incline. Even assuming that if at the time of his deposition before the Court in April 1977, he was not connected with the Safety Organisation of the mine, the fact that he was associated with it during the period in which the accident took place, should have been specifically brought out before the Court.

Shri Gupta could have told the Safety Officer that since he had seen the condition of the Nakari, half an hour after he had seen it at 8.30 a.m., it might be necessary to take some further precautionary matters. Especially so, when according to him his impression was that the width of the Nakari had increased a bit at 9 a.m. When asked on 27-4-77 that with his impression being that the water level was rising, why he had not deputed someone to keep a constant watch over the Nakari and why he himself had not gone down to the embankment itself, to see the situation more properly there, his general reply was that the level of the water was not alarming and that his presumption was that Shri Choudhary must have taken some action. When he told the Court on 27-4-77 that his impression was that workers should be withdrawn from the working when the water reached above the level of 1105 feet, he was asked whether there was any bench-mark showing a level at 1105 feet RL. His reply was that he did not know whether such a bench-mark was there in the mine. Should he and the Safety Officer not then have taken the trouble of ensuring that some kind of arrangement was made that would enable the watchmen and the Safety personnel to see the level when it touched the 1105 feet and higher marks. Especially so, when both of them were officially associated with the safety of the mine, though one of them was supposed to deal with safety matters only on paper. A brick column to indicate the water level was supposed to have been on the Nakari near the depillaring area. It is rather surprising that it should have been washed away by the 1976 flood, when such columns survived that flood in the Saunda 'D' and NCDC-Saunda Collieries, on either side of Central Saunda. When questioned whether while he was going down the Bangsora Incline with the Safety Officer and was there with him till both of them came up together after some hours—he had asked Shri Choudhary about any safety action having been taken by him, Shri Gupta's only reply was that the Safety Officer had told him then that the rise of the water level did not contribute any danger.

No flood alarm devices

30.3 It is surprising that once again, such a complacent attitude should have been taken about matters relating to safety in the colliery, particularly when from the Headquarters—C. C. Ltd.—there were constant directions, as indicated by the

Managing Director, that safety was of paramount importance in all the mines and that there could be no question of sacrificing safety for the sake of increasing the production from the mines. If the Safety Officer, or Shri K. K. Gupta, had been on the surface of the mine and had dealt exclusively with all matters relating to safety, greater attention could have been paid to the Hathidari goaf and to the rising water level that day. That they were not there was because the Colliery just took it for granted that there could never be any chance at all, at any time, of the water ever entering the mines.

Safety Devices

30.4 When asked whether they had any safety device against the danger of inundation, the Agent, Shri S. K. Mukherjee said there was no such safety device, as flood alarm installed at Central Saunda or the adjacent collieries, because it was not necessary. The Court felt, however, that if there had been a flood alarm system : flood lights to facilitate movement in the dark in the Inclines ; and at least 2 watchmen at a time under a Patrolling Officer to observe the water rise during the rainy season, the accident would not have taken place on 16th September. It is an irony of fate that such measures are now being resorted to in the mines on the Nakari river.

Agent unaware of Hathidari goaf

30.5 The Agent of the Colliery, Shri S. K. Mukherjee who saw water flowing over the Nakari bridge at about 11 a.m. on 16th September just assumed that since that had also happened in the past without any injury to the mine, there would be no danger to the Central Saunda Colliery. That was rather odd, because when the water had flowed over the bridge in the past years, he was not then directly responsible for the safety of the Central Saunda Colliery. But having taken over charge of the Colliery on 3rd August 1976—i.e. six weeks before the accident—and having seen the water over that bridge on the 16th, he should normally have discussed with his junior officers its exact implications in order to satisfy himself that there was thus no danger really in his Colliery that day. One can understand that his anxiety on the early morning of 16th September was to expedite the repair of the steam valve which had gone out of order and had resulted in the stoppage of production from the Sirka Seam. But when in that connection he wanted to go to the Bhurkunda Workshop and say the water over the Nakari bridge around 11 a.m., he should have switched his attention away from production in the mine to the safety of the workers in the mine. In other words, repairing the steam valve should have then taken a priority lower than an examination of the possibility of the rising water endangering the lives of the workers underground, particularly in the Hathidari Seam, the goaf in respect of which was nearest to the Nakari river.

It is a pity that the Agent was not even aware of the Hathidari goaf in the Colliery, the small nullah flowing over it or the embankment constructed across it in relation to an HFL chosen by his predecessor. He said that he had not been informed of these features when he took over charge. But one is supposed to study straight away all the statutory maps and plans of the Colliery on assuming charge. He could surely have done that in the six weeks after he had become Agent : and if he had, the Hathidari goaf and every factor connected with it would then not have escaped his notice and review. But if this had not been done earlier, a discussion in some detail with the Manager on the 16th after he had seen the water over the Nakari bridge around 11 a.m. would at least have made him aware of the special instructions that the Manager was supposed to have given to Jit Singh about the Hathidari goaf and about water reaching the toe of the embankment. And then, that could have brought out before him for his scrutiny all the considerations, like the embankment, the HFL, etc. that had been taken by the Management into account about the safety of the Hathidari Incline. In those 6 weeks, it would also appear, the Agent had not even gone into the duties assigned to all the officers of the Colliery, for if he had done that, he would certainly have noticed the anomaly in the Safety Organisation of the Colliery. In his deposition he informed that Court that during the short period between his taking over charge and the day of the accident, he had concentrated, amongst other things, on the safety of the large number of persons employed in the mines but that should surely have brought to his attention the fact that the Safety Officer, with a dual charge, was dealing with safety matters only on paper and that the safety organisation was hardly going by all the directions that it was receiving from the headquarters on the subject.

PART-III

Backwater Effect

Was it backwater that caused the accident.

31.1 Part II of this Report has dealt with a number of questions relating to the inrush of water into the mine. The question that will now be dealt with is whether it was a direct flow from the Nakari or a backwater effect from its confluence with the Damodar that resulted in the water attaining RL 1115' near the Hathidari goaf of the Central Saunda Colliery, which caused the inundation of the mine.

DGMS's Report

31.2 When the accident took place in the Colliery, on the left bank of River Nakari, the general impression and the understanding then, and for quite some time thereafter was that the high flood conditions of River Damodar on 16th September 1976 prevented the free flow of its tributary, the Nakari, towards the confluence and thus caused the water to rise above the 1115' crest level of the embankment at Central Saunda. The Accident Report of the Directorate General of Mines Safety dated 22nd December 1976 also came to the same conclusion.

This Report made after an inquiry into the accident, stated that due to heavy rains, the Damodar and Nakari rivers were in high floods on 16th September and that the water flowed back into the mine along the small nullah, which normally used to discharge into the Nakari river. This inquiry did not go into the question of a factor other than the backing up of the Damodar waters along the course and hinterland of the Nakari which could have caused the accident, evidently because in none of the statements made before the DGMS between 17th and 23rd September, 1976, was there any hint or suggestion about a heavy discharge of water from Nakari Reservoir, upstream of the colliery, causing the inundation of the mine. The Patratu Dam across this reservoir is maintained and operated by the Patratu Thermal Power Station authorities referred to as PTPS in this Report.

Management's study of the problem

31.3 In his deposition, Shri B. L. Wadhwa, Managing Director of the Central Coalfields Ltd., however, told the Court that though on 17th September, i.e. a day after the accident, the impression gathered was that the water of the Nakari found it difficult to flow into the Damodar subsequently and as time passed on during the departmental inquiry ordered by the Management, different theories came up informally for their consideration. Some officers mentioned that the reason for the inundation could either be that the Nakari found it difficult to find its way into the Damodar, or that too much water having been released from the reservoir at the Patratu Dam made it difficult for the Nakari to contain that water, with the result that it overflowed into the mine. With such doubts expressed, the Managing Director requested their sister organisation, the Central Mine Planning & Design Institute (CMPDI) to go into the question as to whether there was a possibility of the water released from the Patratu dam causing the accident in the mine. He also cautioned his officers not to make any wild guesses or announcements of their doubt on the subject, because they were maintaining excellent relations with the Patratu authorities who were not only supplying them with electric power but also their valued customers for coal. He, therefore, asked his officers that with a study made on the subject, the conclusions should be presented before this Court of Inquiry.

The Management was asked to submit their departmental inquiry on the accident, but despite reminders, it was not received by the Court on the ground that they were not able to trace out that report.

Management's conclusions

31.4 The Management's Statement submitted to the Court on 12-3-77 took the line that it could not be the backwater of the Damodar which gushed into the subsided goaf area and caused the accident. According to them the level of the Damodar had started rising from the early hours on 16th September when the collieries situated on its banks were duly warned by the alarm system installed on the banks of that river. The persons from those mines were, therefore, withdrawn by 6 a.m. There was, however, nothing unusual

observed, the Management said, in the condition of the Nakari on the forenoon of 16th September. But around 12 noon on that day, the Manager of the Saunda-D Colliery, upstream of Central Saunda, was informed that the water in the Nakari was rising very fast. He, therefore, went to the road bridge connecting his Colliery with Bhurkunda and saw the Nakari water around 12.30 p.m. rising at a galloping rate. This was due, according to the Management, to a sudden and massive release of the Nakari water from the Patratu Dam, about 11 kms. upstream from the Central Saunda Colliery. This sudden rush of the water therefore raised the level of the Nakari and the connecting nullah at Central Saunda above 1115' which resulted in drowning the Hathidari workings. Their contention is that the Damodar did not and could not contribute to the ingress of water into those workings and their main argument in this connection is that if the Damodar water through the Nakari was to get into the subsided Hathidari goaf, it should have first attained the RL of 1115' at the Sirka Incline surface of the NCDC—Saunda Colliery, downstream of Central Saunda, which is nearer to the confluence than the Central Saunda Colliery and where the river bank is lower than 1115'. Even at the time of the drowning of the Hathidari workings, the RL of flood water at the area adjoining the Sirka Incline surface of NCDC—Saunda, according to the Management, was very much lower than 1115'.

31.5 The entry of the large quantity of water, which they could never have anticipated or foreseen, say the Management, was pure accident only, over which they had absolutely no control. In spite of all the safety measures taken by them, the most unexpected rush of water due to the sudden release from the Patratu Dam, without any prior warning whatsoever, rushed into the Hathidari seam. It is their submission that no amount of human efforts on the part of the Management could have avoided the accident, inasmuch as no opportunity was available to them to take adequate steps toward off the accident. If they had received the slightest indication of such a heavy release of water from the Patratu Dam, they would have certainly taken all steps to withdraw the men from the mine.

Basis of the Management's conclusion

32.1 In order to substantiate their contention that it was not the backflow from the Damodar, but a massive and sudden flow of water from the Patratu dam without any forewarning that caused the accident, the Management presented to the Court the studies that had been undertaken in that connection by Shri B. P. Baliga, Superintending Engineer (PHE) of the CMPDI.

32.2 Shri Baliga based his studies, amongst other things, on the isohyetal maps maintained by the Meteorological Department of the Government of India; Damodar Valley Corporation's (DVC's) records showing at the Ramgarh Road Bridge the hourly readings of the rise in the flood level of Damodar, the annual highest flood level and discharge from 1945 to 1976, the stage velocity discharge graph and hydrograph of the highest flood in 1976 showing the discharge in cusecs at different times of the day. He took into account the rainfall in the various sections of the Damodar and Nakari catchments and the data furnished by the Patratu Thermal Power Station (PTPS) authorities. He also presented to the Court, amongst other documents, an album (Exhibit 4) containing his 54 drawings showing the studies he had made of the Nakari and Damodar Rivers in the Patratu-Barkakana-Ramgarh reach. Exhibit 4A contains the summary of the studies made by Shri Baliga.

32.3 Based on the studies and the evidence of the witnesses who appeared before the Court, the contention of the Management is that it was a discharge of 71,962 cusecs of the Nakari water that made the water level rise above 1115' at the Central Saunda Colliery to inundate the Hathidari seam. The stage discharge rating, contained in drawing No. PHE/843-2/77-8 at page 46 of the Management's Exhibit 4 indicate these figures, a copy of which is shown as Annexure V-f in volume II of this Report.

The build-up of this voluminous discharge, according to them, was due to:

- (a) an excessive release of water from the Nakari reservoir through the spillway gates at the Patratu dam on account of the heavy rainfall;

- (b) run-off of water from the intercepted catchment between the Patratu dam and the Central Saunda Colliery; and
- (c) the surge of water that would travel in the event of failure of the causeway and/or the coffer dam No. 2 on the Nakari river between the Patratu dam and the Colliery, as a result of the abnormal high release from the reservoir.

32.4 The release through the spillways is dealt with in the subsequent sub-paragraph. So far as (b) above is concerned, the Management's calculation of the run-off from the 26.97 sq. miles intercepted catchment, according to Dicken's formula or any other standard formula is that it can be upto a maximum of 11,830 cusecs, depending on the rainfall in that area.

As regards (c), above, the Management's assertion is that the Coffor dam which is 2.4 km. downstream of the Patratu dam was damaged on the 16th September when the Nakari water reached the lintel level of the pump house adjacent to the Coffor dam. This meant that the excessive release from the Nakari reservoir—in the region of 50,000 cusecs, if not more—caused the water to flow 12 feet over the coffer dam. The breach of this dam, therefore, caused a sudden release of water impounded on the upstream side of the coffer dam and accelerated the sudden surge downstream to reach the Central Saunda Colliery.

Release from the Patratu Spillways

32.5 Due to the cyclonic weather in Bihar from 10th September onwards, the rainfall was unusually high on the 16th and the preceding days, according to the Management, in the 81.32 sq. miles of the Nakari catchment, as compared to the Barkakna-Gidi area near the confluence of the Nakari and the Damodar. As a result of this heavy downpour, the condition of the Patratu Dam started becoming dangerous from the midnight of 15th September. The danger mark of the reservoir being 1332.50' the water reached that level from the morning of 16th September and remained so for more than 11 hours on that day. The water even rose 2.10' higher than the danger level during that period for more than 7 hours continuously. In order, therefore, to save the Dam, the PTPS were compelled to discharge heavy quantities of water from the spillway gates. According to the Management's estimation, the release even at 7 a.m. on the 16th would have been in the region of 50,000 cusecs, if not more; between 10.30 to 11 a.m. it could have corresponded to 48,000 cusecs and during the time-span between 11 a.m. to 2 p.m., it could not have been less than 45,000 cusecs and the range would have been anything from 45,000 to 59,000 cusecs.

The flow of water from the spillways increased in volume as it passed through the intercepted catchment and with its velocity being in the range of 12 to 16 feet per second, it took about one hour to reach the Central Saunda Colliery from the Patratu Dam. This would mean, according to the Management, that in case 50,000 to 55,000 cusecs were released from the spillways around 11.30 a.m., as stated by the Court's eye-witness, Shri D. N. Majee, the water would have reached the Central Saunda Colliery around 12.30 p.m. The velocity of 15 to 16 feet per second being colossal, anyone from that Colliery standing at that time on the highest point on the bank of Nakari to see the rise of water, would have only got about 27 seconds to run away to safety, which means that he would have been certainly swept away and would not have been able to inform anyone else about the sudden water level rise at the Colliery.

In arriving at their calculation of the discharge of water from the Patratu dam, the Management studied the documents presented to the Court by the PTPS and came to the conclusion that there was no correlation whatsoever between the discharge figures given by the PTPS corresponding to their spillway gates opening vide Exhibit CR-2A, and discharges corresponding to partial gate opening with reference to reservoir levels given by them in Exhibit CR-3E. They also studied the data supplied by PTPS to work out the run-off from the Nakari catchment. According to them based on that data the reservoir level at 8 a.m. on 16th September would work out to 1341.50 feet, i.e. 1 foot below the crest of the Patratu dam and 11 feet above the danger level. This would be based on a rainfall of 6 inches between 8 a.m. of 15th September and 8 a.m. of 16th September, but even assuming a maximum

value of 2-1/2 inches rain, the reservoir would have reached a level of 1334.00 against the figure of 1330.50 shown by the PTPS in Exhibit CR-5B.

32.6 From what has been indicated in this paragraph, the Management's logic seems to be that since it would require a discharge of 71,962 cusecs at Central Saunda to cause the inundation of the Hathidari seam, it is not very pertinent to be very specific about the constituents of that heavy discharge. If, for instance, the flow in the intercepted catchment was lower than 11,830 cusecs and so also the flow as a result of the damage to the Coffor dam No. 2, the release from the spillways would have been higher. If on the other hand, flow from the intercepted catchment and from the coffer dam was at the maximum as calculated by them, the release from the spillway gates would have been lower. But according to them the release from the Patratu dam could hardly be less than about 45,000 cusecs or so.

32.7 The Management are confident that on 16th September the condition of the Damodar at the confluence at the time of the accident was not responsible for causing the entry of water into the goaf of the Central Saunda Colliery through the Nakari, for according to the study made by them, the Damodar has a beautiful bank profile to contain the water well within its banks, even under conditions of say a lac cusecs discharge from Nakari. Around 1 p.m. on 16th September, the water-level in Damodar river was less than 1108 feet as Shri Baliga had collected the data in respect of rainfall recorded by the self-recording rain gauge stations in the upper catchment of the Damodar at the confluence. The PTPS, according to the Management, in arriving at a higher level of water at the confluence, did not indicate the actual intensity of the rainfall for causing the condition of the Damodar at the confluence, nor did they indicate the basis for the intensity of the rainfall. If there really was a backflow, then the level at the NCDC-Saunda mine—just below the Central Saunda Colliery and nearer the confluence—according to them, would have attained a figure higher than 1115 feet which caused the entry of water into the Hathidari goaf. That did not happen, as according to the evidence of the Manager of NCDC—Saunda, the water at his mine suddenly jumped to only 1108 feet RL near about 1 p.m. on 16th September, but the Nakari still flowed towards the confluence. The lowest point at which water could enter the Sirka incline of NCDC—Saunda is RL 1117 feet and the water entered that incline, not on 16th September, but the next day.

Deposition of witnesses

33.1 The conclusions reached by the Manager as a result of their studies, were substantiated by the witnesses produced by them before the Court. Shri D. N. Majee, an Assistant Engineer (Civil) in the Public Health Engineering Department of the Government of Bihar, stationed at Patratu—who was called in as a Court witness and was examined on two occasions, 28th April and 19th November, 1977—also made a number of points in his deposition which were corroborated by the studies undertaken by the Management. Shri Majee, as well as Shri J. N. Prasad, Block Development Officer, another Court witness, spoke about the heavy rainfall at Patratu and the alarming condition of the Nakari reservoir. Shri Majee who observed the reservoir level at 1332 feet on 14th September, saw that the level had touched the figure of 1336 feet on the morning of 16th September due to the abnormally high flow of water from the Nakari catchment and that the water was over-spilling the spillway gates. According to him, the release from the Patratu dam around 11.30 a.m. that day was 50,000 to 55,000 cusecs when all the spillway gates were opened. He, as well as Shri Nageshwar Sahu, Mechanical Fitter at the Central Saunda Colliery, who was Management's witness, said that they had been to the Pump House near Coffor Dam No. 2 and saw the water flowing 12 feet above the crest of the dam and touching the lintel level of the Pump House. This, according to the Management, corroborated their stand that the release from the Nakari spillways was excessive and was in the region of 50,000 cusecs, if not more.

33.2 The Management who cross-examined the witnesses produced by the PTPS came to the conclusion that the statements of the witnesses Nos. 1 to 5, 7 and 8 were full of contradictions and were not even in conformity with the entries made in the concerned PTPS exhibits. The grievance of the Management is that not a single witness of the PTPS was

from their own organisation but from the State Government's Public Health Engineering Department and that the PTPS should have at least asked their own officers—like the gauge reader, Junior Engineer the Asstt. Engineer, the Executive or the Superintending Engineer who were directly concerned with the operation of the Nakari reservoir, recording its levels and release from the spillway gates—to come and depose before the Court. Since Shri N. Kerketta, the General Manager-cum-Chief Engineer, Patratu Thermal Power Station, was not an eye-witness to the discharge from the spillways on the morning of the 16th and it was his Executive Engineer and Superintending Engineer who supervised that discharge, the Management were surprised that despite their presence in the Court, they were not produced as witnesses to depose on oath the exact situation prevailing at the Patratu dam on the day of the accident. They did not also appreciate Shri Majee's second deposition when he took the line that all that he had deposed earlier might have been related not to 16th September, but to the Vishwa Karma Puja Day which is generally on 17th September every year. This according to them could well have been due to some persuasion exercised on him by the PTPS authorities. The evidence of PTPS's witnesses, like Shri Ramadhar Prasad and Shri Satish Prasad, besides that of Shri Majee himself, according to the Management, would lead to the conclusion that it was not on the 17th but on the 16th that water entered the Pump House to submerge the pumps there, due to the heavy release from the Patratu spillways.

Conclusions of the PTPS

34. The conclusions reached by the PTPS authorities—based on the evidence from their witnesses and the detailed studies carried out by them, as contained in the Exhibits—P. 4 to P. 13 are quite contrary to the conclusions arrived at by the Management. These studies contradict almost everything contended by the Management. The conclusions of the PTPS, in brief, are as follows:

(a) The rainfall in the catchment of the Nakari reservoir at the Patratu dam, according to the DVC's isohyetal map, was very small on 15th and 16th September.

(b) The reservoir at 8 a.m. on 16th September, according to (a) above would have touched RL 1331 feet only, if there had been no release from the dam. But, since according to them, the actual condition of the reservoir was 1330.5 feet RL, it meant that only a small quantity of water had to be released that morning. The release was only 768 cusecs between 7 a.m. to 10 a.m. and 2560 cusecs between 10 a.m. to 7 p.m. The PTPS rebut the Management's calculations of the Nakari level also, as these are based according to them on wrong assumptions. After calculating the discharge from the spillways at different distances downstream of the dam, their conclusion is that the 59,000 cusecs discharge mentioned by the Management is purely imaginary and is established to be wrong on the basis of their own surveys and drawings, as indicated in Exhibit 4. The Management did not also submit any calculations, state the PTPS, to prove their claim about the release of water from the Patratu dam.

(c) There could be no sudden and heavy discharge from the spillways causing a tidal wave, but even assuming that such a discharge did take place, the energy dissipator would have absorbed that shock as it is designed for that purpose. Thereafter, the water would start flowing in a normal fashion towards the Colliery. Though they did not make any actual calculations, the PTPS think that flow of the water from the Patratu dam would have become normal at a distance of about 1,000 to 1,500 feet downstream of the spillway gates.

(d) There was a heavy precipitation in the upper reaches of the Damodar, according to the pattern of rainfall in that river's catchment as per the isohyetal map. If the intensity of rain in the intercepted catchment of 27 sq. miles between the dam and the Central Saunda Colliery, the PTPS argue, could be around 1 inch per hour as asserted by the Management, then adopting the same rate for the Damodar catchment of 1040 sq. miles upstream of the confluence, the peak discharge from that catchment would workout to 4,62,000 cusecs at the confluence. The Management, according to PTPS, had not conducted any study of Damodar upstream of the confluence and did not calculate the inflow of Damodar and Nakari to the confluence and the outflow downstream from the confluence.

(e) The causeway, just below the Patratu dam was breached around 7.15 p.m. on the 16th and the Colfer dam No. 2 was damaged on the forenoon of the 17th September: hence things were normal in that connection before the accident at the Central Saunda Colliery around 12.30 p.m. on 16th September. The maximum discharge at that colliery was only 12,568 cusecs round about 9 a.m., as a result of the maximum rainfall that took place between 3 to 6 hours that day. On the 17th, the maximum discharge from the Nakari at the Colliery was 38,086 cusecs at 1 p.m. So on both those days the Nakari's flow to the Colliery was very much below 71,962 cusecs and could not have raised the water level there to 1115 feet. The discharge of 12,568 cusecs on the 16th would have raised the level at Central Saunda to about 1100 feet RL only, say the PTPS, according to stage discharge rating curve of the Management at sheet No. 46 in Exhibit 4. For the level, therefore, to go up from 1100 feet to 1115 feet, it would be the effect of the Damodar flood that would be responsible. That would cause a change in the regime conditions of the Nakari river and reduce its velocity of flow to an appreciable degree.

(f) The highest flood level on 17th September would not be less than 1125 feet at the confluence of the Damodar with Nakari. This fact, they add, is corroborated by the written statement of the General Manager, C.C.L., Barkakana, which says the water level on 17th September had submerged the roofs of the residential buildings on the banks of the two rivers near the confluence. The level of these roofs was not less than 1125' RL.

(g) On 16th September, their contention is that the flood level at the confluence was not less than 114' which was the level of the suspension bridge downstream that was washed away round about 12 hours on that day. With the level at the confluence being 1114', the same level would have prevailed at the Central Saunda Colliery, if there had been no discharge of the Nakari. But since there was a flow from the Nakari, downstream of the Patratu dam, the level exceeded the 1141' level at the Colliery. In other words, it was really the rise in the level of the Damodar at the confluence that led to the disaster in the mine.

Reliability of the studies of the two parties

35. Both the Management and the PTPS have carried out a series of detailed and technical studies. These studies, amongst other factors, cover their computation of the rainfall on and a couple of days before 16th September in the different catchments of the River Damodar. They have further computed the rainfall in the Nakari catchments—above the Patratu dam, between the Dam and Central Saunda and between the Colliery and the confluence of the two rivers. Both have spelt out what they assert was the actual release of water from the spillways of the Patratu Dam. They have taken into consideration their assessment of the bed and flood slopes of the two rivers, and values of other parameters and have worked out the profile and water regime and have also calculated the discharges at various cross-sections at different reaches of the rivers. But not on any vital point have the two parties come to the same conclusion: instead, each party questions the veracity of the studies made by the other. The Management assert that they had carried out the physical survey connected with their studies, in May 1977, and had also carried out a reconnaissance upto the level of the Damodar and Nakari just for visual appraisal and determination of the relevant factors. The PTPS contend that nowhere in the world are the discharges visually estimated for calculating the discharges and a well organised team has to work to ascertain the river cross sections, the bed-slope HFL of water elevation, the co-efficient of rugosity including measurement of velocity by current meter to determine the discharge through the various sections of the river. In almost all the standard books, they say, it has been suggested that after making the theoretical calculations, the actual happenings have to be verified by observations a number of times, so that necessary corrections of the co-efficient factors on which calculations are made, can come to represent the actual position. So while the PTPS contention is that the Management's theoretical calculations are without any base and data, the Management in their turn have their doubts about the studies carried out by the PTPS. The PTPS survey, purported to have been made some time in October 1977, they say, cannot be relied upon because it was carried out during a period when there was substantial flow from the upper reaches of the Damodar. A proper survey is not amenable in such conditions and the Management therefore question the survey and the results derived from that survey.

Degree of reliability of eye-witnesses

36.1 With doubts cast about the authenticity of the studies, is it possible to rely solely on the evidence of the witnesses who deposed that there was abnormal rainfall which raised the level of the Nakari reservoir and that, consequentially, there was heavy discharge from the spillway gates, which damaged the Coffor Dam No. 2 and which, with high velocity, suddenly and with galloping speed reached the Central Saunda Colliery to overflow the earthen embankment protecting the Hathidari goaf. That there was no backwater effect from the confluence, till about 1 p.m. at least on 16th September was also indicated by a number of witnesses of the Management.

36.2 It is difficult to go by the evidence of the witnesses to establish the exact flow of water into the Nakari reservoir when there are no rain gauges in the catchment. A gauge is there just below the Patraru dam itself, but its measurements can hardly lead to an unquestionable conclusion about the rainfall in the entire catchment and the rate of flow towards the reservoir, on which there is a wide divergence of view between the Management and PTPS. But the data of the rain gauge near the Dam could obviously lead to some conclusions. If the statement of the PTPS that no spillway gates were opened till 7 a.m. on 16th September is taken as correct, then the conclusion could well be, as argued by the Management, that with the rainfall being as recorded by the gauge, the accumulation of water with a reasonable run-off inside the dam commencing from the morning of 14th to the morning of 16th September would have touched a height well above 1330', after taking into account the outflow from the reservoir for consumption purposes on the 14th and 15th September. As this would have meant a level higher than the FRL which would normally not be allowed for the safety of the dam, the spillway gates would have been opened at 7 a.m. on 16th September to release an amount of water very much more than what is asserted by the PTPS, in order to bring down the water-level below 1332.5'. Thereafter it could comparatively be a lesser discharge, with the FRL having been brought down even below the 1332.5' figure.

Unusual release from Patraru dam

36.3 There is no doubt that the discharge from the spillway gates was somewhat on the high side. The Manager Saunda-D Colliery, Shri P. K. Das, as mentioned in paragraph 31.4 was struck by the excessive inflow of the Nakari water near his mine, up-stream of Central Saunda. He deposed before the Court that he contacted Shri Kerketta over the telephone at about 12.30 p.m. and told him about the very abnormal rise in the Nakari and had asked whether that could be due to release of large quantities of water from the Patraru dam. In reply Shri Kerketta had said that his dam was in a dangerous condition, that he had released the water already and had ordered a further release. He had warned Shri P. K. Das that if he did not do so the dam could collapse with the result that everything downstream would be washed away. Shri Das added that later on that evening, due to the still rising Nakari level, he sent Shri R. Choubey, his Senior Executive Engineer to PTPS authorities to find out how much more water they were going to release by night, so that he could take action in his mine accordingly. Shri Kerketta is reported to have expressed his inability to Shri Choubey to decrease the release as his dam was in a very much dangerous condition. Though Shri Kerketta denied his having received a telephone call from Shri P. K. Das at 12.30 p.m. since he was not in office but with his Board of Consultant Members whom he accompanied in the inspection of the Power Station from about 10.40 a.m. to 4.30 p.m. that day he did admit that he met the representative of the Saunda-D Colliery around 5 p.m., and informed him that the discharge from the reservoir was being kept minimum to maintain the RL upto the maximum water level permissible in the dam. In view of the continuing rain he was informed that the gate opening would have to be increased.

What comes out from all these depositions is clear. It means that the release of the water from the Patraru Dam was on the high side and not about 800 cusecs only between 7 a.m. and 10 a.m. or about 2500 cusecs only between 10 a.m. and 7 p.m., as stated by the PTPS : otherwise why should the Management of Saunda-D have taken up the matter with the PTPS authorities, as contended by them, both at 12.30 p.m. and 5 p.m. on 16th September. But as deposed by the eye-witnesses, it is not possible to accept their assessment of how excessive the water-release exactly was. The Management have questioned the PTPS's figures of the volume of discharge,

not only by theoretical calculations but by raising serious doubts about the figures shown in their log books and by asserting that there appear to be interpolations in their records, especially those at the Pump House near the Coffor dam. But despite all that, it is difficult to accept the assessment of the eye-witnesses about the actual discharge from the spillways or from the Coffor Dam. The Court had occasion to visit the Pump House and see the water marks there. Irrespective of the fact whether the water had reached the lintel level or not, the fact that a water-mark was there even at a lower level means that the water had gushed into the Pump House, and establishes that there was an increase in the level of the water above the crest of the Coffor dam. It is also difficult for the Court to accept the assertion of the PTPS that the dam was damaged not on the 16th but on 17th September.

Even if there was an unusual flow of water from the Patraru spillways, the Court is not also convinced of the eye-witness accounts of the Managements of the NCDC-Saunda and Central Saunda Collieries, the implication of which is that the Nakari discharge alone raised the RL to above 1115 feet near the Hathidari goaf.

36.4 There are no eye-witnesses either on behalf of the Management or the PTPS about the state of the water regime around the confluence of the Damodar and Nakari on 16th September and neither are there any discharge or gauge measurement stations in the vicinity of the confluence which could have recorded the level attained by the water that day. And since the studies made by the parties are contradictory and there is a wide disparity between the conclusions arrived at by them on this subject, the Court has to try and determine whether or not it was the rising level of the Damodar at the confluence which caused the disaster in the mine. According to the Management the level at the confluence on the 16th, particularly at the time of the accident was 1102 feet. Since this has been controverted by the PTPS, according to whom the flood level at the confluence at that time could not have been less than 1114 feet, it is necessary for the Court to determine what could have been the water level at the confluence on 16th September.

Bed levels of the Damodar and Nakari

37.1 In determining the level of the confluence the Court is of the opinion that it stands to reason that when a tributary joins the river, the condition of the river at the confluence would have a tendency to hamper the free flow from the tributary when the water level of the river at the confluence rises higher than the bed-level of the tributary.

According to the Management the bed-level of the Nakari is 1083 feet near the confluence, as indicated in drawing No. 48 of their Exhibit No. 4; and the bed-level of the Damodar there, as per their drawing No. 28, works out to about an average of 1070 feet. The PTPS have also shown the figure of 1070 feet at page 11 of Exhibit P-5, and though their assessment of the bed-level of the Nakari may be a couple of feet or so higher than the figure or 1083 feet, the Court would be prepared to go by the Management's assessment, for the purpose of determining whether or not there could have been a backflow even based on their own calculations.

With 1070 feet and 1083 feet being the levels of the river and the tributary near the confluence, the flow of the Nakari to the river would begin to get hampered with the water level of the Damodar rising above 1083 feet.

Laminar flow

37.2 The next question to determine is whether and when the Damodar rose above the level of 1083 feet, so as to hamper the free flow of the Nakari and to cause a rise in its level towards the Central Saunda Colliery due to the backwater effect.

The Management has carried out two studies. One is about the laminar flow according to which, as shown in their drawing at page-46 of Exhibit 4, water, whatever may be the source, could not enter the earthen embankment at the Hathidari goaf corresponding to RL 1115 & until and unless the discharge from the upstream side was about 72,000 cusecs out of which, at best, 12,000 cusecs could be attributed to the maximum run-off from the catchment between the Patraru dam and the Central Saunda Colliery. Their assertion, therefore, is that the condition of Damodar around 1 p.m. on 16th September, by itself, could not cause the entry of water into the Hathidari goaf, unless there was a sudden release of

water from the Patratu dam as shown in their studies. The drawing shows the stage discharge rating, corresponding to the water-level of 1115' at Central Saunda. Adopting the Manning Formula, and taking the co-efficient of rugosity as .03 and the bed-slope into consideration, the discharge at the mine has been worked out in the neighbourhood of 71,962 cusecs, with the level of the Damodar around the time of the accident being 1102'. This level of 1102' has been related with a 3 lac cusecs discharge of the Damodar, according to the DVC data of the maximum discharge of Damodar on 16th September at the Ramgarh road bridge. Though the discharge at the Ramgarh road bridge, downstream, may be higher than at the confluence, the Management in order to give a picture on the worst side, are prepared to assume that the discharge at the confluence was the same as at the Ramgarh road bridge.

Profile of the Nakari

37.3 The Management's other study is reflected in their drawing No. PHE/843-4/77-8, Plate No. 4, at page 48 of Exhibit 4, a copy of which can be seen at Annexure V-g in Volume II of this Report. This study, however, indicates that the water level of 1115' at the Central Saunda Colliery could also have been reached with the Damodar's level at the confluence being high enough to raise the level of the Nakari by backwater effect. This drawing shows the profile of the Nakari from the confluence, upstream to Central Saunda and beyond, under the condition of the Damodar, as determined by the Standard Step Method, which is an accepted method for such computations. It indicates the condition of the Damodar on 16th September, during the period in question, with allowance of a few hours after the occurrence of the accident.

The PTPS have, of course, contended that the Management's working out the profile for a confluence level of 1102.5' RL and the Nakari discharge of 45,000 cusecs is not all correct. The profile, according to them should have been worked out for the Damodar level at the confluence being 1125' RL and the Nakari discharge being 1.40 lac cusecs as per the Management's own assumptions. The Management's drawing of the Nakari's water profile according to PTPS should, therefore, be treated as an exercise about the definition of curves but not indicative of the actual curves at the higher flood level on 17th September. The Court is, however, more concerned with the situation on 16th September. According to the PTPS survey of the cross-section area of the confluence, and their rating chart prepared on the basis of the Manning Formula, the level at the confluence for a discharge of about 3.10 lac cusecs would work out to 1114' RL which caused the washing away of the suspension bridge below the confluence, the rising of the Nakari above 1114' RL and the entry of water in the Hathidari goaf. Though the PTPS may have doubts about the water profile of the Nakari as drawn by the Management, the Court would, nonetheless, like to determine whether there would have been a rise in the level of Nakari due to backwater effect on 16th September, even assuming that the Management's water profile is correct.

Submergence of the RCC bridge.

38. Taking into account the water profile of the Nakari at page 48 of Exhibit 4 and the bed levels of the Nakari and the Damodar, both as assessed by the Management, the Court will now examine at what time and to what extent the water at the confluence rose much higher than the 1083' bed level of Nakari, so as to cause a backwater profile towards the Central Saunda Colliery.

Paragraph 28.2 of this Report which has indicated the submergence under water of the RCC bridge—which is downstream of the NCDC—Saunda Colliery and across the Nakari near the confluence—brings out two important points. Firstly, that it was at least between 9.15 to 10.30 a.m. on the 16th September that the level of the Nakari had increased to be above the bridge and, secondly, that with that so happening, it meant that the water level of the Damodar at the confluence had risen well above the 1083' bed level of the Nakari tributary so as to cause the submergence of the RCC bridge. According to what was said by Shri Kundu, the Senior Executive Engineer and by Shri S. K. Mukherjee, the Agent of the Central Saunda Colliery, water was flowing about 2 ft. over the bridge. PTPS who surveyed top level of this bridge found it to be 1110' RL and so came to the

conclusion that the level of the water at the bridge had risen to 1112' due to this high flood in the Damodar. Since an afflux is localised at bridges and could be of the order of 3 to 4 feet at this RCC bridge, as indicated by Shri Baliga, the real water level would work out to 1112' minus 4', i.e., 1108'. In their written statement, the Management also admitted that the submergence of the bridge corresponded to the highest flood level of 1108'. Thus with level at the confluence being near 1108' or even slightly less, the conclusion that is inescapable is that with reference to the water profile drawing at page 48 of Exhibit 4, the backwater was very much there and that, consequently, the discharge of the Nakari at Central Saunda would be lower than the figures shown in that drawing.

Determination of water levels on 17th September

39.1 That even before 9 a.m. the height of the water of the Damodar at the confluence was above the bed-level of the Nakari can be deduced from the Management's own description and from a study of the DVC data on the subject. The abnormality prevailing on 16th September, is contained in the Management's written statement which states that "the level of the River Damodar started increasing from the early morning of 16th which was apparently due to the heavy rainfall in the upper catchment region of the river near its source in the district of Palamau. On the 16th early morning the Damodar crossed the danger mark at Associated Karanpura Colliery and all the working persons from the inclines adjacent to River Damodar, i.e., Sirka 1 & 2, Saunda 1 & 2, Bansgora 4 and 5 and Sirka 3 and 4 were withdrawn."

The Associated Karanpura Colliery is just above the confluence, and to find out what could have been the condition nearer the confluence itself, it would not be improper to derive some conclusion from the DVC data before the Court. In fact, the Management themselves had an occasion to depose before the Court that it would be prudent to depend upon the observations of Damodar at the gauge discharge station Ramgarh road bridge and then reconstruct the picture at the confluence, taking that as the base. The Court would, therefore, like to make an exercise based on the DVC and other relevant data, to get a fair idea about the time from which the confluence level started rising on 16th September.

Water level at the Ramgarh road bridge

39.2 The Court had obtained from the DVC :

- (a) the daily rainfall data from 1st to 21st September, 1976 recorded by the 4 rainfall stations in the Damodar catchment above the confluence, at Chandwa, Sillachaik, Khalari and Barkagaon; and
- (b) the daily maximum water level and discharge in cusecs observed at Ramgarh Road Bridge on River Damodar from 1st to 21st September, 1976 beginning from 6 a.m. of data to 6 a.m. of next data. The gauge and discharge station of the DVC nearest to the Central Saunda Colliery is at Ramgarh Road bridge, about 15 river miles downstream.

39.3 The Management also produced before the Court :

- (i) the River Gauge Report of the Hydraulic Data Division of the DVC containing an hourly record at Ramgarh Station of the gauge reading and water-level from the 12th to 20th September, 1976 which is marked as Exhibit 8; and
- (ii) a DVC statement showing the yearly maximum discharge and gauge in RL of Ramgarh site on river Damodar, which is marked as Exhibit 9.

39.4 From the above records, it emerges that :—

- (a) The highest flood in the year 1976 was on 17th September, when the maximum level attained, as established from flood marks, was 1040.09' at the Ramgarh Station. That level was the highest ever reached since the year 1945, according to that record.
- (b) Though all the gauges got submerged due to the rising floods, and remained under water from 0900 hrs. of 16th September to 0010 hrs. of 17th September, 1976, the gauge reading observed at 9 a.m. of 16th was 1025.49' at the Ramgarh Road Bridge.

39.5 While Exhibit 9 reveals the highest level reached at the Ramgarh Road Bridge on 17th September as 1040.09', the drawing at page 11 of PTPS's Exhibit, P-5, shows it to be 3.45' higher i.e., 1043.54' which almost tallies with the Management's figure of 1043.42' shown in its drawing at p. 38 of Exhibit 4. Since the DVC's HFL figure of 1040.09' is related to their Damodar bed level figure of 1003', as indicated at p. 51 of Exhibit 4, it means that the depth of water at the bridge was 1040.09' minus 1003' = 37.09'. If 37.09' is added to the figure of 1006.63' being the bed-level of the Damodar as shown by the Management at page 38 of Exhibit 4, the HFL at the bridge would work out to 1043.72' which would be about the same as the figure of 1043.54' of PTPS. It would, therefore, not be unreasonable to accept the figure of 1043.54' as being the highest level reached by the Damodar at the Ramgarh Road Bridge on 17th September, when it has not been questioned by the Management, and especially so when it represents the correlation survey from the Patraru Dam to the Ramgarh Road Bridge.

The Court would now like to relate this figure to the highest flood level attained at the confluence that day.

Water level at confluence

39.6 While the study of the Management calculates the level at the confluence as 1123.53' at page 28 of Exhibit 4, section I of PTPS drawing indicates the level as 1125'. The Management's written statement says the flood situation reached its climax when a number of residential quarters on the banks of the Damodar and Nakari got submerged upto the flood level on 17th September which was the day when the Damodar attained its highest level. According to the PTPS the roof level tops of the quarters and the temple which were submerged is 1125', so that the water level attained on that day must have also been RL 1125'. Since no actual measurement of the roof tops have been produced and not all the houses and the temple are built at the same level around the confluence, the Court would not mind adopting the figure worked out by the Management at 1123.53', which is 1.47' less than the PTPS figure.

In the light of what has been stated above, the difference on 17th September between the highest water-level at the confluence and the Ramgarh Road Bridge would work out to 1123.53' minus 1043.54' = 79.99 feet.

Confluence level on 16th September

40. If it is assumed that the difference of 79.99' could have also prevailed on 16th September, then the level at the confluence that day would work out to something as follows, by adding 79.99' to the Ramgarh Road Bridge level:—

	Level at Ramgarh road bridge : Exhibit 8.	Likely level at confluence
6 a.m.	1021.38'	1101.37'
7 a.m.	1022.38'	1102.37'
8 a.m.	1022.79'	1102.78'
9 a.m.	1025.49'	1105.48'

In case the level at the Ramgarh road bridge is not taken as shown in this table, but 3.45' higher, as has been done by the Management and PTPS in working out the highest flood on the 17th, then the level at the confluence would also become higher, ranging from 1104.82' at 6 a.m. to 1108.93' at 9 a.m., thus raising at 9 a.m. the water level at the RCC bridge to or even more than those heights. It would, therefore, not have been between 11 and 11.30 a.m.—as brought out by the Management and indicated in paragraph 28.3—but around 9 a.m. or so, that the water reached or even over-reached the level of the RCC bridge.

The assumption about carrying the difference in the levels on the 17th to 16th September cannot, of course, be all that perfect, but the fact that it reveals the condition at the confluence at 9 a.m. being 1105.48' or 1108.93'—round about the level which submerged the RCC bridge as brought out in paragraph 38—implies that the water level at the confluence was considerably higher than the bed-level of the Nakari and that the backwater effect, even according to page 48 of Exhibit 4 must have started from 6 a.m. on the 16th, if not earlier.

That the level at the confluence kept on rising also after 9 a.m. is substantiated by the Management's drawing at page 52 of Exhibit 4, which reveals the constantly rising level of the Damodar based on DVC Ramgarh observations. According to the Management also, around 11 a.m., the water level at the Central Saunda Colliery was at least 5' below the top of the earthen embankment there, which means 1110', and reflects clearly the rising level at the confluence.

Backwater contributing to the disaster

41. From what has been brought out in the preceding paragraphs, it is not possible to accept the Management's assertion that the condition at confluence around 1 p.m. on 16th September could not be due to the run-off from the upper catchment as a result of the rains, but would have been achieved only when there was a discharge of 63,000 cusecs from the Nakari contributing to the Damodar. Or for that matter, their assertion that at that time the water level of the Damodar would have been less than 1108'. It is obvious that the level of the Damodar was rising considerably due to the flow from the upper catchment, that this hampered the free flow of the Nakari to the confluence and that, consequently, it was the rise in the level of the Nakari due to backwater that contributed to the accident. According to the PTPS the level at the confluence was 1114' or 1115' : if that is taken as correct, then the logical conclusion would be that the discharge of the Nakari at the Central Saunda Colliery would be very insignificant, i.e., 12,568 cusecs or even lower, as mentioned by the PTPS, and that it must almost have been the backwater effect alone that caused the disaster. It is not necessary for the Court to go into the figure of 1115' at the confluence, for what it is concerned with primarily is to examine the Management's contention that it was only a massive discharge of the Nakari that caused the accident. So going on the data supplied by the Management itself, it is clear that the rising level of the Damodar at the confluence with a discharge from the Nakari, though much less than 71,962 cusecs, resulted in the rise in the level of the Nakari due to backwater which caused the disaster.

Water level at NCDC Saunda

42.1 It has been argued on behalf of the Management that if it was the water of the Damodar that entered the Hathidari goaf of Central Saunda at the level of 1115' around 1 p.m. on 16th September, then that water should have at that time first inundated the NCDC-Saunda upto the same level of 1115'. The NCDC-Saunda Colliery on the Nakari is downstream of Central Saunda and since according to the Management, the tendency of the backflow would be to raise the level at the downstream colliery higher than the level at the colliery upstream, the water of the Damodar could have even reached a height of 1117' around 1 p.m. to enter the Sirka Incline of NCDC-Saunda. But as that did not happen on 16th September when the water level at 1 p.m. at NCDC-Saunda that day was only 1108', it could not have been the backflow that caused the disaster in Central Saunda.

42.2 The PTPS have, however, nowhere stated that it was the water of the Damodar which, as a backflow, entered the goaf at Central Saunda—and that for the reason perhaps that the term 'backflow' from a river into its tributary can evidently only take place when there is no or a very little flow of water along the course of the tributary. What the PTPS have contended is—and which the Court have accepted in principle, but not necessarily with their computed relative figures—that the rising level of the Damodar at the confluence hampered very considerably the flow of the Nakari and raised the level of that tributary at Central Saunda to a height which caused the water to enter the Hathidari goaf at Central Saunda. Since both the phenomena were there—the rising level of the Damodar as well as discharge from the Nakari—the Court does not feel it necessary to try and determine whether it was the Damodar water of the Nakari water, or a mixture of both that entered into Central Saunda Colliery. It was a backwater effect that caused the accident and it is not very pertinent to go into the make-up of that water, though it is obvious that it would have been the Nakari water in greater quantities that gushed into the goaf.

42.3 The acceptance by the Management of the observations of the Manager, NCDC-Saunda Colliery to the effect that the water level at this colliery had reached the figure of 1108' at 1 p.m. can lead to a very interesting conclusion.

Though the deposition of Shri S. N. Chatterjee, Manager, NCDC, Saunda Colliery before the Court on 14-7-77 had made it clear that the levels of the Nakari at his mine had not been recorded anywhere in writing, the Management of Central Saunda have gone by his observations of the water levels and have even agreed with the unsigned document containing the water levels, produced on 18-11-77 by the DGMS from NCDC-Saunda and which has been marked as X-9 for identification.

Shri Chatterjee told the Court that he had occasion to visit the Nakari from 9.30 a.m. to 2 p.m. on 16th September and could see that river from the verandah of his office and read the HFL pillar from there which he did almost every hour. He had noted nothing abnormal: the Nakari was flowing towards the confluence till 2 p.m. and there was no backflow from the Damodar. The level was about 1102' at 9.30 a.m. and at about 1104' to 1105' shortly before 1 p.m. Near about 1 p.m., however, he noted a sudden increase in the level when it jumped to RL 1108'. The figures shown in X-9 are slightly different. The document indicates the water rising in the Damodar at 4 a.m. and touching the RL of 1108' at 2 p.m. When asked what the level of the Nakari would have been at Central Saunda at about 1 p.m., Shri Chatterjee stated that the level there would always have been high at any point of time than the level at NCDC-Saunda. When the Court ordered the Management to indicate the HFL at Central Saunda when the known level at NCDC-Saunda was RL 1108' at 1 p.m. on 16th September, the information was supplied by Shri B. P. Baliga on 1-11-77 which is reproduced below:

"In compliance with the order, the undersigned has carried out necessary computations. Stage discharge rating curve for Nakari at NCDC-Saunda (at appropriate reach) has been determined. Corresponding to Nakari stage of RL 1108.00' at NCDC-Saunda, corresponding stage for the same discharge for Nakari at Central Saunda (near goaf area) and as determined by stage discharge rating curve at this reach would work out to RL 1110.20' for flow from Nakari towards Damodar."

42.4 The conclusion that can be drawn from what Shri Chatterjee and Shri Baliga told the Court is, therefore, very clear. It means that water entered the Hathidari goaf around 1 p.m. with the level of the Nakari there being at RL 1110.20' and not RL 1115' as has been contended by the Management all along. It also implies that the discharge of the Nakari at Central Saunda at that time would have been in the neighbourhood of only 48,867 cusecs, according to the Management's Exhibit 4A, and not nearly 72,000 cusecs as has been their contention.

The above conclusion is based on the Management's own assertion that there was an unhampered free flow of Nakari towards the confluence till about 1 p.m. at least on 16th September. But since it has been established that the level of the water at the confluence started rising constantly from early morning that day which raised the level of the Nakari at Central Saunda, then it was that backwater effect also which made the water attain the level of 1108' at NCDC-Saunda at 1 p.m. With the level at the Colliery downstream being 1108', the level at upstream Central Saunda would have become slightly higher, as is evident from the Management's water profile shown in their drawing 48 in Exhibit 4. NCDC-Saunda is nearer the confluence than Central Saunda and if its position is fixed in that drawing it makes it quite clear that the level at NCDC-Saunda would be somewhat lower than at Central Saunda. Though that drawing is based on figures of discharges from the Nakari and of the Damodar at the confluence which have been questioned by the PTPS, it nonetheless reflects the fact that it would be backwater effect that would cause the level at Central Saunda to be higher than the level at NCDC-Saunda. What exactly would have been the level around 1 p.m. at Central Saunda, with the level at NCDC-Saunda at that time being 1108' has not been worked out by any party, but it seems unlikely that with these two collieries being quite close to each other, the level could go up as high as 1115' at Central Saunda. This, therefore, would again lead to

the same conclusion, i.e. the water entered the Hathidari goaf not at the level of 1115' which is the case of the Management, but at a level lower than that figure. Even assuming that it was not the backwater effect, but a pure backflow which caused the disaster, then the level at Central Saunda at which the water entered the goaf around 1 p.m. would have been even less than 1108' the accepted figure by the Management at NCDC-Saunda.

Thus what comes out from the Nakari having attained a level 1108' around 1 p.m. at NCDC-Saunda—which has been accepted by the Management is that water probably entered the goaf in Central Saunda at that time at a level the less than 1115', whether it was an almost free flow of the Nakari, or a backwater effect from the confluence, or even a backflow which caused the accident.

43.1 If the water then entered into the Hathidari seam at a level below 1115', the conclusion would be that the embankment whose crest was also at 1115' and which had been constructed by the Management to protect that goaf got breached by the rush of water. It has, of course, been contended on behalf of the Management that the failure of the embankment was not due to sloughing but due to overtopping. Shri B. P. Baliga, who saw the embankment in connection with his study, told the Court that no work on that bundh subsequent to the accident would have been undertaken during the period from 16th September, 1976 to sometime in February, 1977 when he visited the bundh. When he saw the bundh in February he found its base had not been damaged and that, according to his judgement on visual inspection, the failure of that earthen embankment was due to overtopping. He had reasons to subscribe to this conclusion, particularly because according to him failure of an earthen bund under draw down conditions is not uncommon. This would, according to the Court, imply that though the embankment was in fact found damaged after the accident, that damage according to the Management had been caused not by the force of the water breaching the embankment at a level lower than 1115', but by the water overtopping its crest at 1115' and by the water's subsequent recession after the accident. Shri Kerketta ruled out the failure of the earthen embankment under draw down conditions, as such conditions, he said, would have damaged the sides of the embankment, which did not happen at Central Saunda. What has been asserted by the Management, the Court feels is a mere conjecture and there can hardly be any ruling out the possibility of the embankment having been breached and damaged at a height of about 1110' or so, i.e., 5 feet below its crest. There were no eye witnesses present at the embankment when the water started gushing into the goaf. What Jit Singh deposed was that when he visited the goaf round about 1215 hrs. and 1245 hrs., he found that the water had increased over the topping of the embankment, but he did not and could not obviously have noted at that juncture whether the water was overtopping the crest which was intact or had already been damaged.

Apart from the fact that the embankment could have been breached and its crest washed away by the impact of the water, there is another possibility also which could justify the water entering the goaf at a level lower than 1115'. Since the material used for the construction of the embankment, as indicated in paragraph 24.1, was just local earth, its top could have been eroded down to level of about 1110' or so, as a result of the rains during the monsoons and more particularly by the cyclonic conditions that were supposed to have set in a few days before 16th September, 1976 in Bihar.

43.2 What has been brought out in this and the preceding paragraph does raise doubts about the height which the Nakari had attained at Central Saunda to cause an ingress of water into the goaf. The Court is, however, not so much concerned about establishing the exact figure of the water level which caused the inundation of the Hathidari goaf, as it is about the question as to whether it was a free massive flow of the Nakari or the rising level of the Damodar which contributed to the disaster. And it has come to the conclusion, as brought out earlier, that the accident was caused not just by the discharge of the Nakari, but by the combined effect of the flow of the tributary and the rising level of the river at the confluence.

PART-IV

Sanction and Inspections

Sanction by DGMS.

44. Though the Directorate General of Mines Safety were not a party to this Inquiry, as indicated in paragraph 6 of this Report, the Court has, nonetheless, to observe that they should not simply assume that a Management's application contains all the facts and information that are relevant to granting them a depillaring permission. They should in general realise that even if there are no mala fide intentions in a public sector undertaking, the Management can still make mistakes in drawing up their application or, inadvertently, not bringing out all that is pertinent to their seeking a depillaring permission. In this particular case, if the DGMS had not just taken it for granted that all the particulars contained in the application and the accompanying plan were correct, they could have brought to the notice of the Management the likely danger of inundation in the mine. And while doing that, they would have thus automatically alerted their own Inspecting Officers about keeping a more careful watch on matters relating to the inundation of the mine. As happened in this case, neither the Management nor the DGMS really thought that there could be possibilities of water entering the Central Saunda Colliery. But even if those possibilities were remote, they should not have simply ignored them, for doing so could mean endangering the lives of the persons working in that mine.

The DGMS should have, therefore, in the first instance checked up the contents of the Management's application with the records and plans of the mine which they are required properly to maintain in their possession. But this was not done, either at their offices at Ranchi or at the headquarters at Dhanbad. If the Ranchi office did not have a comprehensive history of the mine which they are, however, supposed always to maintain, their officers could then have carried out an inspection to verify all the facts that are relevant to a depillaring operation, but even that was not satisfactorily done. The following paragraphs elaborate these observations of the Court.

Uptodate history of mines.

45.1 DGMS's own instructions are very specific about the maintenance by their offices of all previous records and upto-date history sheets of the mines under their control. A history sheet is meant to depict a complete picture of the mine, along with the relevant plans. Dangers in the mines from surface and underground inundations, inflammable gas and fire, etc. are supposed to be noted and maintained in a "danger book" in the regional office and the Group Inspecting Officer has to prepare a detailed note on the status of safety in respect of the mines under his supervision and control. Apart from the fact that no inspection has to be undertaken without going through the past records of the mine, the Inspecting Officers, in the case of mines in the neighbourhood of rivers, water-courses and large tanks, are supposed to pay greater attention to the question of possible inundation, when danger is there, and to initiate precautionary measures every year before the onset of the rainy season. During the month of May they are to remind the Managements and to examine the protective measures and also to undertake surprise inspections during the rainy season to see that the precautions laid down are being followed. The logic of such instructions is very plain. It means firstly that while examining an application for depillaring, for instance, its contents should be compared with the previous records and the upto-date history sheet of the mine. And secondly, with the help of such records, the officers should always become familiar with the important surface and underground features when carrying out the inspections of the mine.

A proper maintenance and study of such records would have very markedly brought to the attention of the regional office at Ranchi, while dealing with the Management's application, the existence of a big nullah, in very close proximity to and in fact, vertically above the area applied for depillaring by the Management. The Court was, therefore, surprised when the Deputy Director of Mines Safety, Shri K.

B. Mazumdar said that he did not have the history sheet of the mine with him while processing the depillaring application. If the history sheet had not been maintained in his office or was not there when he was processing the application, he could have asked the Head Office for the history of the mine. But that was not also done.

Verification by Inspection

45.2 In the absence of the history sheet, Shri Mazumdar could then have properly checked up by an inspection the information supplied in the Management's application. When questioned, he told the Court that during his inspection on 27-6-74 he had noted the 1958 HFL of 288.34 metres in the Management's statutory plan (Exhibit-D), but when it came to check up whether there were any contours lower than that level in the area proposed to be depillared, he said he could not physically verify the slopes because that area was covered by thick and high bushes. He added that he was told by the Management that the land was sloping down uniformly from the only one contour of 295.50 metres, he had noted in their plan, towards the river whose HFL was 288.34m. He could have asked the Management then to produce their statutory surface plan (Exhibit-3), and if that had been done, he would have seen a contour line lower than the HFL in the area proposed to be depillared. He admitted that he saw the surface plan during his general inspection in December 1974 but did not correlate those contour figures with those contained in the Management's application plan. He said that this was because he had assumed, as one would normally do, that the contour lines shown in the surface plan must also have been shown in the Management's application. That was obviously a wrong conclusion drawn, because he should have noticed it when he examined the application, that it did not indicate the contour lines drawn as prescribed in Regulation 59(3)(a). Under that Regulation the Management are required to maintain plans showing the surface contour lines drawn at vertical intervals not exceeding five metres. It would, therefore, stand to reason that when a Management apply for depillaring which is related to a water-course and its HFL, they should indicate all the contour lines in the plan accompanying their application.

The inspections carried out by Shri Mazumdar in December 1974 and in May and August 1975, if properly done, should have also brought to his notice the existence of the small nullah, the extraction of pillars lying vertically below which caused the accident in the mine. The embankment across that nullah should also have come to his attention during his inspections prior to the accident. But his deposition was to the effect that the small nullah and embankment were never in his knowledge, meaning as he brought out that he was, firstly, not apprised of those features by the Management verbally or through their plans and that, secondly, he himself never noticed those features during his inspection.

Depillaring commenced prior to grant of permission

46.1 Though he did not in his earlier depositions inform the Court evidently because he was not specifically asked to do so, it came out later that Shri Mazumdar during his inspection on 13-12-74 had gone down the 24th Incine of the Hathidari seam with the Manager of the mine and had inspected the depillaring going on there. This was brought to the attention of the Court by the Joint Director, Shri J. C. Aggarwal who referred to that fact, which is contained in Shri Mazumdar's own Inspection Report of 13-12-74 (page 1, 7 and 8 of Exhibit F. 3). Knowing then that the Management had started the depillaring before the DGMS had authorised them to do so,—as mentioned in paragraph 22.2 of this Report,—the Deputy Director should not have simply gone by the non-statutory plans presented to him and should not have taken it for granted that whatever the Management had depicted in the plan accompanying the application was correct.

Not mentioned in the sanction file.

46.2 What is surprising is that 3 days after this inspection of the Hathidari seam on 13-12-74 when he put up the file to the Joint Director recommending the sanction of the depillaring application, he did not mention the fact that the Management had already started the depillaring. When asked why he did not bring out that fact in the file-Exhibit R-9, his explanation was not at all satisfactory. The explanation was to the effect that as he had already mentioned that in

his Inspection Report, it was not necessary for him to have done so in the file which dealt with the sanctioning of the depillaring operation. Asked when in those circumstances his senior officers would have seen his Inspection Report which indicated that depillaring had commenced before permission had been granted, he said that they would have seen that Report after his submission to them on 26th June, 1975. When told that his Joint Director, Shri Aggarwal and his Director, Shri S. D. Prasad, while sanctioning the application in January 1975, would not have known about the Management having started the depillaring perhaps even a month or two before December 1974, Shri Mazumdar had to admit that the late submission of his Report to them could not bring out the violations by the Management in proper time before his senior officers. The reason for the delay in the submission of his report, he added, was the burden of his work and delay in typing out the Report.

Verbal information

46.3 Asked why he had not at least verbally informed his senior officers about the unauthorised depillaring prior to January 1975, Shri Mazumdar said that he did not have an opportunity of verbally telling them about it. When he was informed that Shri Aggarwal was aware of the unauthorised depillaring prior to January 1975, and had told the Court that he had discussed it with Shri Prasad and had arrived at a conclusion not to prosecute the Management, Shri Mazumdar denied having verbally informed either Shri Aggarwal or Shri Prasad about the unauthorised depillaring. Shri Prasad also told the Court that Shri Aggarwal had not informed him or discussed with him the fact that depillaring had already been commenced by the Management.

The Court also brought to the notice of Shri Mazumdar the spot enquiry made by him and which was received by the Manager of the mine on 20-12-74. That spot enquiry revealed two facts related to insufficient air in the working places and there being no arrangements of spraying the faces. When asked why he did not also mention in that report the fact that the Management had started the depillaring prior to receiving the permission, Shri Mazumdar said it was because he expected that the depillaring permission would be given shortly and it was for that reason he felt that there was not going to be any violation. His main contention was always to the effect that the file on the depillaring permission which was opened in September 1974 dealt only with the questions regarding the throw of the faults and the reasons for non-development from the in-bye. As there were no other objections from his senior officer and since he had on 16-12-74 dealt with the questions raised in the file, he anticipated an early sanction of the depillaring operation. This is a contention which it is most difficult to accept for if the note written 3 days after his inspection of the Hathidari seam on 13-12-74 had brought out the fact of the depillaring which had already commenced, the Court cannot just assume that his senior officers would not have taken action of some sort in that regard.

46.4 The deposition made by the officers of the DGMS on unauthorised commencement of depillaring are contradictory. If the deposition of Shri Mazumdar is assumed to be correct then the inference would be that he did not bother to inform his senior officers about it because he was confident that the depillaring permission would be granted shortly and that in this context, the violation by the Management was not all that serious. His logic was that whatever had been indicated in the Management's application was correct and that there was, therefore, no danger of inundation in the mine. If, on the other hand, Shri Aggarwal's deposition is assumed to be correct, the inference would be that both he and Shri Prasad knew about the unauthorised depillaring but did not consider it as a serious violation, because it did not constitute a danger of inundation. In fact Shri Aggarwal told the Court that when he came to know on the 15th or 16th December 1974 about the commencement of the unauthorised depillaring from Shri Mazumdar, he did not consider that the extraction of approximately one pillar was a very serious affair. And that on the stand that the officers of the DGMS work in good faith and completely depend on the data supplied by the Management. In other words, since that data did indicate any danger of inundation, they took it to be correct. Shri Aggarwal said that he discussed the matter with Shri Prasad, who in general being very kind-hearted had told him that the application should be processed immediately in order to

regularise the depillaring which had already been commenced. Shri Prasad's contention was also to the effect that they have full trust in the information supplied by the Management and that they never expect any concealment of information from a nationalised Management.

The Court feels that it was evidently on this assumption that Shri Prasad did not see the Statutory plans when he made a surprise visit to inspect the depillaring area in the Hathidari seam. That inspection, Exhibit F, was carried out on 12-2-75, i.e. about 40 days after granting the depillaring permission when one could have gone through the relevant statutory plans connected with depillaring. He was, however, satisfied by seeing the hand plans only which he said did not at all show the nullahs.

The implication that really matters, and which comes out from what has been indicated above, is that everyone in the DGMS just took it for granted that whatever was contained in the Management's application was perfectly authentic and correct.

Scrutiny of the application

47.1 It was not only the officers at Ranchi, but in the DGMS headquarters at Dhanbad also, that took such a complacent attitude. Shri S. R. Sarkar, Deputy Director at Dhanbad, who had to go through the applications before passing them on for sanction to the zonal/regional offices, told the Court that if the Management's application did not say anything unusual and the plan did not show anything then sitting at the head office he could naturally not guess that there was anything missing in either the application or the plan. The examination of the application, he said, is based on what is contained in the application, he itself and not with any reference to the updated plans in the Headquarters supplied by the Management under Regulation 50. Even supposing that the purpose at the time of forwarding an application to a regional or zonal office for necessary action is to go through the application and plan only to see that they are prima facie in order, the Court is certain that just an ordinary scrutiny of the application itself without any reference to the records maintained at the Headquarters could have revealed some inconsistencies in the application and plan. It could have been noted, for instance, that though the Management's plan had shown the river, it had not indicated the figure of the height that the bank of the river would extend upto the highest known flood level or the contours relevant to that HFL figure.

Scrutiny of the sanction

47.2 If initially even such an ordinary scrutiny of the application is not considered very necessary, it is as per the DGMS's own instructions and as brought out also by Shri Prasad, incumbent on the Head Office—on receiving a copy of the letter sanctioning the application—to examine it in order to ensure that nothing important has been missed in the zonal office and that the permission has been properly granted. Being, therefore, aware of the provisions of Regulation 60 and also knowing that the Head office had with them the plans of the Central Saunda Colliery like Exhibits U, U-1, U-2 for example, which showed the HFL, the big nullah and the contours, the Court wanted to find out whether the Head Office had examined the letter of sanction from Ranchi with reference to the information available with them. It was surprised when Shri Sarkar's reply was that he did examine the permission letter, but without any reference to the mine history or the plans of the mine. Even the type of whatever examination was carried out at the Headquarters of the permission letter is not mentioned in the DGMS's file, Exhibit-V. The notings dated the 27th and 28th of January 1975 in that file are simply to the effect that the sanction letter should be recorded in the register. This again brings out that in practice even the headquarters also assume that anything contained in an application is always correct, despite the specific instructions which requires it to be meticulous and careful in examining the letters of sanction.

Difficulties in the DGMS

47.3 The main contention of the DGMS's field officers who deposed before the Court was generally to the effect that it is

impossible for them to ascertain the correctness of any application by a physical verification because of the extensive number of plans submitted to them and the number of seams being worked in a particular mine, and that it also becomes difficult for them to keep in mind all the details in respect of all the mines. But when asked whether all this had been brought to the notice of the Director General, the reply received was that the DG knew about this aspect of their working. The Court feels that in these circumstances, if the inspection organisation is understaffed, the Director General should formulate more realistic written instructions following his understanding of the aspects of the working of the field officers. In respect of the headquarters staff who, according to Shri Sarkar, also have their practical difficulties in dealing with large number of applications, the DGMS should also work out a more realistic procedure for their working.

Violation of Regulation 60

48. The Court has also observed another type of complacent in the DGMS. Regulation 60 of the Coal Mines Regulation makes it obligatory on the Management to submit to the DGMS by 31st October every year two copies of the underground plan of the mine showing, amongst other things, all the important surface features such as a river, stream, water course, etc. which is within 200 metres of any part of the workings measured on the horizontal plane. One copy of the plan received by the DGMS at Dhanbad, is meant to be endorsed by them to their regional offices which deal with those mines and those offices are required to keep them in a separate folder along with the history sheet of the mines. It did come out that there was a proposal (Exhibit G) to delete Regulation 60, which the DGMS thought was necessary, but the Court noted that the Government had rejected that proposal in April 1969. With that being so, the DGMS after that should not have been lax when the Management did not submit those plans and should have ensured that two copies of the updated underground plans were regularly received by them every year, so that they could despatch one copy to their office at Ranchi. If that had been done, the regional office would have at least been continuously made aware on paper of the existence of a big nullah and would have become very cautious in sanctioning the depillaring in and under its close proximity. A copy of the underground plan for the period ending 31-10-74, probably, but the plan for the year ending 31-10-75, certainly, would have brought out also the existence of the small nullah flowing over the area which was to be depillared and was being depillared. The Inspecting Officers should, even otherwise, have been aware of such important features as the river and the nullahs near and inside the property of the mine in order to relate them to depillaring operations of the Management.

Accident Report of DGMS

49. If the field officers and the regional officer had not been able to relate the big nullah with the area already developed and the area proposed to the depillared, with reference either to the history of the mine or the inspections made by them over the years, that failure could have at least been noted in Accident Report of the DGMS. That Report containing the inquiry made of the circumstances connected with the accident was brought out on 22-12-76.

While submitting the Report, the officers dealing with it had with them the seized statutory plan of the mine (Exhibit D) which showed that the depillaring had reached vertically below the big nullah. The inference that depillaring apart, the DGMS officers should not have even allowed the Management, without their permission, to develop the Hathidari seam upto that extent in the years past was, however, not mentioned in the Report. Annexure 'C' of that Report, which is a plan of the surface area through which the flood waters entered the mine, and which is marked as Exhibit K, however, shows the big nullah, but there is no cross-reference to it in the body of the Report which is required, when submitting a report. While that plan does not show that depillaring had been done vertically below that nullah, for the reason perhaps that it was not easy to carry out an underground survey so soon after the accident, it does indicate that that nullah is still within 15 metres of the depillared area. That being so, the Report could have brought out the fact that the depillaring permission had been wrongly given and that no Inspecting

Officer, after the sanction, had noticed that the depillaring was actually proceeding near to and under that big nullah and also vertically below the small nullah. It is difficult to say that the omission of the implications of these two nullahs in the Accident Report—written under the guidance of Shri S. D. Prasad, the then Director of Mines Safety—especially with reference to the depillaring that had taken place under them, was an attempt to disassociate the officers of the DGMS from the accident that took place in the mine. But even if that was not so, the Report could have brought out the fact that while granting the permission, no note had been taken of the fact that the development of the seam had progressively gone nearer to and under the big nullah and that the depillaring near or under it and directly under the small nullah had never been detected during the inspections. Or even if detected, it was probably ignored on the assumption of the inspecting officers that there was no possibility of an inundation ever in the Central Saunda Colliery.

When examined, the Court was informed by Shri A.N. Mukhopadhyay, the then Joint Director of Mines Safety, who submitted the Accident Report, that in the inquiries held by them, the general procedure is to concentrate on and bring out the facts and contraventions that directly contribute to the cause of the accident. Each and every violation is not pointed out in the accident enquiry report. The water, according to him, had backed through into the mine, not from the big nullah but through the smaller nullah, and the Report had brought out the fact that the Management had not shown that small nullah, originating over the area where the pillars had been extracted, in the plan submitted to the DGMS for obtaining the depillaring permission.

"While it is correct that the depillaring under the small nullah (which was not brought in writing to the notice of the DGMS by the Management) resulted in the inundation of the seam, the Accident Report could have, nevertheless also given, as per the DGMS's own instructions, the background information on the aspects of the working of the mine relevant to the accident. Since depillaring was directly connected with the development of the seam, the improper way in which it had been developed and which should have obviously been observed by the Inspecting Officers, or for that matter the depillaring had started even prior to the sanction, was not brought out in the Accident Report, which could have also given the circumstances, step by step, leading logically to the accident in the mine.

PART-V

Conclusions

50. It is when an accident takes place that a number earlier violations of the Coal Mines Regulations come to the fore, indirectly and directly connected with the accident.

In this case, the Court has brought chronologically the events that led to the accident in the Central Saunda Colliery. Firstly, the development of the Hathidari seam which had taken place, ignoring the proximity of the big nullah. Secondly, the Management's consequential application seeking permission to depillar that developed area near to and under the big nullah. Thirdly, to continue that depillaring even under the small nullah, which was later discovered running directly over the area to be depillared, but which was not brought to the notice of the DGMS in writing. Fourthly, ignoring the highest known flood level in the mine. Fifthly, the non-maintenance of a regular watch of the rising level of water during the rainy season, especially near the embankment designed by the Management, on their own, to prevent the inflow of water. And then, the failure to adopt the relevant safety precautions which with the level of the water rising, could have prevented sending persons down to the Hathidari seam and could have also led to the withdrawal of those who were continuously there to operate the pump in that seam.

51. The above failures constitute violation by the Management of the Coal Mines Regulations dealing with the dangers of inundation from surface water; the maintenance of the proper plans and sections of the mine relevant to inspections

by the DGMS, and the submission regularly to them of the plans showing the underground working in the Hathidari seam.

Though the Management defaulted in this and other ways, the DGMS also should not have just assumed that whatever was depicted in the depillaring application and plan was unquestionably correct. With their knowledge and experience, and the duration of their supervision of the mine, they should have taken such relevant factors as the water-courses and the HFI into account, and should not have failed during their general and specific inspections to notice physically the big and the small nullahs, the improvised embankment, and the implications of these features related to the depillaring taking place in the Hathidari seam. It did, however, come out before the Court that during his working, a Deputy Director of Mines Safety can have as many as 22 to 25 collieries under his charge and 70 to 110 other mines, situated for instance, partly in the Hazaribagh district, whole of Ranchi and the whole of Palaman district in Bihar and upto the border of U.P. and Madhya Pradesh. If then the Inspecting Officers must meticulously follow all the detailed instructions laid down for them, steps will necessarily have to be taken by the DGMS to see that the inspection organisation is properly geared to carry out all those instructions and is not understaffed.

52. During an Inquiry, it is not unnatural for those in the Management or elsewhere, connected in varying degrees with the violations, to defend themselves by producing such facts and arguments they think will help in disassociating them from the accident. But doing this theoretically, or even otherwise, prolongs the examination of a Court. An example in this case, was the argument that it was a massive discharge of water from the Patrati Dam which caused the inundation of the mine. There are other arguments also, the examination of which brought out contradictions and shortcomings which even if remotely connected with an accident, should not have been allowed to keep on persisting in the mine.

53.1 Even with the various violations pointed out in this case, the loss of lives in the Hathidari seam could have reasonably been averted if there had been a timely appreciation by the Management of the rising level of water at the embankment adjacent to the goaf. But there was hardly any adequate arrangement made by them about the safety in mines in this regard. Safety related to surface water inundating the mine was not given the prominence and importance that it obviously has, with reference to what is also contained in Regulations 41A and 190 of the Coal Mines Regulations. That apart, there should be some imagination always on the part of the Management to anticipate any likely inundation, since the Regulations are general in character and cannot always list out measures which are pertinent to some peculiar conditions in any particular mine.

53.2 Entrusting the Safety Officer and the officer who was supposed to help him, with duties connected with production of coal from mine—and that also without getting the permission from DGMS—meant underrating safety and diluting the responsibility of those officers in taking full and proper measures to avoid any accident in the mine.

On 16th September, the Senior Overman had been asked to keep a watch on the water level. But he could effectively never do so, because there was evidently no means of his being able to read the exact rising level of the water. If there had been bench-mark or a pillar near the embankment, he could have communicated to the Manager at 11 a.m. the exact increase in the water level, even if it was supposed to be slight according to his deposition. With that done, the Manager could have drawn his own conclusions. The Overman could not also keep a constant watch at the Hathidari goaf—from which the danger of inundation was greater—as he was supposed to inspect three other goafs also in order to check the garland drains around them and to repair them, if necessary. This means that he could not stay at the Hathidari goaf all the time in order to keep a constant watch on the rising level of water at the embankment. What is more, it meant that the instructions given to him and what he saw and did were all very perfunctory and that there was no serious attempt at safety by keeping a real

watch on the rising level of the water on 16th September. If it had been observed that the water had started rising above the toe of the embankment and was touching the level of 1108', 1110' or 1112', and if there had been some specific instructions about the withdrawal of persons connected with those water levels, workmen would not have been sent down the Hathidari seam, or if they were already there, they could have been withdrawn. Water would have gushed into the seam through the Hathidari goaf, but would not have taken the life of the persons engaged in shiling the water pump in that seam.

54. Various persons connected with different aspects of safety in the mine, related to its possible inundation, did not play their roles in an adequate and efficient manner. If that had been done, then even with the previous shortcomings and default's in the depillaring operations, the accident may not have taken place in the mine. The DGMS is meant to be associated with and should be more alert in such matters. But the main responsibility for things going wrong in this connection is that of the Management, which did not prescribe and implement specific practical steps and procedures to prevent an accident from a possible inundation of the mine. With water-courses of different shape and sizes within the property of the mine itself, and being connected with the nearby big tributary which flows into the Damodar not far away, there should never have been any complacency about the possibility of an inundation in the mine. The dam upstream is meant to discharge water in a judicious manner, but even with that being done, the rising level of the Damodar down below and its backwater effect should not be ruled out for ever. On 16th September there was a somewhat large discharge of the Nakari water from the Patrati Dam, but that by itself was not the sole cause of the accident that took place in the mine. The PTPS authorities should, however, never ignore the existence of the mines along the Nakari river and should forewarn the Managements about the large discharge of water from the Patrati Dam.

55. I direct that the Management of the Central Saunda Colliery should bear the entire cost of this Inquiry. The actual expenditure should be computed by the DGMS and, after it has been audited, it should be recovered from the Management.

Acknowledgement

56. I am grateful to the two Assessors, Prof. S. S. Saluja and Shri S. Das Gupta nominated by the Government to assist the Court of Inquiry. They have been very helpful in assisting the causes and circumstances of the accident and have associated themselves with the preparation and completion of the Report.

The Secretary of the Court, Shri Satpal Singh, worked very steadfastly throughout the Inquiry and Shri P. K. Bhatia, who recorded the depositions of the witnesses, did that in an efficient and most satisfactory manner.

I have also to thank the DGMS and the Management who provided all the facilities for holding the Inquiry at Ranchi.

Sd/-

(N. P. DUBE),

Former Labour Secretary
to the Government of India
COURT OF INQUIRY

New Delhi,

the 22nd December, 1978.

Sd/-

(PROF. S. S. SALUJA)
Director, Institute of Technology
Banaras Hindu University
ASSESSOR

Sd/-

(S. DAS GUPTA)
General Secretary, Indian National
Mine Workers' Federation
ASSESSOR

ANNEXURE-I

Names of the Deceased	
1. Shri K. Pandey	Foreman Trainee (Elec. & Mech.)
2. Shri Tribhuban Prasad Lal	Electric Helper
3. Shri Rajdeo Ahir	Tyndel
4. Shri Ramnath	Pump Khalasi
5. Shri Idnis	Mechanical Fitter
6. Shri Sitaram Sahu	Electrician
7. Shri Kishun	Tyndel
8. Shri Bhulai	Tyndel
9. Shri Birju Pasi	Pump Helper
10. Shri Fakir Md.	Fitter Helper

ANNEXURE-II**List of Witnesses Examined on Behalf of:—****PARTY NO. 1 (MANAGEMENT)**

1. Shri Balbinder Singh	Pump Cleaner.
2. Shri Abhilakh Yadav	Tyndel.
3. Shri Kundan Singh	Tyndel.
4. Shri P.K. Das	Manager, Saunda 'D' Colliery.
5. Shri R. Choubey	Senior Executive Engineer (E&M), Saunda 'D' Colliery
6. Shri N. Nayak	Executive Engineer (E&M) Central Saunda Colliery.
7. Shri K.K. Gupta	Under Manager, Central Saunda Colliery.
8. Shri A. Kundu	Senior Executive Engineer, Central Saunda Colliery
9. Shri O.N. Sharma	Foreman & Incharge, Electri- city, Central Saunda Colliery.
10. Shri A.K. Sen Gupta	Electrical Supervisor, Central Saunda Colliery.
11. Shri Sitaram Rajak	Contractor's Labour
12. Shri Nageshwar Sahu	Mechanical Fitter, Central Saunda Colliery.
13. Shri Pratap Kumar Mazumdar	Surveyor, Central Saunda Colliery.
14. Shri B.P. Baliga	Superintending Engineer, CMPDI.
15. Shri S.K. Dutta Choudhury	Safety Officer, Central Saunda Colliery.
16. Shri Jit Singh	Overman, Central Saunda Colliery.
17. Shri S.N. Chatterjee	Manager, NCDC-Saunda Colliery.
18. Shri Chhatradhary Pandey	Time Keeper, Central Saunda Colliery.
19. Shri Diljan	Pump Khalasi, Central Saunda Colliery.
20. Shri Sukh Dev Raj Sharma	Assistant Colliery Manager, Central Saunda Colliery.
21. Shri K. Doraiswami	Manager, Central Saunda Colliery.

1	2
22. Shri B. Mewar	Agent, Central Saunda Colliery (17-12-73 to 3-8-76)
23. Shri S.K. Mukherjee	Agent, Central Saunda Colliery (from 3-8-76).
24. Dr. R. Kumar	Superintendent (Mine), CMPDI.
PARTY NO. 3 (PTPS)	
1. Shri Satish Chandra	Assistant Engineer, PHED.
2. Shri Vasudev Singh	Pump Khalasi, Colfer Dam.
3. Shri Ramadhar Singh	Assistant Pump Operator, PHED.
4. Shri Hiralal Thakar	Pump Operator, PHED, Colfer Dam.
5. Shri Hira Prasad Singh	Asstt. Pump Operator PHED, Filtration Plant.
6. Shri Prabha Shankar Bajpai	Supdt. (Electrical) BASL.
7. Shri Ramadhar Prasad	Junior Engineer, PHED, Patratu.
8. Shri S.N. Barla	Pump Operator Grade-II, Sewerage Treatment Plant.

COURT

1. Shri Dharendra Nath Majee	Asstt. Engineer, PHE D Patratu.
2. Shri N. Kerketta	General Manager-cum-Chief Engineer, PTPS.
3. Shri Jyoti Narayan Prasad	Block Development Officer, Patratu.
4. Shri Krishan Nand Tiwari	Electric Helper, Central Saunda Colliery.
5. Shri K.B. Mazumdar	Deputy Director of Mines Safety.
6. Shri S.D. Prasad	Director of Mines Safety.
7. Shri S.K. Puri	Safety Officer, Central Saunda Colliery (Feb. 74 to May 75).
7. Shri Awadesh Narain Sinha	Safety Officer, Central Saunda Colliery (May, 75 to Mar. 76).
9. Shri B.L. Wadehra	Chairman-cum-Managing Director, CCL.
10. Shri A.K. Chatterjee	General Manager, CCL Barkakana.
11. Shri J.C. Aggarwal	Jt. Director of Mines Safety (Retd.).
12. Shri A.N. Mukhopadhyay	Director of Mines Safety, Ranchi.
13. Shri S.R. Sarkar	Dy. Director, National Council for Safety in Mines, Sitarampur.

ANNEXURE-III**List of Exhibits**

Exhibits filed on behalf of Party No. 1 (Management)

Sl. No.	Exhibit marked	Description of the documents
1	2	3
1.	1	Level Book of the Surveyor.
2.	2	Surface Plan of Barkakana as on 17-9-1976 (Blue Print).

1	2	3	1	2	3
3.	2A	CCL, Master Plan (Blue Print)—Surveyor has signed it and dated it as 12-5-1977.	25.	19	Safety set-up of Central Saunda.
4.	2B	CCL, Section of Seams (not to scale).	26.	20	Exercise calculation made on factor of safety and Mine Pillars of the Hathidari Seam by Dr. Kumar
5.	2C	Surface Plan of Hathidari Seam (Blue Print) as signed by Surveyor on 12-5-1977.	27.	20A	The Report of Dr. Kumar pertaining to area of extraction/nature of subsidence, etc. (Plan enclosed with the Report not accepted as an exhibit)
6.	2D	Working Plan of Hathidari Seam (Blue Print) as signed by Surveyor on 12-5-1977—scale 1 cm=12 mts.	28.	21	Combined Plan of Barkakana—Surface Plan on tracing paper.
7.	2E	Working Plan of Hathidari Seam (Blue Print) as signed by Surveyor on 12-5-1977—scale 1"=200'. It gives names of dead persons and also the date of recovery.	29.	22	Index Register of list of Plans etc. under Regulation 62(4).
8.	3	The original Surface Plan, mounted on cloth. (Copy at Annexure IV-E).	30.	23	Noting dated 1-11-77 of Shri Baliga regarding his comments on PTPS letters dated 9th and 14th August and 13th and 14th September, 1977. This noting is on 13 pages and contains 5 set of drawings.
9.	4	Drawing relating to study of Nakari River and Damodar River (Patratu Barkakana Ramgarh Reach). It consists of 54 drawings and three pages of table of contents.	31.	23A	Plan—Nakari Reach between Jainagar Railway Bridge and Saunda 'D' Road Bridge.
10.	4A	Report on study of Nakari Reservoir Operation by Shri B.P. Baliga.	32.	23B	Plan—Cross Section at CH-2135/22677/etc.
11.	5	Regulation Manual for DVC.	33.	23C	Plan—Cross Section at CH-27677/28677/etc.
12.	6	Daily Isohytel Map (18 maps) of Damodar Valley Area for the period 1-9-76 to 18-9-76 along with forwarding letter from Mr. P.K. Ghosh, Additional Chief Mining Engineer, CIL.	34.	23D	Plan—Nakari Road between Saunda 'D' Road Bridge and Saunda Common boundary.
13.	7	Rainfall data for Damodar Valley area from 15-9-76, received from Mr. U.S. Das, Meteorologist, Regional Meteorological Centre, Alipore, Calcutta.	35.	23E	Plan with Section on 'A B' CH-33237 near Saunda 'D'
14.	8	Hourly Gauge Reading of the Damodar River at Ramgarh Station for period 12-9-76 to 20-9-76 obtained from Hydraulic Data Division, D.V.C., signed by the Assistant Engineer, Hydraulics dated 8-7-77.	36.	23F	Plan—Cross Section at Chainage 33810.
15.	5.9	Statement showing yearly maximum discharge and gauge in R.L. of Ramgarh site on river Damodar right from the year 1945 upto 1976 obtained from Hydraulic Data Division at DVC.	37.	24	Results of studies made by Management (Shri Baliga) in respect of three quarries referred to in Order Sheet No. 35 dated 19-11-1977.
16.	10	Blank Proforma for reservoir operation, that is, daily flow balance sheet as maintained by DVC.	38.	25	List of Dead Persons duly signed by DGMS Party No. 1 (Management) and Party No.2 (RCMS).
17.	11	Memorandum on Flood Warning Service No. W2(C)-20/65-1668 dated 20th May, 1975 issued by DAVC Authorities.	Exhibits filed on behalf of party No. 3 (PTPS)		
18.	12	Act No. 14 of 1948 DVC (14 pages).	1.	P-1	Log-Book of Sewerage Treatment Plant.
19.	13	Topographic Map of Hazaribagh at Ranchi District prepared by Surveyor General of India and containing map reference sheet 73, R/6 3rd addition dated 1943 (a document 34 years old).	2.	P-2	Note-Book of Shri Satish Chandra.
20.	14	Bihar State Electricity Board PTPS Topographic map of Thermal Power Station and surroundings.	3.	P-2A	Note-book of Shri Ramadhar Prasad.
21.	15	Diary of Shri Dutta Choudhury, Safety Officer.	4.	P-3	Log-Book of Colfer Dam Pump House.
22.	16	Old Surface Plan (1956).	5.	P-4	Study made by Shri N. Kerketta, General Manager-cum-Chief Engineer, Patratu Thermal Power Station. This is study of Nakari Reservoir Catchment etc. in order to ascertain the causes of flooding of Central Saunda Mine.
23.	17	Geological Map of Mauza Saunda	6.	P-5	A set of eighteen drawings relating to Nakari and Damodar River.
24.	18	Office Order No. CS/SON/ 36/76/1220 dated 7-4-76 filed by the Management relating to allotment of duties at Central Saunda (Hathidari).	7.	P-6	Log-Book maintained for Reservoir Level and Gate Operation for the year 1973.
			8.	P-7	PTPS letter in connection with Shri Baliga's evidence No. 12/GM dated 9-8-1977.
			9.	P-8	PTPS letter in connection with Shri Baliga's evidence No. 15/GM dated 14-8-1977.
			10.	P-9	PTPS letter in connection with Shri Baliga's evidence No. 21/GM dated 10-9-1977.
			11.	P-10	PTPS letter in connection with Shri Baliga's evidence No. 23/GM dated 14-9-1977.
			12.	P-11	PTPS letter in connection with Shri Baliga's evidence No. 2150 dated 24-10-77.
			13.	P-12	PTPS letter No. 2228 dated 8-11-77.
			14.	P-13	Result of studies made by PTPS (Shri Kerke) in respect of the quarries referred to in Order Sheet No. 35 of 19-11-1977.

1	2	3	1	2	3
Exhibits filed in the Court (Documents seized or produced by DGMS)			under Regulation 101 of CMR (Copy at Annexure IV-C).		
1.	A	Statement dated 21-9-1976 of Shri Balbindra Singh, Tyndel.	29.	C-1	Letter dated 9-8-74 of Management enclosing Exhibit C.
2.	A-1	Statement dated 18-9-76 of Shri Abhilakh Yadav, Tyndel.	30.	D	The original Working Plan mounted on cloth, of Hathidari Seam. (Copy at Annexure IV-D).
3.	A-2	Statement dated 18-9-76 of Shri Kundan Singh, Tyndel.	31.	E	Field Diary of Surveyor.
4.	A-3	Statement dated 18-9-76 of Shri Nilachal Nayak, Engineer.	32.	E-1	Measurement Book of Surveyor.
5.	A-4	Statement dated 22-9-76 of Shri K.K. Gupta, Under Manager.	33.	F	Inspection Report, dated 12-2-75 of DGMS relating to inspection of depillaring area in Hathidari Seam from New Hathigora Incline.
6.	A-5	Statement dated 23-9-76 of Shri A. Kundu, XEN (E&M).	34.	F-1	Letter No. RRL/3762/Ranchi, dated 30-8-75 issued to Management by DGMS relating to depillaring in Hathidari area.
7.	A-6	Statement dated 22-9-76 of Shri O.N. Sharma, Foreman Incharge (Electrical).	35.	F-2	Shri K.B. Mazumdar, Deputy Director of Mines Safety, Ranchi, Report, dated 28-8-75 with regard to complaint from President, Colliery Mazdoor Sangh.
8.	A-7	Statement dated 22-9-76 of Shri A.K. Sen Gupta, Electrical Supervisor.	36.	F-3	General Inspection Report of the Mine by DGMS on 13th, 18th and 20th December, 1974, containing 16 pages.
9.	A-8	Statement dated 21-9-76 of Shri Pratap Kumar Mazumdar, Surveyor.	37.	F-4	General Inspection Report of the Mine by DGMS for the period 7th, 8th, 12th, 13th, 23rd and 26th May, 1975 containing 13 pages.
10.	A-9	Statement dated 17-9-76 of Shri S.K. Dutta Choudhury, Safety Officer.	38.	F-5	The Inspection Report, dated 7-5-75 and 12-5-75 by Shri J.C. Aggarwal, Joint Director of Mines Safety.
11.	A-10	Statement dated 21-9-76 of Shri Chhatardhari Pandey, Register Keeper.	39.	F-6	The violations pointed out to the Management with regard to the general inspection by DGMS on 7th, 8th, 12th, 13th, 23rd, and 26th May, 1975 communicated to the CCL, vide DGMS letter No. RRL/3812/Ranchi, dated 3rd September, 1975.
12.	A-11	Statement dated 22-9-76 of Shri Diljan, Pump Khalasi.	40.	F-7	Letter No. RR/4444, dated 17th October, 1975 from DGMS to the Agent, Central Saunda Colliery regarding complaint, dated 18-3-75 of Colliery Mazdoor Sangh.
13.	A-12	Statement dated 22-9-76 of Shri S.R. Sharma, Asstt. Colliery Manager.	41.	G	Correspondence between DGMS and the Ministry of Labour regarding Regulation 60 of CMR, 1957.
14.	A-13	Statement dated 17-9-76 of Shri K. Doraiswami, Manager.	42.	H	Attendance Register of Central Saunda Colliery (Form C).
15.	A-14	Statement dated 23-9-76 of Shri K. Doraiswami, Manager.	43.	I	Water Danger Plan
16.	A-15	Statement dated 21-9-76 of Shri B. Mewar.	44.	J	Letter No. SEZ/25 (Coal), dated 2-1-75 of DGMS according sanction for depillaring.
17.	A-16	Statement dated 17-9-76 of Shri S.K. Mukherjee.	45.	K	Surface Plan filed by DGMS as enclosure to their enquiry report.
18.	A-17	Statement dated 23-9-76 of Shri S.K. Mukherjee.	46.	L	Manager Shri Doraiswami's Statutory Diary.
19.	A-18	Statement dated 22-9-76 of Shri K. N. Tewari.	47.	M	Diary of Shri S.R. Sharma.
20.	B	Plan enclosed with the Management Application No. CS/9468/74, dated 10-4-74 asking for depillaring sanction (Zonal Office File). (Copy at Annexure IV-A.).	48.	N	Surveyor Shri Mazumdar's Report Book [Regulation 49 (2) of CMR, 1957].
21.	B-1	Proforma enclosed with Exhibit B.	49.	O	Cap Lamp Register (originally marking for identification).
22.	B-2	Application No. CS/9468/74, dated 10-4-74 of Management produced by D.G.M.S.	50.	Q	Seizure List, dated 17-9-1976 containing 10 items.
23.	B-3	Application No. CS/9468/74 dated, 10-4-74 of Management seized by DGMS.	51.	Q-1	Seizure List, dated 23-9-76 containing only 2 items.
24.	B-4	Plan enclosed with the Management application No. CS/9468/74, dated, 10-4-74 (seized by DGMS.).			
25.	B-5	Proforma enclosed with Exhibit B-4.			
26.	B-6	Plan dated 5-4-77 enclosed with Management's letter, dated 10-4-77 (showing River faintly) HQ file.			
27.	B-7	Plan dated 5-4-77 enclosed with Management's letter, dated 10-4-77 not showing the River Nakari-HQ file (Copy at Annexure IV-B).			
28.	C	Plan enclosed with the Management application dated 9-8-74, regarding depillaring sanction			

1	2	3	1	2	3
52.	R	Plan No. CMB-1/N/8-72, dated 15-12-72 on which Director General of Mines Safety granted a permission under Regulation 100 to split pillars as final operation in No. 1 East Panel of Upper Nakari Seam indicated the High Flood Level as 1130 ft. without showing the date thereof.			mission for extraction of pillars under Regulation 100 which was refused by the Chief Inspector of Mines by his letter No. 41620G, dated 22nd August, 1963.
53.	R-1	Director-General of Mines Safety by his letter No. 15124-G dated 20th August, 1971 granted a permission under Regulation 100 to split pillars as final operation in No. 1 West Panel of Upper Nakari as indicated on plan, dated 11-3-71 enclosed with Management's letter No. DSOC/BHK/Permission/3956-58, dated 26-3-71 Bhurkunda No. 1 Colliery. On this plan the HFL was shown as 1130 ft. without showing the date thereof.	60.	R-8	Accident Report No. RR/4748, dated 5th November, 1975 pertaining to a fatal accident, dated 21st August, 1975 and the spot inspection by Shri K.B. Mazumdar on 22-8-75.
54.	R-2	Plan No. BHK-1/L/SIMA/3, dated 28-12-67 enclosed with Manager's letter No. CMB-1/1046, dated 28-12-67 submitted to Director-General of Mines Safety for obtaining a permission under Regulation 127 showed the HFL of Nakari as 1130 ft. without showing the date thereof.	61.	R-9	Noting and papers dealing with depillaring sanction at Zonal Office.
55.	R-3	Plan No. BHK-1/L/SIMA/3, dated 29-3-68 enclosed with Manager's letter No. CMB-1/382, dated 30th March, 1968 for obtaining permission under Regulation 122 showed the HFL of Nakari as 1130 ft. without showing the date thereof.	62.	R-9(i)	Noting in DGMS Zonal Office file on application of Management regarding sanction for depillaring.
56.	R-4	Plan No. 69 dated 20-1-66 of Upper Semana Seam submitted along with the Management's letter No. DSOC/BHK/Dipp-Sirka/571, dated 18/20th January, 1966 for obtaining a permission for depillaring in Sirka Seam Mine to the Chief Inspector of Mines shows the HFL of Nakari river as 1130.09 on 23-7-58.	63.	R-10	Telegram No. 161 ON-198 from Vizianagaram to Mines Safety, Ranchi, dated 10th May, 1977 regarding visit of Mazumdar to PTPS.
57.	R-5	On Plan No. CMB-1/LN/8, dated 23-1-76 enclosed with Deputy Chief Engineer's letter No. DCME/BHK/DGMS-Permission/1356-59, dated 14/19th January, 1976 for obtaining a permission under Regulation 126(2) for developing Lower Nakari Seam of Mine No. 1 of Bhurkunda within 15 metres and under the nullah, the HFL of Nakari river was shown as 1130 ft. Permission was granted by Director's letter No. DIR/SEZ/RR/2955, dated 24-6-76.	64.	S	Joint Survey Plan submitted by DGMS.
58.	R-6	Plan showing the proposed workings of Agrada 'B' Seam on the South side and the rise side of the Seam—Plan No. SND/S/ARGB/Lay out/D-M/8/70-71 signed by Surveyor Shri Banerjee on 8-7-70 enclosed with Management's letter No. SAUN/Angada/South/70/14030-32, dated 24-7-71—Regional Office Dy. No. 4759, dated 28-7-1970—HFL shown as 337.7 metres date of HFL not shown.	65.	T	History file of the Central Saunda Mine.
59.	R-7	In plan No. SA-1/63 of 28-6-63 the HFL of Nakari river was shown as RL as 1129.39 as on 23-7-58. This plan was submitted with Manager's letter No. M/Dep/2204, dated 25th July, 1963 for obtaining a per-	66.	T-1	Item 1.7 of History file of the Central Saunda Mine.
			67.	U	Working Plan of Central Saunda Mine, Nakari Seam, dated 29-10-64.
			68.	U-1	Central Saunda Colliery working plan of Hathidari Seam, dated 29-10-64.
			69.	U-2	Central Saunda Colliery working plan of Hathidari Seam, dated 20-11-70.
			70.	V	DGMS headquarters file No. MI 590 (B/1)-74-Vol. I (Central Saunda Colliery).
			71.	V-1	Signature, dated 28-1-75 of Shri S.R. Sarkar in the file, Exhibit V.
			Exhibits file in the Court by witnesses or seized by the Court.		
			1.	CR-1	Working Plan of Hathidari Seam (Blue Print).
			2.	CR-2	Letter No. 660, dated 28th/29th March, 1977 from the General Manager-cum-Chief Engineer, Patratu Thermal Power Station regarding release of water from Dam.
			3.	CR-2A	Enclosures to Exhibit CR-2.
			4.	CR-3	Letter No. 52, dated 13th May, 1977 from Patratu Thermal Power Station enclosing document relating to rainfall, rain gauge records etc.
			5.	CR-3A	List of information and documents relating to Exhibit CR-3.
			6.	CR-3B	Rain gauge Record-Patratu from 15-8-76 to 10-9-76
			7.	CR-3C	Area capacity curve Nakari Reservoir.
			8.	CR-3D	Discharge rating chart for spillway gates.
			9.	CR-3E	Table for discharge for partial gate opening.
			10.	CR-3F	Gate Log Book for period 1-8-74 onwards.
			11.	CR-3G	Statement relating to inflow in the Nakari Dam.
			12.	CR-3H	Gauge Register for the period 1972.
			13.	CR-3I	Reservoir Level of Nakari, 1968-75.
			14.	CR-3J	Telex message sent by Patratu to Chairman, Bihar State Electricity Board, Patna on 19-9-76.
			15.	CR-4	Letter No. 1345, dated 24-6-77 from PTPS.

1	2	3
16.	CR-4A	F.I.R. of Balbinder Singh, subsequently marked as a document for identification and marked 'Z' vide Order Sheet No. 16(v), dated 8-8-1977.
17.	CR-5	Letter No. 1346, dated 24-6-77 from PTPS.
18.	CR-5A	Gate Operation and Inspection Schedule of Nakari Dam and Spillway, PTPS.
19.	CR-5B	Operation of Gate and discharge of water from 10 to 20th September, 1976.
20.	CR-6	The Plan topographical map of PTPS filed by PTPS and originally marked item 'Y' for identification is now authenticated.
21.	CR-7	Letter No. 1278, dated 15-6-77 from Shri N. Kerketta to Shri Satpal Singh, Secretary to the Court along with 4 pages of enclosed note, dated 14-6-1977.
22.	CR-7A	Letter No. 2238, dated 9-7-70 from Shri D.N. Mehta, Supdt. Engineer, Tenughat Dam Circle No. 1 to Additional Chief Engineer, PTPS.
23.	CR-7B	Letter No. 1796, dated 23-8-70 from Shri N.R. Krishnamurthy, Supdt. Engineer (C), Patratu Civil Circle (Power House), Patratu to Sh. D.N. Mehta, Supdt. Engineer (C), Tenughat Dam Circle No. 1.
24.	CR-7C	Memo. No. 3655, dated 24-1-73 from Managing Director, NCDC Ltd., Ranchi to Shri Sahey, G.S. PTPS, Patratu.
25.	CR-7D	Memo. No. 2172, dated 18-7-76 from Shri N. Kerketta, General Supdt. to Dy. Chief Mining Engineer, Bhurkunda Colliery.
26.	CR-7E	Memo. No. 1686, dated 24-9-76 from Shri J.P. Verma, Executive Engineer (Civil) I, Patratu to Shri K. N. Pradhan, Executive Engineer (Civil), Civil Division No. II PTPS.
27.	CR-8	Letter No. 1129, dated 31-5-1977 from Shri N. Kerketta to Shri Satpal Singh, Secretary to the Court.
28.	CR-8A	Letter No. 970, dated 9-3-70 from Supdt. Engineer, P. W. D., Hazaribagh Road Circle to Chief Engineer, (Civil) PTPS.
29.	CR-8B	Letter No. 136, dated 22-4-76 from Shri N. Kerketta, General Manager-cum-Chief Engineer, PTPS to Supdt. Engineer, P.W.D. Hazaribagh.
30.	CR-8C	Report about the Coffer Dam along with sketch enclosed.
31.	CR-9	Nakari Dam, Inspection Schedule Register 104 pages.
32.	CR-10	Letter No. Saun/Peen/HEL/PREC/77-78/7711-17, dated 23-6-77 from Shri R.P. Singh, Dy. Chief Mining Engineer, Saunda/Basgura Colliery to Joint Director of Mines Safety, regarding Danger of inundation.
33.	CR-10A	Saunda Colliery Working Plan of New Argada Incline-Plan No. SNI/NEW-AGD-HEL/2-B/77-78, dated 13th June, 1977.
34.	CR-10B	Saunda Colliery Plan showing the outskirts of all the present working seams quarries with HFL lines and the surface positio

1	2	3
		and main fault. Plan No. SND/GEN/HFL 2/77-78, dated 13-6-1977.
35.	CR-10C	Saunda Colliery Part Offset Plan of Sirka Seam Working Plan No. SND/SIR/OFFSET 2A/77-78, dated 12th June, 1977.
36.	CR-11	Level Book of NCDC, Saunda Colliery.
37.	CR-11A	Flood level markings in respect of HFL of 1964 at NCDC Saunda as per Exhibit CR-11 and as reflected on the tracing paper.
38.	CR-11B	The calculation of 1964 HFL at NCDC, Saunda as reflected on a tracing paper in 1966 and bearing signature of the Surveyor, dated 27-8-1966.
39.	CR-12	Survey of India Plan, Reference Sheet No. 48 Q, pertaining to serial survey of Damodar Valley and Hazaribagh area.
40.	CR-13	Seizure Memo. No. Nil, dated 29-8-1977 pertaining to daily Shift Incharge Report book of Gidi 'A' Pilot Mine.
41.	CR-13A	The Register mentioned in the exhibit 13 was received from the DGMS. The entry in the Register pertaining to 16-9-1976 is relevant. The extract of this entry is retained by Court.
42.	CR-14	Sixteen documents filed by Shri B.L. Wadehra on 15-12-77 and marked compendiously.
	CR-14A	These pertain to instructions on production and safety, issued by Shri Wadehra
	CR-14-O	from time to time.

ANNEXURE-IV

List of Documents marked for Identification

Sl. No.	Marked	Description of the document
1	2	3
1.	Z	The FIR Report of Balbinder Singh was originally accepted as an exhibit CR-4A and subsequently marked 'Z' for identification. Order Sheet No. 16(v), dated 8-8-1977 refers.
2.	X-7	Unsigned Report of inrush of flood water in different Mines of Argada area is marked X-7.
3.	X-8	Unsigned report of inrush of flood water in different inclines of Karanpura areas is marked X-8.
4.	X-9	Unsigned Progress of water level and position of different inclines at Saunda Colliery is marked X-9.
5.	X-10	Note (unsigned) filed by DGMS on the danger of eruption of Surface Water into the underground workings and the necessary safety conditions which are to be practiced, is marked X-10.
6.	X-11	Table (unsigned) showing HFL in six of the mines is marked X-11.

[No. N. 11015/5/79-MI]

MEENA GUPTA, Under Secy.